रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73 REGISTERED No. D(D)—73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 24, 1977/पौष 3, 1899
No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 24, 1977/PAUSA 3, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1977

का० आ० 3948—यत, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 42 मिरयालगुडा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले एक उम्मीदवार श्री मोगिली, मुल्लाय्या, येरुकला बाजार, सूर्यपेट, जिला नालगोंडा (आंध्र प्रदेश), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मोगिली मुल्लाय्या को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० आ० प्र०-लोक स०/42/77]
आई० के० के० मेनन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 23rd November, 1977

S.O. 3948.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mogili Pullaiah, Yerukola Bazar, Suryapet District Nalgonda (Andhra Pradesh), a contesting candidate for the general election held in March, 1977 to the house of the people from 42-Miryalguda constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mogili Pullaiah to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP—HP/42/77]
I. K. K. MENON, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1977

का० आ० 3949—केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ,

अत अब एकाधिकार एव निर्बन्धनकारी व्यापार नियम, 1970 के नियम 5 के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस आदेश की अनुसूची मे विनिर्दिष्ट क्षेत्रो के ग्रस्त गतिविधियो के लगे हुए उपक्रमो के वर्ग के सम्बन्ध मे उक्त नियम के उपनियम (1) मे निर्दिष्ट साधारण सूचना के प्रकाशन से, इस आदेश द्वारा अभियुक्त प्रदान करती है।

अनुसूची

1 गहरे समुद्र मछुआ पोत का अधिग्रहण ।
2 गहरे समुद्र मछुआ पोत का चार्टरिंग।
3 मैरिन उत्पाद विधायन के लिये पोत स्थल स्थापन।

[फाइल स० 38/12/76-सी एल-5]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

ORDER

New Delhi, the 8th December, 1977

S.O. 3949.—Whereas the Central Govrnment is of opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest ,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of rule 4A of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970, the Central Government hereby dispenses with the publication of the general notice referred to in sub-rule (1) of the said rule, in respect of class of undertakings which propose to engage in activites in the areas specified in the Schedule to this Order.

SCHEDULE

1 Acquisition of deep-sea fishing vessels
2 Chartering of deep-sea fishing vessels
3 Establishment of on-shore facilities for processing Marine Produce

[F. No 38/12/76 C L V]

का० आ० 3950—केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक व समीचीन है

अत अब, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा नियम 1970 के नियम 5 के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, कृषि एवं सिचाई मत्रालय कृषि विभाग द्वारा मत्स्य ग्रहण प्रानायको के आयात के लिये आवेदन-प्रपत्र के रूप में विहित किये गये प्रपत्र को उस प्रपत्र के रूप मे विनिर्दिष्ट करती है, जिसमे, गहन समुद्र मत्स्य ग्रहण पोतो की प्राप्ति का प्रस्ताव करने वाली कम्पनियो द्वारा एकाधिकार एव निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 51) की धारा 21 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नोटिस दिया जायेगा।

[फाइल स० 38/12/76-सी० एल० 5]

S.O. 3950.—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest ,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of rule 5 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970, the Central Government hereby specifies the Form, which has been prescribed as the application form by the Ministry of Agriculture and Irrigation, Department of Agriculture for importing of Fishing Trawlers as the form in which a notice under sub-section (1) of section 21 of the Monopolies and Restrictive Trade practices Act, 1969 (54 of 1969), shall be given by undertakings proposing to acquire deep sea fishing vessels

[F No 38/12/76-C L V]

का० आ० 3951—केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित मे ऐसा करना आवश्यक व समीचीन है

अत अब एकाधिकार एव निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा नियम 1970 के नियम 5 के उप-नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, कृषि एव सिचाई मत्रालय, कृषि विभाग द्वारा, मत्स्य ग्रहण पोत के भाड़े पर देने के लिये, आवेदन-प्रपत्र के रूप मे विहित किये गये प्रपत्र को, उस प्रपत्र के रूप मे विनिर्दिष्ट करती है, जिसमे गहन-समुद्र मत्स्य ग्रहण पोतो को भाड़े पर देने का प्रस्ताव करने वाली कम्पनियो द्वारा, एकाधिकार एव निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 21 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, नोटिस दिया जायेगा।

[फाइल स० 38/12/76-सी० एल० 5]

S.O. 3951.—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest ,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of rule 5 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970, the Central Government hereby specifies the Form, which has been prescribed as the application form by the Ministry of Agriculture and Irrigation, Department of Agriculture for chartering of fishing vessels, as the application form in which a notice under sub-section (1) of section 21 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), shall be given by undertakings proposing to charter deep-sea fishing vessels

[F No 38/12/76 C L V]

का० आ० 3952—केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित मे ऐसा करना आवश्यक व समीचीन है ,

अत अब, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा नियम, 1970 के नियम 6 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1951 (1951 का 65) के अन्तर्गत लाइसेंस अथवा अनुज्ञा के लिए, आवेदन-प्रपत्र के रूप मे विहित किये गए प्रपत्र को, प्रपत्र 49 के रूप में विहित करती है, जिसमे, समुद्री उत्पाद विधायन के लिये अभिनट सुविधाओ की स्थापना के लिये प्रस्ताव करने वाले उपक्रमो द्वारा एकाधिकार एव निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 22 की उपधारा (2) के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिया जायेगा।

[फाइल स० 38/12/76-सी० एल० 5]

कान्त मणि शर्मा, अवर सचिव

S.O. 3952. Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest ,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (3) of rule 6 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970, the Central Government hereby specifies the Form IL, which has been prescribed as the application form for licence or permission under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), as the form in which an application under sub-section (2) of section 22 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), shall be made by undertakings proposing to establish on shore facilities for processing Marine produce

[F No 38/12/76-C L V]

K. M. SHARMA, Under Secy

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1977

का० आ० 3953—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली के न्यायालय मे राम लाल नारग तथा अन्यों के विरुद्ध दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना नियमित मामला संख्या 4/76-सी०आई०यू०(ए) के अभियोजन का सचालन करने हेतु श्री आर० एल० मेहता, अधिवक्ता, दिल्ली को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 225/67/77-ए० वी० डी०II]

टी० के० सुब्रमनियन्, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 6th December, 1977

S.O. 3953.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri R. L. Mehta, Advocate, Delhi, as a special public prosecutor for conducting the prosecution of the Delhi Special Police Establishment Regular Case No. 4/76-CIU(A) against Ram Lal Nagrang and others in the Court of Chief Metropolitan Magistrate, Delhi.

[No. 225/67/77-AVD. II]

T. K. SUBRAMANIAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1977

स्टाम्प

का० आ० 3954.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899(1899 का 2) की धारा 20 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) दिनाक 5 नवम्बर, 1977 के, पृष्ठ 3911 और 3912 पर प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 31 अक्तूबर, 1977 की अधिसूचना संख्या 33/स्टाम्प (का० आ० सं० 3477) में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के नीचे दी गई सारणी में क्रम संख्या 4, 11, 14 और 16 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित क्रम सख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी और अर्थात् :—

1	2	3
"4	कनाडियन डालर	12.74";
"11	जापानी येन	28.00";
"14	पौंड स्टार्लिंग	6.3190";
"16	स्विस फैंक	25.10";

[संख्या 38/स्टाम्प—का० सं० 33/3/77-वि० कर]

एम० डी० रामास्वामी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 5th December, 1977

STAMPS

S.O. 3954.—In exercise of the powers confe red by sub-section (2) of section 20 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 33/Stamps-(S.O. No. (3477), dated the 31st October, 1977, published at pages 3911 and 3912 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 5th November, 1977; namely :—

In the Table below the said notification, for Serial Nos. 4, 11, 14 and 16 and the entries relating thereto, the following Serial Nos. and entries shall, respectively be substituted, namely :—

1	2	3
" 4	Canadian dollars . . .	12.74" ;
" 11	Japanese Yen	2800 " ;
" 14	Pound Sterling	6.3190" ;
" 16	Swiss Francs	25.10" ;

[No. 38/Stamps—F. No. 33/3/77-ST]

S.D. RAMASWAMY, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1977

का० आ० 3955:- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना 1970 के खण्ड 3 के उपखण्ड (च) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, एतद्द्वारा दिसम्बर, 1977 के छटे दिन से प्रारम्भ होकर दिसम्बर, 1980 के पाचवें दिन को समाप्त होने वाली ; वर्ष की अवधि के लिये, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशकों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है:--

1. श्री कमल टण्डन,
   निदेशक,
   ग्योर गेसेस (प्राइवेट) लिमिटेड
   5 ईस्ट निजामुद्दीन,
   नई दिल्ली-110013

2. श्री पी० एल० जुनेजा,
   एडवोकेट,
   भारत का सर्वोच्च न्यायालय,
   फ्लेट, नं०, 1 शंकर मार्केट,
   कनॉट सर्कस, नई दिल्ली।

[संख्या एफ० 9/33/77-बी० ओ०-I]

बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 6th December, 1977

S.O. 3955.—In pursuance of sub-clause (f) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints the following persons as Directors of the Bank of Maharashtra for a period of three years commencing on the 6th day of December, 1977 and ending with the 5th day of December, 1980.

1. Shri Kamal Tandon,
Director,
Pure Gases (P) Ltd.,
5, East Nizamuddin,
New Delhi-110013.

2. Shri P. L. Juneja,
Advocate,
Supreme Court of India,
Flat No. 1, Shankar Market,
Connaught Circus,
New Delhi.

[No. F. 9/33/77-BO.I]

BALDEV SINGH, Joint Secy.

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय)

बंगलौर, 29 सितम्बर, 1977

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का० आ० 3956:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, इस अधिसूचना द्वारा, इस समाहर्तालय के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपसमाहर्ताओं को, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली 1944 के नियम 191-क तथा 191-ख के अन्तर्गत 'निर्माण फार्मूला' अनुमोदित करने के लिए समाहर्ता की शक्तियां प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं।

2. इस समाहर्तालय के दिनांक 7-12-70 की पूर्व अधिसूचना सं० 9/70 इस अधिसूचना द्वारा निरस्त की जाती है।

[केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिसूचना सं० 5/77]

आर० एन० शुक्ल, समाहर्ता

(Office of the Collector of Central Excise)

Bangalore, the 29th September, 1977

CENTRAL EXCISES

S.O. 3956.—In exercise of the powers conferred on me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby empower the Deputy Collectors of Central Excise in this Collectorate to exercise the powers of the Collector under Rules 191-A and 191-B of Central Excise Rules, 1944, in regard to approval of manufacturing formula.

2. This Collectorate earlier Notification No. 9/70 dated 7-12-1970 is hereby rescinded.

[Central Excise Notification No. 5/77]

R. N. SHUKLA, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1977

का० आ० 3957.—मैसर्स भारत पल्वराईजिंग मिल्स प्रा० लिमिटेड, बम्बई, को आई० डी० ए० क्रेडिट के अन्तर्गत कीटनाशक के विनिर्माण के लिए कच्चे माल आयात करने के लिए 1,09,93,000 रुपये के लिए आयात लाइसेंस सं० पी०/डी०/2204468, दिनांक 24-12-75 प्रदान किया गया था। इन्होंने उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है। आगे यह भी बताया गया है कि विषयाधीन लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति 66,44,354 रुपये की धनराशि तक उपयोग में लाने के पश्चात् खो गई है और यह सीमा-शुल्क कार्यालय, बम्बई में पंजीकृत करायी गयी थी।

2. अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं० पी०/डी०/2204468, दिनांक 24-12-75 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है तथा निदेश देता है कि उनको उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए।

लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति रद्द की जाती है।

[संख्या: एस०पी०सी०एच०/बी०-3(2)/ए०एम०-76/आर० एम० III/990]

जी० एस० ग्रेवाल, उप-मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi)

ORDER

New Delhi, the 5th December, 1977

S.O. 3957.—M/s. Bharat Pulverising Mills Pvt. Ltd., Bombay were granted Licence No. P/D/2204468 dated 24-12-75 for import of raw materials for manufacture of pesticides for Rs. 1,0993,000/- under IDA Credit. They have requested for issue of a duplicate Exchange Control purpose copy of the Licence on the ground that the Original Exchange Control copy of the licence has been misplaced. It has further been stated that the Exchange Control copy of the licence in question was misplaced after utilising Rs. 66,44,354 and that the same had been registered with the Collector of Customs, Bombay.

2. In support of their contention, the applicant has filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the Original Exchange Control copy of Licence No. P/D/2204468 dated 24-12-75 has been lost and directs that duplicates Exchange Control copy of the said licence should be issue to them.

The Original Exchange Control copy of the licence is cancelled.

[No. SP-CH/B-3(2)/AM. 76/RM. III/990]

G. S. GREWAL, Dy. Chief Controller

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1977

का० आ० 3958.--पूर्त अक्षयनिधि अधिनियम, 1890 के मामले में और पाश्चूर इंस्टिट्यूट आफ इंडिया के मामले में।

यत: पाश्चूर इन्स्टिट्यूट आफ इण्डिया ने केन्द्रीय सरकार से यह आवेदन किया है कि भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 14-26/61-इंस्ट, दिनांक 31-8-1962 के साथ संलग्न की गई अनुसूची में निर्दिष्ट उन अचल सम्पत्तियों का वास्तविक मूल्य बतलाते हुए संशोधन किया जाए जो उक्त अधिसूचना के आधार पर भारत के पूर्त अक्षयनिधि के कोषपाल के अधिकार में है।

अत: अब पूर्त अक्षयनिधि अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त आवेदन के अनुसार केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अनुसूची के पैरा 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :--

अनुसूची

अचल सम्पत्ति	वास्तविक मूल्य	
1. अलर्क रोधी अनुसंधान केन्द्र भवन, कसौली	2,23,200.00 रु०	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली द्वारा अधिकृत
2. लेडी लिनलिथगो सेनेटोरियम बिल्डिंग, कसौली	22,18,300.00 रु०	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली द्वारा अधिकृत
3. शेल्टनलाज, कसौली	26,000.000 रुपये	रिक्त

[संख्या एस० 22020/11/76-एम० सी० (एम० एस०)]

आर० वी० श्रीनिवासन्, उप सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 31st August, 1977

S. O. 3958.—In the matter of Charitable Endowment Act, 1890 and in the matter of the Pasteur Institute of India.

Whereas an application has been made to the Central Government by the Pasteur Institute of India that the Schedule attached to the Government of India, Ministry of Health's notification No. F. 14-26/61-Instt., dated the 31-8-1962 may be amended indicating the actual value of the immovable properties specified therein, which are vested in the Treasurer of Charitable Endowments for India by virtue of the said notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890) and on the application as aforesaid, the Central Government hereby directs that para 1 of the said schedule may be substituted as under :—

SCHEDULE

Immovable Property	Actual Value	
	Rs.	
1. Anti-rabies Research Centre Building, Kasauli.	2,23,200.00	Occupied by the CRI, Kasauli.
2. Lady Linlithgow Sanatorium Building, Kasauli.	22,18,700.00	Occupied by the CRI, Kasauli.
3. Shelton Lodge, Kasauli	26,000.00	Vacant.

[No. S. 22020/11/76-MC (MS)]

R.V. SRINIVASAN, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1977

का० आ० 3959.—केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (कानपुर) नियमावली, 1972 के नियम 1 के उपनियम (3) के खण्ड (iv) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कानपुर के उन क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करती है जिनमें उक्त नियम लागू होंगे, अर्थात् :—

जी० टी० रोड पर स्थित काकोरी गांव से लेकर गंगागन्ज तक का क्षेत्र, गंगागंज से दक्षिण की ओर 1.6 कि० मी० तक पी०ए०सी० रोड से विभाजित क्षेत्र जिसमें पी०ए०सी० ग्राउन्ड के निकट स्थित क्षेत्र से लेकर इस ग्राउन्ड की पूर्वी सीमा तक का सम्पूर्ण क्षेत्र शामिल है।

पी० ए० सी० ग्राउण्ड की पूर्वी सीमा से लेकर हरजेन्द्र नगर-जाजमऊ रोड से विभाजित जाजमऊ स्थित जे० के० रेयन और पायनीयनर तानारी फैक्टरी तक का क्षेत्र जिसमें कृष्ण नगर, गांधी ग्राम, शिव कटरा, कुष्ठ रोग अस्पताल हरजेन्द्र नगर, सफीपुर, जाजमऊ लेबर कालोनी और जाजमऊ तक चकेरी हवाई अड्डे का सारा क्षेत्र आता है।

जे० के० रेयन मिल से लेकर गंगा और टैगोर रोड से विभाजित भज्जा पुर्वा की पूर्वी सीमा तक का क्षेत्र, जिसमें जाजमऊ मकू पुर्वा और पैराशूट कलोनी का क्षेत्र शामिल है।

भज्जापूर्वा की पूर्वी सीमा वाला क्षेत्र, पील रोड के क्रासिंग पर टैगोर रोड और ओल्ड जी० टी० रोड को मिलाने वाली लाइन, जिसमें लाल कुर्ती, ओम पुर्वा, जगाए पुर्वा, पोखर पुर्वा, चन्द्र नगर, बंगाली कालोनी, शाहदुल्लापुर, नेताजी नगर, एच० ए० एल० कालोनी, पटेल नगर, महाराजपुर, लालबंगला, घनश्याम बाग, काजी, खेड़ा, [illegible] और बेकीगंज का क्षेत्र शामिल है।

पील रोड और इलाहाबाद चकेरी रोड के क्रासिंग और पील रोड तथा नेपियर रोड से विभाजित क्षेत्र से लेकर जी० टी० रोड तक का क्षेत्र।

नैपियर रोड और जी० टी० रोड के संगम वाला क्षेत्र और जी० टी० रोड से विभाजित क्षेत्र से लेकर काकोरी गांव तक का क्षेत्र।

[सं० एस० 11011/7/76-के० स०स्वा०यो०]

राजकुमार जिन्दल, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd November, 1977

S.O. 3959.—In pursuance of clause (i) of sub-rule (3) of rule 1 of the Central Government Health Scheme (Kanpur) Rules, 1972, the Central Government hereby specifies the following areas in Kanpur to which the said rules shall extend, namely :—

Area starting from Kakori village located at G. T. Road upto Ganga Ganj, from Ganj area divided by PAC Road upto 1.6 k.m. in southern side covering whole area located near PAC ground upto east border of this ground.

From east border of PAC ground area divided by Harjender Nagar-Jajmau Road upto J. K. Rayon and Pioneer Tanary Factory at Japmau, covering by Krishna Nagar, Gandhi Gram Shiv Katra, Leprosy Hospital, Harjinder Nagar,Safi pur, Jajmau Labour Colony and whole area of Chakeri Aero-drome upto Janmau.

From J. K. Rayon Mill, area divided by Ganga and Tagore Road upto eastern border of Bhajja Purwa, area covering by Jajmau, Maiku purwa and Parachute Colony.

Area covering eastern border of Bhajjapurwa, a line joining the Tagore Road with Old G. T. Road at the crossing of Peel Road, are covering Lal Kurti, Om Purwa, Jugal Pulwa, Pokhar purwa, Chandra Nagar, Bengali Colony, Shahdulapur,

Netajinagar, Hal Colony, Patel Nagar, Maharajpur, Lal Banglow, Bhanshyam Bagh, Kaji-Khera, Chau Khera and Devi Ganj.

Area from the crossing of Peel Road and Allahabad Chakeri Road and area divided by Peel Road and Napier Road upto G. T. Road.

Area covering the junction of Napier Road and G. T. Road and area divided by G. T. Road upto Kakori village.

[No. S. 11011/7/76-CGHS(P)]

R. K. JINDAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1977

का० आ० 3960.—स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम 1966 (1966 का 51) की धारा (5) के खण्ड-(ङ) के अनुक्रम में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस० एस० पुरी, मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, चण्डीगढ़ को श्री एच० एस० चन्ना, जिन्हें त्याग पत्र दे दिया है, के स्थान पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के सदस्य के रूप में मनोनीत करती है।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय की तारीख 30 जून, 1977 की अधिसूचना संख्या बी० 17013/1/77-एम० ई० (पी०जी०) में क्रम संख्या 3 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाये :—

"3. श्री एस० एस० पुरी,
मुख्य सचिव,
पंजाब सरकार, चण्डीगढ़।"

[संख्या बी० 17013/1/77-एम० ई० (पी० जी०)]

पी० सी० जैन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th November, 1977

S.O. 3960.—In pursuance of clause (e) of Section 5 of the Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1966 (No. 51 of 1966), the Central Government hereby nominates Shri S. S. Puri, Chief Secretary to the Government of Punjab, Chandigarh to be a Member of the Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh *vice* Shri H. S. Chhina resigned.

In the Ministry of Health and Family Welfare Notification No. V. 17013/1/77-M.E. (PG), dated the 30th June, 1977, for Serial No. 3, following shall be substituted :—

"3. Shri S. S. Puri, Chief Secretary,
Government of Punjab, Chandigarh."

[No. V. 17013/1/77-M.E.(PG.)]

P. C. JAIN, Desk Officer.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1977

का० आ० 3961.—राष्ट्रपति मूल नियम के नियम 45 के उपबन्धों के अनुसरण में, नव तूतीकोरिन पत्तन (निवास-आबंटन) नियम, 1971 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नव तूतीकोरिन पत्तन (निवास-आबंटन) संशोधन नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नव तूतीकोरिन पत्तन (निवास आबंटन) नियम, 1971 के नियम 9 के उपनियम (i) के खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) पत्तन के उपसंरक्षक, यातायात प्रबन्धक, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी सचिव, अधीक्षण इंजीनियर, बन्दरगाह मास्टर, कार्यपालक इंजीनियर, पाईलट, चिकित्सा अधिकारी और लेखा अधिकारियों का पूल।'

[सं० पी०ई०टी०-17/76]

डी० सी० अहीर, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 7th December, 1977

S.O. 3961.—In pursuance of the provisions of Rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following rules to amend the Port of New Tuticorin (Allotment of Residences) Rules, 1971, namely :—

1. (1) These rules may be called the Port of New Tuticorin (Allotment of Residences) Amendment Rules, 1977;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Port of New Tuticorin (Allotment of Residences) Rules, 1971, for clause (ii) of sub-rule (1) of rule 9, the following clause shall be substituted, namely :—

"(ii) Pool for the Deputy Conservator, the Traffic Manager, the Financial Adviser & Chief Accounts Officer, the Secretary, the Superintending Engineers, the Harbour Master, the Executive Engineers, the Pilots, the Medical Officers and the Accounts Officers of the Port."

[No. PET-17/76]

D. C. AHIR, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1977

का० आ० 3962.—सीमेन्ट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, एक्सप्रेस बिल्डिंग, चर्चगेट, मुम्बई के बारे में नियोजकों और उसके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व इंडियन नेशनल सीमेण्ट एण्ड एलाइड वरर्क्स फेडरेशन, मजदूर कार्यालय, कांग्रेस हाउस, मुम्बई करता है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, उक्त नियोजक और कर्मकार एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के माध्यस्थम् को निर्देशित करने के लिए सहमत हैं, और उक्त करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध करा दी गई है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के अनुसरण में उक्त करार प्रकाशित करती है।

करार

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन निम्नलिखित के बीच

पक्षकारों के नाम

नियोजकों के प्रतिनिधि :	दि सीमेण्ट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन एक्सप्रेस बिल्डिंग, चर्च गेट स्टेशन के सामने, मुम्बई-400020
कर्मकारों के प्रतिनिधि :	दि इण्डियन नेशनल सीमेण्ट एण्ड एलाइड वरकर्स फेडरेशन, मजदूर कार्यालय, कांग्रेस हाउस, मुम्बई-400004।

ऊपर नामित पक्षकार, तारीख 14-9-1977 के करार द्वारा, जिसकी एक प्रति इससे उपाबद्ध है और उपाबन्ध 'क' के रूप में चिह्नित है, तारीख 22-8-1977 की अपनी हड़ताल की सूचना से, दि इण्डियन नेशनल सीमेण्ट एण्ड एलाइड वरकर्स फेडरेशन द्वारा उठाये गये विवादों को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10-क के अधीन माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने के लिए सहमत है।

उपरोक्त निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित विवाद को निम्नलिखित के माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट करने का पक्षकारों के बीच करार किया जाता है :—

(1) श्री जी० रामानुजम, 2/44 रोयापेठा हाई रोड, मद्रास-14

(2) श्री आर० पी० नेवाटिया बजाजस, भवन नारीमन पॉइन्ट, मुम्बई-400020।

(i)	विवादग्रस्त विनिर्दिष्ट मामला	क्या इससे संलग्न तारीख 22-8-77 के मांग-चार्टर में अन्तर्विष्ट मांगें न्यायोचित हैं? यदि हैं तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?
(ii)	विवादग्रस्त पक्षकारों के विवरण जिसमें अन्तर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी शामिल है।	(क) सीमेण्ट मैनुफैक्चरर्स, एसोसिएशन, एक्सप्रेस बिल्डिंग चर्च गेट के सामने, स्टेशन मुम्बई-400020। (ख) दि इण्डियन नेशनल सीमेण्ट एण्ड एलाइड वरकर्स फैडरेशन, मजदूर कार्यालय, कांग्रेस हाउस, मुम्बई-400004
(iii)	यदि कर्मकार स्वयं विवाद में अन्तर्वलित है तो उसका नाम, या उस संघ का नाम, यदि कोई हो जो संबंधित कर्मकार या कर्मकारों का प्रतिनिधि है	इण्डियन नेशनल सीमेण्ट एण्ड एलाइड वरकर्स फेडरेशन।
(iv)	प्रभावित उपक्रमों में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या	90,000 (लगभग)
(v)	उन व्यक्तियों की प्राक्कलित संख्या जो विवाद द्वारा प्रभावित हैं या जिनके विवाद से प्रभावित होने की संभावना है।	90,000 (लगभग)

हम इस बात पर भी सहमत हैं कि मध्यस्थों का एकमत निर्णय हम पर आबद्धकर होगा। यदि मध्यस्थों की राय विभाजित है तो वे किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को अधिनिर्णायक नियुक्त करेंगे जो परस्पर स्वीकार्य होगा और जिसका पंचाट हम सब पर आबद्धकर होगा।

मध्यस्थ निर्देश किए जाने की तारीख से दो मास के भीतर अपना पंचाट दे देंगे। यह अवधि पक्षकारों की सहमति से बढ़ाई जा सकती है। पंचाट के प्रवर्तन की अवधि मध्यस्थों द्वारा विनिश्चित की जाएगी। मध्यस्थ पंचाट देने में पक्षकारों की दलीलों पर सम्यक् रूप से विचार करेंगे।

पक्षकारों के हस्ताक्षर :—

नियोजकों के प्रतिनिधि :— सीमेण्ट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के लिए और उनकी ओर से	कर्मकारों के प्रतिनिधि :— इण्डियन नेशनल सीमेण्ट एण्ड एलाइड वरकर्स फेडरेशन के लिए और उनकी ओर से
बी०बी० राजू (उपाध्यक्ष)	एन० एन० द्विवेदी (अध्यक्ष) 13-10-77
साक्षी	साक्षी :
1. पी० बी० गुणीशास्त्री 14-10-77	1. ह०/– अपाठ्य 13-10-77

उपाबन्ध 'क'

उद्देशिका

भारत के प्रधानमंत्री की इच्छाओं का आदर करते हुए, इंडियन नेशनल सीमेंट एण्ड एलाइड वरकर्स फ़ेडरेशन तथा सीमेंट मैन्यूफ़ैक्चरर्स एसोसिएशन ने, अपने सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए, हड़ताल सूचना तारीख 22 अगस्त, 1977 में उल्लिखित समस्याओं से उठने वाले विवाद को माध्यस्थम के माध्यम से तय करने की बात मान ली है। सीमेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार, मध्यस्थों को, अन्य बातों के साथ-साथ, साधारण आर्थिक स्थिति, सीमेंट उद्योग के वित्तीय साधनों, अदायगी हैसियत तथा संघटक एककों का उत्पादकता के स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। फ़ेडरेशन के अनुसार, मध्यस्थ को अन्य सुसंगत कारकों को भी ध्यान में रखना चाहिए। फ़ेडरेशन तुरन्त हड़ताल समाप्त करने के लिए सहमत है। नियोजक सहमत हैं कि किसी कर्मकार को परेशान न करेंगे।

2 पक्षकार केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन करने के लिए भी सहमत है कि विभिन्न राज्यों में फैले हुए उद्योग की राष्ट्रीय महत्ता को ध्यान में रखते हुए, माध्यस्थम राष्ट्रीय आधार पर और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10क के उपबन्धों के अधीन रहते हुए होना चाहिए और उसके अन्तर्गत वे सभी एकक जो दो भूतपूर्व केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड के विषय-क्षेत्र में थे, करार तारीख 7 मई, 1975 और बाद में स्थापित नए एकक आने चाहिएं। पक्षकार केन्द्रीय सरकार से निवेदन करते हैं कि वह इस निवेदन के अनुसार कार्य करे।

माध्यस्थम करार

पक्षकारों के नाम :

1. कर्मकारों के प्रतिनिधिः—इंडियन नेशनल सीमेंट एण्ड एलाइड वरकर्स फ़ैडरेशन, मजदूर कार्यालय, कांग्रेस हाउस, मुम्बई, जिनका प्रतिनिधित्व निम्नलिखित करेंगे:—

1. श्री एन०एन० द्विवेदी
2. श्री सी० एल० दूधिया

2. नियोजकों के प्रतिनिधिः—सीमेंट मैन्यूफ़ैक्चरर्स एसोसिएशन, एक्सप्रेस बिल्डिंग, चर्चगेट, मुम्बई, जिनका प्रतिनिधित्व निम्नलिखित करेंगे :—

1. श्री अशोक कुमार जैन,
2. श्री बी०बी० राजू

हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता नीचे विनिर्दिष्ट विवाद को, निम्नलिखित के माध्यस्थम को निर्देशित करने के लिए सहमत है :—

(1) श्री जी० रामानुजम, 2/44, रोयापेटा हाई रोड, मद्रास-14

(2) सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा (दस दिन के भीतर) नियुक्त किया जाने वाला एक नामनिर्देशिती ।

विवादग्रस्त विनिर्दिष्ट मामले

1. क्या हमसे संलग्न मांग-चार्टर, तारीख 22-8-1977 में अन्तर्विष्ट मांगें न्यायोचित हैं। यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है।

2. मध्यस्थ निर्देश किए जाने की तारीख से दो मास के भीतर मांगों की बाबत पंचाट देंगे। यह अवधि पक्षकारों की सहमति से बढ़ाई जा सकती है। पंचाट के प्रवर्तन की अवधि मध्यस्थों द्वारा विनिश्चित की जाएगी। मध्यस्थ पंचाट देने में पक्षकारों की दलीलों पर सारभूतरूप से विचार करेंगे ।

3. हम इस पर भी सहमत हैं कि मध्यस्थों का एकमत निर्णय हम पर आबद्धकर होगा। यदि मध्यस्थों की राय विभाजित है तो वे किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को अधिनिर्णायक नियुक्त करेंगे जो परस्पर स्वीकार्य होगा जिसका पंचाट हम सब पर आबद्धकर होगा ।

4. नियोजक मध्यस्थम का खर्च वहन करेंगे। यदि खर्च के प्रश्न से संम्बन्धित ग्राह्यता और युक्तिसंगत के प्रश्न पर कोई विवाद होता है तो मध्यस्थ विवाद का विनिश्चय करेंगे

पक्षकारों के हस्ताक्षर

1. कर्मकारों के प्रतिनिधि :
हस्ताक्षर/- एच०ए० त्रिवेदी 14-9-1977
हस्ताक्षर/- सी०एल० दूधिया 14-9-77

2 नियोजकों के प्रतिनिधि :
हस्ताक्षर/- अशोक जैन 14-9-1977
हस्ताक्षर/- बी०वी० राजू 14-9-1977

साक्षी :

(1) हस्ताक्षर/- पी०वी० गुणीशास्त्री

(2) हस्ताक्षर/- आर०सी० गुप्ता

स्थान : नई दिल्ली
तारीख 14 सितम्बर, 1977

उपाबन्ध

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन अपेक्षित कथन

1. विवाद के पक्षकार : अध्यक्ष,
सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, और सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदस्य,

एक्सप्रेस बिल्डिंग, चर्चगेट मुम्बई-400001

2. विवाद की प्रकृति और उसका कारण : कर्मकारों की निम्न मांगे :

1. न्यूनतम परिलब्धियां:—एक अकुशल कर्मचारी के लिए न्यूनतम कुल परिलब्धियां आधारिक 390 रु० और मंहगाई भत्ता 220 रु० अखिल भारतीय उपभोक्ता कीमत सूचकांक 305 (आधार 1960=100) के अनुसार होंगी ।

2 प्रचालकों के लिए वेतनमान :—निम्नलिखित वेतनमान 1-3-1977 से लागू किए जाएंगे ।

श्रेणियां:—

क 390.00 रु०+(6 50×12) =468.00 —12 वर्ष
ख 416.00 रु०+(7 80 रु०×13)=517 00 रु० —13 वर्ष
ग 448.50 रु०+(10 40रु०×14)=594.10 रु० —14 वर्ष
घ 491 00 रु०+(13.00रु०×14)=663 00 रु० —14 वर्ष
क 513 50 रु०+(18 20रु०×10)=695.50रु० —14 वर्ष
+(20.80 रु०+4)=778.70 रु०

टिप्पण—ऐसे कर्मचारी, जिसके पदाभिधान अगली उच्चतर श्रेणी में पाए जाते हैं, को जैसे ही वह निम्नतर श्रेणी के अधिकतम पर पहुंचे, उच्चतर श्रेणियों में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। प्रोन्नतियां इससे पहले भी गुणावगुण के आधार पर दी जाएंगी और तब भी दी जाएंगी जब उच्चतर श्रेणियों में रिक्तियां हों।

3 टी०सी०, लिपिकीय, निम्नतर तकनीकी और पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द के लिए वेतनमान :—निम्नलिखित वेतनमान 1-3-1977 से लागू किए जाएंगे—

श्रेणियां :

टी०सी० 420.00+8×8रु०=484.00 रु०रो०—10×8रु०
=564 रु०—16 वर्ष

		वर्ष
I	440.00रु०+10×10रु०=550.00रु० रु०रो० 12×9रु०+658 रु०	20
II.	465.00 रु०+12×10 रु०=595.00 रु० रु०रो० 14×10 रु०=725 रु०	20
III.	490 00 रु०+14×10 रु०=630.00 रु० रु०रो० 15×11 रु०=795 रु०	21
IV.	520.00 रु०+19×10 रु०=700.00 रु० रु०रो० 20×11 रु०=920 रु०	21
V.	540.00 रु०+20×5 रु०=640.00 रु०+22×6 रु० =772 रु० रु०रो० 24×11=1036 रु०	22
VI.	550.00 रु०+22×5 रु०=660.00 रु०+24×6 रु० =804.00 रु०रो० 30×11=1134 रुपये	22
VII	585.00 रु०+25×10=835.00 रु० रु०रो०— 30×14 रु०=1255 रुपये	24

टिप्पण :—ऐसे कर्मचारी, जिसके पदाभिधान अगली उच्चतर श्रेणी में भी पाए जाते हैं, को जैसे ही वह निम्नतर श्रेणी के अधिकतम पर पहुंचे, उच्चतर श्रेणियों में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। प्रोन्नतियां इससे पहले भी गुणावगुण के आधार पर दी जाएंगी और तब भी दी जाएंगी जब उच्चतर श्रेणियों में रिक्तियां हों।

4 लगाना :—कर्मचारियों को उनकी श्रेणियों में निम्नलिखित रूप में लगाया जाएगा जो कर्मचारी अपनी नई श्रेणियों के न्यूनतम से कम पर है उन्हें पुनरीक्षित श्रेणियों के न्यूनतम पर लाया जायेगा और जो उन श्रेणियों के न्यूनतम से अधिक पर हैं, उन्हें यदि वे उन श्रेणियों के सोपान में नहीं है तो, अगले उच्चतर सोपान में लगाया जाएगा।

5. समायोजन कर्मचारियों को, उन्हें उनकी नई श्रेणियों में, लगाने के पश्चात्, अधिकतम चार वेतनवृद्धियों तक, प्रत्येक पांच वर्ष सेवा या उसके भाग के लिए, एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी जाएगी।

नये न्यूनतम वेतन, वेतनमान, गृह भाटक भत्ता, अतिरिक्त महगाई भत्ता आदि तीन वर्ष तक प्रवृत्त रहेंगे किन्तु जब तक नया पुनरीक्षण लागू न कर दिया जाए, कर्मचारी अपनी वार्षिक वेतनवृद्धि लेते रहेंगे।

6. महगाई भत्ता. 305 से ऊपर सूचकांक के उठने या गिरने पर निष्प्रभावन की दर 2 रु० प्रति प्वाइंट होगी। उपभोक्ता कीमत सूचकांक का गिरना या उठना केवल 305 प्वाइंट से ऊपर ही समायोजित किया जाएगा अर्थात् मंहगाई भत्ता, 26 कार्य दिवस के लिए 220 रु० से कम नहीं होगा।

7 अतिरिक्त महगाई भत्ता :—प्रचालकों के लिए : ङ श्रेणी के लिए आधारिक वेतन का 2½ प्रतिशत । घ श्रेणी को 5 प्रतिशत और ग, ख और क श्रेणियों को 10 प्रतिशत।

टी०सी० लिपिकीय, निम्नतर तकनीकी और पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द : — उनके आधारिक वेतन का 10 प्रतिशत जमा प्रचालकों को संदेय महंगाई भत्ते से 15 रुपये अधिक।

8 गृह भाटक भत्ता :—विभिन्न प्रवर्गों के लिए विद्यमान गृह भाटक भत्ता 25 रुपये प्रतिमास बढ़ा दिया जाएगा। उनके लिए, जिन्हें कम्पनी के क्वार्टर मिले हैं, गृह भाटक की कटौती वही रहेगी जो इन मांगों की तारीख को विद्यमान थी।

9 छुट्टी यात्रा भत्ता : कर्मचारियों को, प्रत्येक वर्ष, इस बात को ध्यान में लाए बिना कि वे बाहर जाते है या नही और यह कि वे अन्य राज्यों में रहते है या उसी राज्य में (स्थानीय) है, (बिना किसी शर्त के) छुट्टी यात्रा भत्ता, एक मास के वेतन की दर से, जिसमें महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है, दिया जाएगा।

10. नामप्रणाली :—प्रत्येक कर्मचारी की नामप्रणाली तैयार की जाएगी और उन्हें उनके कर्तव्यों के अनुसार समुचित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा।

11. आकस्मिक श्रमिक :—ऐसे आकस्मिक श्रमिकों को, जिन्होंने छह मास की सेवा पूरी कर ली है या कर लेंगे, स्थायी बना दिया जाना चाहिए।

12. संविदा श्रमिक :—संविदा पद्धति को बिल्कुल उत्सादित कर दिया जाना चाहिए और सभी ठेकेदारों के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को कम्पनी की स्थायी पूजी पर ले लिया जाना चाहिए। कोयला और जिप्सम संबन्धी अनुभागों को भी विभागीकृत कर दिया जाना चाहिए।

13. रात्रि पारी भत्ता :—उन सभी कर्मचारियों को, जो द्वितीय या तृतीय पारी में कार्य कर रहे हैं, उनके आधारिक वेतन के 25 प्रतिशत की दर से रात्रि पारी भत्ता दिया जाना चाहिए।

14. ऊष्मा भत्ता :—बायलर हाउस, फाउण्डरी और स्मिथिंग अनुभाग तथा भट्ठे और कोयला मिल विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों को, उनके आधारिक वेतन के 10 प्रतिशत की दर से ऊष्मा भत्ता दिया जाएगा।

15. धूल भत्ता :—पैकिंग हाउस, सीमेंट मिल विभाग, भट्ठे, कोयला मिल विभाग, रज्जुमार्ग, क्रशर, हेल्को, मैनिटेनेंस (खदान) शावेल, डोजर, डम्पर, चालकों, क्लीनरों आदि में कार्य करने वाले कर्मचारियों को उनके आधारिक वेतन के दस प्रतिशत की दर से धूल-भत्ता दिया जाना चाहिए। इन कर्मकारों को प्रतिदिन 100 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम नारियल का तेल भी दिया जाना चाहिए।

16. वर्दियां —(क) निम्नलिखित प्रवर्गों के कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष वर्दियों के 3 सेट दिए जाने चाहिए :

"मिस्त्री, मुकद्दमे और विभिन्न विभागों के मेट।"

(घ) वर्दी ऐसे सभी कर्मचारियों को दी जाएगी जो प्रत्येक वर्ष जनवरी की समाप्ति से पूर्व वर्दी पाने के पात्र है।

17. धुलाई-भत्ता:—कर्मचारियों को 10 रु० प्रतिमास धुलाई भत्ता दिया जाएगा।

18 रेन-कोट (बरसाती).—क्वालिटी रेन-कोट प्रत्येक दूसरे वर्ष ऐसे सभी कर्मचारियों को विनिर्दिष्टतः विद्युत विभाग, उत्खननों के कर्मचारियों, झाड़कशों, ड्राइवरों, ड्रेगलाइन, आपरेटरों, शावल पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों और कूड़ा करकट फैंकने वालों, भारी यान आपरेटरों, गैंगमैनों, खसी परिचारकों, प्रयोगशाला कर्मचारिवृन्द, पम्प परिचायकों, आदि को, जो मानसून के दौरान खुले स्थानों में आते जाते हैं, दिए जाने चाहिएं।

19. ऊनी जर्सी:—क्वालिटी ऊनी जर्सी सभी ऐसे कर्मचारियों को प्रत्येक दूसरे वर्ष दी जानी चाहिए जो सफाई विभाग या उत्खननों में काम करते है या भारी यान आपरेटर और उनके मजदूर और सहायक है या कार और ट्रक ड्राइवर, आदि है।

20 बूट—विद्युत विभाग के सभी कर्मचारियों को रबड़-सोल के शाक-प्रूफ बूट दिए जाने चाहिएं और कैन्टीन और सफाई के कर्मचारिवृन्द को, चपरासियों, भट्ठी विभाग के बरतनों, लिपिक कर्मचारिवृन्द आदि को साधारण बूट दिए जाने चाहिएं।

21. चिकित्सा खर्च:—कम्पनी के कर्मचारियों ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों पर चिकित्सा के लिए जो भी व्यय किए हैं। उन सभी की पूरी पूरी प्रतिपूर्ति कम्पनी को करनी चाहिए।

22. भारी यान भत्ता.—भारी यानों का वर्तमान भत्ता दुगना कर देना चाहिए।

23. छुट्टियां :—कर्मचारियों को रविवार या साप्ताहिक अवकाश दिनों के लिए, संघ के परामर्श से, उस दिन के लिए अतिरिक्त संदाय किया जाना चाहिए या प्रतिस्थानी छुट्टी दी जानी चाहिए।

24. छुट्टी:—सभी कर्मचारियों को वैसी ही बीमारी की छुट्टी और प्रिविलेज छुट्टी मिलनी चाहिए जैसी मासिक रूप में संदाय पाने वाले कर्मचारियों को दी जाती है।

25. रियायती सीमेंट—अपना मकान बनाने वाले कर्मचारियों को सीमेंट के थोक मूल्य के 25 प्रतिशत बट्टे की रियायती दर पर सीमेंट के 200 बोरे तक दिए जाने चाहिएं।

26. अन्तरिम राहत.—कर्मचारियों को तारीख 1-3-1977 से प्रतिमाह 50 रु० अन्तरिम राहत के रूप में दिए जाने चाहिएं।

27. प्रभाव.—उपर्युक्त मांगें तारीख 1-3-1977 से प्रभावी होनी चाहिएं।

28. वर्तमान अधिकार, प्रसुविधाएं, और विशेषाधिकार:—कर्मचारियों के वर्तमान अधिकार, प्रसुविधाएं और विशेषाधिकार आदि बने रहने चाहिएं।

3 प्रभावी कर्मकारों की संख्या :—लगभग 95,000

भारतीय नेशनल सीमेंट एण्ड इलाइड फेडरेशन

हस्ताक्षर : (एन०एस० द्विवेदी)

अध्यक्ष

[संख्या एल-29013/2/77-डी-III-बी]

मनजीत सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 28th November, 1977

ORDER

S.O. 3962.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to Cement Manufacturers Association Express Building Churchgate Bombay and its workmen represented by Indian National Cement and Allied Workers Federation, Mazdoor Karyalaya, Congress House, Bombay.

And, whereas the said employers and workmen have, by a written agreement in pursuance of the provisions of the sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 agreed to refer the said dispute to arbitration by the persons specified therein and a copy of the said agreement has been made available to the Central Government.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of Section 10A of the said Act the Central Government hereby publishes the said Agreement.

AGREEMENT

Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947.

BETWEEN

NAME OF THE PARTIES.

Representing employers :	The Cement Manufacturers' Association, Express Building Opp. Churchgate Station, Bombay-400020.
Representing workmen :	The Indian National Cement & Allied Workers' Federation, Mazdoor Karyalaya, Congress House, Bombay-400004.

The parties above named had by Agreement dated 14-9-1977, a copy of which is annexed hereto and marked as Annexure A, agreed to refer the disputes raised by the Indian National Cement & Allied Workers' Federation by its notice of strike dated 22-8-1977 to arbitration under section 10-A of the Industrial Disputes Act.

In terms of the above, it is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of :

(1) Shri G. Ramanujam, 2/44, Royapettah High Road, Madras-14.

(2) Shri R.P. Nevatia, Bajaj Bhavan, Nariman Point, Bombay-400020.

(i) Specific matters in disputes :	Whether the demands as contained in the Charter of Demands dated 22-8-1977 appended hereto are justified. If so, to what relief are the workmen entitled ?
(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment for undertaking involved :	(a) Cement Manufacturers' Association, Express Building, Opp. Churchgate Station, Bombay-400020.
	(b) Indian National Cement & Allied Workers' Federation, Mazdoor Karyalaya, Congress House, Bombay-400004.
(iii) Name of the workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the Union, if any, representing the workman or workmen in question :	Indian National Cement & Allied Workers' Federation.
(iv) Total number of workmen employed in the undertakings affected :	90,000 (Approximately)
(v) Estimated number of persons affected or likely to be affected by the dispute :	90,000 (Approximately)

We further agree that the unanimous decisions of the Arbitrators shall be binding on us. In case the Arbitrators are, divided in their opinion they shall appoint another person mutually acceptable as Umpire, whose Award shall be binding on us.

The Arbitrators shall make their Award within a period of two months from the date of entering upon the reference. This period can be extended with the consent of the parties.

Signature of the parties :

Representing employers :	Representing workmen :
For and on behalf of the Cement Manufacturers' Association	For and on behalf of the Indian National Cement & Allied Workers' Federation.
Sd/- 14-10-77	Sd/- 13-10-77
B.V. Raju	H.N. Trivedi
(Vice-President)	(President)
Witnesses :	
Sd/-	Witnesses :
1. (P.V. Gunishastri) 14-10-77	
2. Sd/-(Illegible) 13-10-77	

ANNEXURE 'A'

PREAMABLE

In deference to the wishes of the Prime Minister of India, the Indian National Cement and Allied Workers Federation and the Cement Manufacturers' Association representing its members agree to settle, through arbitration, the dispute arising out of the issues mentioned in the strike notice dated 22nd August, 1977. According to the Cement Manufacturers' Association, the arbitrators should take into account, among other matters, the general economic condition, the financial resources of the cement industry, paying capacity and level of productivity of constituent units. According to the Federation other relevant factors have to be taken into account by the arbitrator. The Federation agree to call off the strike with immediate effect. The employers agree not to victimise any worker.

2. Parties have further agreed to request the Central Govt. that in view of the national importance of the industry spread over different States, the arbitration should be on a national basis and under the provisions of Section 10-A of the Industrial Dispute Act, 1947, covering all the units which were under the purview of the two former Central Wage Boards the agreement dated 7th May, 1975, and the new units that have been set up subsequently. The parties request the Central Government to act in furtherance of this submission.

ARBITRATION AGREEMENT

NAMES OF THE PARTIES :

Representing Workmen

(1) Indian National Cement & Allied Workers' Federation, Mazdoor Karyalaya, Congress House, Bombay-400004. represented by—

(1) Shri H.N. TRIVEDI

(2) Shri C.L. DUDHIA

Representing Employers :

(2) Cement Manufacturers' Association, Express Building, Churchgate, Bombay-400020, represented by—

(1) Shri Ashok Kumar Jain

(2) Shri B.V. Raju

We the undersigned, hereby agree to refer the dispute specified below to the arbitration of—

(1) Shri G. Ramanujam, 2/44, Royapettah High Road, Madras-14.

(2) A nominee to be appointed by the Cement Manufacturers' Association (within ten days).

SPECIFIC MATTERS IN DISPUTES

1. Whether the demands as contained in the Charter of Demands dated 22-8-1977 appended hereto, are justified.

If so, to what relief are the workmen entitled ?

2. The arbitrators shall give their award in relation to the demands within two months from the date of entering upon the reference. This period can be extended with the consent of the parties. The period of operation of the award will be decided by the arbitrators. The arbitrators shall give due consideration to the contentions of the parties in giving award.

3. We further agree that a unanimous decision of the Arbitrators shall be binding on us. In case the Arbitrators are divided in their opinion, they shall appoint another person mutually acceptable as an umpire whose award shall be binding on us.

4. The cost of the arbitration will be borne by the employers. If there is any dispute on admissibility and reasonableness on the questions of cost, the arbitrators will decide the dispute.

Signature of the Parties

1. Representative of Workers :
Sd/- H.N. TRIVEDI 14-9-77
Sd/- C.L. DUDHIA 14-9-77

2. Representative of employers :
Sd/- ASHOK JAIN 14-9-77
Sd/- B.V. RAJU 14-7-77

WITNESSES :

(1) Sd/- P.V. GUNISHASTRI
(2) Sd/- R.C. GUPTA

Place : New Delhi

Dated : 14th September, 1977.

ANNEXURE

Statement required under the Industrial Disputes Act, 1947

1. Parties to the Disputes : The Chairman, Cement Manufacturers' Association, and Members of Cement Manufacturers' Association, Express Bldg. Churchgate, Bombay-400001.

2. Nature and Cause of the more Demands of the workers as dispute : below :

1. MINIMUM EMOLUMENTS :—Minimum total emolument for an unskilled employee should be basic Rs. 390/- and D.A. Rs. 220/- at the All India Consumer Price Index Number 305 (Base 1960=100).

2. SCALES OF PAY FOR OPERATIVES :—The following scales should be introduced from 1-3-1977.

GRADES :

		Years
E	Rs. 390.00+(Rs. 6.50×12)=Rs. 468.00	—12
D	Rs. 416.00+(Rs. 7.80×13)=Rs. 517.40	—13
C	Rs. 448.50 +(Rs. 10.40×14)=Rs. 594.10	—14
B	Rs. 481.00+(Rs. 13.00×14)=Rs. 663.00	—14
A	Rs. 513.50+(Rs. 18.20×10)=Rs. 695.50+ (Rs. 20.80×4) =Rs. 778.70	—14

N.B. :— Employees whose designation are also found in next higher grade will be promoted in higher grades as and when they reach the maximum of the lower grade. Promotions will be given earlier on merit and also when vacancies fall in higher grade.

3. SCALES OF PAY FOR T.C., CLERICAL, LOWER TECHNICAL AND SUPERVISORY STAFF :—The following scales should be introduced from 1-3-1977.

GRADES :

		Years
T. C.	Rs. 420.00+Rs. 8×8=Rs. 484.00-EB-Rs. 10×8=Rs. 564	—16
I	Rs. 440.00+Rs. 10×10=Rs. 550.00-EB-Rs. 12×9=Rs. 658	—20
II	Rs. 465.00+Rs. 12×10=Rs. 585.00-EB-Rs. 14×10=Rs. 725	—20
III	Rs. 490.00+Rs. 14×10=Rs. 630.00-EB-Rs. 15×11=Rs. 795	—21
IV	Rs. 520.00+Rs. 18×10=Rs. 700.00-EB-Rs. 20×11=Rs. 920	—21
V	Rs 540.00+Rs. 20×5=Rs. 640.00+ Rs. 22×6=Rs. 772.00-EB-Rs. 24×11=Rs. 1036	—22
VI	Rs. 550 00+Rs. 22×5=Rs. 660.00+ Rs. 24×6=Rs. 804.00-EB-Rs. 30×11=Rs. 1134	—22
VII	Rs. 585.00+Rs. 25×10=Rs. 835.00-EB-Rs. 30×14=Rs. 1255	—24

N.B. :—Those whose designations are also found in next higher grades will be promoted to higher grades as and when they reach the maximum of the lower grades. Promotions will be given earlier on merit and also when vacancies fall in higher grades.

4. FITMENT :—Employees will be fitted into their respective grades as under :

Those who are below the minimum of their new grades will be brought to the minimum of the revised grades and those who are higher than the minimum of the grades will be fitted at the next higher step if they are not in step of the grades.

5. ADJUSTMENT :—Employees will be given one additional increment in their respective new grades for every five years of service or part thereof with a maximum of four increments after fitting them into new grades.

The new minimum salary, scales of pay HRA, Additional D.A. etc. will remain in force for three years but the employees to get their yearly increment till the new revision is introduced.

6. DEARNESS ALLOWANCE :—Rate of neutralisation for rise or fall over 305 Index should be Rs. 2/- per point. Rise or fall in consumer price index will be adjusted only above 305 points i.e. dearness allowance should not go below 220/- for 26 working days.

7. ADDITIONAL DEARNESS ALLOWANCE :—For Operatives: 2½% of basic salary to E grade, 5% to D grade and 10% to C, B & A grades. For T.C., Clerical, Lower Technical and Supervisory Staff : 10% of their basic salary plus Rs. 15 more than the D.A. payable to operatives.

8. HOUSE RENT ALLOWANCE :—The existing House Rent Allowance for different categories will be increased by Rs. 25 per month. Deduction of the house rent will remain the same as existed on the date of these demands, for those who are Provided Company's quarters.

9. LEAVE TRAVEL ALLOWANCE :—Employees will be given leave travel allowance (without any condition) at the rate of one month's salary including dearness allowance every year irrespective of whether they go out or not and whether they are residing in other states or in the same State (Local).

10. NOMENCLETURES :—Proper nomencletures of each employee should be prepared and they should be classified into appropriate grades according to their duties.

11. CASUAL LABOUR :—Casual employees who have or will complete six months service should be made permanent.

12. CONTRACT LABOUR :—Contract system should be totally abolished and the employees working under all contractors should be taken on Company's permanent roll. Coal and gypsm handling sections should also be departmentalised.

13. NIGHT SHIFT ALLOWANCE :—All employees who are working in 2nd or 3rd shift should be given night shift allowance at the rate of 25% of their basic salary.

14. HEAT ALLOWANCE :—Employees working in Boiler House, Foundry and Smithing Section and kiln and coal mills department should be given heat allowance at the rate of 10% of their basic salary.

15. DUST ALLOWANCE :—Employees working in Packing House, Cement Mills Department, Kiln, Coal Mills Department, Ropeway, crusher, halco, sanitation, (quarry) shovel, dozer, dumper, drivers, cleaners, etc. should be given dust allowance at the rate of 10% of their basic salary. These workers should also be given 100 grams jaggery and 50 grams coconut oil every day.

16. UNIFORMS :—(a) Employees in following categories should be given 3 sets of uniforms every year :

"Mistries, mukadams, mates of different departments".

(b) Uniforms should be supplied to all employees who are eligible fo euniforms before the end of January every year.

17. WASHING ALLOWANCE :—Employees should be given washing allowance of Rs. 10/ P.M.

18. RAIN COATS :—Quality rain coats should be supplied to all employees who have to move in open during monsoon particularly the employees of electrical department, quarries, sweepers, drivers, dragline operators, cleaners working on shovel and dumpers, heavy vehicle operators, gangmen, silos attendents, lab, staff, Pump attendents etc. every alternate year.

19. WOOLEN JERSIES :—Quality woolen jersies should be supplied to all employees working in sanitation department, quarries, heavy vehicle operators and their mazdoors and helpers, car and truck drivers etc. every alternate year.

20. BOOTS :—Rubber-sole shock-proof boots should be supplied to all employees of electric department and ordinary boots to tea canteen staff, sanitation staff, peons, burners of kiln department clerical staff etc.

21. MEDICAL EXPENSES :—Employees should be fully reimbursed by the Company of the Medical expenses incurred by them and on their family members.

22. HEAVY VEHICAL ALLOWANCE :—Existing allowance of heavy vehicles should be doubled.

23. HOLIDAYS :—Employees should be paid for the holidays which fall on Sundays or weekly offs by way extra payment of a day or a substitute holiday be given in consultation with the Union.

24. LEAVE :—All Employees should get same sick leave and privilege leave as given to monthly paid employees.

25. CONCESSIONAL CEMENT :—Employees building their houses should be given upto 200 bags of cement on concessional rate at a discount of 25% of the wholesale rate of cement.

26. INTERIM RELIEF :—Employees should be paid Rs. 50 each per month from 1-3-1977 as interim relief.

27. EFFECT :—The above demands should be given effect from 1-3-1977.

28. EXISTING RIGHTS, BENEFITS AND PRIVILEGES :—Employees should continue to get their existing rights, benefits and privileges etc.

3. No. of workers to be affected. About 95,000

For INDIAN NATIONAL CEMENT AND ALLIED WORKERS' FEDERATION,

Sd/-

(H.N. TRIVEDI)

President

[No. L-29013/2/77-D. III. B]

MANJIT SINGH, Under Secy.

S.O. 3963.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bomaby in the industrial dispute between the employers in relation to Shri the management of Messrs Transocean Shipping Agency (Private) Limited, Bombay and their workmen which was received by the Central Government on the 3rd December, 1977.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/3 of 1976

PARTIES :

Employers in relation to the management of M/s. Transocean Shipping Agency (Private) Limited, Bombay.

AND

Their Workman

(Shri L. A. Gracias)

APPEARANCES :

For the Employers—Shri S. Chowdhary, Labour Adviser.

For the Workman—Shri K. R. Dengle, Advocate.

INDUSTRY : Shipping STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 21st November, 1977

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour acting under Section 10(2) of the Industrial Dispute Act, 14 of 1947 have referred the following dispute to this Tribunal for adjudication as per their order No. L-31013(2)/75-D.IV(A) dated 27-1-1976.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Messrs Transocean Shipping Agency Private Limited, Bombay, in terminating the services of Shri L. A. Gracias, Clerk, is legal and justified? If not, to what relief is Shri L. A. Gracias entitled?"

The workmen in his statement of claim has stated that he was working in Messrs Transocean Shipping Agency (Private) Limited or its sister concern as a 'B' grade Clerk from 1960 till 26-5-1975 when he was discharged from service with one month's pay in lieu of notice. He contends that the said order of discharge without being preceded by a formal enquiry is not legally tenable. He says that because of his trade union activities the management terminated his services. He prays for reinstatement in service, with back wages and continuity of service.

The management in their written statement questions the maintainability of this reference and the jurisdiction of this Tribunal to entertain the same. According to them, since no employee of theirs is engaged in work within the vicinity of the major port of Bombay the Central Government is not the appropriate Government to refer the dispute to this Tribunal. They say that since they had lost confidence in the workman they had to dispense with his services. They deny the averment that the past record of service of this workman was clean. They also state that before terminating his services, the workman was given an opportunity to explain his conduct by the letter dated 3-5-1975. They pray that the reference may be rejected.

During the course of the arguments, Mr. Chowdhary for the management has taken an additional plea namely, that since the workman had not raised this dispute regarding re-instatement with the management in the first instance, there can be no industrial dispute in the eye of law that can be referred to adjudication.

The points that arise for consideration are :—

(1) Whether the reference in question is not maintainable for the reasons given by the management?

(2) Whether the termination of the services of the workman without holding an enquiry is justified?

(3) Whether the workman is entitled to be reinstated with full back wages and continuity of service?

(4) If not, what compensation, if any, is he entitled?

(5) To what relief?

Point 1:

The workman who is examined as WW-1 originally joined the service of Messrs Marine Transport Company (P) Ltd. in the year 1960 as a 'B' grade Clerk. They were doing the business of Shipping and Chartering Agency and also as clearing and forwarding agents. Till the year 1971 this company was handling the ships of several countries including Soviet Russia. In the year 1971 when the Russian Government threatened to discontinue engaging this company as their shipping agents if they handled ships of other countries, the management constituted the present company Messrs Transocean Shipping Agency to handle ships of U.S.S.R. lines and Messrs Mahart and Hungarian Shipping Company Limited. Consequent upon the formation of this new company the service of WW-1 were transferred to it. At the relevant time he was the Dock and Customs Clerk of this new company (hereinafter called the company). On the date his services were terminated he was drawing a basic pay of Rs. 350, D.A. of Rs. 87187 p, H.R.A. of Rs. 40 and medical allowance of Rs. 10 per month. He was also getting Rs. 700 to 800 per month by way of overtime wages. On 26-5-1975 the company terminated the services of WW-1 by their letter Ex. W-1 of even date which reads as follows :—

"On account of your action against orders and interest of the company on various occasions for which you were given proper notices and you accepted the liability, it has been decided to terminate your services which hereby do with immediate effect. You will be paid one month's salary in lieu of notice.

Please arrange to return as early as possible all items of our company's property in your possession to enable us to settle your accounts.

Your accounts will be settled after checking your commitments."

The Transport and Dock Workers' Union of which WW-1 is a member took up his cause and issued the notice Ex. W-2 demanding a withdrawal of the notice Ex. W-1 terminating his services. As no reply was received from the management, the Union addressed the letter Ex. W-3 to the A.L.C.(C) requesting him to admit the dispute in conciliation. Ex. W-4 is the failure of conciliation report submitted by the A.L.C.(C) to the ministry of Labour on receipt of which the present reference is made to this Tribunal by the Government of India, under Section 10(2) of the Industrial Disputes Act.

In their written statement the company took the plea that since no employee of theirs is engaged in work in the vicinity of the major Port of Bombay the Central Government is not the appropriate authority to make the present reference. Shri S. Chowdhary the learned Labour Adviser appearing for the management has not chosen to press this point.

Shri S. Chowdhary submits that since the workman did not serve a notice of demand on the management claiming reinstatement before approaching the government there can be no industrial dispute within the meaning of the Act. Reliance is placed on 1968, I, LLJ, page 834 (S.C.)* in support of this proposition. The Delhi High Court in (1969) 37 F.J.R. 69** understood this decision as having finally established the position that a demand by the workman must be raised first on the management and rejected by them before an industrial dispute can arise and exist and that the making of such a demand before the Conciliation Officer and the communication of the same to the management by the Conciliation Officer is not sufficient to constitute an industrial dispute. This decision of the Delhi High Court has been dissented from bf the Rajasthan High Court in (1968) 35 F.J.R. 305*** and by the Patna High Court in (1969) 39 F.J.R. 461**** and the Punjab and Haryana High Court in the decision reported is 1977, II, LLJ, page 207***** while explaining the Supreme Court decision these decisions lay down that it is not necessary that the dispute must be preceded by a demand and a refusal in express terms by the parties concerned. It is further stated that it is for the Tribunal to decide on the material placed before it. The question whether an industrial dispute existed or no. Following the aforesaid decisions of the Punjab and Haryana High Court and Patna High Court I hold that this reference is not liable to be rejected for the reason that no demand in writing for reinstatement was made by WW-1 on the management before approaching the Conciliation Officer. It is also not quite correct to say that the workman did not press his demand for reinstatment even before he or his Union placed the matter before the Assistant Labour Commissioner (C) for conciliation. In the notice Ex. W-2 served on the management the Union called upon them to withdraw the notice of termination Ex. W-1 which can only mean reinstatement and nothing else I do not therefore agree with the argument that in the notice Ex. W-2 reinstatement was not demanded.

For the aforesaid reasons point 1 held against the management.

Point 2:

The workman WW-1 worked as a Customs and Dock Clerk in this company and its sister concern from 1960—1975 when

*Sindhu Resettlement Corporation Ltd. vs. Industrial Tribunal, Gujarat and others.

**Fedders Lloyd Corporation Private Limited vs. Lieutenant Governor, Delhi.

***Goodyear India Ltd., Jaipur vs. Industrial Tribunal, Jaipur and others.

****Rodlo Foundation Engineering Ltd., vs. State of Bihar.
*****Algu Ram vs. State of Punjab and others.

his services were terminated. During the years 1972 to 1975 the conduct of WW-1 was adversely commented upon by the management on 3 or 4 occasions. On 9-3-1972 WW-1 is said to have visited the vessel 'I.M.A.N.' in the stream in the discharge of his normal duties and begged the Captain of the ship to give him bread, butter etc. The Captain of the ship is said to have reported this matter to Captain A. Krivobokov representative of the U.S.S.R. Ministry of Merchant Marine at Bombay who in his turn passed on the complaint to Mr. Pramanik (EW-1) the Chief Executive of the company. EW-1 by his letter Ex. E-7 dated 13-3-1972 directed WW-1 to work in the Export Import Section and not to go on board the Soviet vessels. In Ex. E-7, EW-1 impressed upon WW-1 that while preparing bills he should be more realistic in future. Soon after this incident of 9-3-1972 WW-1 obtained a certificate Ex. W-5 from the Captain of the ship S. S. IMAN to say that he had attended that vessel to his full satisfaction and there was no cause for any complaint against him (WW-1) whatsoever. On 11-5-1972 EW-1 addressed the letter Ex. E-8 to WW-1 finding fault with him for having been found at about 6.00 P.M. on 10-5-1972 typing the bills of lading (first and second copies) Guiseppe di Vittorio on behalf of vegetable vitamin company which had nothing to do with the company in question. On 8-9-1972 the letter Ex. E-9 was addressed by EW-1 to WW-1 bringing to the latter's notice the various mistakes committed by him which were likely to result in financial loss and difficulties in audit of receipts of stevedorial charges. In that letter EW-1 remainded WW-1 not to repeat such mistakes in future. In the letter Ex. E-10 dated 5-12-1974 EW-1 brought to the notice of WW-1 the various instances in which he submitted incorrect and inflated vouchers. He was asked to submit an explanation by 9-12-1974. As per the request of WW-1 contained in the letter Ex. E-11 dated 9-12-1974 time was extended for submitting the explanation till the first week of January, 1975. On 4-1-1975 WW-1 expressed regret in the following words :

> "as already explained personally earlier I regret for the whole affair and undertake that such incidents will not occur in future. I request that I may be excused this time. Thanking you".

On 28-9-1973 the Trade representative of the U.S.S.R. in India Shipping Department addressed the letter Ex. E-13 to EW-1 the Chief Executive of the company that when the U.S.S.R. Officer Captain Grishanov asked WW-1 to carry out certain tasks he did not obey inspite of repeated reminders. EW-1 was also told that this type of non-cooperative attitude would not be congenial for agency work. In this letter the U.S.S.R. representative drew the attention of EW-1 to the earlier incident of 9-3-1972 (asking the Captain of the Soviet ship for bread, butter etc.) Finally the letter expressed the view that disciplinary action against WW-1 was "most essential".

Then on 19-3-1975 the Soviet vessel MV "Aleksander Tsyu Rupa" laden with military cargo among others arrived in stream anchorage. The ship was met in the stream by WW-1 and one Mr. Minoo of D.B.C. Sons, Bombay and two officers of the embarkation department. It may be mentioned that before a ship is given a berth at the Port it is met by the Customs Clerks of the shipping agent concened for the purpose of collecting tonnage certificate, loading marks certificate, light dues payment certificate, safety certificate, gear certificate, crew list, stores list etc. When a ship carries military cargo among other things it is met by the embarkation offices (drawn from the armed forces). In the case of Soviet vessels carrying military cargo the hatch list should be collected by the vice consul of the U.S.S.R. at Bombay in person and in his absence by his authorised representative from the Captain of the ship. In the case of MV 'Tsyu Rupa" the hatch list was missing. The Soviet vice consul in his letter Ex. E-4 dated 4-4-1975 to EW-1 stated that according to the Master of the vessel Tsyu Rupa the hatch list was collected by the company's representative who boarded the vessel in stream (who is WW-1) and that the same should be handed over to him (the vice consul) at the earliest, being confidential papers. On receipt of this letter EW-1 adressed the letter Ex. W-2 dated 4-5-1975 to WW-1 calling upon him to explain the allegation made by the vice consul EW-1 further asked WW-1 to explain how he could be present on board the vessel along with the embarkation (military) Officer. To this WW-1 submitted the explanation Ex. E-3 wherein he admitted having met the ship in stream along with two embarkation officers. He further stated that while he was collecting the ship's documents from the Chief mate the embarkation Officers were collecting cargo documents from the Captain Golubev and cargo mate. After collecting the necessary documents from the Chief mate he and Minoo returned to the shore along with the embarkation officers. He denied the allegation that the hatch list was collected by him. The vice consul in his letter Ex. E-5 dated 8-5-1975 repeated the allegation that WW-1 collected the hatch list from the Captain of the ship, who is said to have parted with it by mistake. He further stated that the master of the ships were complaining to him about WW-1's behaviour and suspicious way of asking questions about cargo. He also stated that he was being told by the masters and chief mates of the Russian vessels that WW-1 was still begging for bread, butter etc. He concluded by saying that the management should take immediate steps to see that WW-1 did not have any access to the Russian vessels or their documents. Ex. E-6 is the letter written by one Major Moogewerf of the embarkation department to EW-1 informing him that the Russian consulate was complaining that the hatch list must have been handed over by mistake either to the embarkation officer or WW-1. He further stated that a thorough investigation carried out at the embarkation headquarters revealed that the embarkation officers did not collect the hatch list and that the same might have been collected by WW-1. On receipt of these complaints the management terminated the services of WW-1 as per their letter dated 26-5-1975. EW-1 the company's Chief Executive stated that as there could be no categorical proof regarding the culpability of WW-1 regarding the loss of the hatch list he did not consider it necessary to hold a "legal investigation". He further stated that except the letters E-4 to E-6 referred to above there was no other proof that it was WW-1 that collected the hatch list. Mr. Chowdhary for the company stated that the company only entertained a suspicion that it was WW-1 that collected the secret document and that the said suspicion is not based on any tangible evidence. During the course of the argument Mr. Chowdhary further submitted that when their principals did not repose any confidence in WW-1 and in the face of their repeated allegations that it was WW-1 that collected the secret document the company had no option but to terminate his services. When the court put him the question as to why WW-1 was not transferred to some other department of this company or back to the sister concern where it would not be necessary for him to visit the Russian or their ships Mr. Chowdhary had no satisfactory answer to give. It is then sought to be argued that in view of the earlier instances of misconduct and the grave allegations made by the Russians his services were terminated. It may be noticed that for the earlier misconduct which is evidenced by the letters E-7, E-8, E-9 and E-10 the company did not choose to terminate the services of WW-1. He was merely warned and his apology was accepted. Therefore it must be held that the only reason that weighed with the company in terminating the services of WW-1 was the suspicion entertained by them regarding the responsibility of WW-1 for the loss of the hatch list. The question is whether on such vague suspicion the company is justified in terminating the services of WW-1. The law on this point is laid down in the decision reported in 1975, I, LLJ, page 262 (S.C.) M/s. Johnson Pumps India Ltd. vs. L. Michael and another. It is stated there that such belief or suspicion of the employer should not be a mere whim or fancy. It must rest on some tangible basis and the power has to be exercised by the employer objectively and in good-faith. In other words there should be some prima facie proof of the guilt of WW-1. On their own showing except for the suspicion entertained by the company there is no other material on which the guilt of WW-1 can be established. The suspicion must rest on some facts which are capable of being proved. On the mere assertion of the Captain of the Russian ship that when there were four persons present on board his ship he must have handed over the hatch list to WW-1 alone by mistake cannot be accepted as sufficient proof of the guilt of WW-1. It follows that the termination of the services of WW-1 on the mere suspicion that he was the person that collected the hatch list cannot be justified.

The case of WW-1 that he was victimised for his trade union activity cannot also be accepted. This plea has been raised for the first time by WW-1 in his statement of claim. In the notice issued by the Trade Union to the management or before the Assistant Labour Commissioner (C) in the conciliation proceedings this plea was not specifically raised though WW-1 says that it was orally raised before the Conciliation Officer. As this plea is raised at a belated stage it cannot be accepted as true.

Point 2 found accordingly for the workman.

Point 3 :

The workman in his statement of claim has prayed for reinstatement. Shri Chowdhary for the company submits that the evidence on record shows that the relations between WW-1 and the Chief Executive EW-1 are very much strained, and in such circumstances no useful purpose will be served by the company being directed to take back WW-1 in their service. He further submitted that even if reinstatement is to be ordered the company should not be diretced to pay back wages from the date of termination to the date of reinstatement. I agree with Mr. Chowdhary when he says that the order of reinstatement may not serve any useful purpose in view of the strained relations obtaining between EW-1 and WW-1. Further the management says they have lost confidence in WW-1. I feel that in the circumstances payment of compensation for wrongful removal from service will be more appropriate.

Point 3 found accordingly.

Point 4 :

Mr. Chowdhary submits that since the workman has not taken any steps to obtain alternative employment he should be awarded only nominal compensation. WW-1 has stated in the course of his evidence that from the date he was discharged from service by the company till November, 1977 he has not been gainfully employed anyhhere inspite of his best efforts. Because of his advanced age (40 years) no company is prepared to entertain him in service. He further stated the post of Dock and Customs Clerk is not available in any other company of shipping and clearing agents. In his cross examination he stated that he had tried for the post of a customs clerk at Mackinnon and Meckenzie, Parekh Shipping Company, Madhavalal and Company, and Khemka and Company. He only made personal and oral enquiries at these various companies for a job. No written application was submitted. These trials were made during the period June to October, 1975. He denied the suggestion that he secured a job with Messrs Navbharat Shipping and Forwarding Agents. According to him ever since he lost his job he, his wife and four children (3 of whom are of school going age) are being maintained by his father-in-law. He has not got his name registered with the employment exchange. Finally he stated that except for the post of Dock and Customs Clerk in which post he has specialised he has not tried for any other post. I see no reason to disbelieve the evidence of WW-1 when he says that inspite of his best efforts he has not been able to secure an alternative job. Regarding the quantum of compensation, on the date he was discharged from service according to EW-1 his basic pay was Rs. 350, D.A. Rs. 870 or Rs. 900, Rs. 40 H.R.A. and Rs. 10 medical allowance. Besides this he was getting Rs. 500 to Rs. 800 by way of overtime as a Customs Clerk. He had put in a total service of 15 years in the Transocean company or its sister concern from 1960—1975. Mr. Chowdhary suggested that 7-1/2 months pay with allowances should be a reasonable compensation. Having regard to the basic salary and allowances amounting to Rs. 1300 per month WW-1 was actually drawing on the date of discharge from service, and, the opportunities available to him for earning overtime wages to the tune of Rs. 500 to Rs. 800 per month and the long period of service he has put in I consider that Rs. 20,000 should be a reasonable compensation for this illegal discharge from service. This works out roughly at the rate of one month's wages for each completed year of service which cannot be considered to be excessive.

Point 5 :

In the result I hold that the termination of the services of the workman Shri L. A. Gracias is not justifiable and that he is entitled to Rs. 20,000 by way of compensation for the wrongful removal from service. This reference is answered accordingly.

P. RAMAKRISHNA, Presiding Officer.

[No. L-31013(2)/75-D. IV(A)]

NAND LAL, Desk Officer.

S.O. 3964.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Rajasthan, in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank, Jaipur and their workmen.

CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, JAIPUR

Case No. C.I.T.—11 of 1975

REFERENCE :

Government of India, Ministry of Labour, Notification No. L. 12012/41/75/DII/A dated 19th September, 1975.

In the matter of an Industrial Dispute

BETWEEN

Shri B. R. Bhargava through the Association of Punjab National Bank Employees, Ajmer.

AND

The Manager, Punjab National Bank, Jaipur.

APPEARANCES

For the workman—Shri C. L. Bhardwaj.

For the Bank—Shri P. V. Balkrishnan.

Date of Award—31-10-77.

AWARD

By its notification quoted above, the Central Government has referred the following Industrial Dispute between the Punjab National Bank and its employee Shri B. R. Bhargava to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the Punjab National Bank in not promoting Shri B. R. Bhargava, now Special Assistant Branch Office, Ajmer, to the post of special Assistant with effect from the 1st October, 1971, is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?"

By its notification was espoused by the Association of Punjab National Bank Employees, Ajmer. The case delineated in the statement of claims is that the workman Shri B. R. Bhargava was appointed as clerk-typist-Godown keeper on 5-6-1956 in the Bank and was posted at its Head Office, New Delhi. Since his appointment, Shri Bhargava was working as clerk in Accounts Department at New Delhi. On 14-4-1971 he was transferred from Delhi to Jaipur on his request with certain conditions. One of the conditions was that Shri Bhargava would not claim officiating chance as Special Assistant till 30-9-1971. All these conditions were accepted by Shri Bhargava. He joined his duty at Jaipur and claimed no promotion to the post of Special Assistant till 30-9-1971. However, the Bank did not give him promotion even after 30-9-1971, though employees junior to him in rank were given promotions. He was promoted only on 10-3-73. It was alleged that the Bank did not act properly in not giving him promotion earlier whenever occasions for promotions arose. It was alleged that the Bank management acted arbitrarily and capriciously, in giving promotion to the junior employees and thereby a perseding Shri B. R. Bhargava. The reliefs claims are (1) Shri B. R. Bhargava be taken to have been promoted as Special Assistant with effect from 1-10-71 and (2) all the arrears of allowances resulting from this promotion be paid to him.

The Union's claim was resisted by the Bank. In its statement of defence, the bank admitted that Shri Bhargava was appointed clerk-typist-Godown Keeper at Head Office, New Delhi on 5-6-56 and since then he was working there in the Accounts Department. On his own request he was transferred from New Delhi to Jaipur where he joined on 21-4-71. His transfer to Jaipur was made with the clear stipulation that he would not claim promotion as Special Assistant till 1-10-1971 because his promotion was likely to affect the seni-

ority of other employees already working at Jaipur Branch of the Bank. Shri Bhargava had accepted these conditions. The promotion was, therefore, not made upto 1-10-71. Later on, he was not promoted because he had not acquired two years experience as a clerk in a branch office of the Bank. One of the essential conditions for promotion is to acquire two years experience as a clerk in some branch. Shri Bhargava had not earned this qualification. As such persons junior to him got the promotion as Special Assistant. When Shri Bhargava acquired the necessary experience of working as clerk for two years in a branch office he was given promotion as Special Assistant with effect from 10-3-73. It was denied that the Bank did not act justly or properly in not giving promotion to Shri Bhargava before 10-3-73. In the end it was submitted that the workman was not entitled to any relief.

So far the factual aspect of the case is concerned, there is no dispute between the parties. It is an admitted position between them that Shri Bhargava was appointed clerk-typist-Godown keeper in 1956 and was posted in the Accounts Section of the Bank's Head Quarters at New Delhi. He continued to serve at New Delhi till he was transferred to Jaipur in April, 71. His transfer from New Delhi to Jaipur was made on his own request with a clear stipulation that he would not claim any promotion upto 30-9-71 presumably because his promotion before 30-9-71 was likely to disturb seniority of the other clerical staff already working at Jaipur. Shri Bhargava therefore could not claim promotion before 30-9-71. It may be mentioned that he was given promotions as special Assistant on 10-3-73.

It would be proper at this stage to add a few words about the concept of promotion.

The conception that a workman has not vested right for promotion and the dispute pertaining to his promotion should not be taken to be an Industrial Dispute, is now a thing of past and cannot be allowed to prevail in the present socio-economic change. At one time it was thought that the question of promotion was a management function and had to be left mainly to the discretion of the management. But this thought is no more sound. In a case of unjust withholding of promotion, the aggrieved workman can raise the dispute and such a dispute will be deemed to be an industrial dispute. There is the direct authority of the Supreme Court on the point. Vide Brook Bond (India) Ltd. Vs. their workmen (1966) Vol. I Labour Law Journal 402. It was observed :

> "Generally speaking, promotinon is a management function, but it may be recognised that there may be occasions when a Tribunal may have to interfere with promotions made by the management where it is felt that persons superseded have been so superseded on account of malafide or victimization."

The malafides or victimization will be presumed to exist in a case where all things being equal, the senior is ignored. Again, if a person fulfilling all the qualifications for promotion and being senior to others is overlooked by the management, the malafides or victimization or unfair labour practices will be readily presumed. It cannot be, therefore, successfully contended that the question of promotion cannot be agitated as an industrial dispute.

The same view was taken in Brook Bond (India) (Pvt.) Ltd. vs. their workmen (1963)—I, L.L.J. 256. It was observed therein :—

> "There could be no doubt that promotions to which industrial employees are entitled normally would be treated as the function of the management. It must be left to the discretion of the management to select persons for promotion. On the other hand, labour also wants that the claims of employees who are eligible for promotion should be duly considered."

It is true that promotion in the course of industrial employment is the prerogative of the management. It is for the management to select persons for promotion. But this discretion must not be exercise by whim or caprice.

In the instant case, some employees junior to Shri Bhargava were promoted as Special Assistant after 30-9-1971. Ex-facie this action of the management cannot be upheld.

The Bank has taken the plea that promotion was denied to Shri Bhargava before 10-3-1973 as he had not acquired clerical experience for two years. It was submitted that according to the promotion rules, a cashier, a godown keeper, a typist and a stenographer must have a clerical experience of at least two years for promotion as Special Assistant. Shri Bhargava had not acquired this basic experience. I have examined the contention and found not much merit in it.

It is in the knowledge of every body that when vacancies arise for promotions the cases of eligible employees are put before the competent authority for making promotions. Such an authority examines the case of every eligible candidate and passes suitable orders for giving or withholding promotions. A record in writing is kept of all these proceedings conducted by the competent authority. The Bank has not furnished any such record before me to show that Shri Bhargava was taken into consideration for promotion, but was not found suitable as he lacked two years clerical experience. Admittedly, he was senior to some employees who were given promotion by superseding him. He has, therefore, a right to contend that before superseding him or denying promotion to him he should have been taken into consideration.

In the context of these premises, the stand taken by the Bank that Shri Bhargava was taken into consideration for promotion does not appear true. The Bank's plea, therefore, cannot be substained. It can be safely said that Shri Bhargava was not at all taken into consideration for promotion when employees junior to him were promoted.

The next pertinent question that arises for consideration is as to what would be the proper in the circumstances of the case.

It is well established that power to promote a workman belongs to the employer and this power cannot be exercised by the Tribunal as if it were the employer. The only relief the Tribunal can give in such cases is to direct the employer to consider properly the claims of the aggrieved workman for promotion. I am fortified in my submission by the Supreme Court authorities-quoted above and State of Mysore Vs. C. R. Seshadri (Supreme Court Labour Judgments Vol. 11 page 381). There are also two other authorities on the point. They are : State of Mysore and Syed Mohammed (1968) S.C.R. 366 and State of Mysore Vs. P. N. Naniupdian (1959), 3, S.C.R. 633.

The only relief which is, therefore, available to Shri B. R. Bhargava from this Tribunal is to obtain direction to the Bank to consider him for promotion on the date employees junior to him were promoted as Special Assistant.

For the foregoing reasons I pass an award in the following terms :—

(1) The Punjab National Bank did not act properly in not considering Shri B. R. Bhargava for promotion as Special Assistant on the day, employees junior to him were promoted.

(2) The Punjab National Bank shall now consider within three months of the publication of this award, the claim of Shri B. R. Bhargava for promotion as if he was eligible for promotion on the day employees junior to him were promoted as Special Assistant. It will be open to the Bank to record a finding whether Shri B. R. Bhargava had acquired the necessary qualifications for promotion as Special Assistant on the day employees junior to him were promoted.

In the peculiar circumstances of the case I leave the parties to bear their own cost of litigation.

The award be sent to the Central Government for publication as required by law.

S. S. BYAS, Presiding Officer

[No. L-12012/41/75-D. II. A]

S.O. 3965.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Rajasthan, in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank, Jaipur and their workmen.

CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, JAIPUR

Case No. CIT-3/1976

Ref :—Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, Notification No. L. 12012/145/73/LR.III dated the 31st October, 1975.

In the mater of Industrial Dispute

BETWEEN

All India Punjab National Bank Employees Association, Delhi.

AND

Punjab National Bank, Jaipur

PRESENT :

Shri P. D. Bansal—for the Association.

Shri P. V. Balkrishanan—for the Bank.

Date of Award

31st October, 1977

AWARD

The Central Government, by its notification cited above, has referred the following industrial dispute between the Punjab National Bank, Jaipur, and their workman Shri Surjit Singh, to this Tribunal for adjudication.

"Whether the action of the management of the Punjab National Bank, Jaipur, in terminating the services of Shri Surjit Singh, Clerk-cum-Cashelr with effect from the 4th January, 1970 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

The workman's cause was jointly espoused by the two Unions, (1) All India Punjab National Bank Employees Association, Delhi, and (2) The Association of the Punjab National Bank Employees, Rajasthan State Unit, Ajmer.

The case delineated in the statement of claims by the Unions is, that the concerned workman Shri Surjit Singh was appointed Godown Keeper on temporary basis on 11-7-1967. He continued to work in that capacity till 31-1-1970. During this period, he worked continuously. However, the Bank in order to break the continuity of his service gave four artificial breaks of one day each in November, 67, January, 68, April, 68 and September, 68. On 20-5-1970, Shri Surjit Singh was taken back by the Bank as a probationer to the post of Clerk-cum-Cashier. Since then, he was working in that capacity till now. It was alleged that the termination of workman's services on 3-1-1970 was bad and illegal in violation of the statutory provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, and the bipartite settlement dated 19-10-1966. The management of the Bank was approached by the Unions to treat Shri Surjit Singh as a regular employee right from 11-7-1967 condoning the breaks in service. The attempt proved abortive. The matter was taken to the Concillation Officer, (Central), Ajmer, but there too no conciliation could take place due to the non-cooperative attitude of the Bank. The reliefs claimed are :

1. The workman Shri Surjit Singh be treated and taken as a permanent employee with effect from 11-7-1967.

2. He be deemed confirmed from 11-7-1968.

3. Payment of wages for artificial breaks on four occasions.

4. Reinstatement of the workman with effect from 4-1-1970.

5. Annual increments for the year 1968 and thereafter.

The claim was resisted by the Bank in its statement of defence. In its reply, the Bank admitted that Shri Surjit Singh was appointed temporary Godown Keeper on 11-7-1967. It was also admitted that intermittent breaks in service were given to him in November, 67 and January, April and September, 68. Thereafter, he was re-appointed as temporary Godown Keeper on 6-9-1968 and his services came to an end on 3-1-1970. The workman was selected as a Clerk-cum-Cashier on the basis of a written test and interview. He was thereafter appointed as a probationer Clerk-cum-Cashier with effect from 20-5-1970. Since then, he has been working in that capacity till now. It was denied that the intermittent breaks were artificially created. It was also denied that the termination of the workman's services on 3-1-1970 was bad or invalid. It was alleged that the termination was perfectly justified and contravened no statutory provisions. In the end, it was submitted that the workman was not entitled to any relief.

On behalf of the Union, two witnesses, Shri Surjit Singh, the concerned workman and Shri Jankilal were examined. In rebuttal, the Bank examined no witness. Both the parties of course filed documents.

In view of the rival contentions of the parties, the following questions arise for consideration.

1. Nature of appointment—Whether temporary or permanent?

2. Whether the termination was illegal and void ?

3. Whether the workman is entitled to earn annual increments and continuity in service from 11-7-67 ? and

4. What would be the proper relief in the circumstances of the case?

I shall deal with these questions and seriatim.

Re-1—Nature of appointment—Whether temporary or permanent?

It was vehemently contended by the workman that his appointment was of permanent nature. In support of his allegation, he examined himself and adduced no other evidence. He stated on oath that his appointment was of permanent nature. But, he stands completely belied by his own statement of claims. In para 2 of it, it was pleaded that he was appointed temporarily as a Godown Keeper on 11-7-67. The workman cannot be allowed to turn round and disown his own pleadings. Again, documents Ex. W.2, Ex.W.3 and Ex.W.5 clearly reveal that the workman was appointed temporarily as a Godown-Keeper. The workman is the author of all these three documents. In these documents, he has made clear admissions that his official appointment made on 11-7-67 was purely temporary in nature. There is nothing like automatic confirmation of a temporary employee. Temporary service for any length of time does not make an employee permanent. The Unions have not put forward any material before me in the shape of Circulars or Notifications or Certified-Standing Orders or Bipartite Settlement to show that the temporary appointment stands converted automatically into a permanent appointment by putting service of some specified length.

There is yet another aspect of the matter. The directions regarding absorption of temporary employees are contained in paragraphs 20.12 and 20.13 of the bipartite settlement dated 19-10-66, which are reproduced below :—

"20.12. Other things being equal, temporary workman (other than godown-keeper) will be given preference for filling permanent vacancies and if selected they may have to undergo probation.

20.13. Temporary godown-keepers and godown-watchman who are required to look after one or more godowns belonging generally to one party and whose salary and allowances are generally borne by the parties who are owners of the goods in the godowns, shall, if their work has been found satisfactory and if their services can be utilised to look after other godowns in the same place or other places or in the clerical establishment of the bank, on completion of one year's service, be given preference for absorption in the permanent service of the bank, subject to the bank's recruitment rules, if any."

It can be safely gathered from the above two paragraphs that a temporary employee can be absorbed in permanent

service subject to the Bank's Recruitment Rules. The workman, Shri Surjit Singh, qualified himself for the permanent posting only in May, 1970. As such, he could not be taken to be in permanent service before his selection. It, therefore, follows that he was a temporary employee upto 3-1-70.

Re.-2—Whether the termination was illegal and void? Before proceeding further, it may be stated that the workman remained in the Bank's service from 11-7-67 to 3-1-70 with some intermittent breaks before he was finally selected as a permanent employee in May, 70. There is no dispute between the parties that the workman was in the Bank's continuous service from 11-7-67 to 3-1-70 with only four breaks, each of one day. It is thus clear that on 3-1-70 when his services were terminated, he had put in more than 240 days service. Thus, he had been in continuous service for one year as defined in S. 25-B(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter to be referred as the Act), because he had worked for more than 240 days during the period of 12 calendar months preceding the date of termination of his services. In other words, the workman had been in the banks continuous service, as required by sub-section (2) of Sec. 25-B of the Act.

Having examined the factual position by me, I may now turn to the question whether the termination of the workman's services was or was not legal. It was contended by the Unions that as the workman had put in one year's continuous service as defined in S. 25-B of the Act, his services could not be terminated without complying with the conditions mentioned in S. 25-F of the Act. It was argued that every termination of services amounts to retrenchment and the retrenchment can be made only when the conditions mentioned in S. 25-F of the Act were fulfilled. Since these conditions were not fulfilled, the retrenchment is illegal. In reply, it was argued on behalf of the Bank that his services being temporary in nature, for fixed specified period, came to an automatic and with the efflux of time. It was argued that the termination was automatic on the expiry of the contractual period of service. Hence, the question of retrenchment does not arise. It is a matter of automatic termination and not of retrenchment.

The contentions raised on behalf of the Bank have no merit or substance in view of the law laid down by the Hon'ble Supreme Court in two cases, referred to below. The contentions that retrenchment does not cover the case of the employees, because their services had come to an end by efflux of time or that their appointments were of temporary nature etc. were also raised before the Hon'ble Supreme Court and were repelled. In Sundara Money's case, the Hon'ble Supreme Court observed as follows, vide A.I.R. 1976 S.C. 1111.

> "Termination . . . for any reason whatsoever in Section 2(OO) are the key words. Whatever the reason, every termination spells retrenchment. So the sole question is has the employee's service been terminated? Verbal apparel apart, the substance is decisive. A termination takes place where a term expires either by the active step of the matter or the running out of the stipulated term.
>
> Termination embraces nor merely the act of termination by the employer, but the fact of termination howsoever produced.
>
> That to write into the order of appointment the date of termination confers no moksha from S. 25F(b) is inferable from the proviso to Section 25F(a).
>
> The transitive and intransitive senses are covered in the correct context. Moreover, an employer terminates employment not merely by passing an order as the service runs. He can do so by writing a complete order, one giving employment and the other ending of limiting it. A separate subsequent . . . determination is not the sole magnetic pull of the provision. A pre-emptive provision to terminate is struck by the same vide as the post-appointment termination."

The same view was reiterated in the subsequent case of M/s. Hindustan Steel Limited and it was observed vide A.I.R. 1977 S.C. 31.

> "Termination of service by running out of time stipulated in the contract of service amounts to retrenchment. Non-compliance of S. 25F(b) renders the retrenchment illegal."

Therefore, the termination of services of workman amounts to retrenchment.

S. 25-F relates to retrenchment. This section postulates three conditions to be fulfilled by an employer before effecting a valid retrenchment, viz., (a) one month's notice in writing indicating the reasons for retrenchment or wages in lieu of such notice, (b) payment of compensation equivalent to 15 days average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months, and (c) notice to the appropriate Government in the prescribed manner.

Retrenchment in violation of these provisions of Sec. 25-F is void ab initio. The termination of service without complying these provisions will not be retrenchment in the eye of law. The workman will be entitled to continuity of service.

In the instant case, admittedly no compensation as required by Sec. 25-F(b) was paid to the workman. This non-compliance in itself is sufficient to vitiate the termination of the workman's services made on 3-1-70. In Sundara Money's case, the termination was struck down for non-compliance of S. 25-F(b) of the Act. I, therefore, hold that the termination of the workman's services was illegal and void ab initio, because his retrenchment was in direct violation and contravention of the mandatory provisions of S. 25-F(b) of the Act.

Re.-3—Whether the workman is entitled to earn annual increments and continuity in service from 11-7-67?

It was contended by the Unions that the workman should be allowed annual increments falling due in 1968, 1969 and 1970. I find no force in the submission. It is well settled that annual increments are given to those who are in regular cadre and not to temporary employees appointed for specified fixed period. Likewise, the continuity of service cannot be granted. The workman's services were terminated on 3-1-67. Thereafter, he was taken back due to his selection in the competitive examination. The two services, one before 3-1-67 and the other starting from May, 1970 cannot be clubbed together for any purpose. The workman is, therefore, not entitled to the annual increments as well as to have the continuity of service.

Re.-4—Relief

In Sundara Money's case, it was observed that re-instatement is the necessary relief that follows from the illegal retrenchment. The workman, Shri Surjit Singh, is, therefore, entitled to re-instatement.

The case has a peculiar feature. The workman on his selection was re-employed as Clerk-cum-Cashier on permanent basis in May, 1970. There is, therefore, no question of his re-instatement to the post of Godown-Keeper. Doing so will cause a great harm to the workman.

The proper relief in the peculiar circumstances of the case would be;

(1) to award compensation to the workman Surjit Singh for the period from 6-4-70 to 19-5-70 at the rate of the wages he was drawing last on 3-1-70 as Godown Keeper, and (2) difference in pay, if any, between what was actually paid to him for the period from 4-1-70 to 5-4-70 and that he was drawing last on 3-1-70 as Godown Keeper. No other reliefs like annual increments or continuity in service etc. can be granted. I make my award accordingly.

The award be submitted to the Central Government as required by law.

S. S. BYAS, Presiding Officer

[No. L-12012/145/73-LR. III/D. II. A.]

New Delhi, the 9th December, 1977

S.O. 3966.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India, Chandigarh and their workmen.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI.

I. D. No. 101 of 1977

In re :

The General Secretary,
Central Bank of India Employees Union, Haryana,
146—A Lal Kurti,
Ambala Cantt.

Versus

The Zonal Manager,
Central Bank of India, Sector 17-B.
Chandigarh.

PRESENT :

Shri H. L. Chibbar and Shri R. K. Joshi for the Bank.
The workman concerned in person.

AWARD

The Central Government as appropriate Government referred an Industrial Dispute vide its No. L. 12012/31/75-DII/A dated the 29th May, 1975 to Industrial Tribunal, Chandigarh in the following terms :—

"Whether the action of the management of the Central Bank of India, Chandigarh in not treating Shri Ajit Kumar Sharma, Clerk, in continuous employment with effect from the 12th June, 1969, is an act of unfair labour practice ? If so, to what relief is the said workman entitled ?"

2. After the case was registered a notice was sent to the respective parties and a statement of claim was filed on behalf of the workman. In reply whereto a written statement was filed on behalf of the Management. Thereafter the following issues were framed :

1. Whether the action of the management of the respondent bank in not treating Shri Ajit Kumar Sharma, Clerk in continuous employment with effect from 12-6-1969, is an act of victimization and unfair labour practice ?

2. If issue no. 1 is decided for the workman and against the management ? To what relief, if any, is workman entitled ?

3. Thereafter the case was fixed for the evidence of the Management and after recording the two witnesses of the Management the case was transferred to the Industrial Tribunal, Delhi and then to this Tribunal. On transfer of this case it was ordered to be registered vide my order dated 17-7-1977 and notices were issued to the parties. On 17th August, 1977 it was stated on behalf of the Bank and the workman by Shri H. L. Chibber and Shri R. K. Joshi that 'Parties have compromised. Ex. C/1 is correct. A no dispute award be returned.' Ex. C/1 is the settlement which has been filed in this case and it has been stated in the said settlement that parties have mutually settled the dispute and the dispute no longer survive and a no dispute award be made in this matter. In view of the settlement and in view of the statements recorded above, a no dispute award is passed in the instant case. Parties are left to bear their own costs. Requisite copies of the award may be sent to the appropriate Government for necessary action.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

Dated the 5th September, 1977.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) DELHI.

Ref. C. G. I. D. 101 of 1976

In the matter of Industrial Dispute between the management of Central Bank of India.

AND

Its workman as represented by CBIEU Haryana.

RESPECTFULLY SHEWETH :

That the parties to the above dispute have arrived at an amicable settlement of the dispute, as per the mutual negotiations, held between the parties and duly recorded in the minutes of joint discussions held on 3rd and 4th August, 1976 at Bombay.

That in view of the mutual settlement of the dispute between the parties, the dispute no longer survives and it is, therefore, prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to make a no-dispute award in the matter.

For CBIEU Haryana

Sd/

General Secretary.

For Central Bank of India.

Sd/-

Authorised Representative

Sd/-
Assistant Zonal Manager (Personnel)

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer.

[No. L-12012/31/75-D. II. A]

S.O. 3967.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India, Chandigarh and their workmen.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFIER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I. D. No. 109 of 1977

In re :

The General Secretary,
Central Bank of India Employees Union,
Haryana,
Ambala Cantt.

....Petitioner

Versus

The Zonal Manager,
Central Bank of India,
Sector—17,
Chandigarh.

....Respondent

PRESENT :

Shri H. L. Chibber and Shri R. K. Joshi for the Bank.

The workman concerned in person.

AWARD

The Central Government as appropriate Government referred an Industrial Dispute vide its No. L. 12012/34/75-DII/A dated the 29th May, 1975 to Industrial Tribunal, Chandigarh in the following terms :

'Whether the action of the management of the Central Bank of India, Chandigarh in stopping one Grade increment of Shri Vishal Mani, Assistant Cashier-cum-Godown Keeper, Addalat Branch, Patiala Branch of the Bank is legal and justified or is it an act of discrimination and unfair labour practice ? In either case, to what relief is the said workman entitled ?'

2. After the case was registered by the Tribunal a notice was sent to the respective parties and a statement of claim was filed on behalf of the workman. In reply thereto a written statement was filed on behalf of the Management. In the meanwhile this case was transferred to Industrial Tribunal, Delhi from where it was transferred to this Tribunal and it is in these circumstances that this matter has come up for final disposal before this Tribunal. On transfer of this case it was ordered to be registered vide my order dated 16-7-1977 and notices were issued to the workman. On the 17th August, 1977 it was stated on behalf of the Bank and the workman by Shri H. L. Chibber and Shri R. K. Joshi that 'Parties have compromised. Ex. C/1 is correct. A no dispute award be made.' Ex. C/1 is the settlement which has been filed in this case and it has been stated in the said settlement that parties have mutually settled the dispute and the dispute no longer survive and a no dispute award be made in this matter. In view of the settlement and in view of the statements recorded above, a no dispute award is passed in the instant case. Parties are left to bear their own costs. Requisite copies of the award may be sent to the appropriate Government for necessary action.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

Dated : the 1st September, 1977.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) DELHI

Ref. C. G. I. D. 109 of 1976

In the matter of Industrial Dispute between the management of Central Bank of India.

AND

Its workman as represented by CBIEU Haryana.

RESPECTFULLY SHEWETH :

That the parties to the above dispute have arrived at an amicable settlement of the Dispute, as per the mutual negotiations, held between the parties and duly recorded in the minutes of joint discussions held on 3rd and 4th August, 1976 at Bombay.

That in view of the mutual settlement of the dispute between the paries, the dispute no longer survives and it is, therefore, prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to make a no-dispute award in the matter.

For CBIEU Haryana

Sd/-

General Secretary.

For Central Bank of India
Assistant Zonal Manager (Personnel)

Sd/-
Authorised Representative.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer.

[No. L-12012/34/75-D. II. A.]

S.O. 3968.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India, Chandigarh and their workmen.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I. D. No. 103 of 1977

In re :

The General Secretary,
Central Bank of India Employees' Union, Haryana,
146-A, Lalkurti,
Ambala Cantt.

Versus

The Zonal Manager,
Central Bank of India,
Sector 17, Chandigarh.

PRESENT :

Shri H. L. Chibber for the Management.

Shri R. K. Joshi for the workman.

AWARD

The Central Govt. as appropriate Govt. referred an Industrial Dispute vide its No. L-12012/103/73-LRIII dated the 25th February, 1975 to Industrial Tribunal, Chandigarh in the following terms :

'Whether the action of the management of the Central Bank of India in terminating the services of Shri Baljit Singh, Clerk-cum-Typist at the Nawanshahr Branch of the Bank with effect from the 16th June, 1973 is legal and justified. If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. After the case was registered by the Tribunal a notice was sent to the respective parties and a statement of claim was filed on behalf of the workman. In reply thereto a written statement was filed on behalf of the Management. Thereafter the following issues were framed :

1. Whether the action of the management of the respondent bank in terminating services of Shri Baljit Singh, clerk-cum-typist at the Nawanshahr Branch of the Bank is legal and justified?

2. If issue No. 1 is decided for the workman and against the management, to what relief is the workman entitled?

3. Thereafter the case was adjourned for the evidence of the Management and three witnesses were recorded and it was thereafter that the case was transferred to CGIT, Delhi and ultimately to this Tribunal for final disposal. On transfer of this case it was ordered to be registered vide my order dated 16-7-1977 and notices were issued to the parties. On the 17th August, 1977 it was stated on behalf of the Bank and the workman by Shri H. L. Chibber and Shri R. K. Joshi that 'parties have compromised. Ex. C/1 is correct. A no dispute award be returned.' Ex. C/1 is the settlement which has been filed in this case and it has been stated in the said settlement that parties have mutually settled the dispute and the dispute no longer survive and a no dispute award be returned in this matter. In view of the settlement and in view of the statements recorded above, a no dispute award is returned in the instant case. Parties are left to bear their own costs. Requisite copies of the award may be sent to the appropriate Govt. for necessary action.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

Dated : 5th September, 1977.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) DELHI.

Ref. No. C.G.I.D. No. 103 of 1977

In the matter of Industrial Dispute between the management of Central Bank of India.

AND

Its workman as represented by CBIEU Haryana.

RESPECTFULLY SHEWETH :

That the parties to the above dispute have arrived an amicable settlement of the dispute, as per the mutual negotiations held between the parties and duly recorded in the minutes of joint discussions held on 3rd and 4th August, 1976 at Bombay.

That in view of the mutual settlement of the dispute between the parties, the dispute no longer survives and it is, therefore, prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to make a no-dispute award in the matter.

For CBIEU Haryana

Sd/-
General Secretary.

Sd/- Authorised Representative
For Central Bank of India

Sd/-
Assistant Zonal Manager (Personnel)

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

[No. L-12012/103/73-LR. III]

S.O. 3969.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India Chandigarh and their workmen.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI.

I.D. No. 102 of 1977

In re :

The General Secretary, Central Bank of India Employees' Unin, 146-A, Lalkurti, Ambala Cantt.

Versus

The Zonal Manager, Central Bank of India, Chandigarh.

PRESENT :

Shri H. L. Chibber and Shri R. K. Joshi for Bank.

The workman concerned.

AWARD

The Central Govt. as appropriate Govt. referred on Industrial dispute vide its No. 12012/114/74/LRIII dated the 20th March, 1975 to Industrial Tribunal, Chandigarh in the following terms :

"Whether the action of the management of the Central Bank of India, Chandigarh in denying benefits to Shri Bachan Singh, Armed Guard, Ladwa Branch of the Bank arising out of his confirmation with effect from 2nd January, 1964 is legal and justified ? If not to what relief is he entitled ?"

2. After the case was registered by the Tribunal a notice was sent to the respective parties and a statement of claim was filed on behalf of the workman. In reply thereto a written statement was filed on behalf of the Management. Thereafter the following issues were framed :

1. Whether Shri Bachan Singh, an employee of the respondent Bank, is entitled to any benefits said to arise out of his confirmation from 2nd January, 1964 and what those benefits are ?

2. If issue No. 1 is decided in favour of the workman to what relief, if any, is he entitled ?

3. Thereafter the case was adjourned for the evidence of the Management and only one witness was recorded and it was thereafter that the case was transferred to CGIT, Delhi and ultimately to this Tribunal for final disposal. On transfer of this case it was ordered to be registered vide my order dated 16-7-1977 and notices were issued to the parties. On the 17th August, 1977 was stated on behalf of the Bank and the workmen by Shri H. L. Chibber and Shri R. K. Joshi that 'parties have compromised. Ex. C/1 is the correct. A 'no dispute award be returned' Ex. C/1 is the settlement which has been filed in the case and it has been stated in the said settlement that parties have mutually settled the dispute and the dispute no longer survives and a no dispute award be returned in this matter. In view of the settlement and in view of the statement recorded above, a no dispute award is returned in the instant case. Parties are left to bear their own costs. Requisite copies of the award may be sent to the appropriate Govt. for necessary action.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

Dated : the 5th September, 1977.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL), DELHI.

Ref. No. C.G.I.T. No. 80 of 1976.

Ref. No. 14/C (of Chandigarh) of 75

I. D. No. 102 of 1977

In the matter of Industrial Dispute between the management of Central Bank of India.

AND

Its workman as represented by CBIEU Haryana.

RESPECTFULLY SHEWETH :

That the parties to the above dispute have arrived at an amicable settlement of the dispute, as per the mutual negotiations, held between the parties and duly recorded in the minutes of joint discussions held on 3rd and 4th August, 1976 at Bombay.

That in view of the mutual settlement of the dispute between the parties, the dispute no longer survives and it is, therefore, prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to make a no-dispute award in the matter.

For CBIEU Harvana

Sd/-
General Secretary.

Sd/-
Authorised Representative
For Central Bank of India

Sd/-
Assistant Zonal Manager (Personnel)

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer.

[No. L-12012/114/74-LR. III]

S.O. 3970.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay in the industrial between the employers in relation to the management of Canara Banking Corporation Limited, Mangalore and their workman, which was received by the Central Government on the 3rd December, 1977.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/11 of 1974

PARTIES :

Employers in relation to the Canara Banking Corporation Limited, Mangalore.

AND

Their workman.

Shri M. Padmanabha Prabhu.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri Narayan Shetty, Advocate.

For the workman.—Shri M. P. Prabhu, (The workman in person)

INDUSTRY : Banking STATE : Karnataka

Bombay, the 3rd November, 1977

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour by virtue of the powers conferred on it under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the following industrial dispute for adjudication to this Tribunal vide its order No. L-12025/44/72/IRIII dated 22-3-1974 :—

"Whether the action of the management of Canara Banking Corporation Limited in terminating the services of Shri M. Padmanabha Prabhu, Accountant with effect from the 17th September, 1968 was justified ? If not, to what relief is he entitled ?"

The statement of claim runs into 60 typed pages and it is unnecessary to summarise the entirety of it. The facts relevant for appreciating the points covered by the present order may be briefly stated. Shri M. Padmanabha Prabhu (hereinafter referred to as the 'employee') is a B. Com. graduate. He joined the Canara Banking Corporation Limited (hereinafter referred to as 'the Bank') as an Apprentice Clerk in January, 1958. After the period of Apprenticeship he was confirmed as a Clerk on 14-7-1959. In 1961 he was promoted to the post of Probationary Accountant in which capacity he worked till March, 1967. On 27-3-1967 the employee was reverted to the post of a Clerk, for alleged misconduct. The said action on the part of the Bank was challenged before the Assistant Labour Commissioner (C) Bangalore through the Mysore State Bank Employees' Federation Bangalore. Before the Conciliation Officer the parties entered into a settlement of the dispute whereby the Bank agreed to promote the employees as an Accountant (Officer-grade) with effect from 1-10-1967. He was to be confirmed after the probationary period of six months. His starting salary was fixed at Rs. 290/- besides other allowances. He was confirmed as an Accountant in the Officer's grade with effect from 1-4-1968 as per the terms of the agreement. The Bank by their letter dated 16-9-1968 terminated the services of the employee under Regulation 10(i) of Chapter II of the Service Regulations with effect from 17-9-1968 after paying him the salary due for 17 days of that month and salary and allowances for three months in lieu of notice. The employee challenged the fairness of that order but in vain. Then he approached the Canara Banking Corporation Employees' Union to take up his cause. The representation on behalf of the Union also was not considered by the Bank. Thereafter the employee raised an industrial dispute under Section 2A of the Act before the Assistant, Labour Commissioner (C) Bangalore. Before the Assistant Labour Commissioner (C) the Bank contended that the employees was not a workman within the meaning of the Act, but an Officer. The Assistant Labour Comissioner (C) submitted to the Ministry failure of conciliation report on 21-4-1972. The Central Government declined to refer the dispute for adjudication by their order dated 1-8-1972 for the reason that the employee was not a workman within the meaning of Section 2(s) of the Act. The employee filed a Writ Petition before the High Court of Mysore questioning the above order. The High Court by its ex-parte order dated 30-11-1973 while quashing the order dated 1-8-1972 directed the Central Government to refer the dispute to an Industrial Tribunal for adjudication. Acting on the directions of the High Court the Government has referred the dispute to this Tribunal for adjudication by its order dated 22-3-1974. The employee prays for reinstatement with continuity of service and back wages on the ground that the order terminating his services without holding enquiry is illegal and opposed to the principles of natural justice. He maintains that he is a workman within the meaning of the Industrial Disputes Act and that this Tribunal has jurisdiction to entertain the reference.

The management filed a written statement stating that the provisions of the Industrial Disputes Act do not apply to the present case because the employee is not a workman within the meaning of Section 2(s) of the Act. The Bank also submits that this dispute has become stale as it is being raised by the employee for the first time three years after the termination of his services. Lastly it is submitted that the employee should pursue his remedy if any under the Karnataka Shops and Commercial Establishments Act and not under the Industrial Disputes Act. The Bank also submits that the present dispute in an individual dispute and not an industrial dispute between the Bank and its workmen in general as stated in the order of reference. For this reason also this reference is said to be not maintainable.

Shri Shetty for the Bank urged that the question of maintainability of the reference should be decided in the first instance. On the question of maintainability, the points that arise for consideration are :—

(1) Whether the employee in question is not a 'workman' within the meaning of Section 2(s) of the Industrial Disputes Act?

(2) Whether the present reference as it is worded is not proper?

(3) Whether the employee is not entitled to avail himself of the provisions of the Industrial Disputes Act in view of the Provisions of the Karnataka Shops and Commercial Establishments Act?

(4) Whether the claim in question is liable to be rejected on the grounds of delay?

The parties have not chosen to adduce any oral evidence. They have relied on certain documents which are marked by consent.

Point 1 :

The employee was promoted as a Probationary Accountant on 10-11-1961 and in that capacity he worked till the date of reversion to the substantive post of Clerk in March, 1967 It is not disputed that during the period 1961 to 1967 a Probationary Accountant was a 'workman' within the meaning of the Industrial Disputes Act. It is also not disputed that the post of Accountant is an Officer's post in this Bank. Duties and functions of the Accountant are given in the Service Regulations a copy of which is placed on the record. Chapter I, Regulation 11 (vii) (2) and 11 (xiii) of the Canara Banking Corporation Limited Service Regulations 1963 read as follows :—

"11 (vii) (2) The following posts in the Bank shall be held by officers and an employee occupying any of the said posts shall, during the period of such occupation, be deemed to be an officer;

(a) ———
(b) ———
(c) ———
(d) ———
(e) ———
(f) ———
(g) Accountants.
. . . . . ."

"11 (xiii) **General Powers and Duties of Accountants.**

Every Branch will have one or more Accountants who will be joint custodians of the securities and cash at the branch and will be responsible for the proper maintenance of accounts. They shall have the managerial and supervisory powers necessary for the day-to-day working of the branch. They shall be under immediate control of the Agent and shall look to the internal routine work of the branch in accordance with the instructions of the Branch Agent. They will have the control over the clerical and subordinate staff of the branch. They will assist the Agent in the development of the business of the branch."

When the employee was reverted to the post of a Clerk in March, 1967 he raised an industrial dispute questioning the order of reversion before the Assistant Labour Commissioner (C) Bangalore. That dispte was amicably settled between the parties. A Memorandum of Settlement dated 21-9-1967 was signed before the Assistant Labour Commissioner (C) Bangalore, Para. 2 of the terms of that settlement reads as follows :—

"It is agreed that the Bank shall promote Shri M. Padmanabha Prabhu as an Accountant in the Officers grade with effect from 1-10-1967."

It is not disputed that in terms of the settlement the employee was confirmed as an Accountant on 1-4-1968. Admittedly on the date of the order of termination of service viz. 17-9-1968 he was drawing more than Rs. 600 per

month It is contended on behalf of the Bank that since the employee was occupying the position of an Officer, this dispute under the Industrial Disputes Act regarding the termination of his service cannot be gone into The employee argues that though he was nominally occupying the position of an Officer he was not being treated as an Officer by the Bank The learned Advocate for the Bank invites attention to an unreported decision of the Supreme Court in Civil Appeal No 118 of 1963* (decision dated 27 11-1963) for the proposition that a clerk who becomes an officer of the Bank by his own voluntary choice cannot be permitted to turn round and say that the Officer's grade given to him must be treated as a Clerical grade or that of a probationary Accountant In the case decided by the Supreme Court the Bank offered the Clerk a post of an Officer The clerk gave it in writing saying "I irrevocably opt for the Bank's rules and so accept the emoluments offered to me in the Bank grade viz Rs 110-10-200" After having been promoted to the post of an Officer the employee demanded payment of special allowance of Rs 40 per month as clerk supervisor, over and above the salary that was given to him in the Officer's grade and the Supreme Court turned down that plea in the following terms :—

> "It was a free choice which a clerk always has, to give up his status of a clerk and become an Officer of the bank, if an offer of that kind is made to him But after having done so and become an officer by his own voluntary choice a clerk cannot turn round and say that the officer's grade given to him must be treated as his grade as a clerk and thereafter he must be given the supervisor's allowance provided under the Sastry Award This is what the respondent really wants He accepted the officer's grade voluntarily and after he was given that grade and made an officer, he came forward with the claim that he was still a clerk and entitled to the allowance This he cannot be permitted to do in the face of his letter of November, 12, 1955"

In the instant case also the employee raised an industrial dispute with the Bank regarding his wrongful reversion to the post of a clerk During the conciliation proceedings the Bank offered him the post of an Accountant in the Officer's grade which offer the employee accepted The salary in the Officer's grade was paid to him and by the relevant date he was drawing the salary in that grade In the circumstances the employee should not be permitted to say that he was nominally occupying the position of an Officer while in fact he was discharging the clerical functions

Then the employee Shri Prabhu contended that the settlement before the Conciliation Officer was a void agreement and therefore should not be looked into for the purpose of determining his status I do not agree with this contention The terms of the agreement have been fully implemented by both the parties In pursuance of that agreement the Bank offered the employee an Officer's post of an Accountant which he accepted He was also confirmed in that post with effect from 1-4-1968 in terms of that settlement Admittedly he was drawing the scale of pay of that post given to him in terms of the agreement Having enjoyed the benefit of that agreement the employee should not be permitted to repudiate the same

The next contention that though he was occupying the Officer's post of an Accountant he was not given the powers of an Officer His complaint is that no power of attorney was executed in his favour He says that his confirmed signatures were not circulated to various branches to enable him to sign the inter-branch Balance of payment sheets He further stated that the powers exercised by him as a probationary Accountant were not different from those exercised by him as an Accountant He further contends that after his promotion to the post of Accountant in terms of the settlement he made it clear to the management that he did not give up his rights under the Industrial Disputes Act No such communication addressed by the employee to the Bank has been filed and even if there is one such a communication would not alter the position

For the foregoing reasons point 1 held against the workman

*M/s. Hindustan Mercantile Bank Ltd vs Thakurdas Tahiram Advani

POINT 2

The facts of the case clearly show that it is an individual dispute regarding the termination of the service of one employee, but the preamble to the reference is worded as follows

> "Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Canara Banking Corporation Limited and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed. ."

The schedule portion clearly indicates the scope of the dispute i e to say that it is an individual dispute It is argued on behalf of the management that the order of reference is vitiated by an error apparent on the face of the record because it refers to the existence of a collective dispute while in fact it was an individual dispute A similar point was raised in the case reported in 1970 Lab I C 203** His Lordship Mr Justice Kalisasam (as he then was) rejected that argument in the following words :—

> "The submission on behalf of the petitioner is that there is nothing to indicate that the Government was aware of the fact that the dispute was between an individual workman and the management and as the Government was under the impression that it was a collective dispute between the workmen and the management of T V Sundaram Iyengar and Sons (P) Ltd the order is vitiated due to the misconception by the Government This plea is mainly based on the wording of the notification that an industrial dispute has arisen between the "workmen and the management of T V Sundaram Iyengar and Sons (P) Ltd" I am unable to accept this contention, for, it is clear that what the Government was considering and what it was referring was whether the non-employment of Thiru S. Krishna is justified and if not to what relief he is entitled The plea that the Government was under the misapprehension that the dispute was collectively between the workmen and the management is not borne out from the documents It is clear that the Government was dealing with the dispute which related to the dismissal of Thiru S. Krishna and they referred that dispute."

Following the above decision I hold point 2 against the Bank.

POINT 3 :

It is stated that under Section 39 of the Karnataka Shops and Commercial Establishments Act the remedy of an individual employee against the improper order of termination of his service is to prefer an appeal to the authority mentioned in that Act and not to involve the provisions of the Central Act (Industrial Disputes Act) The Full Bench decision of the Andhra Pradesh High Court reported in 1977 II, LLJ, page 332† is relied upon for this proposition. It may be noticed that the order of termination in question was served on the employee while he was working at the Mangalore Branch of the Bank In its judgement the Andhra Pradesh High Court observed as follows —

> "Even if the Shops Act and the I D Act do not coincide in regard to the entire field they cover, there is repugnancy pro tanto by reason of insertion of S 2A in the I D Act, whereby individual disputes which are not espoused by the union or by other workman, are also brought within the ambit of that Act so that a reference can be made under S. 10 (1) of the I D Act in regard to the same. The dispute of an individual workman, in regard to termination of services, squarely falls within the field covered by Ss 40 and 41 of the Shops Act and to that extent there is repugnancy between the two Acts.
>
> In view of the fact that the Shops Act has been assented by the President, the provisions of Shops Act relating to the termination of the services of an employee of a shop establishment must prevail

**T V Sundaram Iyengar and Sons (P) Ltd vs State of Madras.

†Visakhapatnam Dt. Marketing Co-op. Society vs Govt of A P and others

over S. 2A of the I. D. Act and over the other provisions of that Act in so far as the same are attracted by reason of the said S. 2A."

The Full Bench of the Madras High Court has considered the same question in the case reported in 1977, II, LLJ, page 312**, but has come to a different conclusion, and held that the remedy given to an aggrieved workman under the Industrial Disputes Act and the Shops and Establishments Act is alternative and that the workmen can choose either of those remedies but not both. In this case the workman has chosen to avail himself of the remedy given to him under the Central Act which he is perfectly entitled to under the Madras High Court Full Bench decision. I prefer to follow the decision of the Madras High Court.

Point 3 held against the Bank.

POINT 4:

The services of the employee in question were terminated with effect from 17-9-1968. He raised the present dispute before the Assistant Labour Commissioner (C) Bangalore for the first time on 11-9-1971 i.e. 3 years after the alleged wrongful termination of service Shri Shetty for the Bank urges that in view of this delay the present reference should not be entertained. He says that an enquiry into the dispute will have the effect of unsettling the existing conditions of service under the Bank. I am not inclined to reject this reference on the ground of delay alone. Shri Shetty has not explained in what manner an enquiry into this dispute will unsettle the existing service conditions.

Point 4 held against the Bank.

In view of the finding on point 1 this reference is rejected.

P. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

[N. L-12025/44/72-I.R. III]

JAGDISH PRASAD, Under Secy.

**Safire Theatre Vs. Commissioner for Workmen's Compensation and others.

का०आ० 3971.—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ङ) के उप-खण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 2134 तारीख 7 जून, 1977 द्वारा सिक्यूरिटी पेपर मिल होशंगाबाद को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 18 जून, 1977 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः, अब, औद्योगिक अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के 18 दिसम्बर, 1977 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस० 11017/10/77-डी० 1(ए)]

एल० के० नारायणन, डेस्क अधिकारी

S.O. 3971.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required, had in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2134 dated the 7th June, 1977 the Securlty Paper Mill, Hoshangabad, to be public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six month from the 18th June, 1977.

And whereas the Central Government is of the opinion that the public interest requires the extension of the said period by a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 18th December, 1977.

[N. S. 11017/10/77/DI(A)]

L. K. NARAYANAN, Desk Officer

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अप्रैल 1977

का० आ० 3972—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 36 के अनुसरण में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वर्ष 1975-76 सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट आम सूचना के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है :—

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वार्षिक रिपोर्ट, 1975-76

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों की सूची

1975-76

अध्यक्ष

श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी

श्रम मंत्री

भारत सरकार

उपाध्यक्ष

श्री ए० के० एम० इशाक

उपमंत्री स्वास्थ्य और परिवार नियोजन

भारत सरकार

सदस्य

केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि

3. श्री बालगोबिन्द वर्मा, उप-मंत्री श्रम, भारत सरकार ।
4. श्री एन० पी० दुबे, सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय।
5. श्री डी० एम० निम, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय।
6. डा० जे० बी० श्रीवास्तव, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, भारत सरकार।
7. श्री ए० के० सैन, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग।

राज्य सरकारो के प्रतिनिधि :

8. श्री एम० आर० पाई, सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य, आवास एवं नागरिक प्रशासन विभाग।
9. श्री टी० एस० गिल, सचिव, असम सरकार, श्रम विभाग।
10. श्री आई० सी० कुमार, सचिव, बिहार सरकार, श्रम और रोजगार विभाग।
11. श्री एम० एच० जगद, सचिव, गुजरात सरकार, पंचायत एवं स्वास्थ्य विभाग।
12. श्री पी० पी० कैपरीहन, सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग।
13. श्री पी० के० मट्टो, सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग।
14. श्री यू० महाबला राओ, सचिव, केरल सरकार, श्रम विभाग।
15. डा० प्रकाश नारायण, निदेशक स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश सरकार।
16. श्री आर० पासुथि, सचिव, तमिलनाडु सरकार, श्रम विभाग ।
17. श्रीमती प्रतिभा डी० पाटिल, मंत्री, जन स्वास्थ्य, महाराष्ट्र सरकार।
18. श्री टी० जे० रामाकृष्णन, सचिव, कर्नाटक सरकार, समाज कल्याण एवं श्रम विभाग।
19. श्री सोवर कानूनगो, सचिव, उड़ीसा सरकार, श्रम, रोजगार तथा आवास विभाग।
20. श्री एन० के० जोशी, श्रमायुक्त और अतिरिक्त सचिव, राजस्थान सरकार, श्रम विभाग।
21. श्रीमती जी० के० मेखों, सचिव, पंजाब सरकार, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन विभाग।
22. श्री के० एन० श्रीवास्तव, आयुक्त सहित सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, श्रम विभाग।
23. श्री आर० एन० सेनगुप्ता, सचिव, प० बंगाल सरकार, श्रम विभाग।

संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि :

24. श्री के० डी० गुप्ता, श्रमायुक्त तथा पदेन सचिव, (श्रम) दिल्ली प्रशासन।

नियोजकों के प्रतिनिधि :

25. श्री डी० पी० मुखर्जी
26. श्री आर० एन० जोशी
27. श्री मदन मोहन मंगलदास
28. श्री पी० चेन्तसल राव
29. श्री वी० बी० कामथ

कर्मचारियों के प्रतिनिधि :

30. श्री टी० एन० सिद्धान्ता
31. मिस ई० वसूजा
32. श्री विष्णु बैनर्जी
33. श्री के० रंगास्वामी
34. श्री राम देसाई।

चिकित्सा व्यवसाय के प्रतिनिधि :

35. डा० जे० मजूमदार
36. श्री कविराज केशव प्रसाद आत्रेय

संसद् के प्रतिनिधि :

37. श्री डा० बाई० पवार
38. श्री एस० एम० बैनर्जी
39. श्री राजा कुलकर्णी

पदेन सदस्य :

40. श्री टी० एन० लक्ष्मीनारायणन, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थाई समिति के सदस्यों की सूची

1975-76

अध्यक्ष: श्री बाल गोबिन्द वर्मा—उप-श्रम मंत्री, भारत सरकार

केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि : सदस्य

2. श्री एन० पी० दुबे, सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय।
3. डा० जे० बी० श्रीवास्तव, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवायें।
4. श्री ए० के० सेन, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग।

राज्य सरकारों के प्रतिनिधि :

5. श्री टी० जे० रामाकृष्णन, सचिव, कर्नाटक सरकार, समाज कल्याण एवं श्रम विभाग, बंगलौर।

6. श्रीमती प्रतिभा डी० पाटिल, मंत्री, जन स्वास्थ्य, महाराष्ट्र सरकार।

7. श्री आर० एन० सेनगुप्ता, सचिव, पं० बंगाल सरकार, श्रम विभाग।

नियोजकों के प्रतिनिधि :

8. श्री आर० एन० जोशी

9. श्री पी० चेन्तसल राव

10. श्री बी० बी० कामथ

कर्मचारियों के प्रतिनिधि :

11. श्री टी० एन सिद्धान्ता

12. श्री विष्णु बसर्जी

13. श्री राम देसाई

चिकित्सा व्यवसाय के प्रतिनिधि :

14. डा० जे० मजूमदार

संसद के प्रतिनिधि :

15. श्री राजा कुलकर्णी

पदेन सदस्य :

16. श्री टी० एन० लक्ष्मीनारायणन, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।

चिकित्सा लाभ परिषद के सदस्यों की सूची 1975-76

अध्यक्ष : डा० जे० बी० श्रीवास्तव, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें

सदस्य

केन्द्रीय सरकार तथा निगम के प्रतिनिधि :

2. डा० शरद कुमार, उप-महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें (चिकित्सा)

3. चिकित्सा आयुक्त · क० रा० बी० निगम

राज्य सरकारों के प्रतिनिधि:

4. डा० टी० एन० संधी, उप निदेशक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें, आन्ध्र प्रदेश सरकार।

5. श्री बी० एल० दास, प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, असम सरकार।

6. डा० एस० के० वर्मा, प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, बिहार सरकार।

7 डा० एच० एन० पटेल, निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, गुजरात सरकार।

8. डा० हकूमत राय, सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें (सामाजिक बीमा), हरियाणा सरकार।

9 डा० कृष्ण स्वरूप, निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, हिमाचल प्रदेश सरकार।

10 डा० बी० वी० पुत्ताराज उर्स, निदेशक, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन सेवायें, कर्नाटक सरकार।

11. डा० टी० एन० एन० भट्टाधिरीपाद, प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी (कर्मचारी राज्य बीमा योजना), केरल सरकार

12. डा० पी० एस० दावे, प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, मध्य प्रदेश सरकार।

13. डा० आर० सी० जिगे, निदेशक, ककर्मचारी राज्य बीमा योजना, महाराष्ट्र सरकार।

14. डा० पी० सी० रथ, प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उड़ीसा सरकार।

15. डा० मोहन सिंह, निदेशक, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, पंजाब सरकार।

16. डा० बी० एम० शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाये (परिवार नियोजन), राजस्थान सरकार।

17. डा० पी० आर० बालकृष्णम, निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें एव परिवार नियोजन, तमिलनाडु सरकार।

18. डा० एम० के० अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, के० रा० बी० योजना, उत्तर प्रदेश सरकार।

19. श्री एस० एम० मुखर्जी, निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा (एम० बी०) योजना, पश्चिमी बंगाल सरकार।

नियोजकों के प्रतिनिधि :

20. डा० सुरेन्द्र प्राण लाल शाह

21. श्री आर० एन० जोशी

22. श्री आर० एल० मोयला

कर्मचारियों के प्रतिनिधि :

23. श्री एस० डब्ल्यू० धवे

24. डा० टी० राजगोपाल

25 डा० जी० कृष्णाविरान

चिकित्सा व्यवसाय के प्रतिनिधि :

26 डा० डी० एस० सूनागेकर

27. डा० नरेन्द्र नाथ भट्टाचारजी

28. वैद्य लीला बती पटेल ।

'कर्मचारी राज्य बीमा निगम' एक नजर में

	31-3-75	31-3-76	1975-76 के दौरान प्रगति
राज्य .	18	18	—
केन्द्र .	365	388	23
कर्मचारी .	43,85,000	51 50,000	7,65,000
बीमाकृत व्यक्ति	47,75.000	56,00.000	8 25,000
परिवार एकक	47,54,150	55,84,050	8,29,900
बीमाकृत महिलायें	3,46,550	4,35,450	88,900
कुल लाभाधिकारी	1,84,66,950	2,16,82,050	32,15,100
कर्मचारी जो अभी योजना के अन्तर्गत लाने हैं .	6,65 000	7,25,000	60 000
नकद भुगतान कार्यालय .	613	653	42
निरीक्षण कार्यालय	121	114	(—) 7
क० रा० बी० हस्पताल .	57	57	—
क० रा० बी० डिस्पेंसियां .	25	24	(—) 1
पलंग			
(क) क० रा० बी० हस्पताल	9.255	10,631	1,376
(ख) क० रा० बी० डिस्पेंसिया	467	465	(—) 2
(ग) रक्षित . .	3,302	3,671*	369
योग .	13,024	14,767*	1,743
रा० बी० औषधालय . .	804	861*	57
बी० चि० अ० तथा बी० चि० अ०	6,348	7,119*	771

	पूंजीगत निर्माण (लाख रुपयों में)		
स्वीकृत राशि	5,486.00	6,974.98	1,488.98
अग्रिम	4,080.01	4,663.14	583.13
आय तथा व्यय	1974-75	1975-76	
राजस्व आय	7,097 20	8,371.37	
राजस्व व्यय	6,249.05	7,558.06	

*अस्थाई

1. **उपलब्धियां**

योजना का विस्तार

1.1 वर्ष में सब से महत्वपूर्ण कदम क० रा० बी० अधिनियम, 1975 द्वारा 30 नवम्बर, 1975 से क० रा० बी० योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिये मजदूरी दर में 500 रु० से 1000 रु० तक वृद्धि करना था जिससे लगभग 8 लाख अतिरिक्त कर्मचारी, उन कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या को मिलाकर जो हाल के कुछ वर्षों में मजदूरी कभी-कभी बढ़ने के कारण इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते थे, इस योजना के अन्तर्गत आ गये। संशोधित अधिनियम, 1975 की अन्य विशेष बातें, जो वर्ष में लागू हुई, निम्नलिखित हैं:—

(क) मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में अंशदान की तालिका तथा तत्सम्बन्धी दैनिक मानक लाभ दरें, योजना के अन्तर्गत आने के लिये 500 रु० से 1000 रु० तक मासिक मजदूरी दर में वृद्धि के कारण, बदल दी गई है। परिवर्तित तालिका में 2 रु० से कम औसत दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी अंशदान की अदायगी से मुक्त कर दिया गया है, इससे पूर्व यह दर 1 रु० 50 पै० थी। 2 रु० से कम, 12 रु० तथा अधिक लेकिन 15 रु० से कम 16 रु० तथा अधिक औसत मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए दैनिक मानक लाभ दर भी बढ़ा दी गई है।

(ख) अधिनियम के अधीन देय अंशदानों की अदायगी न करने के लिये और अधिक सख्त दण्ड देने तथा देय अंशदानों की अदायगी न करने पर आवश्यक दण्ड के रूप में कैद की व्यवस्था की गई है। कुछ मामलों में पहला अपराध सिद्ध होने के बाद उसी अपराध के लिये बढ़ी हुई सजा की भी व्यवस्था है। किसी भी अंशदान के लिये देय राशि या अधिनियम के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार की राशि न देने के कारण हुई हानि की वसूली निगम भू-राजस्व के बकाया के तौर पर चूककर्ता नियोजक से वसूल कर सकता है तथा अदालतों को अधिकार दिये गये हैं कि चूककर्ता नियोजक से किसी निश्चित अवधि के अन्दर अंशदानों की राशि को दिलवाये।

(ग) किसी भी कारखाने या संस्थापना के पूर्ण या उसका कोई भाग बेच, उपहार पट्टा या लाइसेंस या अन्य किसी माध्यम से स्थानान्तरण के मामले में यह व्यवस्था की गई है कि स्थानान्तरण कर्ता या उस व्यक्ति को जिसको कारखाना या संस्थापना का स्थानान्तरण किया गया है मिलकर या अलग-अलग, स्थानान्तरण की तिथि तक की अवधियों के लिये अंशदानों की देय राशि या अधिनियम के अन्तर्गत देय अन्य राशि देनी होगी।

(घ) केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति बिना निगम द्वारा पदों के सृजन के लिये अधिकतम मासिक आय दर 500 रु० से बढ़ा कर 1200 रु० कर दी गई है। जहां मजदूरी सीमा की वृद्धि, अंशदानों की परिवर्तित तालिका तथा मानक लाभ दर सम्बन्धी व्यवस्थायें 30-11-75 से लागू हैं वहां दूसरी सारी व्यवस्थायें भी 1-9-75 से लागू हो चुकी है।

संस्थापनाओं के नये वर्गों पर विस्तार :

1.2 (क) समीक्षाधीन वर्ष में केरल, प० बंगाल, असाम, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक तथा संघ राज्य पांडीचेरी के विभिन्न केन्द्रों में संस्थापनाओं के नये वर्गों तथा विभिन्न तिथियों से दिल्ली में संस्थापनाओं के कुछ अतिरिक्त वर्गों जिनके अन्तर्गत लगभग 67,400 कर्मचारी आते हैं, पर योजना का विस्तार दिया गया। इसका ब्यौरा परिशिष्ट-1 भाग 'क' में दिया गया है।

(ख) इन कर्मचारियों के परिवार भी 13 सप्ताहों की समाप्ति पर चिकित्सा देख-रेख के अधिकारी हो जाते हैं।

1.3 पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, प० बंगाल, तथा संघ राज्य गोआ, दमन द्वीव की राज्य सरकारों ने संस्थापनाओं के नये वर्गों पर योजना का विस्तार करने के अभिप्राय से छः मास का नोटिस देते हुए प्रारम्भिक अधिसूचना जारी की। केन्द्रीय सरकार ने भी अधिनियम के उपबन्धों का भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा अशोक होटलों तथा दिल्ली परिवहन निगम पर विस्तार करने के अभिप्राय से अधिसूचित किया है तथा छः मास के नोटिस अवधि के समाप्त होने पर इन संस्थापनाओं पर योजना का विस्तार करने की संभावना थी।

नये क्षेत्रों में कार्यान्वयन :

1.4 असम, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, प० बंगाल तथा संघ राज्य गोआ दमन दीव राज्यों में योजना का विस्तार 44 नये क्षेत्रों में 39,700 कर्मचारियों (उप-केन्द्रों के उन कर्मचारियों को छोड़कर जिनको परिशिष्ट-1 में दिखाये गये मुख्य केन्द्र में शामिल कर लिया गया है) पर किया गया । इसका ब्यौरा परिशिष्ट-1 भाग-क में दिया गया है। जम्मू व कश्मीर हिमाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, ... राज्यों में योजना के शीघ्र विस्तार के प्रयत्न जारी हैं जहां कि योजना का कार्यान्वयन अभी तक किसी भी केन्द्र में नहीं हुआ है।

1.5 वर्ष के अन्त तक योजना विभिन्न राज्यों व चण्डीगढ़, दिल्ली तथा पाण्डीचेरी, गोआ दमन दीव संघ राज्यों में 388 केन्द्रों के लगभग कुल 5,50,000 कर्मचारियों पर (स्थापनाओं के नये वर्गों के कर्मचारियों को छोड़कर) लागू थी।

परिवारों पर चिकित्सा देख-रेख का विस्तार :

1.6 असम, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, प० बंगाल, तथा संघ राज्य गोआ, दमन और द्वीप राज्यों के 52 क्षेत्रों में चिकित्सा देख-रेख का विस्तार 41650 अतिरिक्त परिवार (बी० व्य०) एकको अर्थात् लगभग 1,19,950 अतिरिक्त लाभाधिकारियों उप-केन्द्रों में उन परिवारों (बी० व्य०) को छोड़कर जिनको परिशिष्ट-1 में दिखाये गये मुख्य केन्द्र में शामिल किया गया है पर किया गया । इसका ब्यौरा परिशिष्ट-1 भाग-क में दिया गया है। वर्ष के अन्त तक कुल परिवार एककों की संख्या, जिन पर योजना का विस्तार हुआ है लगभग 55,84,050 (अर्थात् बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों सहित 2,16,82,050 लाभाधिकारी, जो मजदूरी सीमा में वृद्धि तथा संस्थापनाओं के नये वर्गों पर योजना के विस्तार के कारण आते हैं) थी।

2. **अस्पताल में भर्ती करना**

(i) पहले से ही चालू कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल तथा अनेक्सिया 50 पलंग वाला कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, कसबहल (उड़ीसा), 21-1-76 को चालू किया गया था। एक अन्य 80 पलंग वाला क० रा० बी० अस्पताल, गान्धी नगर, कोटायम (केरल) 14-7-75 को केरल सरकार को बेच दिया, क्योंकि निगम को इस अस्पताल की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार चालू अस्पतालों की संख्या 57 रह जाती है। इसके अतिरिक्त 31-3-76 तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत 24

क० रा० बी० अनैक्सियां काम कर रही थी, क्योंकि बाद में यह पता चला कि राजगंगापुर में 16 पलंगों वाला क० रा० बी० वार्ड चालू नहीं हुआ।

इन संस्थापनों में पलंगों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

परियोनाजओं की प्रकार	परियोजनाओं की संख्या	निर्मित पलंगों की संख्या	
		सामान्य	क्षय
अस्पताल . . .	57	9236	1395
अनैक्सियां . .	24	123	282
	योग .	9419	1677
		=	11096

इन अस्पतालों तथा अनैक्सियों का ब्यौरा परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

(ii) निर्माणाधीन क० रा० बी० हस्पताल व अनैक्सियां

निम्नलिखित हस्पताल तथा अनैक्सियां निर्माणाधीन थी :—

क्रम सं०	स्थान तथा राज्य	पलंगों की संख्या		विवरण
		सामान्य	क्षय	
	अस्पताल			
1.	ग्वालियर (म० प्र०) .	75	—	
2.	अंधेरी (महाराष्ट्र) .	600	—	
3.	थाणी (महाराष्ट्र) .	600	—	
4.	उल्हास नगर (महाराष्ट्र)	100	—	
5.	कण्डीवेली (महाराष्ट्र) .	624	—	
6.	मानिकटोला (प० बंगाल)	400	—	
7.	कल्यापुर आसंसोल (")	—	150	
8.	ठाकुरपुर (") .	—	250	
9.	मंगलौर (कर्नाटक)	100	—	
10.	दक्षिणी मद्रास (तमिलनाडु)	500	—	
11.	पाण्डीचेरी . .	50	—	
12.	नैनी (इलाहाबाद) (उ०प्रदेश) . .	100	—	
	अनैक्सियां :			
(i)	कावेरी नगर (तमिलनाडु) . .	10	—	
(ii)	हिसार (हरियाणा) .	12	—	
(iii)	सोनीपत (हरियाणा) .	12	—	
(iv)	गुलबर्ग (कर्नाटक) .	20	—	
(v)	के० जी० एफ राबर्टस सोनपेट्ट (कर्नाटक) .	32	—	
(vi)	राजगंगापुर (उड़ीसा)	18	—	

(iii) स्वीकृत क० रा० बी० अस्पताल व अनैक्सियां

निम्नलिखित अस्पताल व अनैक्सियां स्वीकृत हो गई हैं :—

क्रम सं०	स्थान व राज्य	पलंगों की संख्या	
		सामान्य	क्षय
	अस्पताल		
(1)	थाना (महाराष्ट्र) . .	300	—
(2)	बदेल (प० बंगाल) . .	—	250
(3)	गाजियाबाद (उ० प्र०) . .	100	—
(4)	लखनऊ (") . .	100	—
(5)	आगरा (") . .	100	—
(6)	मैसूर सिटी (कर्नाटक) . .	100	—
(7)	जैकेपुर (उड़ीसा) . .	25	—
(8)	बड़ौदा (गुजरात) . .	200	—
(9)	सूरत	150	—
	अनैक्सियां		
(1)	भिवानी (हरियाणा) . .	20	—
	कुल	1095+	250=
			1345

(iv) देश में वर्ष के अन्त तक 771 राज्य बीमा औषधालय चालू कर दिये गये थे। इसके अतिरिक्त ..... तक 18 और औषधालय निर्माण के भिन्न-भिन्न स्तरों पर निर्माणाधीन है।

(v) योजना के अन्तर्गत 31-3-76 को पूंजीगत निर्माण के लिये स्वीकृत राशि निम्न प्रकार है :—

परियोजना का वर्ग	31-3-75 को स्वीकृत राशि	31-3-76 को स्वीकृत राशि
	(लाख रुपयों में)	
(क) अस्पताल/अनैक्सियां/औषधालय/उपकरण तथा स्टाफ क्वार्टर आदि . .	4603.50	6020.43
(ख) महाराष्ट्र राज्य को ऋण . .	334.00	357.58
(ग) सहायक अनुदान . . .	100.00	100.00
(घ) निगम के कार्यालय एवं स्टाफ क्वार्टर .	448.50	496.97
	5486.00	6974.98

3. बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों को चिकित्सा देख-रेख की प्रकार :

परिवार (बी० व्य०) एककों को दी जाने वाली चिकित्सा देख-रेख की प्रकार की राज्य वार स्थिति परिशिष्ट 3 मे दी गई है।

आयोग, समितियां और सम्मेलन

4. निगम :

25 अप्रैल 1975, 20 जुलाई, 1975 तथा 28 फरवरी, 1976 को० क० रा० बी० निगम की तीन बैठकें हुई। इन बैठकों में लिये गये

महत्वपूर्ण निर्णय परिशिष्ट–4 में दिये गये है।

5. स्थायी समिति :

क० रा० बी निगम की स्थायी समिति की चार बैठकें 2 जून, 1975, 16 सितम्बर, 1975, 20 दिसम्बर, 1975 तथा 27 फरवरी, 1976 को हुई। इन बैठको में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय परिशिष्ट–5 में दिये गये है।

6. चिकित्सा हितलाभ परिषद:

चिकित्सा हितलाभ परिषद की दो बैठकें 22-12-75 व 24-2-76 को हुई। परिषद् की महत्वपूर्ण सिफारिशे परिशिष्ट-6 में दी गई है।

7. क्षेत्रीय बोर्ड :

वर्ष के अंत सभी राज्यों में क्षेत्रीय बोर्डों का गठन हो चुका था। विभिन्न क्षेत्रीय बोर्डों की वर्ष के दौरान हुई बैठकों की संख्या नीचे दी गई है :—

क्षेत्रीय बोर्ड का नाम	बैठकों की संख्या और तारीख
आन्ध्र प्रदेश	— —
असम	2 11-4-75 व 9-8-75
बिहार	3 4-6-75, 2-12-75 व 9-3-76
दिल्ली	3 15-7-75, 13-8-75 व 8-1-76
गुजरात	2 6-8-75, व 16-12-75
हरियाणा	2 19-8-75 व 23-10-75
कर्नाटक	3 2-4-75, 18-8-75 व 7-12-75
केरल	3 14-7-75, 26-8-75 व 13-2-76
मध्य प्रदेश	3 13-8-75, 21-9-75 व 9-3-76
पंजाब	2 25-8-75, व 9-3-76
महाराष्ट्र	3 2-7-75 व 7-8-75 व 22-11-75
पाण्डीचेरी	4 17-4-75, 25-8-75, 23-12-75 व 12-3-76
उड़ीसा	3 25-4-75, 10-8 75 व 26-11-75
राजस्थान	4 10-7-75, 18-8-75, 5-9-75 व 1-12-75
तमिलनाडु	3 1-4-75, 22-8-75 व 20-12-75
उत्तर प्रदेश	3 2-5-75, 23-7-75, व 2-9-75
प० बंगाल	3 29-4-75, 12-8-75 व 17-12-75

8. स्थानीय समितियां :

क० रा० बी० (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-क के अधीन, वर्ष के अन्त तक समस्त देश में 194 स्थानीय समितियां स्थापित हो चुकी थी।

9. समीक्षाधीन वर्ष में चिकित्सा सेवायें तथा आबंटन समितियो द्वारा किये गये कार्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	राज्य का नाम	बैठकों की संख्या	सूची पर लाये गए केसों की संख्या	शेष केसो की संख्या
1	2	3	4	5
1.	गुजरात	2	18	—
2.	बृहत्तर बम्बई	5	16	—
3.	पश्चिमी महाराष्ट्र	6	29	—
4.	पंजाब	4	6	—
5.	पश्चिमी बंगाल	0	0	—

10. सामान्य प्रयोजन उप-समिति :

समीक्षाधीन वर्ष में क०रा०बी०नि० की सामान्य प्रयोजन उप-समिति ने 8 मार्च, 1976 से 12 मार्च, 1976 तक आन्ध्र प्रदेश का दौरा किया तथा राज्य मे कार्य कर रहे विभिन्न क०रा०बी० संस्थाओं का निरीक्षण किया।

प्रशासन

11. क्षेत्रीय संगठन :

31 मार्च, 1976 को सभी राज्यो और संघ शासित क्षेत्रों में 15 क्षेत्रीय कार्यालय, 2 उप क्षेत्रीय कार्यालय, 287 स्थानीय कार्यालय, 94 लघु स्थानीय कार्यालय, 3 उप स्थानीय कार्यालय, 267 भुगतान कार्यालय और 114 निरीक्षण कार्यालय कार्य कर रहे थे।

12. कर्मचारियों की संख्या :

निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल प्राधिकृत संख्या (निदेशालय चिकित्सा दिल्ली के कार्यालय/क०रा०बी० अस्पताल दिल्ली को छोड़कर)31 मार्च, 1975 को 7752 की तुलना में 31 मार्च, 1976 को 7920 थी। 31 मार्च 1976 को मुख्यालय तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राधिकृत कर्मचारी वर्ग को परिशिष्ट–7(भाग-1) में दिखाया गया है। निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली के कार्यालय तथा क०रा०बी० अस्पताल दिल्ली के लिए प्राधिकृत कर्मचारी वर्ग को परिशिष्ट-7 के भाग-2 में दिखाया गया है।

13. कर्मचारियों का स्थायीकरण :

वर्ष 1974-75 के लिए श्रेणी-1 और श्रेणी-2 के स्थायी पदों के सृजन का केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो गया है और इन पदों के स्थायीकरण का कार्य पहले से ही हो रहा है। श्रेणी-3 और श्रेणी-4 के लिए स्वीकृत पदों के स्थान पर लगभग अधिकतर क्षेत्रो/कार्यालयों में स्थायीकरण कर दिया गया है। शेष कार्यालयो में कर्मचारियों के स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

14. संगठन एवं पद्धति अध्ययन :

वर्ष में संगठन एवं पद्धति विभाग ने विभिन्न क्रियात्मक क्षेत्रों मे अपना परियोजना सम्बन्धी (प्रोजेक्ट) अध्ययन का क्रम जारी रखा। इसके अतिरिक्त इस वर्ष यह आवश्यक निर्णय लिया गया कि निगम के कार्य-अध्ययन कार्यक्रम में आल इण्डिया ई०एस०आई०सी०एम्पलाइज फैडरेशन को भी सम्मिलित किया जाए। तदनुरूप सं० एवं प० विभाग ने देश में स्थानीय कार्यालयों के विभिन्न कार्यों के लिए नियमों एवं सिद्धान्तो को बनाने के लिए कुछ चुने हुए स्थानीय कार्यालयो का कार्यमापन-अध्ययन, मुख्यालय में कार्य विश्लेषण, निगम के क्षेत्रीय कार्यालयो में नि०श्रे०लि० एवं उ०श्रे०लि० का कार्य विश्लेषण तथा नि०श्रे०लि० एवं० उ०श्रे०लि० में अनुपात का पुनः निर्धारण आदि कार्य किए। ये अध्ययन फैडरेशन के प्रतिनिधि की देख रेख में किए गए।

वर्ष मे संगठन एवं पद्धति विभाग ने क्षेत्रीय कार्यालयों की राजस्व वसूली शाखाओं का कार्याध्ययन किया तथा कारखानों/संस्थापनाओं को योजना के अन्तर्गत लाने तथा उससे सम्बन्धित दूसरे मामलों की कार्यविधियो को नियमित किया गया। अंशदानों की वसूली 'अंशदान टिकटों' के स्थान पर नकद प्रक्रिया निकाली गई और यह प्रणाली प्रयोगात्मक आधार पर दिल्ली में प्रारम्भ की गई।

वर्ष में संगठन एवं पद्धति विभाग द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर।

(1) वार्षिक रिपोर्ट एवं सांख्यिकी सार को पुन. नए रूप में तैयार करना।

(2) क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्ट के प्रपत्र में परिवर्तन करना।

(3) पुराने घोषणा पत्रों की छटाई।

(4) बीमा निरीक्षक द्वारा की गई निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा के लिए सिद्धान्तत्व।

(5) क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रयुक्त विभिन्न प्रपत्रों का सरलीकरण करना/समाप्त करना आदि के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिए गये।

15. सुझाव पुरस्कार योजना :

सुझाव पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पुरस्कार प्रदान करने हेतु सुझावों की समीक्षा करने के लिए जो केन्द्रीय समिति बनाई गई है, उसने क्षेत्रीय कार्यालय, तमिलनाडु के प्रधान लिपिक श्री पी० एस० कृष्णामचारी को उनके द्वारा दिए गए हितलाभ फार्मों को इस्तेमाल करने के सुझाव (जोकि खाता प्रणाली के चालू करने के कारण बच गए थे) पर 125 रु० का पुरस्कार प्रदान किया गया जिसके परिणाम स्वरूप मितव्ययता हुई।

16. अधिकारी तथा कर्मचारी-वर्ग का प्रशिक्षण :

समीक्षाधीन वर्ष में, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान ने मुख्यालय में काम करना आरम्भ किया तथा चार मण्डलीय प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई जिनके मुख्यालय दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, और बंगलौर रखे गए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से विभिन्न केन्द्रों में चलाए जा रहे हैं। स्थानीय कार्यालय प्रबन्धकों तथा बीमा निरीक्षकों के लिए चार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा त्रिचूर में चलाए गए जिसमें 91 सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया।

निगम के मध्य-प्रबन्ध स्तर के अधिकारियों जैसे उप-क्षेत्रीय निदेशक/लेखा-अधिकारी सहायक क्षेत्रीय निदेशक के लिए नवम्बर, 1975 में नई दिल्ली में अनुस्थापन (ओरियेंटेशन) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने पाठ्यक्रम के कार्यकाल में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की कार्यविधि तथा उससे सम्बन्धित समस्याओं पर वाद-विवाद के अतिरिक्त कुछ आधुनिक प्रबन्ध कार्यविधियों पर भाषण सुने।

निम्न श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक/प्रधानलिपिकों के स्तर के सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न केन्द्रों में 24 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 569 कर्मचारियों ने भाग लिया।

मार्च 1976 में मुख्यालय में सतर्कता उपायों पर एक पाठ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यालय से, निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से लिए गए विभिन्न श्रेणियों के 29 सरकारी कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण दिया गया ताकि निगम के सभी कार्यालयों में सतर्कता की बढ़ी हुई मांग को पूरा किया जा सके। इस पाठ्यक्रम के लिए कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग आदि तथा प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध सचिवालय संस्थान के दो भूतपूर्व निदेशकों द्वारा सतर्कता क्षेत्र में विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की गईं।

17. प्रचार आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से विभिन्न भाषाओं में कई वार्ताओं और परिचर्चाओं का प्रसारण किया गया। निगम के अधिकारियों ने विभिन्न केन्द्रों में कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षार्थियों के समक्ष भाषण भी दिये।

उपरोक्त के अतिरिक्त अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के बहुत से महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की प्रगति के संबंध में समाचार भी प्रकाशित हुए।

योजना का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ पहले की तरह निकट सम्पर्क बनाये रखा गया। जिन कर्मचारियों/बीमाकृत व्यक्तियों तथा मजदूर संघों के प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय कार्यालयों/स्थानीय कार्यालयों से सम्पर्क किया, उनकी शंकाओं का समाधान किया गया और उनका उचित मार्गदर्शन किया गया।

विस्तार क्षेत्र :

18. योजना के अन्तर्गत आये कर्मचारी आदि (परिशिष्ट 8 तथा 9):

परिशिष्ट 8 और 9 में योजना के विस्तार क्षेत्र संबंधी ब्यौरे (रोजगार के अतिरिक्त क्षेत्रों को मिलाकर) दिये गये है। 31-3-1976 को योजना के अन्तर्गत आए नियोजकों की संख्या लगभग 34,384 थी जबकि एक वर्ष पूर्व यह संख्या 27,444 थी। इनमें से लगभग 32404 नियोजक कार्यान्वित क्षेत्रों में थी। पिछले वर्ष यह संख्या 25,654 थी तथा शेष 1,980 नियोजक उन क्षेत्रों में थे जहां कि अभी कार्यान्वयन किया जाना है। कार्यान्वित केन्द्रों के कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 51.50 लाख थी और उन क्षेत्रों के कर्मचारियों की संख्या लगभग 7.25 लाख थी जिनमें कि अभी कार्यान्वयन किया जाना है। डाक्टरी इलाज पाने के हकदार बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या लगभग 56.00 लाख और परिवार (बी० व्य०) एककों की संख्या लगभग 55.84 लाख थी। कुल मिलाकर डाक्टर इलाज पाने के हकदार हिताधिकारियों (बीमाकृत व्यक्तियों सहित) की कुल संख्या 31-3-1976 को लगभग 216.82 लाख थी।

19. चिकित्सा सुविधा के स्तर मे सुधार :

19.1 अंतरंग रोगियों के इलाज के लिये हस्पतालों में पलंगों की व्यवस्था

वर्ष 1975-76 के दौरान निम्नलिखित क० रा० बी० अस्पतालों मे 548 नये पलंगों की व्यवस्था की गई :—

(1) क० रा० बी० अस्पताल, सनत नगर (आ० प्र०)	100
(2) क० रा० बी० अस्पताल, विजयवाड़ा (आ० प्र०)	20
(3) क० रा० बी० अस्पताल, दिल्ली . .	40
(4) क० रा० बी० अस्पताल, फरीदाबाद (हरियाणा) .	102
(5) क० रा० बी० अस्पताल, राजाजी नगर (कर्नाटक) .	50
(6) क० रा० बी० अस्पताल, (सामान्य) नन्दानगर (इन्दौर)	51
(7) क० रा० बी० अस्पताल (चैस्ट), इन्दौर . .	35
(8) क० रा० बी० अस्पताल, बारली (महाराष्ट्र) .	100
(9) क० रा० बी० अस्पताल, कन्सबहल (उड़ीसा) .	50

मथन (बिहार), एजूकोन (केरल) व उज्जैन (क० प्र०) में क० रा० बी० अस्पतालों में पलंगों की संख्या क्रमशः 110, 150 व 65 से घटकर 100, 25 एवं 40 रह गई।

31-3-1976 को क० रा० बी० योजना के अन्तर्गत पलंगों की कुल संख्या 14,303 थी जिनके ब्यौरे परिशिष्ट-10 में दिये गये है।

19.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कर्मचारी राज्यबीमा अस्पतालों में भरे हुए पलंगों की प्रतिशतता और प्रतिदिन प्रति पलंग आवर्ती लागत इस प्रकार थी :—

अस्पताल का नाम	दिये गये पलंगों की संख्या				वर्ष 1975-76 में भरे पलंगों की प्रतिशतता	वर्ष 1975-76 में प्रतिदिन प्रति पलंग लागत
	सामान्य	प्रसूति	क्षय	योग		
1	2	3	4	5	6	7
						(रु० पै०)
आन्ध्र प्रदेश :						
1. क० रा० बी० अस्पताल, सनातनगर, हैदराबाद	235	45	30	310	61%	40.97
2. क० रा० बी० अस्पताल, सीरपुर कागज नगर	60	—	—	60	93%	26.17
3. क० रा० बी० अस्पताल, विजयवाड़ा	86	—	10	96	95%	25.83
4. क० रा० बी० अस्पताल, वारंगल	20	10	—	30	160%	20.51
5. क० रा० बी० अस्पताल, अदोनी	25	—	—	25	180%	17.70
6. क० रा० बी० अस्पताल, विशाखापत्तनम	39	2	9	50	94%	21.94
बिहार :						
7 क० रा० बी० अस्पताल, मैथुन	100	—	—	100	63%	27.35
8. क० रा० बी० अस्पताल, मुंगेर	30	—	—	30	47%	16.32
9. क० रा० बी० अस्पताल, डालमियानगर	50	—	—	50	68%	21 75
दिल्ली :						
10. क० रा० बी० अस्पताल, बसईदारापुर, नई दिल्ली	286	54	—	340	96%	28 92
गुजरात :						
11 क० रा० बी० अस्पताल, बापूनगर अहमदाबाद	500	—	—	500	67%	36.47
12. क० रा० बी० अस्पताल, नरोदा, अहमदाबाद	—	—	200	200	75%	18.82
हरियाणा :						
13. क० रा०बी० अस्पताल, फरीदाबाद	170	—	12	182	52%	17.80
14. क० रा० बी० अस्पताल, जगाधरी	60	—	—	60	47%	31.20
15. क० रा० बी० अस्पताल, पानीपत	15	—	35	50	52%	34.85
कर्नाटक :						
16. क० रा० बी० अस्पताल, राजाजीनगर, बंगलौर	335	35	44	414	90%	26.40
17. क० रा० बी० अस्पताल, डाण्डेली	24	—	—	24	112%	11.45
केरल :						
18. क० रा० बी० अस्पताल, मलाकुन्नाथुकुवा (जिला त्रिचूर)	—	—	100	100	82%	20.40
19 क० रा० बी० अस्पताल, असरामन (जिला क्विलोन)	80	20	—	100	120%	21.65
20. क० रा० बी० अस्पताल, अलप्पी	51	4	—	53	99%	22.93
21. क० रा० बी० अस्पताल, फलरकाड़ा, (जिला त्रिवेन्द्रम)	50	—	—	50	158%	20.77
22. क० रा० बी० अस्पताल, त्रिचूर	55	5	—	60	127%	18.35
23. क० रा० बी० अस्पताल, उद्योग मण्डल (एर्नाकुलम)	112	8	—	120	86%	21.51
24. क० रा० बी० अस्पताल, एर्नाकुलम,	40	10	—	50	64%	26.03
25 क० रा० बी० अस्पताल, पडाक्थूर (जि० कोट्टायम)	50	—	—	50	15.56%	15.56
26 क० रा० बी० अस्पताल, पारीपल्ली	100	—	—	100	102%	16.77
27. क० रा० बी० अस्पताल, एजुकोन	25	—	—	25	143%	14.60

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश :						
28. क० रा० बी० अस्पताल, (सामान्य) इंदौर	150	—	—	150	99%	25.30
29. क० रा० बी० अस्पताल, (चेस्ट) इंदौर	—	—	75	75	132%	11.10
30. क० रा० बी० अस्पताल, उज्जैन	40	—	—	40	160%	16.00
महाराष्ट्र :						
31. एम० जी० एम० अस्पताल, बम्बई	671	14	15	700	99%	34.13
32. क० रा० बी० अस्पताल, मुलुंद, बम्बई	60	—	300	360	76%	37.05
33. क० रा० बी० अस्पताल, वोली बम्बई	325	25	—	350	62%	46.38
34 क० रा० बी० अस्पताल, नागपुर	130	20	—	150	101%	24.65
35. क० रा० बी० अस्पताल, औंध, पूना	200	—	120	320	51%	30.41
उड़ीसा :						
36. क० रा० बी० अस्पताल, वृजराज नगर	25	—	—	25	अप्राप्य	52.50
37. क० रा० बी० अस्पताल, चौद्वार	44	6	12	50	अप्राप्य	27.00
38. क० रा० बी० अस्पताल, कंसबहल	50	—	—	50	अप्राप्य	48.84
पंजाब :						
39. क० रा० बी० अस्पताल, अमृतसर	100	25	—	125	50%	44.12
40. क० रा० बी० अस्पताल, लुधियाना	56	24	—	80	63%	46.34
41 क० रा० बी० अस्पताल, जालंधर	48	12	—	60	50%	42.15
राजस्थान :						
42. क० रा० बी० अस्पताल, जयपुर	87	26	—	113	80%	36.54
तमिलनाड :						
43. क० रा० बी० अस्पताल, मद्रास	486	100	39	625	90%	29.68
44. क० रा० बी० अस्पताल, कोयम्बतुर	250	25	25	300	118%	29.43
45. क० रा० बी० अस्पताल, मदुरई	140	50	12	202	103%	18.19
उत्तर प्रदेश :						
46. क० रा० बी० अस्पताल, पाण्डुनगर कानपुर	212	—	—	212	97%	20.67
47. क० रा० बी० अस्पताल, आजादनगर कानपुर (चेस्ट अस्पताल)	—	—	180	180	99%	24.81
48 क० रा० बी० अस्पताल, (प्रसूति तथा सामान्य) कानपुर	74	70	—	144	100%	24.08
49. क० रा० बी० अस्पताल, मोतीनगर	70	24	6	100	98%	25.72
पं० बंगाल :						
50. क० रा० बी० अस्पताल, सियालदाह	250	—	—	250	82%	26.82
51. क० रा० बी० अस्पताल, कमरहाटी	171	4	—	175	86%	25.22
52. क० रा० बी० अस्पताल, बालटीकुरी	400	16	—	416	56%	22.18
53. क० रा० बी० अस्पताल, सेरामपुर	150	16	—	166	97%	21.17
54. क० रा० बी० अस्पताल, कल्याणी	266	—	—	266	72%	24.90
55. क० रा० बी० अस्पताल, उलुबेरिया	166	—	—	166	91%	22.89
56. क० रा० बी० अस्पताल, बंगूरअल्ली	—	—	150	150	91%	23.99
57. क० रा० बी० अस्पताल, गोरहाटी	147	19	—	166	74%	23.50
58. क० रा० बी० अस्पताल, बजबज	150*	—	—	150	57%	17.98

*300 स्वीकृत पलंगों में से 150 पलंग चालू हो गये हैं।

20. 31-3-1976 को औषधालयों, विशेषज्ञों, बीमा चिकित्सा अधिकारियों/बीमा चिकित्सा व्यवसायियों तथा एम्बुलैंसों के ब्यौरे परिशिष्ट-10 में दिखाए गए हैं।

21 कृत्रिम दांतों की व्यवस्था :

समीक्षाधीन वर्ष के ऐसे 7 बीमाकृत व्यक्तियों को निःशुल्क कृत्रिम दांत दिए गए जिनके दांत रोजगार चोट के कारण टूट चुके थे। योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 56 बीमाकृत व्यक्तियों को कृत्रिम दांत दिये जा चुके हैं।

22. बीमाकृत व्यक्तियों के कृत्रिम अंग लगाने की व्यवस्था :

समीक्षाधीन वर्ष में 69 केसों में कृत्रिम अंग लगाये गये। योजना के अंतर्गत अब तक कुल 796 बीमाकृत व्यक्तियों के कृत्रिम अंग लगाये गए या लगाये जा रहे हैं या पुनः लगाये गये है।

23. चश्मों की व्यवस्था :

समीक्षाधीन वर्ष में ऐसे 4 बीमा कृत व्यक्तियों को निःशुल्क चश्मे दिए गए जिनकी नेत्र दृष्टि रोजगार चोट के कारण कमजोर हो गई थी।

चिकित्सा हितलाभ की व्यवस्था

24. डिस्पैंसरियों और अस्पतालों में उपस्थिति और घर जाकर इलाज करना (परिशिष्ट 11 व 12) :

24.1 (क) प्रतिवर्ष प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्ति और प्रति 1000 परिवार (बी०व्य०) एकक उपस्थिति, (ख) बीमाकृत व्यक्तियों और परिवारों के घर जाकर इलाज करने और (ग)(1) अस्पतालों में दाखिल किये गये और (2) विशेषज्ञ के पास जांच के लिये भेजे गये बीमाकृत व्यक्तियों के केसों की संख्या संबंधी आंकड़े इन परिशिष्टों में दिए गए हैं। ये आंकड़े प्रारम्भ में डिस्पेंसरियो और पैनल डाक्टरों द्वारा भेजे गये विवरणों पर आधारित हैं। चिकित्सा के लिए उपस्थितियों की दर का हिसाब लगाने के लिए केवल रिपोर्ट भेजने वाली डिस्पेंसरियों/निदानशालाओं से सम्बद्ध बीमाकृत व्यक्ति परिवार (बी०व्य०) मान लिये गये हैं।

24.2 समीक्षाधीन वर्ष में प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्ति नई उपस्थिति की अखिल भारत दर 1974-75 की तुलना में 3367 से घटकर 3078 रह गई हैं। प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्ति पुरानी उपस्थिति दर भी 1974-75 की तुलना में 6404 से घटकर इस वर्ष 6008 रह गई है। इस वर्ष पुरानी और नई उपस्थितियों का अनुपात 1.95 था जबकि 1974-75 में वह 1.90 था।

24.3 प्रति 1000 परिवार एकक नई उपस्थिति की अखिल भारतीय दर की तुलना में 3226 से बढ़कर 3309 हो गई है। प्रति 1000 परिवार एकक पुरानी उपस्थिति दर भी 1974-75 की तुलना में 6574 से घटकर 6431 रह गई है। नई उपस्थिति की तुलना में पुरानी उपस्थिति का अनुपात 1974-75 के 2.01 से घट कर 1975-76 में 1.94 रह गया है।

24.4 बीमाकृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में घर पर जाकर इलाज करने की कुल संख्या 1974-75 की तुलना में लगभग 9% घट गई है। परिवारों के संबंध में घटोत्तरी लगभग 32% है। प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्ति विजिटों की संख्या के हिसाब से घर की विजिटों की घटनाओं में 1974-75 की तुलना में 1975-76 में 73 से घटकर 60 रह गई है।

24.5 अस्पतालों में दाखिल किए गए कुल केसों में वृद्धि 1974-75 की तुलना में 1975-76 में 189912 से बढ़कर 211269 हो गई है। विशेषज्ञों के पास भेजे गये केसों की संख्या 1975-76 की 979257 से बढ़कर 1975-76 में 1075341 हो गई है।

25. बीमारी प्रतिरूप (परिशिष्ट 13) :

25.1 समस्त भारत के लिये बीमारी प्रतिरूपो विषयक सूचना जो कि प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्ति नये केसों की संख्या के रूप में व्यक्त की गई है, बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों के सदस्यों के लिये अलग-अलग प्रत्येक 51 कारण ग्रुपों के लिये इस परिशिष्ट में दिखाई गई है।

25.2 बीमाकृत व्यक्तियों के संबंध में सभी कारण ग्रुपों को मिलाकर घटना दरे 1974-75 की तुलना में 1975-76 में घटी हैं तथा उनके परिवारों के संबंध में बढ़ी है। प्रत्येक बीमाकृत व्यक्ति से संबंधित प्रत्येक अवधि में बीमाकृत व्यक्ति के परिवार से संबंधित 1.075 नई अवधियां रही हैं जबकि 1974-75 में यह 0.958 थी। यदि यह बात ध्यान में रखी जाये कि प्रत्येक बीमाकृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की संख्या 2.88 है तो नये केसों की घटनाओं के आधार पर रुग्णता के मामले बीमाकृत व्यक्तियो की तुलना में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों के संबंध में पहले की तरह कम हो रहे हैं।

25.3 बीमाकृत व्यक्तियों की बीमारी के कारण ग्रुपवार घटनायें लगभग सभी सूचित बीमारियों में बीमाकृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के संबंधित तदनुरूपी दरों से काफी कुछ मिलती है। फिर भी, केवल थोड़े से कारण ग्रुपों की घटनाओं में बहुत अधिक अन्तर से यह पता चलता है कि कुछ ऐसे विशिष्ट रोगों में अधिक इलाज की आवश्यकता होती है जो किसी विशेष समूह (बीमाकृत व्यक्ति या परिवार) की अपेक्षाकृत आसानी से हो जाते हैं।

चिकित्सा हितलाभ संबंधी अन्य मामले

26. चिकित्सा निर्देशी :

वर्ष के अन्त में अलग-अलग राज्यों में ड्यूटी पर तैनात पूर्णकालिक और अंशकालिक चिकित्सा निर्देशियों का उनके द्वारा निपटाये गये केसों की संख्या सहित, विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :—

क्र० सं०	राज्य का नाम	चिकित्सा निर्देशियों की संख्या		वर्ष 1975-76 में निपटाये गये केसों की संख्या
		अंशकालिक	पूर्णकालिक	
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10	—	7,604
2.	आसाम	5	—	695
3.	बिहार	5	—	2,811
4.	चण्डीगढ़ प्रशासन	1	—	18
5.	दिल्ली	—	1	2,165
6.	गोआ	—	—	—
7.	गुजरात	13	2	25,471
8.	हरियाणा	12	—	1,445
9.	कर्नाटक	15	—	12,893
10.	केरल	8	1	6,373
11.	मध्य प्रदेश	13	—	12,369
12.	महाराष्ट्र			
	(अ) बृहत्तर बम्बई	3	3	21,611
	(ब) नागपुर	8	—	4,726

1	2	3	4	5
	(ख) पश्चिमी महाराष्ट्र	2	—	1,999
13.	उड़ीसा . .	5	—	1,851
14.	पंजाब . .	10	—	1,409
15.	राजस्थान .	12	—	2,679
16.	तमिलनाडु . .	2	1	4,889
17.	पाण्डिचेरी . .	1	—	596
18.	उत्तर प्रदेश .	17	—	1,409
19.	प० बंगाल . .	7	5	27,618
	योग . .	149	13	1,40,631

27. चिकित्सा हितलाभों की व्यवस्था पर खर्च-राज सरकारों की प्राधिकृत प्रदायगियां :

समीक्षाधीन वर्ष में क० रा० बी० योजना के अंतर्गत चिकित्सा लाभ की व्यवस्था पर खर्च में निगम के अंशदान के रूप में निगम द्वारा राज्य सरकारों को 30,54,77,703.74 रुपये की प्रदायगियां प्राधिकृत की गई। उक्त राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

	रुपये पैसे
1. 1970-71 के लिये अन्तिम प्रदायगी .	3,72,132.70
2. 1971-72 के लिये अन्तिम प्रदायगी	19,32,392.52
3. 1972-73 के लिये अन्तिम प्रदायगी	57,17,681.07
4. 1973-74 के लिये अन्तिम प्रदायगी	41,84,011.40
5. 1974-75 के लिये अन्तिम प्रदायगी	34,29,486.05
6. 1974-75 के लिये लेखे में प्रदायगी	1,28,25,000.00
7. 1975-76 के लिये लेखे में प्रदायगी	27,70,17,000.00
योग	30,54,77,703.74

प्रति व्यक्ति लागत सहित राज्य सरकारों द्वारा किये गये अनुमानित व्यय के ब्यौरे को परिशिष्ट 15 में दिखाया गया है।

28. चिकित्सा हितलाभों के खर्च पर नियन्त्रण रखने के उपाय :

समीक्षाधीन वर्ष में निगम ने 530 दवाईयों, इन्जेक्शनों तथा औषधियों के लिये भेषज निर्माताओं से दर ठेके किये। राज्य सरकारों को दर ठेकों के विषय में उन्हें अमल में लाने के लिये सूचित कर दिया गया है।

29. क० रा० बी० अधिनियम, 1948 की धारा 58(3) के अन्तर्गत राज्य सरकारों और क० रा० बी. निगम के बीच करार :

क्रम सं०	उन राज्य सरकारों के नाम जिनके साथ करार करने के लिये अभी तक पत्र व्यवहार हो रहा है	की गई या प्रस्तावित अद्यतन कार्यवाही
1.	उत्तर प्रदेश सरकार	करारनामे के अनुबन्धित मसौदा विलेख को निष्पादन के लिये राज्य सरकार को भेजा है।
2.	महाराष्ट्र सरकार	करारनामे का अन्तिम मसौदा विलेख प्राप्त हो चुका है तथा निष्पादन के लिए कार्यवाही की जा रही है।
3.	गुजरात सरकार	करारनामे पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

बीमाकृत व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार

30. स्थानीय कार्यालयों के कार्यों की दक्षता :

समीक्षाधीन वर्ष में देश भर में 287 में से 266 ग्रेड-1 तथा ग्रेड-2 स्थानीय कार्यालयों में खाता प्रणाली कार्य कर रही थी। 44 स्थानीय कार्यालयों में टेलर प्रणाली भी प्रयोग के तौर पर काम कर रही थी।

31. नकद हितलाभ में सुधार :

अपंगता के सभी कठोर मामलों में जहां अनुमानित अपंगता 25% से अधिक होने की संभावना होती है, चिकित्सा मण्डल द्वारा कुछ समय किये जाने वाले मूल्यांकन के अनुमान में से 75% तक की अनन्तिम प्रदायगी तत्कालिक सहायता के लिये नकद रूप में दे दी जाती है। जब चिकित्सा मण्डल के परिनिर्णय का पता चलता है, प्रदायगियों का आवश्यक समायोजन कर दिया जाता है। इस क्रियाविधि का चलन जो प्रतिवर्ष होता था अब प्रतिवर्ष स्थायी रूप से इसका अनुसरण किया जाता है।

32. अन्य सुधार :

32.1 निगम ने 28-2-76 को हुई बैठक में तथा विस्तारित बीमारी हितलाभ की प्रदायगी के बारे में 22-3-69 को हुए पहले संकल्प का अतिक्रमण करते हुए यह निर्णय किया गया कि विस्तारित बीमारी हितलाभ की प्रदायगी के लिए 21 बीमारियों की एक सामान्य सूची तैयार की जाए। आरम्भ में विस्तारित बीमारी हितलाभ 124 दिनों के लिए देय होगा जो अ० उ० जि० आयुक्त/चिकित्सा निर्देशी/राज्य में क० रा० बी० योजना के मुख्य कार्यकर्ता या उसके नामित व्यक्ति द्वारा पुराने उपयुक्त मामलों में 309 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

124 दिनों से अधिक दिनों की प्रदायगी उपरोक्त अधिकारियों द्वारा दी गई पुष्टि के आधार पर होगी।

बीमारियों की सूची :

1. क्षय रोग
2. कोढ़
3. मानसिक रोग (मनोविक्षिप्त)
4. दुर्दम्य रोग
5. अघरांगघात
6. पक्षाघात
7. चिरकाल से संकुलित हृदविफलता
8. कच्चा मोतियाबिन्द जबकि प्रभावित नेत्र की वीक्षण शक्ति 6/60 या कम हो,
9. फुप-फुस फोड़ा
10. फुप-फुसपालीतन
11. मायोकार्डियल इन्फर्शन
12. अन्तराकोकस बिम्ब का विस्थापन औरभ्रंस
13. कम्पावात
14. असाध्य रक्त हीनता
15. जलोदर के साथ यकृत का अभितन्तु रोग
16. दृष्टि पटल का वियोजन
17. अस्थियां भंग होने पर उनका न जुड़ना या देरी से जुड़ना
18. एम्पाइमा
19. कपाल के भीतर चोट का लगना
20. मेरु रज्जु सम्पीडन
21. पुराना (साधारण), प्रारम्भिक ग्लोकोमा रोग।

उपरोक्त रोगों के अतिरिक्त, चिकित्सा आयुक्त 124 या 309 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए वि० बी० हितलाभ की प्रदायगी की स्वीकृति दे सकता है जो किसी विशेष बीमारी या विशेष परिस्थितियों में उपरोक्त अधिकारियों की सिफारिश पर मामले की योग्यता पर निर्भर करेगा।

32.2. विस्तरित बीमारी हितलाभ की दर मानक हितलाभ की दर से जोकि पिछली बार बीमारी हितलाभ के लिए देय था 25% अधिक होगी जिसको कि 5 पैसों की अगली उच्च सहगुणक संख्या में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

32.3. निगम ने दिनांक 20-7-75 की हुई बैठक में बीमाकृत व्यक्तियों को निगम या बीमाकृत व्यक्तियो द्वारा दर्ज किये हुए मामलों में चिकित्सा अपील अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के कारण मजदूरी की हानि हेतु, उन्हीं मानदण्डों एवं शर्तों के आधार पर, जो मानदण्ड एवं शर्तें चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने वाले बीमाकृत व्यक्तियों पर लागू होते हैं, सवारी भत्ता या क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया है। सवारी भत्ते की वर्तमान दर 35 पैसे प्रति कि०मी० है, जहां बीमाकृत व्यक्ति बस द्वारा या सवारी के दूसरे साधारण माध्यम से सफर करने योग्य नही या उसे किसी परिचर की आवश्यकता है, तो उसे वास्तविक किराया देना चाहिये परन्तु यह 65 पैसे प्रति कि०मी० की दर से अधिक न हो। ऐसे ही जब बीमाकृत व्यक्ति को चिकित्सा अधिकरण की बैठक में उपस्थित होने के कारण मजदूरी की हानि हो, उसे प्रत्येक दिन या दिनों के लिए आधे दिन या सारे दिन की मजदूरी की क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। यह क्षतिपूर्ति इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या आधे दिन या सारे दिन की क्षति हुई है तथा क० रा० बी० अधिनियम, 1948 (उच्चतम मजदूरी ग्रुप) के अधीन अस्थायी अपंगता हितलाभ की दैनिक दर की अधिकतम राशि तक सीमित होगी।

नकद लाभ

(परिशिष्ट 15 से 17)

33. नकद लाभ अदायगियों की संख्या (परिशिष्ट 15 का खाना-4) :

33.1. निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किये गये स्थानीय लघु/उप स्थानीय भुगतान कार्यालयों में नकद लाभों का भुगतान किया जाता है। 31 मार्च, 1976 को इस प्रकार के कार्यालयों की संख्या लगभग 653 थी जबकि एक वर्ष पूर्व उनकी संख्या 613 थी।

33.2. वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान प्रत्येक राज्य में की गई नकद लाभों की अदायगियों की संख्या खाना 4 में दिखाई गई है। वर्ष 1975-76 के दौरान कुल मिलाकर लगभग 50.32 लाख अदायगियां (स्थायी अपंगता दावों के रूपांतरण के आवेदनों से संबंधित एक मुश्त अदायगियों के 9510 दावों सहित) की गई हैं। यह पिछले वर्ष की अदायगियों से लगभग 1.26 लाख अधिकारी प्रत्येक मास औसतन लगभग 4.19 लाख अदायगियां की गई जबकि 1974-75 में अदायगियों की प्रतिमास औसत 4.09 लाख थी। 1975-76 में प्रति कर्मचारी अदायगियों की संख्या वही है जो 1974-75 में थी अर्थात 1.15।

34. बीमारी हितलाभ (परिशिष्ट 15 के खाना 3 और 6 से 8) :

34.1. 1 जुलाई 1974 और 30 जून 1975 के बीच नये केन्द्रो में योजना के लाभ उपबन्धो के कार्यान्वित हो जाने के कारण और उन क्षेत्रों में वृद्धि होने के कारण जहां योजना पहले से लागू है, समीक्षाधीन वर्ष में 1,15,300 अतिरिक्त कर्मचारी बीमारी हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हो गये। 1975-76 के दौरान बीमारी हितलाभ दावों के हकदार कर्मचारियों की संख्या अनुमानतः 43.71 लाख हो गई है जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 42.56 लाख थी (खाना 3 देखिये)।

34.2. वर्ष के दौरान बीमारी नकद लाभ के रूप में 1281-80 लाख रुपये की राशि अदा की गई जबकि 1974-75 में यह राशि 1135-37 लाख रुपये थी।

34.3. प्रति कर्मचारी नई अवधियों की औसत संख्या 1974-75 की 0.73 से घटकर 1975-76 में 0.72 हो गई है। प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष लाभ दिनों की औसत संख्या 1974-75 के 5-5 से घटकर 1975-76 में 5-0 हो गई है। प्रति कर्मचारी दैनिक लाभ दर की राशि भी 1974-75 के 4-87 से बढ़कर 1975-76 में 5.83 हो गई।

34.4. पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी बीमारी हितलाभ दावों की घटनाओं और अवधियों में प्रत्येक राज्य में आपस में बहुत घट-बढ़ रही। महानिदेशक विभिन्न केन्द्रों पर बीमारी दावों की अवधियों पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। प्रतिमास मुख्यालय में प्राप्त होने वाले संबंधित आंकड़ों का आवधिक रूप में विश्लेषण किया जाता है कि और किसी केन्द्र की किसी असामान्य घट-बढ़ के बारे में क्षेत्रीय निदेशकों और प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारियों से पत्र व्यवहार किया जाता है ताकि वे जहां कहां आवश्यक और संभव समझें इस घट-बढ़ को दूर करने के लिये उपयुक्त और शीघ्र कार्यवाही करें।

34.5. धारा 58(2) के अन्तर्गत अत्यधिक बीमारी हितलाभ : बीमाकृत व्यक्तियों को बीमारी हितलाभ की अदायगियो का प्रभाव-क्षेत्र कुछ राज्यों में समस्त भारत औसत से अधिक पाया गया है। वर्ष 1974-75 में अत्यधिक बीमारी हितलाभ को निगम तथा राज्य सरकारों ने निम्न प्रकार आपस में बांट लिया है :

राज्य का नाम	राज्य में दी गई कुल अधिक बीमारी हितलाभ की राशि (वास्तविक)	समस्त भारत औसत से अधिक राज्य सरकार का अंश
आन्ध्र प्रदेश . . .	8,94,317	22,503
बिहार . . .	6,21,656	44,964
कर्नाटक . . .	24,83,186	3,40,523
केरल . . .	31,35,597	12,32,604
मध्य प्रदेश . . .	25,53,002	8,65,034
उड़ीसा . . .	3,91,984	39,378
पांडीचेरी तथा माहे . .	3,32,519	1,21,233
तमिल नाडु . .	89,31,529	33,45,985

35. विस्तरित बीमारी हितलाभ (परिशिष्ट 15 के खाना 9 और 10) :

35.1. कुछ विशिष्ट रोगों जैसे क्षय, कोढ़, मानसिक और दुर्दम्य रोग आदि से पीड़ित बीमाकृत व्यक्ति बीमारी हितलाभ के 56 दिनों के अतिरिक्त विस्तरित बीमारी हितलाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

35.2. वर्ष 1975-76 में इस मद में बीमाकृत व्यक्तियो को 140.18 लाख रुपये की राशि अदा की गई जबकि पिछले वर्ष यह राशि 114.56 लाख रुपये थी।

35.3. वर्ष 1975-76 तथा 1974-75 के विस्तरित बीमारी हितलाभ दावों की घटनाएं प्रति 1000 जोखिमग्रस्त कर्मचारी और समाप्त दावों की अवधि खाना-9 तथा 10 में दिखाई गई हैं।

36. प्रसूति हितलाभ (परिशिष्ट 15 के खाना 11 और 12) :

36.1. प्रसूति हितलाभ की हकदार महिला कर्मचारियों की संख्या 1974-75 के 3,13,750 से बढ़कर 1975-76 में 3,30,050 हो गई है। प्रसूती लाभ के रूप में अदा की गई कुल राशि 102-65 लाख रुपये थी जबकि 1974-75 में यह राशि 86.03 लाख रुपये थी। प्रति प्रसूति दावा नकद लाभ की औसत राशि 1974-75 के 509 से बढ़कर 536 रुपये हो गई है।

36.2. प्रति 1000 बीमाकृत महिला कर्मचारी दावों की संख्या 1974-75 के 53.8 से बढ़कर 1975-76 में 58.0 हो गई है।

37. अस्थायी अपंगता हितलाभ (परिशिष्ट 16 के खाना 3 से 6):

वर्ष 1975-76 के दौरान रोजगार चोट से ग्रस्त कर्मचारियों की संख्या 46.89 लाख थी जबकि 1974-75 में यह संख्या 43.36 लाख थी (देखिए खाना 3)। वर्ष 1975-76 में अस्थायी अपंगता हितलाभ के रूप में अदा की गई राशि 248-35 लाख रुपये थी जबकि 1974-75 में यह राशि 207.66 लाख रुपये थी। नई अवधियों की औसत संख्या प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष लाभ दिनों की संख्या और औसत लाभ दर क्रमशः 0.06, 0.77 और 6.91 है जबकि 1974-75 में यह क्रमशः 0.06, 0.85 और 5.64 रुपये थी (देखिये खाना 4 से 6) प्रति अवधि का औसत काल घट कर 14-67 से 13-19 हो गया है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी इन दावों की घटनाओं और काल में विभिन्न राज्यों में घट-बढ़ रही।

38. स्थायी अपंगता हितलाभ (परिशिष्ट 16 के खाना 7 से 10) :

38.1. वर्ष 1975-76 में स्वीकृत नये केसों की संख्या 16,670 थी जबकि पिछले वर्ष यह 11,167 थी। प्रति 1000 बीमाकृत कर्मचारी घटनायें 1974-75 के 2.58 से बढ़कर 3.55 हो गई। प० बंगाल में यह घटनाएँ अपेक्षाकृत अधिक हुईं।

38.2. वर्ष के प्रारम्भ में निधि के बावेवारों की संख्या 36,479 थी जो वर्ष के अन्त में बढ़कर 43,517 हो गई (देखिये खाना 10)। लाभ के रूप में वास्तव में संवितरित राशि 296-43 लाख रुपये थी (176-59 लाख रुपयों की रूपांतरित राशि सहित) जबकि 1974-75 में यह राशि 260-02 लाख रुपये (161-39 लाख रुपयों की रूपांतरित राशि सहित) थी।

38.3. वर्ष के दौरान स्वीकृत नये केसों से संबंधित स्थायी अपंगता हितलाभ दावों का पूंजीकृत मूल्य 542.40 लाख रुपये था जबकि 1974-75 में यह 342-19 लाख रुपये थी। वर्ष के अंत में स्थायी अपंगता हितलाभ निधि 1505-26 लाख रुपये थी जबकि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में यह 1161.24 लाख रुपये थी।

38.4. आवधिक अदायगियों के बदले में रूपांतरित मूल्य लेने का विकल्प करने वाले स्थायी अपंगता हितलाभ के दावेदारों की संख्या 1974-75 में 9,957 थी जोकि 1975-76 में घटकर 9,510 हो गई।

39. स्थायी अपंगता हितलाभ दावे (परिशिष्ट 17):

39.1. (क) उद्योगों के मुख्य समूहों और (ख) उद्योग वार प्रति 1000 कर्मचारी दावों की घटनाओं के आधार पर वर्ष के दौरान स्वीकृत स्थायी अपंगता हितलाभ के 16,670 केसों का विश्लेषण किया गया है। पिछले वर्ष की तरह 'वस्त्र' में दुर्घटनाओं की संख्या सबसे अधिक थी और इसके बाद 'इंजीनियरिंग' तथा 'धात्विक खनिज' आते हैं वस्त्रोद्योग तथा धात्विक खनिज में यह घटनायें ज्यादा थी जबकि खाद्य, पेय तथा तम्बाकू में कम थी। वर्ष 1974-75 की तदनुरूपी घटनाओं की तुलना करने से यह मालूम होता है कि इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति अनुभव की गई घटनाओं का लगभग सभी उद्योगों में निकट संबंध है।

39.2. इस वर्ष औसत स्थायी अपंगता 9.83% थी जबकि पिछले वर्ष यह 9.48% थी। अधिकतम दुर्घटनायें आठवें मजदूरी ग्रुप अर्थात् 8 रुपये और 15 रुपये के बीच दैनिक मजदूरी वाले ग्रुप में हुई।

39.3. महिला कर्मचारियों में स्थायी अपंगता हितलाभ के केसों की संख्या केवल 278 थी। इन घटनाओं के कम होने के कारण संभवतः यह है कि महिलाओं को जोखिम वाले व्यवसायों और ड्यूटियों आदि पर नहीं लगाया जाता।

40.1 आश्रितजन हितलाभ (परिशिष्ट 16 के खाना 11 और 12) :

40.1. आश्रितजन हितलाभ के लिये स्वीकृत नये दावों की संख्या 1974-75 के 429 से बढ़कर समीक्षाधीन वर्ष में 534 हो गई (देखिये खाना 11 और 12)। पिछले वर्ष की तुलना में यह घटनायें अधिक है। वर्ष के दौरान स्वीकृत आश्रितों की संख्या 1,337 थी।

40.2. वर्ष के प्रारम्भ में तथा अन्त में सभी आश्रितों का श्रेणीवार वितरण इस प्रकार है :—

विवरण	31 मार्च को	
	1975	1976
विधवाएँ . . .	3702	4052
पुत्र और पुत्रियां . .	6317	6727
पिता . . .	493	578
माता . . .	696	769
अन्य आश्रित बालक . .	493	555
कुल . . .	11701	12681

40.3. आश्रितजन हितलाभ के रूप में अदा की गई राशि 1974-7 में 51.13 लाख रुपये थी जो 1975-76 में बढ़कर 57.97 लाख रुपये हो गई। वर्ष के दौरान स्वीकृत आश्रितजन हितलाभ दावों का पूंजीकृत मूल्य 116 99 लाख रुपये था जबकि 1974-75 में यह 93-97 लाख रुपये था। 31 मार्च, 1976 को आश्रितजन हितलाभ निधि 682.35 लाख रुपये थी जबकि 31 मार्च, 1975 को यह 571.34 लाख रुपये थी।

अंशदान तथा प्रवर्तन

41. अंशदानों से आय : वर्ष 1975-76 में कुल 75,94,03,303.21 रुपए की राशि एकत्र की गई।

42. अंशदान एकत्र करने का तरीका :

अंशदान मुख्यतः कर्मचारी राज्य बीमा निगम की टिकटों के माध्यम से एकत्र किये जाते हैं जोकि हमारे बैंकरों की शाखाओं में बेचे जाते हैं। अंशदान फैंकों के द्वारा भी प्राप्त होते हैं। समीक्षाधीन वर्ष में 38 और लाइसेंस दिये गये 18 लाइसेंस रद्द कर दिये गये जिससे अंशदान काडों को फैंक करने के लिये फैंकिंग मशीन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 759 हो गई। इसके अतिरिक्त, अंशदानों की नकद अदायगी की प्रणाली भी प्रयोगात्मक आधार पर 30-11-75 से दिल्ली में आरम्भ की गई है।

43. निरीक्षण : समीक्षाधीन वर्ष में मुख्यालय ने निरीक्षण कार्य की प्रगति पर कड़ी निगरानी जारी रखी। निरीक्षकों ने नियोजकों और उनके कर्मचारियों की रिकार्ड रखने तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम तथा विनियमों के विभिन्न उपबन्धों का पालन करने में मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण जारी रखा।

वर्ष के अन्त में कुल मिलाकर 242 बीमा निरीक्षक थे (200 नियमित तथा 42 छुट्टी रिजर्व)। वर्ष में कुल 23,822 निरीक्षण किये गये।

44. कर्मचारी बीमा न्यायालय : वर्ष 1975-76 में निम्नलिखित राज्यों में नये कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय स्थापित किये गये :

राज्य का नाम	स्थान
महाराष्ट्र	सतारा
मध्य प्रदेश	दुर्ग
	सूधर
	बिलासपुर

45. कानूनी कार्यवाही : वर्ष के दौरान दायर किये गये न्यायालय दावों, राजस्व वसूली पर हुए खर्च की राशि और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन वसूल की गई राशि, राज्य-वार परिशिष्ट 18 में दिखाई गई है।

बजट और वित्त

46. वित्तीय तथा लेखा व्यवस्थाएँ :

46.1. 1975-76 के परिशोधित प्राक्कलन और वर्ष 1976-77 के बजट प्राक्कलन निगम की 28 फरवरी, 1976 को हुई बैठक में स्वीकार किये गये तथा 1 अप्रैल, 1976 को केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त हुई। ये राज्यसभा/लोकसभा के पटल पर क्रमश. दिनांक 2-4-76 और 8-4-76 को प्रस्तुत किये गये।

46.2. निगम के लेखाओं की लेखा परीक्षा का कार्य केन्द्रीय सरकार ने नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली को सौंपा है। महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व, संबंधित राज्य महालेखाकारों के माध्यम से लेखा परीक्षा का संचालन करता है जोकि उप लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। समेकित लेखा परीक्षा रिपोर्ट महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व द्वारा तैयार की जाती है। क० रा० बी० निगम के लेखाओं की वर्ष 1972-73 की समेकित लेखा परीक्षा रिपोर्ट महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व ने 8-1-76 को केन्द्रीय सरकार को भेजी थी और कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 15-1-76 को प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट की परीक्षा कर ली गई है। वर्ष 1972-73 के परीक्षित लेखों को स्थायी समिति, क०रा० बी० निगम को अंगीकरण हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। तत्पश्चात् इनको लोकसभा तथा राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत करने हेतु केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे।

47. बैंकिंग व्यवस्था :

निगम के कार्यालयों के लिये वर्ष के दौरान स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं तथा इसके सहायक बैंकों में 25 बैंक खाते खोले गये और 4 खाते बंद किये गये। 31 मार्च, 1976 को स्टेट बैंक आफ इंडिया, इसके सहायक बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में बैंक खातों की कुल संख्या 436 थी।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया की 26 शाखाओं और इसके सहायक बैंकों के साथ कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान टिकट बेचने की व्यवस्था की गई। 31 मार्च, 1976 को अंशदान टिकटों का विक्रय कुल 408 शाखाओं में किया जा रहा था।

48. विनियोजन :

वर्ष के आरम्भ में सामान्य नकद शेष में 30,79,37,000 रुपये का विनियोजन था। वर्ष के दौरान स्टेट बैंक आफ इण्डिया की आवधिक जमा (टर्म डिपाजिट) में कुल 34,90,00,000 रुपये का विनियोजन किया गया जिसमें से 16,60,00,000 रु० वसूल किये गये और 12,26,37,000 रुपये की जमा रसीदें विभिन्न आरक्षित निधि खातों में उनके वार्षिक विनियोजन के स्थान पर हस्तांतरित कर दी गई है। इस प्रकार वर्ष के अंत में 36,83,00,000 रुपये विनियोजन के रूप में सामान्य रोकड़ शेष में शेष रहे।

31 मार्च, 1976 को विभिन्न आरक्षित निधियों के अंतर्गत कुल विनियोजन तथा सामान्य नकद शेष 99,39,53,222.33 रुपये था जबकि वर्ष के प्रारम्भ में यह राशि 81,09,53,222.33 रुपये थी।

विनियोग के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

	1-4-1975 को जैसा था	31-3-76 को जैसा था
	रुपये	रुपये
1. भारत में केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	3,32,94,442.33	3,32,94,442.33
2. 12 वर्षीय डाक प्रमाण पत्र	21,15,000.00	..
3. स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नई-दिल्ली में मियादी जमा (फिक्स्ड डिपाजिट)	77,55,43,780.00	96,06,58,780.00
योग:	81,09,53, 222.33	99,39,53,222.33

49. आय तथा व्यय लेखा तथा तुलन पत्र :

निगम का वर्ष 1975-76 का आय तथा व्यय लेखा तथा 31-3-76 को तुलनपत्र क्रमशः परिशिष्ट 19 और 20 में दिखाये गये हैं, बाह्य लेखा परीक्षकों के द्वारा इनकी लेखा परीक्षा हो चुकी है। 1974-75 वर्ष के लेखाओं की लेखा-परीक्षा भी हो चुकी है। परन्तु लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र अभी महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व नई दिल्ली से प्राप्त नहीं हुआ है।

50. प्रशासन की सापेक्ष लागत : परिशिष्ट 21 में दिये गये विवरण में वर्ष 1970-71 से प्रशासन की सापेक्ष लागत दिखाई गई है। पिछले पांच वर्षों में (1971-72 से 1975-76) हितलाभों के खर्चों की तुलना में प्रशासनिक खर्च अंशदानों की राशि तथा क० रा० बी० निगम के कर्मचारी वर्ग का बीमाकृत व्यक्तियों से अनुपात व नकद लाभ की संख्या नीचे दी गई है :—

	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76
प्रति क० रा० बी० निगम कर्मचारी नकद लाभ अवायगियों की संख्या	780	629	701	633	635
प्रति क० रा० बी० निगम कर्मचारी वसूल किया अंशदान	रु० 68192	रु० 79334	रु० 86154	रु० 81944	रु०95872
कुल लाभों में प्रशासनिक खर्च का अनुपात	12.51%	11.86%	11.04%	14.22%	13.59%
कुल अंशदानों में प्रशासनिक खर्च का अनुपात	9.35%	7.50%	7.72%	10.40%	10.24%
प्रति एक लाख बीमाकृत व्यक्तियों में क० रा० बी० नि० कर्मचारी वर्ग का अनुपात	192	182	177	171	154

'कर्मचारी', 'बीमाकृत व्यक्ति' और 'हिताधिकारी' शब्दों की परिभाषाएं :

(क) किसी विशेष तारीख को कर्मचारियों की संख्या उन फैक्टरियों में प्रभावी पदों की अनुमानित संख्या होती है जो योजना के अन्तर्गत आती है। यह मोटे तौर पर उस तारीख के आसपास फैक्टरी द्वारा प्रतिवेदित नियोजित कर्मचारियों की औसत संख्या होगी और इसमें उस तारीख को वास्तव में नियोजित कर्मचारियों की संख्या से बहुत अधिक अन्तर नहीं होगा। यह ध्यान में रखा जाये कि किसी अवधि में किसी स्वीकृत पद पर वास्तव में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक हो सकती है। क्योंकि किसी नियमित कामगार के स्थान पर उसकी अनुपस्थिति, छुट्टी रिजर्व या अवसरी कामगार अस्थायी तौर पर स्थानापन्न रूप में काम कर रहे होते हैं।

(ख) इस रिपोर्ट के प्रयोजन के लिये किसी तारीख को 'बीमाकृत व्यक्तियों' की संख्या से तात्पर्य उन व्यक्तियों की संख्या से है जो उस तारीख को चिकित्सा हितलाभ के हकदार माने गये हैं। यह भी कि किसी दिन 'बीमाकृत व्यक्तियों' की संख्या उस तारीख को काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या से अधिक हो सकती है क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सा हितलाभ की पात्रता शर्तों के अधीन किसी दिन चिकित्सा लाभ के पात्र व्यक्तियों में न केवल वे व्यक्ति शामिल होंगे जो उस दिन नियोजित थे बल्कि ऐसे भूतपूर्व कर्मचारी भी शामिल होंगे जो उस तारीख से पहले की अवधि के दौरान अंशदान की शर्तों के कारण उस तारीख को इस प्रकार के लाभ के पात्र होंगे।

(ग) किसी तारीख को 'हिताधिकारियों' की कुल संख्या में ऐसे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो उस तारीख को योजना के अंतर्गत चिकित्सा लाभों के पात्र माने गये हैं। इनमें 'बीमाकृत व्यक्ति', शामिल हैं और जहां बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर योजना का विस्तार हो गया है वहां उनके परिवारों के सदस्य भी इसमें शामिल हैं। 'बीमाकृत व्यक्ति' के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या (बीमाकृत व्यक्ति के अतिरिक्त) प्रति 'बीमाकृत व्यक्ति' औसतन 2.88 सदस्य मानकर ज्ञात की गई है।

परिशिष्ट-1

वर्ष 1975-76 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार

भाग-क—नये क्षेत्रों में कार्यान्वयन

राज्य	केन्द्र/क्षेत्र	कार्यान्वयन की तिथि	31-3-76 को कर्मचारियों की संख्या	परिवारों के लिये चिकित्सा देखरेख: लागू होने की तिथि	परिवारों के लिये चिकित्सा देखरेख: योजना के अन्तर्गत आये परिवारों (बी० व्य०) एककों की संख्या
आसाम	चन्द्रपुर	—	—	22-6-1975	1,100
	मारघरीटा	21-12-1975	1,050	21-3-1976	1,100
	जोगीघोपा	1-2-1976	800	13 सप्ताहों की समाप्ति पर योजना के अन्तर्गत आयेगी	—
आन्ध्र-प्रदेश	अन्थेरगांव	—	—	29-6-1975	1,000
	बमम्लनगर	—	—	29-6-1975	1,050
	श्रीरामनगर	13-7-1975	2,500	12-10-1975	2,650
	गोपालापतनम	28-9-1975	500	28-12-1975	550
	राजामून्दरी के उपान्त	26-10-1975	राजामुन्दरी में सम्मिलित	25-1-1975	राजामुन्दरी में सम्मिलित
	कुडाप्पा के उपान्त	29-2-1976	कुडाप्पा में सम्मिलित	13 सप्ताहों की समाप्ति पर योजना के अन्तर्गत आएंगे	--
गोआ, दमन और दीव	पणजी, बिचोलिम, मार-गोआ, एक्सेल्डम तथा मारमगाओ	5-10-1975	10,000	4-1-1976	11,200
गुजरात	हसनपुर	29-2-1976	बांकानेर में सम्मिलित	13 सप्ताहों की समाप्ति पर योजना के अन्तर्गत आएगा	—
हरियाणा	धूलकोट	14-9-1975	850	14-12-1975	950
	बाहलगढ़ (बाहलगढ़ मार्ग को मिलाकर)	25-1-1976	1,900	13 सप्ताहों की समाप्ति पर योजना में आएगा	—
कर्नाटक	केनगेरी	—	—	25-4-1975	बंगलोर में सम्मिलित
	शिमोगा	—	—	25-5-1975	550
	होशकोटे मार्ग	—	—	29-6-1975	बंगलौर में सम्मिलित
	साराक्की	—	—	26-6-1975	बंगलौर में सम्मिलित
	कोनाना कुंटे	—	—	29-6-1975	बंगलौर में सम्मिलित
	यशवन्तपुर	28-9-1975	बंगलौर में सम्मिलित	28-12-1975	बंगलौर में सम्मिलित
	बैलरी के उपांत	25-1-1976	बंगलौर में सम्मिलित	13 सप्ताहों की समाप्ति पर योजना के अन्तर्गत आएगा	--
केरल	पनगप्पारा	27-4-1975	250	27-7-1975	250
	चितिविलकोम	27-4-1975	50	27-7-1975	50
	किडमगुर	27-4-1975	50	27-7-1975	50
	चंगनाचेरी	27-4-1975	1,000	27-7-1975	1,050
	अडक्कनचेरी	27-4-1975	300	27-7-1975	300
	चेन्थुरुठी	27-4-1975	100	27-7-1975	100

1	2	3	4	5	6
केरल	मुलूरकरा	27-4-1975	200	27-7-1975	200
	पटाम्बी	27-4-1975	200	27-7-1975	200
	मन्नानाद	27-4-1975	300	27-7-1975	300
	ओलूरकरा	27-4-1975	200	27-7-1975	200
	नटीसरी	27-4-1975	100	27-7-1975	100
	कुमारनेलूर	27-4-1975	50	27-7-1975	50
	करामुक	28-12-1975	100	28-3-1976	100
	वडनापल्ली	28-12-1975	150	28-3-1976	150
	नाटीका	28-12-1975	300	28-3-1976	300
	वैलूर	28-12-1975	50	28-3-1976	50
महाराष्ट्र	तेलेगांव	28-12-1975	2,500	28-3-1976	2,650
	वेहू कैन्टोनमेंट	28-12-1975		28-3-1976	
	वेहू विलेज	28-12-1975		28-3-1976	
	लोनावाला	28-12-1975		28-3-1976	
	खण्डकला	28-12-1975		28-3-1976	
	माधवनगर	1-2-1976	1,000	13 सप्ताहों की समाप्ति पर योजना के अन्तर्गत आएगा।	—
	चिखलथाना	1-2-1976	5,700	—जैसे ऊपर—	—
उड़ीसा	रूरकेला (हिन्दुस्तान स्टील लिमि० को छोड़कर)	10-8-1975	2,500	9-11-1975	2,800
	जाजपुर रोड	28-3-1976	1,500	13 सप्ताहों की समाप्ति पर योजना के अन्तर्गत आएगा	—
पंजाब	मोहाली	25-1-1976	2,500	—जैसे ऊपर—	—
राजस्थान	चित्तौड़गढ़	—	—	29-6-1975	1,600
	बेछवाल	27-7-1975	बीकानेर में सम्मिलित	26-10-1975	बीकानेर में सम्मिलित
तमिलनाडु	मलूर	—	—	22-6-1975	300
	अस्सूर	—	—	22-6-1975	600
	करूर	—	—	22-6-1975	1,300
	अम्बूर	—	—	22-6-1975	2,450
	करमावाई	—	—	22-6-1975	1,700
	नल्लम्बकम	—	—	22-6-1975	मद्रास शहर में सम्मिलित
	थिरुवनमयूर	13-4-1975	मद्रास शहर में सम्मिलित	13-7-1975	—जैसा ऊपर—
	थोराइपक्कम	13-4-1975	—जैसा ऊपर—	13-7-1975	—जैसा ऊपर—
उत्तर प्रदेश	नैनी के उप नगर	—	—	22-6-1975	इलाहाबाद में सम्मिलित
	मजीदाबाद	—	—	22-6-1975	1,400
प० बंगाल	हरिनघाट	27-7-1975	1,200	26-10-1975	1,300
	रानाघाट	27-7-1975	1,300	26-10-1975	1,400
	चाकवाह	27-7-1975	500	26-10-1975	550

भाग 'ख'—स्थापनाओं के नये वर्गों का विस्तार

राज्य	क्षेत्र	विस्तार की तिथि	योजना के अन्तर्गत आये स्थापनाए	कर्मचारियों की सख्या (अस्थायी अनुमानित आंकड़े)	परिवारों के लिये चिकित्सा देखरेख (विस्तार की तिथि)
1	2	3	4	5	6
केरल	केरल राज्य में क्यूलोन जिले के क्यूलोन तालुक मे मायानद के राजस्व गावो मे	27-4-75	बिना विद्युत शक्ति वाली फैक्टरिया जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी काम करते हैं।	1 600	27-7-75
प० बगाल	हावड़ा जिले मे कलकत्ता शहर, हुगली जिला तथा 24-परगना जिले मे कल्याणी अधिसूचित क्षेत्र	27-4-75	(क) कम विद्युत शक्ति वाली फैक्टरियां जिनमे 10 से 19 कर्मचारी काम करते हैं। (ख) बिना विद्युत शक्ति वाली फैक्टरियां जिनमे 20 या अधिक कर्मचारी काम करते हैं।	19,000	27-7-75
केरल	केरल राज्य में क्यूलोन जिले को छोड कर शेष सभी जिले	27-7-75	बिना विद्युत शक्ति वाली फैक्टरिया जिनमे 20 या अधिक कर्मचारी काम करते हैं।	3,100	26-10-75
असम	बारबारी, धुबरी, डिब्रूगढ़, गोहाटी, गोहाटी के उपनगरो को मिलाकर, जेपोर, जोरहाट, मारिघानी, तेजपुर और तिनसुकिया (i) मकुम (ii) तिनसुकिया के उपान्तों को मिलाकर	3-8-75 एव 17-8-75	(क) विद्युत शक्ति का प्रयोग करने वाली फैक्टरियां जिनमें 10 से 19 कर्मचारी काम करते हैं (ख) बिना विद्युत शक्तिवाली फैक्टरियां जिनमे 20 या अधिक कर्मचारी काम करते है। (ग) होटल/रेस्तरां/दुकानें/पूर्व-दर्शन थियेटर सहित सनेमा/सड़क मोटर परिवहन सस्थापनाए तथा समाचार पत्र संस्थापनाए जिनमे 20 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं।	3,042	2-11-75 एव 16-11-75
बिहार	मुगेर कटिहार, समस्तीपुर, डालमियानगर, जपला, मोकामेह, मारहोवड़ा, रामगढ़, आदित्यपुर और कुमारधोबी।	17-8-75	—जैसा ऊपर—	4,000	16-11-75
राजस्थान	अलवर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्री गगानगर और उदयपुर।	26-10-75	—जैसा ऊपर—	8,000	25-1-76

1	2	3	4	5	6
कर्नाटक . . .	(i) बंगलोर शहर तथा उप नगर	29-2-76	होटल तथा रेस्तरां जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं।	5,500	13 सप्ताह बाद योजना में आने वाले।
	(ii) कुंदापुर चन्ना पटना, चित्रदुर्गा, डंडेली, देवानगिरि गोकाक, गुलबर्गा, हरिहर, होसपट्ट, हावेर, फालगल, कोलार गोल्ड फील्ड्स, कनकपुरा, नन्जनगुड, तथा टी० नरसीपुर।	29-2-76	(क) कम विद्युत शक्ति का प्रयोग करने वाली फैक्टरियां जिनमें 10 से 19 व्यक्ति काम करते हैं।	8 000	—जैसा ऊपर—
		29-2-76	(ख) बिना विद्युत शक्ति का प्रयोग करने वाली फैक्टरियां जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं।		
			(ग) होटल, रेस्तरां, दुकानें पूर्वदर्शन सहित सिनेमा, सड़क मोटर परिवहन संस्थापनाएं तथा समाचार-पत्र संस्थापनाएं जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं।		
उत्तर-प्रदेश . .	गाजियाबाद (गाजियाबाद के उप नगर को मिलाकर) कानपुर (कल्याणपुर को मिलाकर) तथा मोदीनगर।	7-3-76	(अ) विद्युत शक्ति प्रयोग करने वाली फैक्टरियां जिनमें 10 से 19 व्यक्ति काम करते हैं।	8 000	13 सप्ताह बाद योजना के अन्तर्गत आने वाले।
			(ब) बिना विद्युत शक्ति का प्रयोग करने वाली फैक्टरियां जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं।		
			(स) होटल, रेस्तरां, दुकानें, पूर्वदर्शन सहित सिनेमा, सड़क मोटर परिवहन संस्थापनाएं समाचार-पत्र संस्थापनाएं जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं।		
संघ क्षेत्र पांडिचेरी . .	पांडिचेरी नगर पालिका सीमा के क्षेत्र तथा पांडिचेरी संघ क्षेत्र की अधिसूचित जाति, पंचायत।	29-2-76	—जैसा ऊपर—	650	—जैसा ऊपर—
संघक्षेत्र दिल्ली . .	दिल्ली का सारा संघ क्षेत्र	27-3-76	सड़क मोटर परिवहन संस्थापनाएं तथा समाचार पत्र संस्थापनाएं जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं।	5 000	—जैसा ऊपर—

परिशिष्ट-2

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय तथा अनैक्सियां

क्र० सं०	राज्य	स्थान	पलंगों की संख्या — सामान्य	पलंगों की संख्या — क्षय	टिप्पणी
1	2	3	4.1	4.2	5
चिकित्सालय :					
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	310	—	
2.	वही	सिरपुर कागजनगर	110	—	
3.	वही	विजयवाड़ा	86	10	
4.	वही	वारंगल	50	—	
5.	वही	अदोनी	50	—	
6.	वही	विशाखापत्तनम	110	—	
7.	बिहार	मैथोन	110	—	
8.	वही	मुंगेर	30	—	
9	वही	आलमियां नगर	50	—	
10.	दिल्ली	दिल्ली	340	—	
11.	गुजरात	बापूनगर अहमदाबाद	500	—	
12.	वही	नरोदा, अहमदाबाद	—	200	
13.	हरियाणा	फरीदाबाद	170	—	
14.	वही	यमुनानगर	60	—	
15.	वही	पानीपत	15	35	
16.	केरल	मुलकुनाथकवु	—	100	
17	वही	असरामम	100	—	
18.	वही	अल्लैप्पी	55	—	
19.	वही	पेरुरकाडा	550	—	
20.	वही	त्रिचूर	60	—	
21.	वही	उद्योग मण्डल	120	—	
22.	वही	एर्नाकुलम	50	—	
23.	वही	वडावथूर	50	—	
24.	वही	पारीपल्ली	100	—	
25.	वही	एजुकोन	150	—	
26.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	150	—	
27.	वही	ईन्दौर	—	75	
28.	वही	उज्जैन	50	15	
29.	महाराष्ट्र	एम० जी० एम० बम्बई	700	—	
30	वही	बोरली	470	—	
31.	वही	नागपुर	150	—	
32	वही	मुलुन्द	60	540	
33.	वही	औंध	410	—	
34.	कर्नाटक	राजाजीनगर, बंगलौर	330	40	
35.	वही	दान्देली	24	—	
36.	उड़ीसा	चाऊद्वार	50	—	
37.	वही	कन्सबहल	50	—	
38.	पंजाब	अमृतसर	125	—	
39.	वही	लुधियाना	80	—	
40	वही	जालंधर	60	—	
41.	राजस्थान	जयपुर	113	—	
42.	तमिलनाडु	मद्रास	600	25	
43.	वही	कोयम्बतूर	500	—	
44.	वही	मदुरै	177	25	
45.	उत्तर प्रदेश	कानपुर (वैस्ट हस्प०)	—	180	

1	2	3	4	5	
46.	उत्तर प्रदेश	कानपुर (मातृत्व)	144	—	
47.	वही	कानपुर	212	—	
48.	वही	मोदी नगर	100	—	
49.	पश्चिमी बंगाल	सियालदाह	250	—	
50.	वही	कमरहाटी	175	—	
51.	वही	बेलूर-बल्ली	—	150	
52.	वही	सीरामपुर	166	—	
53.	वही	उलूबीरिया	166	—	
54.	वही	बान्करा	416	—	
55.	वही	कल्याणी	226	—	
56.	वही	गौरहाटी	166	—	
57.	वही	बज-बज	300	—	
		कुल	9236	1395	= 10631

अनेक्सियां

क० सं०	राज्य	स्थान	पलंगों की संख्या सामान्य	क्षय	टिप्पणी
1	2	3	4.1	4.2	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	इर्रमनुमा	—	24	
2.	बिहार	इटकी	—	20	
3.	हरियाणा	फरीदाबाद	—	12	
4.	वही	धरमपुर	—	12	
5.	कर्नाटक	बंगलौर	—	32	
6	केरल	पुलायनारकोटा	—	24	
7.	महाराष्ट्र	नागपुर	—	25	
8.	उड़ीसा	पी द्वार	—	12	
9.	वही	ब्रजराजनगर	25	—	
10.	पंजाब	अमृतसर	—	12	
11.	राजस्थान	जयपुर	—	15	
12	वही	बारी उदयपुर	—	16	
13.	वही	पाली	12	—	
14.	वही	भीलवाड़ा	12	—	
15.	वही	जोधपुर	20	—	
16.	वही	श्रीगंगानगर	12	—	
17.	वही	कोटा	24	—	
18.	वही	उदयपुर	12	—	
19.	वही	भरतपुर	12	—	
20	तमिलनाडु	शिवकाशी	12	—	
21.	वही	ताम्बरम	—	52	
22.	वही	कोइलपट्टी	32	—	
23	वही	लालगुडी	10	—	
24.	वही	नागेरकोइल	—	26	
		कुल	183	282	= 465

परिशिष्ट 3

31-3-75 तथा 31-3-76 को परिवारों (बीमाकृत व्यक्ति) एककों पर चिकित्सा देखरेख की किस्म ।

क्रम सं०	राज्य	प्रतिबन्धित देख-रेख		प्रतिबन्धित देख-रेख		पूर्ण देख-रेख	
		31-3-75	31-3-76	31-3-75	31-3-76	31-3-75	31-3-76
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	38,500	47,800 (44,850)	1,19,700	1,75,200 (1,64,650)
2.	आसाम	—	—	20,100	25,650 (24,200)	—	—
3.	बिहार	—	—	85,000	1,04,000 (93,000)	—	—
4.	चण्डीगढ़	—	—	9,000	9,000 (8,000)	—	—
5.	दिल्ली	—	—	—	—	1,56,000	2,06,000 (1,80,000)
6.	गुजरात	—	—	1,47,500	1,60,350 (1,43,500)	3,61,500	4,09,650 (3,66,500)
7.	हरियाणा	—	—	1,29,450	1,41,300 (1,30,500)	12,800	22 200 (20,000)
8.	कर्नाटक	—	—	1,06,400	77,600 (72,950)	1,36,400	2,08,400 (1,96,050)
9.	केरल	—	—	—	—	1,96,250	2,63,600 (2,48,700)
	माहे	—	—	750	1,400 (1,300)	—	—
10.	मध्य प्रदेश	—	—	76,300	89,750 (84,000)	50,700	59,250 (55,500)
11.	महाराष्ट्र						
	बम्बई क्षेत्र	—	—	8,80,000	11,37,800 (10,20,000)	—	—
	गोआ	—	—	—	11,200 (10,000)	—	—
	नागपुर क्षेत्र	5,760	—	45,250	51,450 (48,300)	—	—
	पूना क्षेत्र]	26,600	—	54,700	55,100 (52,000)	82,750	1,21,850 (1,15,000)
12.	उड़ीसा	—	—	54,500	72,300 (64,500)	—	—
13	पाण्डिचेरी	—	—	14,500	55,500 (14,500)	—	—
14.	पंजाब	—	—	53,550	—	81,450	1,60,200 (1,44,500)
15.	राजस्थान	—	—	13,400	24,950 (17,000)	76,450	87,550 (89,000)
16.	ततमिलनाडु	—	—	1,11,200	85,750 1,05,500)	2,62,400	3,19,250 (2,74,500)
17	उत्तर पदेश	2,19,950	2,32,850 (1,18,000)	—	—	2,25,400	2,37,150 (2,22,000)
18.	प० बंगाल	3,60,000	3,74,150 (3,51,000)	2,13,850	2,31,850 (2,17,500)	3,26,150	3,64,000 (3,41,500)
	योग	6,12,300	6,07,000 (5,69,000)	20,539,50	23,42,750 (21,51,600)	20,87,900	26,34,300 (24,17,900)

नोट : कोष्ठक में दी गई संख्याएं परिवार (बीमाकृत व्यक्ति) एककों को निर्दिष्ट करती हैं ।

परिशिष्ट-4

वर्ष 1975-76 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा लिये गए महत्वपूर्ण निर्णय

(i) 20 जुलाई, 1975

1. निगम ने बीमाकृत व्यक्तियों को निगम अथवा बी० व्य० द्वारा दर्ज किए गए मामलों में चिकित्सा अपील न्यायालय में उपस्थित होने हेतु बुलाने पर हुई मजदूरी की हानि हेतु उसी परिमाण तथा उन्हीं अवस्थाओं के अधीन सवारी भत्ता तथा/अथवा क्षतिपूर्ति देने का निर्णय किया जो उन मामलों में लागू होती है जहां बी० व्य० को चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। अब सवारी भत्ते की दर 35 पैसे प्रति कि० मी० है फिर भी जहां बी० व्य० बस द्वारा या दूसरी किसी साधारण सवारी के साधन द्वारा यात्रा करने में असमर्थ है अथवा उसे किसी परिचर की आवश्यकता है तो बी० व्य० को उसके द्वारा किया गया वास्तविक खर्च दिया जाना चाहिए जो 65 पैसे प्रति कि० मी० से अधिक न हो। इसी प्रकार जहां बी० व्य० ने चिकित्सा अपील न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के कारण मजदूरी की हानि की है उसे उस प्रत्येक दिन या दिनों की मजदूरी क्षतिपूर्ति के रूप में दी जानी चाहिए जब उसने मजदूरी की हानि की। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क० रा० बी० अधिनियम, 1948 (उच्चतम मजदूरी ग्रुप) की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत अस्थायी अपंगता हितलाभ की अधिकतम दैनिक दर से अधीन क्या उसकी आधे से कम दिन की मजदूरी की क्षति हुई अथवा अधिक ?

(ii) 28 फरवरी, 1976

1. निगम ने उन 21 बीमारियों के सम्बन्ध में, जिनकी सूची नीचे दी गई है। 124 दिनों के लिए वि० बी० हितलाभ का भुगतान करने का निर्णय लिया जो उपयुक्त पुराने मामलों में क्षेत्रीय उप-चिकित्सा आयुक्त/चिकित्सा निर्देशी/प्र० चि० अधिकारी/राज्य के क० रा० बी० योजना के मुख्य कार्यकर्ता अथवा उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति द्वारा 309 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। 124 दिनों से अधिक दिनों के लिए भुगतान केवल उपरोक्त अधिकारियों की सिफारिशों के प्राप्त होने पर किया जाएगा।

बीमारियों की सूची :

1. क्षय रोग
2. कोढ़
3. मानसिक रोग (मनोविक्षिप्ति)
4. दुर्दम्य रोग
5. अधरांगघात
6. पक्षाघात
7. चिरकाल से संकुचित हृदिवपलता
8. कच्चा मोतियाबिन्द जबकि प्रभावित नेत्र की वीक्षण शक्ति 6/60 या कम हो।
9. फुफ्फुस फोड़ा
10. फुफ्फुसनालोत्सन
11. पार्योकार्डियल इन्फार्क्शन
12. अन्तराकोकस बिम्ब का विस्थापन और ग्रंश
13. कम्पाघात
14. असाध्य रक्तहीनता
15. जलोदर के साथ यकृत का अधिनन्तु रोग
16. दृष्टिपटल का वियोजन
17. अस्थियां भंग होने पर उनका न जुड़ना या देर से जुड़ना
18. एम्पाइमा
19. कपाल के भीतर चोट का लगना
20. मेरु रज्जु सम्पीड़न
21. पुराना (साधारण) प्रारम्भिक ग्लांकोमा

चिकित्सा आयुक्त केवल किसी रोग अथवा विशेष अवस्थाओं में उपरोक्त अधिकारियों की सिफारिशों पर मामले के गुणावगुण पर आधारित 124 दिनों या 309 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए निर्धारित बीमारी हितलाभ के भुगतान की स्वीकृति दे सकता है।

2. निगम ने विस्तारित बीमारी हितलाभ की दर मानक हितलाभ की दर से जो कि पिछली बार बीमारी हितलाभ के लिए देय थी 25% अधिक वृद्धि करने का अनुमोदन कर दिया है जिसको कि 5 पैसों की अगली उच्च बहुगुणक संख्या में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

3. निगम ने निम्नलिखित संकल्प पास किया :

"संकल्प पास किया गया कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 यथा अद्यतन संशोधित की धारा 85ख(1) के अन्तर्गत हानियों की उगाही करने हेतु महानिदेशक अथवा उनके द्वारा अधिकृत कोई दूसरा अधिकारी नियोजक/नियोजकों से उगाही कर सकता है अथवा हर्जाना ले सकता है जो संलग्न तालिका 'क' में दिए गए दरों से अधिक न होगा।"

4 निगम ने अपने ही व्यय पर समस्त भारत में निर्मित क० रा० बी० परियोजनाओं की मरम्मत तथा अनुरक्षण के कार्य की देखभाल हेतु अपनी ही मशीनरी रखने का निर्णय लिया। प्रयोगात्मक कार्यवाही के रूप में अभी कुछ क्षेत्रों को चुना गया है जहां ऐसी मशीनरी रखने का प्रस्ताव है।

परिशिष्ट-5

वर्ष 1975-76 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थायी समिति द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

(1) 2 जून, 1975

स्थायी समिति ने निम्नलिखित संकल्प पास किए :

"संकल्प पास किया कि केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन निगम द्वारा अथवा बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा दर्ज किए गए

मामलो में निगम बी० व्य० को चिकित्सा अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए उसी परिमाण तथा उन्हीं शर्तों के अधीन परिवहन भत्ता देगा तथा/अथवा मजदूरी की हानि के लिए क्षतिपूर्ति करेगा—जो बी० व्य० के चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने वाले मामलों में लागू होती है ।"

(2) 16 सितम्बर, 1976

1. स्थायी समिति ने 1-4-75 से चिकित्सा देखरेख पर व्यय सीमा में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की, जो निम्न प्रकार है :—

(क) प्रतिबन्धित चिकित्सा देखरेख	65 से 70 रु० प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष
(ख) विस्तरित चिकित्सा देखरेख	70 से 75 रु० प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष
(ग) पूर्ण चिकित्सा देखरेख	80 से 95 रु० प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष

स्थायी समिति ने यह भी स्वीकार किया कि औषध दवाइयों तथा दूसरी रोग निवारण हेतु दवाइयो पर प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी व्यय सीमा के अतिरिक्त 25 रु० से अधिक परन्तु 45 रुपये से कम की अनुमति होगी तथा व्यय राज्य सरकार तथा क० रा० बी० निगम के बीच व्यावहारिक अनुपात में बांटा जाएगा ।

2 स्थायी समिति ने चिकित्सा हितलाभ परिषद् की 11-2-75 को हुई बैठक में की गई सिफारिश पर संशोधित औषध-कोष की स्वीकृति प्रदान की ।

(3) 20 दिसम्बर, 1975

1. स्थायी समिति ने विस्तरित बीमारी हितलाभ की दर में वृद्धि करने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की तथा निगम द्वारा निम्नलिखित संकल्प अंगीकार करने की सिफारिश की :—

"संकल्प पास किया कि विस्तरित बीमारी हितलाभ की दर एक विस्तरित बीमारी हितलाभ की अवधि के दौरान मानक हितलाभ की दर मे जो कि अधिनियम के अन्तर्गत पिछली बार बीमारी हितलाभ के लिए देय थी 25% अधिक होगी जिसको पाच पैसे की उच्च बहुगुणक संख्या में परिणित कर दिया जाएगा ।"

इससे आगे यह संकल्प पास किया कि यह संकल्प 1-4-76 से निम्न प्रकार लागू होगा :—

(क) बढ़ी हुई दर पर हितलाभ 1-4-76 को या उसके पश्चात् के विस्तरित बीमारी हितलाभ के सभी मामलों के लिए देय होगा ।

(ख) ऐसे बीमाकृत व्यक्तियों को भी 1-4-76 से बढ़ी हुई दर पर हितलाभ देय होगा जिनके विस्तरित बीमारी हितलाभ के मामले 1-4-76 को चालू है तथा जिन्होंने विस्तरित बीमारी हितलाभ अभी तक समाप्त नहीं किया है ।

(ग) ऐसे बीमाकृत व्यक्ति भी केवल 1-4-76 से बढ़ी हुई दर पर हितलाभ के अधिकारी होंगे जिन्होंने इसका कारण से विस्तरित बीमारी हितलाभ नहीं लिया कि उनके मामलों की पात्रता सम्बन्धी निर्णय 1-4-76 से पहले नहीं हुआ है ।

2. स्थायी समिति ने निम्नलिखित संकल्प का अनुमोदन किया तथा निगम द्वारा उसका अंगीकार करने की सिफारिश की ।

"संकल्प पास किया कि अद्यतन संशोधित क० रा० बी० अधिनियम, 1948 की धारा 85-ख(1) के अन्तर्गत हर्जानों की उगाही करने के उद्देश्य से महानिदेशक अथवा उनके द्वारा किसी अन्य अधिकृत अधिकारी नियोजक/नियोजकों से हर्जाना की उगाही तथा वसूली कर सकता है जो संलग्न तालिका 'क' में दिए गए दरों से अधिक न होगी ।"

(4) 27 फरवरी, 1976

स्थायी समिति ने यह भी स्वीकार किया कि बीमाकृत व्यक्तियों को जो अधरंग अथवा दूसरे रोगों से विकलांग हैं, पहिया-गाड़ी प्रदान की जाए तथा बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को, हृदय अधरंग में गति देने वाले उपकरण प्रदान किए जाएं जहां समर्थ हृदयरोग विशेषज्ञ चिकित्सा हितलाभ परिषद् की सिफारिश पर आवश्यक समझे ।

2. स्थायी समिति ने क० रा० बी० योजना के अन्तर्गत एम्बुलेंस यान की व्यवस्था करने हेतु मापदण्ड को स्वीकार किया तथा चिकित्सा हितलाभ परिषद की 22-12-75 को हुई बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर क० रा० बी० औषधालयों में कर्मचारी वर्ग के संशोधित मानकों की भी स्वीकृति प्रदान की ।

तालिका-'क'

हर्जाने की उगाही हेतु मानक तालिका

चूकों की क्रम सं०	1 मास अथवा कम	1 मास से अधिक तथा दो मास तक	2 मास से अधिक तथा तीन मास तक	3 मास से अधिक तथा 4 मास तक	4 मास से अधिक तथा 5 मास तक	5 मास से अधिक तथा 6 मास तक	6 मास से अधिक तथा 7 मास तक	7 मास से अधिक तथा 8 मास तक	8 मास से अधिक तथा 9 मास तक	9 मास से अधिक तथा 10 मास तक	10 मास से अधिक तथा 11 मास तक	11 मास से अधिक तथा 12 मास तक	12 मास से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत		
पहली चूक . .	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	12 मास से अधिक हर्जाने की राशि बकाया में पड़ी राशियों के बराबर होगी ।	
दूसरी चूक . .	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		
तीसरी चूक . .	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65		
चौथी चूक . .	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		
पांचवी चूक . .	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
छठी चूक . .	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		
सातवीं चूक . .	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
आठवीं चूक . .	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90		
नौवीं चूक . .	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95		
दसवीं चूक . .	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100		
ग्यारहवीं चूक . .	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	100		
बारहवीं चूक . .	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	100	100		

जहां चूकों की संख्या 12 से अधिक हो, हर्जाने की राशि बकाया राशियों के बराबर होगी ।

परिशिष्ट-6

वर्ष 1975-76 में चिकित्सा हितलाभ परिषद् द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें

(i) 22 दिसम्बर, 1975

1. क० रा० बी० योजना के अन्तर्गत चिकित्सा देखरेख के एक भाग के रूप में परिषद् ने बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिये कृत्रिम उपकरणों की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया तथा निम्नलिखित सिफारिशें की :—

(क) बी० व्य० को जो अधरंग अथवा दूसरे रोगों से विकलांग है पहिया कुर्सी प्रदान करना;

(ख) समर्थ हृदयरोग विशेषज्ञ द्वारा बी० व्य० को तथा उसके परिवार के सदस्यों को जहां आवश्यकता समझी जाए; हृदय की गति देने वाले उपकरण (इम्पलीमेन्टेबल कार्डियक पेस मेकर) की व्यवस्था करना।

2 परिषद् ने क० रा० बी० औषधालयों के विभिन्न वर्गों के कर्मचारी वर्ग के संशोधित मापदण्ड तथा योजना हेतु अम्बुलेंस यान की व्यवस्था करने के लिए एक माप-दण्ड की सिफारिशें की ।

3. चिकित्सा हितलाभ परिषद् ने क० रा० बी० अस्पताल के विभिन्न आकार हेतु उपस्कर; कर्मचारी वर्ग के मानकों का सुझाव देने हेतु एक छोटी उपसमिति गठित की ।

(ii) 24 फरवरी, 1976

परिषद् ने क० रा० बी० आयुर्वेदिक संस्थाओं हेतु एक आयुर्वेदिक नियम पुस्तक (आयुर्वेदिक फार्मूलरी) का अनुसरण करने की सिफारिश की

परिशिष्ट-
भाग-

31 मार्च, 1976 को प्राधिकृत

क्र०सं०	पदों का नाम	मुख्यालय	आन्ध्र प्रदेश		असम		बिहार	
			क्षे० का०	स्था० का०	क्षे० का०	स्था० का०	क्षे० का०	स्था० का०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	महानिदेशक	1	..	..	..	..	..	..
2.	बीमा आयुक्त	1	..	..	..	..	..	..
3.	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी	1	..	..	..	..	..	..
4.	चिकित्सा आयुक्त	1	..	..	..	..	..	..
5.	बीमांकिक	1	..	..	..	..	..	..
6.	प्रशासन निदेशक	1	..	..	..	..	..	..
7.	क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त	..	..	..	..	..	..	..
8.	सं० बीमा आयुक्त/क्षे० नि० ग्रेड—1	2	..	..	..	..	..	..
9.	नि० (सं० एवं प)/उ० वि० स०/क्षे० नि० ग्रेड—2/नि० (यो एव वि०) निदेशक (सतर्कता)	3	..	..	..	..	..	..
10.	प्र० अ०/उप बी० आ०/क्षे० नि० ग्रेड—3/उप मु० ले० अ०/स० क्षे० वि०/सतर्कता अधिकारी	8	1	..	..	..	..	..
11.	उप चि० आ०/चिकित्सा निर्देशी	4	1	..	..	..	1	..
12.	क्षे० नि० ग्रेड—4/उप प्र० अ०/सहा० बी० आ०/उप क्षे० नि०/सहा० बीमांकिक/लेखा अधि०/उप क्षे० नि०/सहायक नि० (योजना)	13	3	..	1	..	1	..
13.	स०क्षे०नि०/प्र०ग्रेड—1/उ०ले०अ०/अनुभाग अधिकारी	22	2	..	..	..	3	..
14.	बी०नि०/ले०नि०/प्र०ग्रेड—2/उ०प्र०/नि० (स०एवं प०)	6	14	15	..	3	7	6
15.	महा निदेशक का निजी सचिव	1	..	..	..	..	..	..
16.	प्र० ग्रेड—3/मु०लि०/सहायक/मु०लि० (खजांची)	81	8	8	1	3	4	9
17.	वैयक्तिक सहायक	11	1	..	..	..	..	..
18.	तकनीकी सहायक	1	..	..	..	..	..	..
19.	कलाकार	1	..	..	..	..	..	..
20.	पुस्तकाध्यक्ष	1	..	..	..	..	..	..
21.	स्वागती	1	..	..	..	..	..	..
22.	उ०श्रे०लि० प्रभारी/उ०श्रे०लि० खजांची/उ०श्रे०लिपिक	69	33	40	4	4	18	14
23.	आशुलिपिक	19	2	..	1	..	2	..
24.	संगणक	4	..	..	..	..	..	..
25.	नि०श्रे०लि०/एड्रेमा-प्रचालक/टैलैक्स-प्रचालक/टेलीफोन प्रचालक	91	80	53	8	4	36	17
26.	गैस्टेटनर प्रचालक	1	..	..	..	..	..	..
27.	स्टाफकार चालक/डिलीवरी गाड़ी चालक	4	1	..	..	..	1*	..
28.	कनिष्ठ पुस्तकालय परिचर	1	..	..	..	..	..	..
29.	जमादार	1	..	..	..	..	..	..
30.	रिकार्ड सार्टर/दफ्तरी (मसैकशन ग्रेड दफ्तरियों सहित)	29	13	19	1	6	7	13
31.	चपरासी	57	12	17	4	1	8	7
32.	चौकीदार	3	2	..	1**	..	1	..
33.	फराश	7	1	..	..	..	1	..
34.	माली	1	1	..	..	..	..	..
35.	लिफ्ट मैन	..	..	..	..	..	..	..
36.	सफाई कर्मचारी	9	2	..	..	..	1	..
	जोड़	457	177	152	21	21	91	66

*स्टाफ कार चालक व चपरासी

**चौकीदार व फराश

--7

--I

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कर्मचारी वर्ग

दिल्ली		गुजरात		कर्नाटक		केरल		मध्य प्रदेश	
क्षे० का०	स्था० का०	क्षे० का०	स्था० का०	क्षे० का०	स्था० का०	क्षे० का०	स्था० का०	क्षे० का०	स्था० का०
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	.	..	.
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	.	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	..	1	..	.	..	..	..
..	..	1	..	.	..	.	..	..	..
..	..	..	..	1	..	.	..	..	.
2	..	..	..	..	..	1	..	1	..
2	..	3	..	2	..	2	..	1	..
4	..	5	..	5	..	3	..	3	..
2	..	5	1	2	2	2	1	1	3
19	4	19	20	13	17	18	26	9	9
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6	2	17	11	11	9	10	8	6	10
1	..	1	..	2	..	1	..	1	..
..	..	..	..	..	..	.	..	..	..
..	.	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	.	..		..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
38	16	69	64	45	65	44	72	31	38
4	..	5	..	4	..	3	..	2	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
68	12	153	66	101	65	90	80	59	31
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	.	1	.	1	..	1	..
.	..	..	..	.	..	..	.	..	.
..	..	..	..	.	..	..	..	..	..
12	6	32	28	20	24	18	28	12	17
13	8	23	31	16	25	15	24	10	12
1	..	2	..	3	1	2	..	2	..
1	..	3	..	2	..	1	..	1	.
.	.	..	..	..	..	.	..	..	.
.	..	..	.	..	..	..	..	..	..
1	..	3	..	2	..	1	..	1	..
175	48	342	221	231	208	212	239	141	120

परिशिष्ट-

भाग-

31 मार्च, 1976 को प्राधिकृत कर्मचारी राज्य

क्र० सं०	पदों का नाम	महाराष्ट्र				उड़ीसा	
		क्षे० का०	उ० क्षे० का० पूना	उ० क्षे० का० नागपुर	स्था० का०	क्षे० का०	स्था० का०
1	2	20	21	22	23	24	25
1.	महानिदेशक	..	..	..	..	..	..
2.	बीमा आयुक्त	..	..	..	..	..	..
3.	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी	..	..	..	..	..	..
4.	चिकित्सा आयुक्त	..	..	..	..	..	..
5.	बीमांकिक	..	..	..	..	..	..
6.	प्रशासन निदेशक	..	..	..	..	..	..
7.	क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त	1	..	..	..	..	..
8.	सं० बीमा आयुक्त/क्षे० नि० ग्रेड–1	1	..	..	..	..	..
9.	नि० (सं० एवं प)/उ० वि० स०/क्षे० नि० ग्रेड-2/नि० (यो० एवं वि०) निदेशक (सतर्कता)	..	..	..	..	..	..
10.	प्र० अ०/उप बी० आ०/क्षे० नि० ग्रेड–3/उप मु० ले० अ०/सं० क्षे० नि०/सतर्कता अधिकारी	3	1	..	..	..	..
11.	उप चि० अ०/चिकित्सा निर्देशी	12	..	..	..	..	..
12.	क्षे० नि० ग्रेड-4/उप प्र०अ०/महा० बी० आ०/उप क्षे० नि०/महा० बीमांकिक लेखाधिकारी/स० नि० (दो)/उ० क्षे० नि०	11	1	1	..	1	..
13.	सं० क्षे० नि/प्र० ग्रेड-1/उ० ले० अ०/अनुभाग अधिकारी	11	1	..	17	2	1
14.	बी० नि०/ले० नि०/प्र० ग्रेड-2/उ० प्र०/नि० (सं० एवं प०)	78	..	1	33	5	3
15.	महानिदेशक का निजी सचिव	..	..	..	..	..	..
16.	प्र० ग्रेड-3/मु० लि०/सहायक/मु० लि० (खजांची)	45	7	3	36	3	5
17.	वैयक्तिक सहायक	2	1	..	..	..	..
18.	तकनीकी सहायक	..	..	..	..	..	..
19.	कलाकार	..	..	..	..	..	..
20.	पुस्तकालय अध्यक्ष	..	..	..	..	..	..
21.	स्वागती	..	..	..	..	..	..
22.	उ० श्रे० लि० प्रभारी/उ० श्रे० लि० खजांची/उ० श्रे० लि०	181	26	10	153	13	12
23.	आशुलिपिक	15	1	1	..	2	..
24.	संगणक	..	..	..	..	..	..
25.	नि० श्रे० लि०/एड्रेमा प्रचालक/टैलैक्स प्रचालक/टेलिफोन प्रचालक	406	50	17	186	25	10
26.	गैस्टेटनर प्रचालक	2	..	..	..	..	..
27.	स्टाफ कार चालक/डिलीवरी गाड़ी चालक	2	..	..	..	1*	..
28.	कनिष्ठ पुस्तकालय परिचर	..	..	..	..	..	..
29.	जमादार	..	..	..	..	..	..
30.	रिकार्ड सार्टर/दफ्तरी (सलैक्शन ग्रेड दफ्तरियों सहित)	92	12	4	64	4	9
31.	चपरासी	54	8	5	94	5	4
32.	चौकीदार	6	1	1	..	1	..
33.	फराश	6	1	1	..	1	..
34.	माली	..	..	..	..	..	..
35.	लिफ्ट मैन	..	..	..	..	..	..
36.	सफाई कर्मचारी	7	1	1	..	1	..
	योग	935	111	45	583	64	44

*स्टाफ कार ड्राइवर व चपरासी

7 (क्रमशः)

I (क्रमशः)

बीमा निगम का कर्मचारी वर्ग

पंजाब		राजस्थान		तमिलनाडु		उत्तर प्रदेश		पश्चिम बंगाल		योग
क्षे० का०	स्था० का०	क्षे० का०	स्था० का०	क्षे० का०	स्था० का०	क्षे० का०	स्था० का०	क्षे० का०	स्था० का०	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	4
..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	5
1	..	..	..	1	..	1	..	..	..	7
..	..	..	..	1	..	..	..	3	..	21
2	..	1	..	4	5	3	..	10	..	48
4	..	1	..	5	..	5	..	11	..	78
3	..	3	..	6	10	5	2	13	19	139
23	14	7	5	28	27	19	14	58	33	553
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
12	4	5	9	19	34	18	12	39	24	479
1	..	..	..	1	..	1	..	1	..	25
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
51	22	19	11	69	127	65	35	147	170	1775
3	..	3	..	6	..	5	..	18	..	96
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4
195	25	36	12	165	151	146	39	347	204	2938
..	..	..	..	1	..	1	..	2	..	7
..	..	1*	..	1	..	1	..	4	..	20
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
20	18	7	14	29	53	31	25	75	69	811
15	9	7	5	20	53	23	25	56	101	767
2	..	1	..	3	..	2	..	4	..	39
2	..	1	..	2	..	2	..	6	..	39
1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	4
..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2
2	..	1	..	3	..	2	..	8	..	46
247	92	93	56	364	455	331	152	806	620	7920

परिशिष्ट-7

भाग-2

31 मार्च, 1976 को निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली, कर्मचारी राज्य बीमा डिस्पेंसरियों तथा कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय में प्राधिकृत कर्मचारी वर्ग और वास्तव में नियुक्त कर्मचारियों की स्थिति का विवरण

क्रम सं०	पदों का नाम	निदेशक का कार्यालय		क० रा० बी० डिस्पेंसरियां		क० रा० बी० अस्पताल		योग	
		प्राधिकृत	वा० नि०	प्राधिकृत	वा० नियु०	प्राधिकृत	वा० नि०	प्राधिकृत	वा० नि०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली	1	1	—	—	—	—	1	1
2.	चिकित्सा अधीक्षक	—	—	—	—	1	—	1	—
3.	विशेषज्ञ (गुरुक, औषध, स्त्रीरोग, विकलांग, विकिरण चिकित्सा, रोग विज्ञान वेहोशी-विज्ञान तथा शिशुरोग)	—	—	—	—	11	4	11	4
4.	उप-मुख्य लेखा अधिकारी	1	1	—	—	—	—	1	1
5.	प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी	1	1	—	—	—	—	1	1
6.	उप-प्रशासन अधिकारी	1	1	—	—	1	1	2	2
7.	बीमा चिकित्सा अधिकारी (जी० डी० ओ० ग्रेड-1 तथा 2)	—	—	142	117	—	—	142	117
8.	लेखा अधिकारी (चिकित्सा)	1	1	—	—	—	—	1	1
9.	चिकित्साधिकारी (जी डी ओ ग्रेड-2)	—	—	—	—	16	15	16	15
10.	रजिस्ट्रार	—	—	—	—	3	1	3	1
11.	हाउस सर्जन	—	—	—	—	10	8	10	8
12	रेडियोलोजिस्ट	—	—	—	—	1	1	1	1
13.	नर्सिंग अधीक्षक	—	—	—	—	1	1	1	1
14.	उप लेखाअधिकारी	—	—	—	—	1	1	1	1
15.	अंशकालिक परामर्शदाता/विशेषज्ञ	—	—	—	—	10	8	10	8
16.	लेखा परीक्षा निरीक्षक	2	2	—	—	—	—	2	2
17.	प्रधान लिपिक	10	8	—	—	3	3	13	11
18.	निरीक्षक (भंडार)	1	1	—	—	—	—	1	1
19.	नि० (चि०) नि० एवं चिकित्सा अधीक्षक का वैयक्तिक सहायक	1	1	—	—	—	—	1	1
20.	उ० श्रे० लि० ग्रेजांची	1	1	—	—	1	1	2	2
21	उच्च श्रेणी लिपिक	31	29	22	22	6	5	59	56
22.	आशुलिपिक	4	3	—	—	1	1	5	4
23.	निम्न श्रेणी लिपिक	45	36	75	71	20	13	140	123
24.	लांड्री पर्यवेक्षक	—	—	—	—	1	—	1	—
25	बायलर परिचर	—	—	—	—	1	—	1	—
26.	लांड्री प्रचालक	—	—	—	—	10	—	10	—
27.	टेलीफोन प्रचालक	—	—	—	—	2	—	2	—
28.	रखवाल	—	—	—	—	1	1	1	1
29	सहायक अधीक्षिका	—	—	—	—	1	—	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	सिस्टर इन्चार्ज	—	—	—	—	2	1	2	1
31.	नर्सिंग सिस्टर	—	—	—	—	17	13	17	13
32	स्टाफ नर्स	—	—	—	—	90	63	90	63
33.	नर्स ए/बी ग्रेड/महिला स्वा० नि०	—	—	48	43	—	—	48	43
34.	आहारविद	—	—	—	—	1	1	1	1
35.	प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड-I	—	—	—	—	8	6	8	6
36.	एक्सरे तकनीशियन/रेडियोग्राफर	—	—	—	—	7	5	7	5
37.	ई० सी० जी० तकनीशियन	—	—	—	—	1	1	1	1
38.	मुख्य औषधकारक	1	1	—	—	1	—	2	1
39.	औषधकारक-व-लिपिक (भंडार)	2	2	19	13	—	—	21	15
40.	औषधकारक	3	3	77	77	3	3	83	83
41.	सोशल गाइड	2	1	—	—	—	—	2	1
42.	प्रयोगशाला (तकनीशियन)	—	—	11	10	—	—	11	10
43.	भण्डारी	—	—	—	—	2	1	2	1
44.	सी० एस० आर० परिचर	—	—	—	—	6	3	6	3
45.	ओ० टी० (तकनीशियन)	—	—	—	—	3	3	3	3
46.	ओ० टी० (सहायक)	—	—	—	—	6	4	6	4
47.	पुस्तकाध्यक्ष	—	—	—	—	1	5	1	—
48.	सहायक पुस्तकाध्यक्ष	—	—	—	—	1	1	1	1
49.	मिडवाइफ/दाई	—	—	57	49	—	—	57	49
50.	एम्बुलेंस चालक/स्टाफ कार चालक	7	6	—	—	5	1	12	7
51.	ड्रेसर्स	—	—	61	61	6	6	67	67
52.	धातु कर्मकार व मिस्त्री	—	—	—	—	1	—	1	—
53	ओर्थो-मोटरिस्ट	—	—	—	—	1	1	1	1
54.	लिनन मिस्ट्रेस	—	—	—	—	1	—	1	—
55.	व्यावसायिक चिकित्सक	—	—	—	—	1	—	1	—
56.	भौतिक चिकित्सक	—	—	—	—	1	1	1	1
57.	वरिष्ठ एम० आर० टी०	—	—	—	—	1	—	1	—
58.	कनिष्ठ एम० आर० टी०	—	—	—	—	1	—	1	—
59.	गैस्टेटनर चालक	1	1	—	—	—	—	1	1
60.	दफ्तरी	4	4	—	—	2	2	6	6
61.	डार्करूम सहायक	—	—	—	—	1	—	1	—
62.	प्रधान रसोईया	—	—	—	—	1	1	1	1
63.	रसोईया सहित मसालची	—	—	—	—	20	13	20	13
64.	चपरासी	15	15	61	61	8	8	84	84
65.	आया	—	—	36	36	4	3	40	39
66.	चौकीदार	—	—	23	23	19	19	42	42
67.	सफाई कर्मचारी (पुरुष/स्त्री)	—	—	74	71	60	42	134	116
68.	दर्जी	—	—	—	—	2	1	2	1
69.	नर्सिंग अर्दली	—	—	—	—	95	79	95	79
70.	स्ट्रेचर वाहक	—	—	—	—	9	5	9	5
71.	एम्बुलेंस परिचर	2	—	—	—	3	2	5	2

परिशिष्ट-8

वर्ष 1975-76 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली फैक्टरियों और कर्मचारियों की संख्या-राज्य वार

राज्य	क्रियान्वित क्षेत्र*		क्रियान्वित क्षेत्र		सभी क्षेत्र	
	फैक्टरियों की संख्या	31-3-76 को कर्मचारियों की संख्या	फैक्टरियों की संख्या	31-3-76 को कर्मचारियों की संख्या	फैक्टरियों की संख्या	31-3-76 को कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	2081	209500	22	14500	2103	224000
असम	303	25000	40	11500	343	36500
बिहार	661	93000	226	180000	887	273000
चण्डीगढ़	89	8000	—	—	89	8000
दिल्ली	3121	180000	—	—	3121	180000
गुजरात	1877	510000	459	90000	2336	600000
हरियाणा	1537	150000	20	5500	1557	156000
हिमाचल प्रदेश	—	—	11	1500	11	1500
कर्नाटक	1441	269000	52	31000	1493	300000
केरल व माहे	1486	250000	15	10000	1501	260000
मध्य प्रदेश	603	139500	15	71500	618	211000
महाराष्ट्र	6822	1252000	331	56000	7153	1308000
उड़ीसा	198	66000	75	24000	273	90000
पाण्डीचेरी	67	14500	—	—	67	14500
पंजाब	2954	147000	46	2500	3000	149500
राजस्थान	834	106000	36	5000	870	111000
तमिलनाडु	2195	380000	187	37000	2382	417000
उत्तर प्रदेश	1405	440000	342	45000	1747	485000
पश्चिमी बंगाल	4730	910000	103	140000	4833	1050000
समस्त भारत (1976)	32404	5150000	1980	725000	34384	5875000
समस्त भारत (1975)	25654	1385000	1790	665000	27444	5050000

*अधिनियम की धारा 1(5) के अन्तर्गत आने वाले सभी नियोजक व कर्मचारी भी सम्मिलित है ।

परिशिष्ट-9

31-3-76 को योजना के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रों, कर्मचारियों, बीमाकृत व्यक्तियों परिवार (बीमाकृत व्यक्ति) एककों तथा हिताधिकारियों की संख्या राज्यवार (अधिनियम की धारा 1(5) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को मिलाकर)

राज्य	केन्द्रों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या	परिवार (बी०व्य०) एककों की संख्या	हिताधिकारियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	43	209500	223000	223000	865250
असम	12	25000	26500	25650	100350
बिहार	19	93000	104000	104000	403500
चण्डीगढ़	1	8000	9000	9000	34900
दिल्ली	1	180000	206000	206000	799300
गुजरात	14	5,10,000	570000	570000	2211600
हरियाणा	19	150500	167000	163500	637900
कर्नाटक	28	269000	286000	286000	1109700
केरल व गोवा	54	250000	265000	265000	1028200
मध्य प्रदेश	20	139500	149000	149000	578100
महाराष्ट्र	33	1252000	1384500	1377400	5351400
उड़ीसा	15	66000	74000	72300	282200
पाण्डीचेरी	1	14500	15500	15500	60150
पंजाब	22	147000	163000	160200	624400
राजस्थान	18	106000	112500	112500	436500
तमिलनाडु	42	380000	405000	405000	1571400
उत्तर प्रदेश	39	440000	470000	470000	1823600
पश्चिमी बंगाल	7	910000	970000	970000	3763600
समस्त भारत (1976)	388	5150000	5600000	5584050	21682050
समस्त भारत (1975)	365	4385000	4775000	4754150	18469950

परिशिष्ट-10

31-3-1976 को पदगों, विशेषज्ञों, औषधालयों, पेनल डाक्टरों तथा ऐम्बुलेंसों की संख्या

क्र० संख्या	राज्य का नाम	उपबन्धित पदगों की कुल संख्या क० रा० बी० योजना के अन्तर्गत				विशेषज्ञ		औष-धालयों की कुल संख्या	बीमा चिकित्सा अधिकारियों की संख्या		बीमा चिकित्सा व्यव-साईयों की संख्या	एम्बुलेंस	विवरण
		सामान्य	प्रसूति	क्षय	योग	पूर्ण कालिक	अंश-कालिक		स्वीकृत	वर्तमान			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आन्ध्र प्रदेश	490	57	95	632	9	76	79	199	199	5	13	
2	असम	16	—	2	18	—	—	17	18	18	—	—	
3	बिहार	196	—	30	226	5	—	90	90	57	—	21	
4	चण्डीगढ़ प्रशासन	2	—	—	2	—	4	1	3	2	—	—	
5	दिल्ली	390	—	125	515	1	27	26	156	117	—	5	
6	गोवा	18	—	2	20	—	—	—	—	—	56	—	
7	गुजरात	1069	—	278	1347	21	217	82	361	338	204	11	
8	कर्नाटक	1025	37	103	1145	6	60	97	214	206	—	11	
9	केरल	659	47	165	871	27	73	93	193	172	—	4	
10	मध्य प्रदेश	272	—	130	402	1	81	50	138	116	3	8	
11	महाराष्ट्र												
	बृहत्तर बम्बई	1283	164	550	1997	12	105	14	13	8	2132	11	
	नागपुर क्षेत्र	171	20	52	243	3	33	23	70	69	—	2	
	पश्चिमी महाराष्ट्र	363		177	540	—	16	19	61	39	349	2	
12	हरियाणा	277	—	53	330	12	22	44	104	99	—	2	
13	उड़ीसा	119	6	12	137	3	—	19	58	48	—	7	
14	पाण्डीचेरी	14	4	10	28	—	9	6	11	11	—	—	
15	पंजाब	317	5	29	351	20	19	16	41	32	84	4	
16	राजस्थान	184	26	31	241	4	52	37	101	98	—	1	
17	तमिलनाडु	1200	387	370	1957	37	70	115	339	321	—	21	
18	उत्तर प्रदेश	356	94	186	636	19	—	91	253	244	—	6	
19	पश्चिमी बंगाल	1945	12	680	2645	—	266	5	—	—	1757	15	
	योग	10366	859	3078	14303	215	1150	864	2426	2194	4589	144	

परिशिष्ट-

1974-75 और 1975-76 में डिस्पेंसरियों में उपस्थिति, जारी विशेषज्ञों को भेजे गये तथा घर पर किये गये निरीक्षणों की

राज्य	अवधि	जोखिमग्रस्त माने गए बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या	डिस्पेंसरियों में उपस्थितियां		
			नये केस	पुराने केस	कुल केस
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश . . . (मे प्र)	1974-75	1,54,500	5,48,235	18,53,944	24,02,179
	1975-76*	1,88,100	5,11,092	17,89,015	23,00,107
असम . . . . (मे प्र)	1974-75	21,500	66,326	69,200	1 35,526
	1975-76	23,350	81,990	87,321	1,69 311
बिहार . . . . (मे प्र)	1974-75	—	—	अ—	– आ
	1975-76*	92,900	1,52,316	2,61,280	4,13,596
चण्डीगढ़ . . . (मे प्र)	1974-75	9,000	12,776	61,780	74,556
	1975-76	8,850	12,595	55,768	68 363
दिल्ली . . . (मे प्र)	1974-75	1,53 000	1,90 902	9 17,990	11,08,892
	1975-76	1,77,900	2,11 090	11,36,510	13,47,600
गुजरात (पे प्र)	1974-75	4,58 050	5,76,894	30,01,875	35,78,769
	1975-76	4 81,300	6 27,247	31,30,305	37,57,552
गुजरात . . . (मे प्र)	1974-75	46,450	1,68,465	1,85,777	3 54,242
	1975-76	49,550	1,92 293	2,87,463	3 99,756
हरियाणा . . . . (मे प्र)	1974-75	1 05,850	3,08,568	4,80,980	7,89 548
	1975-76	1,24,000	3,72,661	6,08 686	9,81,347
हरियाणा (पे प्र)	1974-75	2 300	10 222	13,146	23,368
	1975-76	2,650	4,537	5,516	10,083
कर्नाटक . . . . (मे प्र)	1974-75	2 45 500	8,81,246	20 91,486	29 72,732
	1975-76	2,61,150	9,58,360	20,16,970	29,75 330
केरल . (मे प्र)	1974-75	1,97,050	6,39,489	17,31 349	23,69,838
	1975-76	2,25,550	7 88,617	19 71 831	27,52 448
केरल . . . (पे प्र)	1974-75	700	7,668	11,544	19,212
	1975-76	400	5 273	7,157	12,430
मध्य प्रदेश . . (मे प्र)	1974-75	1,29,350	3,11,011	16 68,816	19 82,827
	1975-76	1,33,700	3,56,086	18,28,919	21,85,005
मध्य प्रदेश . (पे प्र)	1974-75	2 150	3,771	12,521	16,292
	1975-76	2,050	4,501	15,411	19,912

11

किए गये चिकित्सा प्रमाण-पत्र, चिकित्सालयों में भर्ती, घटनाओं की संख्या-राज्यवार (बीमाकृत व्यक्तियों के संबंध में)

प्रति वर्ष प्रति 1000 बी० व्य० डिस्पेंसरियों में उपस्थिति की संख्या		जारी किये गए चिकित्सा प्रमाण पत्रों की संख्या	अस्पतालों में दाखिल किये गये केसों की संख्या	जांच के लिए विशेषज्ञों के पास भेजे गये केसों की संख्या	घर निरीक्षणों की संख्या
नये केस	पुराने केस				
7	8	9	10	11	12
3,548	12,000	3,69,336	—	52,570	अप्राप्य
2,717	9,511	3,81,576	अप्राप्य	66,396	अप्राप्य
3,085	3,219	44,482	81	5,014	3,088
3,511	3,740	50,741	135	5,093	3,169
व्य—	—	—	—	—	—
1,640	2,812	15,4851	2,093	10,069	7,396
1,420	6,864	5,728	40,57	7,121	549
1,423	6,301	4,574	34,45	6,933	अप्राप्य
1,248	6,000	1,13,388	3,269	26,825	38,974
1,187	6,388	1,44,311	4,172	36,017	30,272
1,259	6,554	4,63,546	25,650	1,06,434	3,452
1,303	6,504	4,75,687	16,618	1,20,667	4,587
3,627	4,000	1,13,768	1,531	9,799	1,640
3,881	4,187	1,26,253	1,171	10,496	1,933
2,915	4,544	78,132	2,992	23,679	10,750
3,005	4,909	88,658	5,637	44,264	7,596
4,444	5,716	1,273	—	76	130
1,712	2,093	503	5	57	288
3,590	8,519	6,62,696	18,334	1,07,117	30,616
3,670	7,723	5,34,853	18,389	97,360	20,204
3,240	8,786	5,78,007	24,887	26,899	10,087
3,461	8,742	4,08,532	34,974	30,713	7,436
10,954	16,491	4,753	1,255	984	—
13,183	17,893	1,645	1,390	700	2
2,428	12,902	4,81,603	7,087	56,3184	16,138
2,663	13,679	5,44,367	6,702	55,584	17,399
1,754	5,824	3,063	44	509	55
2,196	7,518	3,703	47	668	54

1		2	3	4	5	6
महाराष्ट्र :						
बम्बई क्षेत्र	(से प्र)	1974-75	18,400	58,774	1,64,464	2,23,238
		1975-76	1,350	3,523	19,517	23,040
बम्बई क्षेत्र	(पे प्र)	1974-75	6,50,900	31,70,099	31,26,911	62,97,010
		1975-76	5,93,450	2,42,1741	26,17,952	50,39,693
नागपुर क्षेत्र	(से प्र)	1974-75	50,000	1,48,375	4,54,933	7,03,308
		1975-76	53,400	1,53,862	6,13,373	7,97,235
पूना क्षेत्र	(से प्र)	1974-75	—	—	—	बम्बई क्षेत्र में
		1975-76	28,750	91,660	2,31,320	3,22,980
पूना क्षेत्र	(पे प्र)	1974-75	—	—	—	—
		1975-76*	66,100	3,01,364	3,41,068	6,42,432
उड़ीसा	(से प्र)	1974-75	54,750	1,60,811	2,02,616	3,63,427
		1975-76	63,150	1,83,762	1,89,684	3,73,446
पाण्डीचेरी व माहे	(से प्र)	1974-75	15,000	52,733	1,68,046	2,20,779
		1975-76	15,800	52,112	1,60,823	2,12,935
पंजाब	(से प्र)	1974-75	31,400	1,40,561	1,55,402	2,95,963
		1975-76	24,100	1,39,053	1,53,658	2,92,711
पंजाब	(पे प्र)	1974-75	33,150	1,87,829	1,67,814	3,55,643
		1975-76	31,850	1,84,180	1,52,558	3,36,738
राजस्थान	(से प्र)	1974-75	89,000	2,74,394	6,51,522	9,25,916
		1975-76	1,00,050	3.14,829	6,49,904	9,64,733
तमिलनाडु	(से प्र)	1974-75	3,86,050	12,90,550	34,47,875	47,38,425
		1975-76	3,82,400	11,47,746	33,78,801	45,26,547
तमिलनाडु	(पे प्र)	1974-75	4,950	22,802	55,345	78,147
		1975-76	4,800	23,645	50,764	74,409
उत्तर प्रदेश	(से प्र)	1974-75	4,40,000	14,44,568	16,95,393	31,39,961
		1975-76	4,52,900	15,83,050	19,09,700	34,92,750
पश्चिमी बंगाल	(पे प्र)	1974-75	5,83,000	23,91,814	23,68,378	47,60,192
		1975-76	6,96,650	23,21,083	21,31,076	44,52,159
समस्त-भारत		1974-75	38,82,000	130,70,883	2,48,59,107	3,79,29,990
		1975-76	42,86,200	1,31,92,268	2,57,52,380	3,89,44,648

*कुछ महीनों के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए, भारित औसत ले ली गई है ।

(से प्र) = सेवा प्रणाली

(पे प्र) = पेनल प्रणाली

7	8	9	10	11	12
3,194	8,938	43,822	29,140	3,401	138
2,610	14,457	4,519	25,541	594	9
4,870	4,804	16,52,611	2,770	1,44,401	19,271
4,081	4,411	13,07,541	707	1,30,726	15,560
2,968	11,099	1,13,768	4,265	18,276	12,333
2,881	12,048	1,64,800	7,511	19,556	9,481
सम्मिलित	(मे प्र)	—	—	—	—
3,180	8,046	62,696	अप्राप्य	2,808	672
बम्बई क्षेत्र	(पे प्र) में	सम्मिलित		—	—
4,559	5,160	2,46,542	342	12,418	1,742
2,937	3,701	1,14,898	1,477	12,037	9,877
2,910	3,004	67,128	1,434	12,041	6,250
3,516	11,203	58,504	498	12,066	1,978
3,298	10,179	43,453	939	7,560	3,854
4,476	4,949	13,767	19,851	2,430	2,417
5,770	6,376	20,067	30,437	2,458	2,773
5,666	5,062	36,467	10,131	12,927	8,042
5,783	4,790	32,176	11,943	13,700	7,917
3,083	7,320	1,50,609	7,379	35,090	1,590
3,147	6,496	1,53,342	8,256	4,0504	2,479
3,343	8,931	15,66,172	12,039	1,29,413	3,408
3,001	8,836	12,99,473	14,175	1,33,171	5,304
4,606	11,181	19,491	861	1,924	1,386
4,926	10,576	7,120	1,016	1,692	1,451
3,283	3,853	4,90,655	11,983	67,626	2,762
3,495	4,217	5,47,145	14,124	104,702	4,482
4,103	40,62	14,19,210	31	116,321	106,406
3,332	3,059	15,01,327	66	1,08,392	96,588
3,367	6,404	85,99,749	1,89,912	9,79,257	2,85,098
3,078	6,008	83,87,583	2,11,269	10,75,341	2,58,898

परिशिष्ट-12

वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 में डिस्पेंसरियों में उपस्थिति तथा घर निरीक्षणो की संख्या—राज्यवार (बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों के सम्बन्ध में)

राज्य		अवधि	जोखिमग्रस्त माने गए परिवारों के (बीमाकृत व्यक्ति) एकक की संख्या	डिस्पेंसरियों में उपस्थिति			प्रति वर्ष प्रति 1000 परिवारो (बीमाकृत व्यक्ति) एककों की डिस्पेंसरियो में उपस्थिति		घर निरीक्षकों की संख्या
				नये केस	पुराने केस	कुल केस	नये केस	पुराने केस	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	(से प्र)	1974-75	1,53,600	6,95,837	21,13,040	28,08,877	4,530	13,757	38,124
		1975-76*	1,87,200	6,48,802	22 40,608	28 89,410	3,466	11,969	52,879
असम	(से प्र)	1974-75	20,600	49,805	35,219	85,024	2,418	1,710	789
		1975-76	22,500	60,552	43,771	1,04,323	2,691	1,945	466
बिहार	(से प्र)	1974-75	..	..	..	..	अप्राप्य	..	..
		1975-76*	92,950	2,57,885	3,53,126	6,11,011	2,774	3,799	10,535
चण्डीगढ़	(से प्र)	1974-75	9,000	24,841	10,685	35,526	2 760	1,187	1,404
		1975-76	8,850	23,783	11,521	35,304	2,687	1,302	1,377
दिल्ली	(से प्र)	1974-75	1,53,000	5,09,268	9,83,372	14,92,640	3,329	6,427	14,027
		1975-76	1,77,900	5,75,565	10,81,980	16,57,545	3,235	6,882	12,705
गुजरात	(से प्र)	1974-75	4,57,600	8,85,895	37,40,997	46,26,892	1,936	8,175	2,754
		1975-76	4,80,900	9,36,362	38,90,542	48,26,904	1,947	8,090	1,798
गुजरात	(पे प्र)	1974-75	46,900	2,19,877	2,21,715	4,41,592	4,688	4,727	403
		1975-76	49,950	2,42,763	2,32,171	4,74 934	4,860	4,648	472
हरियाणा	(से प्र)	1974-75	1,17,650	3,06,434	4,46,593	7,53,027	2,605	3,796	5,873
		1975-76	1,36,950	3,39,138	4,76,512	8,15,650	2,476	3,479	10,041
हरियाणा	(पे प्र)	1974-75	2,600	14,523	21,395	35,918	5,586	8 229	386
		1975-76	2,800	6,824	12,372	19,196	2,437	4,419	359
कर्नाटक	(से प्र)	1974-75	2,44,150	12,05,285	24,95,994	37,01,279	4,937	10,223	11,882
		1975-76	2,60,050	13,76,586	27,07,771	40,84,357	5,294	10,413	12,149
केरल	(से प्र)	1974-75	1,97,050	6,11,023	16,83,445	22,94,468	3,101	8,543	640
		1975-76	2,25,600	7,63,405	19,79,493	27,42,898	3,384	8,774	672
केरल	(पे प्र)	1974-75	700	8,323	12,828	21,151	11,890	18,326	..
		1975-76	350	5,661	7,997	13,658	16,174	22,849	अप्राप्य
मध्य प्रदेश	(से प्र)	1974-75	1,29,100	6,66,452	18,64,348	25,30,800	5,162	14,441	727
		1975-76	1,33,650	6,85,353	17,97,386	24,82,739	5 128	13,448	758
मध्य प्रदेश	(पे प्र)	1974-75	2,050	7,046	13,698	20,744	3,437	6,682	..
		1975-76	2,100	8,175	13,740	21,915	3,893	6,543	..
महाराष्ट्र									
(1) बम्बई क्षेत्र	(से प्र)	1974-75	24,150	71,196	1,53,385	2,24,581	2,948	6,351	932
		1975-76	1,350	3,061	13,082	16,143	2,267	9,690	220
(2) बम्बई क्षेत्र	(पे प्र)	1974-75	6,13,000	17,14,018	15,73,471	32,87,489	2,783	2,555	11,594
		1975-76	5,15,000	16,61,682	12,07,278	28,69,140	3,227	2,344	10,261

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(3) नागपुर क्षेत्र . (से प्र)	1974-75	50,000	2,19,832	8,95,555	11,15,387	4,397	17,911	3,746
	1975-76	50,450	2,22,383	10,54,930	12,77,213	4,408	20,908	3,8
(4) पूना क्षेत्र . . (से प्र)	1974-75	— बम्बई क्षेत्र (से प्र) में सम्मिलित —				—	—	—
	1975-76*	32,200	1,05,116	2,17,440	3,22,556	3,264	6,753	3,184
(5) पूना क्षेत्र . . (से प्र)	1974-75	—	— बम्बई क्षेत्र (से प्र) में सम्मिलित			—	—	—
	1975-76*	68,800	2,91,476	3,04,728	5,96,204	4,237	4,429	3,464
उड़ीसा . . . (से प्र)	1974-75	53 400	1,52,866	1,75,691	3,28,557	2,863	3,290	1,955
	1975-76	62,300	1,83,373	1,85,382	3,68,755	2,943	2,976	1,849
पाण्डीचेरी व माहे . . (से प्र)	1974-75	15,000	54,004	1,25,700	1,79,704	3,600	8,380	2,949
	1975-76	15,800	59,130	1,58,791	2,17,921	3,742	10,050	3,068
पंजाब . . . (से प्र)	1974-75	27,750	1,22,101	1,26,117	2,48,218	4,400	4,545	2,732
	1975-76	20,200	1,10,225	99,940	2,10,165	5,457	4,948	1,786
पंजाब . . . (पे प्र)	1974-75	30,800	1,67,660	1,61,858	3,29,518	5,444	5,255	5,651
	1975-76	30,300	1,60 793	1,40,839	3,01,632	5,307	4,648	5,791
राजस्थान . . (से प्र)	1974-75	88,450	3,77,627	6,69,181	10,46,808	4,269	7,566	1,457
	1975-76	99,450	4,43,185	7,72,029	12,15,214	4,456	7,763	1,545
तमिलनाडु . . (से प्र)	1974-75	3,82,300	14,65,142	40,50,149	55,15,291	3,832	10,594	12,172
	1975-76	3,78,400	14,76,184	44,03,718	58,79,902	3,901	11,638	15,538
तमिलनाडु . . (पे प्र)	1974-75	45,00	31,240	79,781	1,11,021	6,942	17,729	1,387
	1975-76	4,750	35,596	76,031	1,11,627	7,494	16,007	1,936
उत्तर प्रदेश . . (से प्र)	1974-75	4,36,200	7,69,921	17,39,229	25,09,150	1,765	3,987	54,735
	1975-76	4,50,550	9,12,036	17,47,262	26,59,298	2,024	3,878	27,708
पश्चिमी बंगाल . . (पे प्र)	1974-75	5,36,650	19,92,190	17,58,931	37,51,121	3,534	3,121	1,38,404
	1975-76	6,32,850	21,19,044	14,20,802	35,29,846	3,348	2,245	28,106
समस्त भारत . .	1974-75	38,26,100	1,23,42,406	251,52,377	3,74,94,783	3,226	6,574	3,14,723
	1975-76	41,44,150	1,37,14,318	2,66,51,142	4,03,65,460	3,309	6,431	2,12,476

* कुछ महीनों के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं, भारित औसत ले ली गई है।
(से प्र) सेवा प्रणाली।
(पे प्र) पेनल प्रणाली।

परिशिष्ट-13

1974-75 और 1975-76 में रुग्णता के प्रकोप अर्थात, प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्ति और प्रति 100 परिवारों (बी० व्य०) एकक नये केसों की संख्या- समस्त भारत।

कारण ग्रुप संख्या	रोग	बीमाकृत व्यक्ति		परिवार	
		1974-75	1975-76	1974-75	1975-76
1	2	3	4	5	6
1. श्वसन प्रणाली का क्षय रोग		16.5	16.6	11.5	10.9
2. अन्य प्रकार का क्षय रोग		6.4	6.1	5.4	5.1
3. सिफिलिस और उसके अनुगम		4.2	4.6	1.6	2.2
4. गोनोकोकल संक्रमण		6.8	7.6	4.0	4.7
5. सभी प्रकार की पेचिश		246.0	217.3	226.2	202.3
6. हैजा, आन्त्र ज्वर, आन्त्रपथ में होने वाले अन्य संक्रामक रोग		20.4	25.2	25.3	24.9

1	2	3	4	5	6
7	स्कारलेट, ज्वर, डिप्थीरिया, कुकर-खांसी, खसरा, कनपेट, छोटी माता	14.0	14.8	28.6	31.9
8.	टाइफस और अन्य रिकेट्सिया रोग	0 8	1 6	0.8	1 5
9.	मलेरिया	24.7	27.7	27.5	31.8
10	फाइलेरिया रोग, अंकुशकृमि रोग और अन्य कृमि	46 0	49.4	72.2	84.3
11.	संक्रामक और परजीवी वर्ग के अन्य सभी रोग	43.8	49.3	42 5	60.0
12	दुर्दम अर्बुद सभी साइट	0 4	0.9	0.8	1.0
13.	सुदाम्य अर्बुद सभी साइट	1 1	1.1	1.3	1.8
14.	एलर्जिक विकार	99.5	97 3	94.1	103.2
15	अवंटु ग्रंथि के रोग	1.9	2.7	2.3	3.4
16	मधुमेह मेलीटस	5.5	5 1	5.2	6.6
17.	अविटामिनता व अन्य कमियों की स्थिति	124.7	98 2	127.7	126.2
18	अरक्तता	91.6	83 1	117.1	105.5
19	विक्षिप्त और मनोविक्षिप्त	3.9	3.6	3.3	3.2
20.	रक्तधर विक्षिप्ति सी०एन०एस०	1.0	0.9	1.1	1.4
21.	नेत्र रोग	102.5	114.0	108.8	123.7
22.	कान और मोसाटाइड प्रक्रिया के रोग	50 8	48 7	64.2	63.7
23.	रूमेटी ज्वर	9.1	7.2	8.8	7.5
24.	जीर्ण रूमेटी हृदय रोग	2.3	1.0	1.7	2.8
25.	धमनी आकाठिन्यज और व्ययजनक रोग	1.2	1.0	1.2	1.7
26.	अतिरिक्त दाबी रोग	6.7	6.3	5.7	6.4
27.	शिराओं के रोग	9.4	9.3	9.7	8.1
28	तीव्र नेजोफेरनजाइटिस (सामान्य नजला)	291.9	257.0	271.0	287.1
29.	तीव्र ग्रसनीशोथ और टान्सिल शोथ	100 1	81.2	110.3	103.8
30.	इन्फ्लूएंजा	195.7	160.9	151.1	143.3
31.	निमोनिया	9 0	7.0	15.4	12.1
32	श्वसनी शोथ	249.7	228.1	224.0	242.9
33.	सितामयता और व्यावसायिक फुफ्फुसी तन्तुमयता	1.2	0 3	0.4	0.3
34	अन्य श्वसन रोग	82.2	71.3	84.6	88.5
35.	आमाशय तथा पक्वाशय के रोग	131.9	112.3	102.3	101.6
36	उडुक पुच्छशोथ	2.9	2.8	2.9	3.2
37.	उदरीय गुहा का हार्निया	2.7	3.3	2.6	2.7
38	प्रवाहिका और आन्त्रशोथ	212.1	174.4	208.9	205.3
39.	पित्ताशय और पित्तवाहिनी के रोग	3.0	3.3	3.7	2.8
40.	पाचन तन्त्र के अन्य रोग	167.5	143.2	143.1	139.7
41.	वृक्कशोथ और अपवृक्कता	2.5	3.3	2.2	4.0
42.	जननांगों के रोग	18.8	17.9	32.7	34.9
43.	प्रसव, गर्भधारण की जटिलताएं, शिशु जन्म और प्रसवोत्तरकाल	68.5*	75.7*	12 7	11.6
44.	फुन्सी फोडे संयोजक अतिशोथ और अन्य त्वचा संक्रमण	185.6	172.1	204.5	206.5
45.	त्वचा के अन्य रोग	91.5	95.9	90.6	101.2
46.	धमनीशोथ और आमवात	162.6	137.3	119.3	121.4
47.	हड्डियों और संचालन के अन्य अंगों के रोग	10.6	11.9	6.6	6.8
48.	जन्मजात कुरचना और शिशुकाल में होने वाली बीमारियां	0.5	0.6	0.9	1.0
49.	अन्य विशिष्ट और अपरिभाषित रोग	306.0	288.3	268 9	274.2
50.	दुर्घटनाएं, विष देना और हिंसा	188.6	196.2	165.3	181.7
51.	अन्य विविध ग्रुप	3.7	2.7	3.4	3.9
	नये केसों की कुल संख्या	3367.0	3077.8	3225.8	3309.3

*प्रति 1000 बीमाकृत महिला कर्मचारी।

परिशिष्ट–14

वर्ष 1975-76 के अन्तर्गत चिकित्सा लाभ पर किया गया अनुमानित व्यय

क्रम संख्या	राज्य का नाम	जोखिमग्रस्त माने गये कर्मचारियों की संख्या	चिकित्सा हितलाभ पर कुल अनुमानित व्यय जो राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया था	प्रति व्यक्ति लागत
			रुपये	रुपये
1	आन्ध्र प्रदेश	1,76,750	1,77,30,027.54	100.31
2.	असम	21,300	11,54,076 51	54.18
3.	बिहार	84,900	65,75,534.05	77.45
4.	चण्डीगढ़ प्रशासन	7,500	5,25,141.00	70.02
5.	दिल्ली	1,54,750	1,85,63,601.45	119.96
6.	गोआ	4,850	1,34,895.24	27.18
7.	गुजरात	4,57,750	4,01,47,220.00	87.71
8	हरियाणा	1,34,300	88,36,724.59	65.80
9.	कर्नाटक	2,42,650	2,56,95,513.00	105 90
10.	केरल	2,13,200	2,42,50,792.29	113.75
11.	मध्य प्रदेश	1,27,800	1,10,42,207.75	86.40
12.	महाराष्ट्र	11,18,500	8,06,09,805.67	72.07
13.	उड़ीसा	57,750	41,15,532.00	71.26
14.	पाण्डीचेरी	14,750	9,75,761.00	66.15
15.	पंजाब	1,25,750	78,86,736.90	62.72
16.	राजस्थान	94,250	83,30,514.00	88.39
17.	तमिलनाडु	3,64,500	4,54,92,339.96*	124.81
18.	उत्तर प्रदेश	4,22,000	2,53,56,214.12	60.09
19.	पश्चिमी बंगाल	8,06,200	7,36,99,695.00	85.08
	योग	46,89,450	10,11,22,332.01	85.54

*अस्थायी

परिशिष्ट– 15

वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 में बीमारी तथा मातृत्व हितलाभ के दावों की घटनाएं—राज्यवार

राज्य	अवधि	बीमारी/विस्तरित बीमारी हितलाभ के लिए जोखिम-ग्रस्त माने गये कर्मचारियों की संख्या	नकद लाभ अदायगियों की कुल संख्या	प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी नकद लाभ अदायगियों की औसत संख्या।	बीमारी हितलाभ			विस्तरित बीमारी हितलाभ		प्रसूति हितलाभ	
					प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी नये अवधियों की दर	प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी बीमारी हितलाभ दिनों की संख्या औसत	औसत दैनिक दर	प्रति वर्ष प्रति 1000 कर्मचारी नये केसों की दर	प्रति समाप्त केस की औसत अवधि	प्रति वर्ष प्रति 1000 बीमाकृत महिला कर्मचारी पर माने गये प्रसव की दर	प्रति प्रसव अदा की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	1974-75	1,41,150	2,31,040	1.6	1 09	7.0	4.28	3.6	169.2	83.1	551
	1975-76	1,48,800	2,55,649	1.7	1 14	7 1	4.73	3.2	188.9	71.9	602
असम	1974-75	18,400	27,204	1.5	0.97	6.3	3.84	3.2	218.0	52.7	296
	1975-76	18,850	23,659	1.3	0.72	5.2	3 99	3.5	184.2	52.0	449
बिहार	1974-75	76,500	82,569	1.1	0.61	7.2	4.65	2 5	231.1	28.3	498
	1975-76	78,900	96,703	1.2	0.62	7.6	5.15	2.8	277.7	41.3	615
चण्डीगढ़	1974-75	7,100	2,492	0.4	0.25	2.3	4.31	1.4	80.0	82.9	613
	1975-76	7,200	10,160	0.3	0.22	1.8	5.00	0.6	300.0	32.2	668
दिल्ली	1974-75	1,27,900	60,155	0.5	0.22	2.7	4.80	4.2	230.2	15.6	601
	1975-76	1,35,050	72,691	0.5	0.26	3.8	5.86	4.4	192.3	16.4	608
गुजरात	1974-75	3,94,200	3,35,846	0.9	0.44	7.9	5.02	5.0	158.1	39.3	346
	1975-76	4,15,400	3,50,677	0.8	0.44	3.6	6.49	5.1	149.6	70.4	422
हरियाणा	1974-75	1,22,550	49,745	0.4	0.24	2.2	4.36	2.5	187.5	15.8	427
	1975-76	1,24,600	57,747	0.5	0.26	2.4	4.65	2.4	160.7	14.9	514
कर्नाटक	1974-75	2,26,300	3,41,113	1.5	1.03	7.8	4.72	2.5	171.2	62.0	696
	1975-76	2,26,750	2,78,423	1.2	0.83	5.2	5.05	2.2	175.0	57.7	709
केरल व गोवा	1974-75	1,80,050	3,94,883	2.2	1.41	10.5	3.50	3.2	167.9	51.5	370
	1975-76	1,87,900	3,53,568	1.9	1.07	6.8	4.18	3.9	165.4	123.1	398
मध्य प्रदेश	1974-75	1,26,450	2,22,010	1.8	1 01	9.7	4.83	6.3	153.1	32.6	498
	1975-76	1,22,650	2,58,964	2.1	1 20	11.2	6.42	14.2	167.8	44.9	442
महाराष्ट्र	1974-75	10,04,250	8,92,278	0.9	0.50	3.5	5.34	7.3	143.9	37.0	825
	1975-76	10,28,700	9,12,227	0.9	0.52	3.4	6.67	7.4	141.4	29.9	921
उड़ीसा	1974-75	48,650	63,267	1.3	0.83	7.4	4.11	2.3	205.3	88.6	402
	1975-76	51,950	54,462	1.0	0.65	5.6	4.49	2.3	180.6	55.4	541
पाण्डीचेरी	1974-75	11,700	34,218	2.9	1.54	10 2	5.92	2.6	122.6	37.0	1091
	1975-76	13,200	24,952	1.9	1.36	6.4	5.71	3.1	175.0	51.0	775
पंजाब	1974-75	1,06,200	46,130	0.4	0.24	2.0	3.83	2.3	160.9	14.3	408
	1975-76	1,09,750	49,064	0.4	0.25	2.0	4.12	1.6	154.5	13.2	484
राजस्थान	1974-75	80,500	76,835	1.0	0.51	4.2	4.78	4.2	171.1	49.5	493
	1975-76	85,850	73,316	0.9	0.41	3.4	5.43	5.9	159 3	33.3	775
तमिलनाडु	1974-75	3,74,550	8,51,699	2.3	1.71	10.2	5.09	3.6	154.4	41.3	494
	1975-76	3,63,700	7,99,791	2.2	1.70	8.0	6.43	2.6	153.0	41.8	657
उत्तर प्रदेश	1974-75	3,85,050	2,18,463	0.6	0.38	4.3	4.80	2.4	179.8	50.8	111
	1975-76	4,10,500	2,56,829	0 6	0.40	4.9	5.69	2.6	190.7	12.6	530
पश्चिमी बंगाल	1974-75	8,24,400	9,75,991	1 2	0.74	5.6	5.24	3.2	202.3	26.1	809
	1975-76	8,42,250	11,10,948	1.3	0.84	5.8	5.80	7.4	210.2	35.6	609
योग	1974-75	42,55,900	49,05,938	1.2	0.73	5.5	4.87	4.4	165.0	53.8	509
	1975-76	43,71,200	50,31,833	1.2	0.72	5.0	5.83	5.4	166.8	58.0	530

परिशिष्ट—16

1974-75 तथा 1975-76 में स्वीकृत अपंगता और आश्रितजन हितलाभ दावे

राज्य-वार

राज्य	अवधि	जोखिमग्रस्त माने गये कर्मचारियों की संख्या	अस्थायी अपंगता हितलाभ			स्थायी अपंगता हितलाभ				आश्रितजन हितलाभ	
			प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी नये केसों की दर	प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी अ० अ० हि० ल० दिनों की संख्या	अ० अ० हितलाभ की औसत दैनिक दर	स्वीकृत नये केसों की संख्या	प्रतिवर्ष प्रति 1000 कर्मचारी नये केसों की संख्या	एकमुश्त के लिए रूपान्तरित केसों की संख्या	वर्ष के अंत में हिताधिकारियों की संख्या	मृत्यु के स्वीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में हिताधिकारियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	1974-75	144550	0.06	0 89	4.83	409	2.83	377	476	26	382
	1975-76	176750	0.06	0 80	5.38	490	2.77	311	655	61	561
असम	1974-75	18550	0.04	0.82	4 27	53	2.86	40	103	4	73
	1975-76	21300	0 03	0 66	4.49	61	2.86	43	117	2	78
बिहार	1974-75	78050	0 03	0 77	5.13	145	1.86	53	423	7	231
	1975-76	84900	0.03	0.78	6.01	152	1.79	144	431	16	254
चण्डीगढ़	1974-75	7200	0.02	0 34	4.13	20	2.78	15	20	--	12
	1975-76	7500	0.01	0.27	4.47	11	1.47	12	19	2	8
दिल्ली	1974-75	133500	0 03	0 62	5.17	543 29द्	4.28	372	1652	16	401
	1975-76	154750	0.03	0.62	7.64	562 38द्	3.88	509	1742	18	458
गुजरात	1974-75	409050	0.07	0.89	5.78	1693 98द्	4.38	1610	1134	77	1150
	1975-76	457750	0.07	0 84	7.77	1355 106द्	3.19	1072	1523	57	1271
हरियाणा	1974-75	125250	0 04	0.70	4.64	480	3.83	415	646	16	397
	1975-76	134300	0.04	0.68	5.47	521	3.88	448	718	26	424
कर्नाटक	1974-75	226250	0.06	0.82	5 12	581 5द्	2 59	498	494	19	535
	1975-76	242650	0.06	0.73	6.03	491	2.02	324	657	18	567
केरल	1974-75	187050	0.05	0.73	5 25	342	1.8	288	409	7	501
	1975-76	214150	0 05	0.59	6.27	289	1.35	280	418	19	542
मध्य प्रदेश	1974-75	124200	0.19	3.08	6.02	208	1.67	130	592	15	440
	1975-76	127800	0 30	2.91	8.03	259	2.03	109	742	13	464
महाराष्ट्र	1974-75	1020150	0.04	0.52	6.04	3664 113द्	3.70	2381	12961	80	3196
	1975-76	1123350	0 03	0.14	7.48	3442 356द्	3.38	3461	13197	98	3352
उड़ीसा	1974-75	51850	0 05	0.78	4.26	54	1.04	56	256	5	114
	1975-76	57750	0.04	0.59	4 89	97 11द्	1 70	73	275	5	137
पाण्डीचेरी	1974-75	13000	0.10	1.16	5.88	11	0 85	8	23	—	5
	1975-76	13800	0.09	0.95	7.46	22	1.59	26	19	--	5
पंजाब	1974-75	109000	0.03	0.56	4.64	335	3.07	316	555	15	355
	1975-76	125750	0 02	0.52	5.11	421	3.35	382	591	20	391
राजस्थान	1974-76	83400	0 06	0.87	5.35	172	2.66	131	293	23	327
	1975-76	94250	0 03	0 61	5.87	214	2.27	178	329	14	332
तमिलनाडु	1974-75	363100	0.07	0.72	5.53	685 3द्	1.89	517	999	29	722
	1975-76	364500	0.05	0.52	7 23	615 4द्	1 70	818	798	20	774
उत्तर प्रदेश	1974-75	404500	0.03	0 70	5 61	319	0.79	308	3842	19	957
	1975-76	422000	0.03	0.68	7.16	440	1.04	301	3981	60	1128
पश्चिमी बंगाल	1974-75	837500	0.08	1.16	5.85	1205	1.44	2139	11601	71	1903
	1975-76	866200	0.09	1.13	6.59	6723	7.76	1019	17305	85	1935
योग	1974-75	4336150	0 06	0.85	5 64	10919 248द्	2.58	9957	36479	429	11701
	1975-76	4689450	0.06	0.77	6.91	16165 505द्	3.55	9510	43517	534	12681

परिशिष्ट–17

वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 में स्वीकृत स्थायी अपंगता हितलाभ दावे :—

उद्योगवार

उद्योग	अवधि	जोखिमग्रस्त कर्मचारियों की अनुमानित संख्या	दुर्घटनाओं के स्वीकृत केसों की संख्या	प्रति वर्ष प्रति 1000 कर्मचारी स्थायी अपंगता हितलाभ केसों की दर
1	2	3	4	5
खाद्य, पेय एवं तम्बाकू	1974-75	288028	289	1.00
	1975-76	313766	324	1.03
वस्त्र	1974-75	1692753	5715	3.38
	1975-76	1736793	9472	5.45
चमड़ा तथा रबड़	1974-75	98014	178	1.82
	1975-76	103692	273	2.63
रसायन तथा रसायनिक उत्पाद	1974-75	241767	437	1.81
	1975-76	282452	439	1.55
अधात्विक खनिज	1974-75	225696	348	1.54
	1975-76	203771	447	2.19
धात्विक खनिज	1974-75	391947	1186	3.03
	1975-76	426461	1735	4.07
इन्जीनियरी	1974-75	612542	1541	2.52
	1975-76	724157	2015	2.78
परिवहन	1974-75	273743	638	2.33
	1975-76	297656	876	2.94
कागज तथा मुद्रण	1974-75	183020	365	1.99
	1975-76	199111	449	2.26
विविध	1974-75	328640	470	1.43
	1975-75	401591	640	1.59
योग	1974-75	4336150	11167	2.58
	1975-76	4689450	16670	3.55

परिशिष्ट—18

वर्ष 1975-76 में दायर किये गये कानूनी केसों की संख्या तथा सम्बद्ध राशि—राज्य-वार

क्षेत्र का नाम	निम्नलिखित धाराओं के अन्तर्गत दायर किये गये केसों में सम्बद्ध राशि								निम्नलिखित धाराओं के अन्तर्गत की गई कानूनी कार्यवाही द्वारा वसूल की गई राशि			धारा-75 (2)/45-ख	धारा 85 के अन्तर्गत दायर किये गये केसों की संख्या
	धारा-66		धारा-67		धारा-73ब		धारा-75(2)/45ख						
	केस	राशि	केस	राशि	केस	राशि	केस	राशि	धारा-66	धारा-67	धारा-73ब		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आन्ध्र प्रदेश	--	--	—	—	43	254745	509	2765780	2200	—	431456	460680	19
आसाम	—	—	—	—	--	—	78	294220	—	—	—	132722	—
बिहार	--	—	--	--	70	538020	188	1964418	--	--	330030	426525	45
दिल्ली	--	--	--	—	9	61462	416	24520969	3567	—	82263	3056554	26
गुजरात	--	--	--	—	160	124487	93	1087442	--	--	13026	13463	185
कर्नाटक	1	2751	—	--	77	427353	427	2230824	—	--	63636	1027344	32
केरल	--	--	—	--	--	--	1375	5243976	--	--	—	1408651	80
मध्य प्रदेश	--	—	--	--	91	210558	165	1695945	28625	--	10927	67721	20
महाराष्ट्र	--	--	—	—	449	1663554	532	2594353	21963	—	485169	517836	1052
पूना	—	--	--	—	153	633342	127	654465	—	--	82629	87222	102
नागपुर	—	--	--	--	17	855237	24	1117867	--	--	16278	16456	33
उड़ीसा	--	—	—	--	9	49177	8	70906	--	--	268344	85575	9
पंजाब	—	—	--	--	101	245983	628	3366954	13781	—	962529	2443687	204
राजस्थान	--	--	--	—	009	11779	113	1445769	11225	--	1783455	118315	9
तमिलनाडु	--	--	--	—	144	971829	252	1077581	--	--	222328	305726	66
उत्तर प्रदेश	--	--	—	—	109	873435	213	1946380	--	--	1515832	5688947	23
पश्चिमी बंगाल	—	—	—	—	441	2647528	274	1846590	450	—	3498783	16926	350
योग	1	2751	--	—	1882	9570489	5422	33924439	81811	--	9766685	15884350	2255

परिशिष्ट—19

कर्मचारी राज्य

31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए

आय

गत वर्ष (1974–75)	लेखा के शीर्ष	राशि	योग
1	2	3	4
रुपये		रुपये	रुपये
	1 बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को हितलाभ		
	अ—चिकित्सा हितलाभ		
24,98,12,608	(1) चिकित्सा तथा उपचार तथा मातृत्व सुविधाओं आदि पर राज्य में होने वाले खर्चे में निगम के अंश को राज्य सरकारों आदि की अदायगी ।	30,80,17,039	
—	कम —राज्य सरकारों को वर्ष के मध्य चिकित्सा सुविधा संबंधी भुगतान जो पूंजीगत निर्माण/चिकित्सा (संचित) दायित्व आरक्षित निधि को हस्तांतरित ।	—	
24,98,12,608		30,80,17,039	
1 51,80,636	(2) चिकित्सा उपचार व सुविधा व मातृत्व सुविधाएं (निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वहन किया गया व्यय)	1 94,95,306	
26,49,93,244	कुल अ—चिकित्सा हितलाभ		32,75,12,345
	ब—नकद हितलाभ		
11,35,36,831	1 बीमारी हितलाभ	12,81 80,389	
1,1 1,56 000	2 विस्तरित बीमारी हितलाभ	1,40,17,812	
86 03,268	3 मातृत्व हितलाभ	1,02,64,553	
	4 अपंगता हितलाभ		
2,07,65,636	क अस्थायी	2,48,54,977	
3,42,19,000	ख स्थायी (पूंजीकृत मूल्य)	5,42,40 000	
93,97,000	5 आश्रितजन हितलाभ (पूंजीकृत मूल्य)	1,16,99,000	
8,96,653	6 अन्त्येष्टि हितलाभ	8 95,585	
19,88,74,388	कुल ब—नकद हितलाभ		24,41,52,346
46 38 67,632	आगे ले जाया गया योग		57 16,64,691

बीमा निगम

वर्ष की आय तथा व्यय लेखा

रुपये

गत वर्ष (1974-75)	लेखा के शीर्ष	राशि	योग
5	6	7	8
रुपये		रुपये	रुपये
	1. अंशदानों द्वारा :—		
60,34,74,995	नियोजकों तथा कर्मचारियों का अंशदान	73,15,86,339	
2,16,80,542	केवल नियोजकों का अंश	1,78,07,427	
1,00,74,058	केवल कर्मचारियों का अंश	1,00,09,537	
63,52,29,595	कुल अंशदान		75,94,03,303
22,50,000	निगम द्वारा चिकित्सा हितलाभ पर प्रारम्भिक रूप से किये गये व्यय में राज्य सरकारों/संघ राज्यों का अंश	9,94,702	
			9,94,702
—	सहायक अनुदान	—	
	राजस्व के अन्य शीर्ष		
3,47,90,454	ब्याज तथा लाभांश	4,29,03,524	
1,55,75,398	क्षति पूर्ति	64,48,911	
	किराया, महसूल तथा कर		
5,58,488	1. निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	6,91,664	
1,82,59,511	2 अस्पताल, डिस्पेंसरियां तथा स्टाफ क्वार्टर	2,47,78,048	
93,042	शुल्क, जुर्माना अधिहरण	1,69,145	
29,63,122	विविध	17,47,435	7,67,38,727
7,22,40,015	राजस्व के अन्य शीर्षों का योग		
70,97,19,610	आगे ले जाया गया योग		83,71,36,732

1	2	3	4
रुपये		रुपये	रुपये
46,38,67,632	पीछे से लाया गया योग		57,16,64,691
	स—अन्य हितलाभ		
74,890	(क) अपंग बीमाकृत व्यक्तियों के पुनर्वास पर व्यय	33,683	
2,44,176	(ख) चिकित्सा मंडल तथा अपील अधिकरण	3,15,771	
	(ग) बीमाकृत व्यक्तियों की अदायगी :—		
1,14,139	1. सरकारी शुल्क तथा/या मजदूरी की हानि	1,36,509	
—	2. परिवार नियोजन के अन्तर्गत प्रासंगिक व्यय	—	
—	(घ) सहायक अनुदान	—	
2,25,523	(ङ) विविध	2,35,854	
6,58,728	योग स—अन्य हितलाभ		7,21,817
46,45,26,360	बीमाकृत व्यक्तियों व उनके परिवारों के लिये कुल लाभ		57,23,86,508
	2. प्रशासन व्यय :		
	अ—अधीक्षण		
69,556	1. निगम, स्थायी समिति, क्षेत्रीय मंडल आदि	57,683	
1,81,013	2. प्रधान अधिकारी	2,30,286	
36,64,180	3. अन्य अधिकारी	45,15,551	
1,97,92,448	4. लिपिक वर्गीय स्थापना	2,38,73,028	
35,21,247	5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	43,07,210	
79,34,854	6. आकस्मिक व्यय	98,82,613	
3,51,63,298	योग अ—अधीक्षण		4,28,66,371
	ब—क्षेत्रीय कार्य		
9,87,722	1. अधिकारी	9,02,917	
1,99,03,554	2 लिपिक वर्गीय स्थापना	2,34,96,864	
33,81,517	3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	38,10,214	
21,55,958	4. आकस्मिक व्यय	24,51,084	
2,64,28,751	योग ब—क्षेत्रीय कार्य		3,06,61,079
52,61,18,409	आगे ले जाया गया योग		64,59,13,958

5	6	7	8
		रुपये	रुपये
70,97,19,610	पीछे से लाया गया योग		83,71,36,732

70,97,19,610	आगे ले जाया गया योग		83,71,36,732

गत वर्ष (1974-75)	लेखा के शीर्ष	राशि	योग
1	2	3	4
रुपये		रुपये	रुपये
52,61,18,409	पीछे से लाया गया योग		64,59,13,958
	म—अन्य खर्च		
2,81,330	1. विविध खर्चे	2,72,245	
29,282	2. बीमा न्यायालय	3,05,080	
26,133	3. प्रचार तथा विज्ञापन खर्चे	22,127	
61,046	4. बैंकिंग लेखा रखने के व्यय	69,319	
1,29,950	5 लेखा परीक्षा शुल्क	1,39,635	
96,818	6. छुट्टी तथा पेंशन अंशदान	1,22,199	
2,14,695	7. कार्यालयों की इमारतों/स्टाफ कारों का मूल्यह्रास	2,53,606	
4,99,829	8. कार्यालयों की इमारतों की मरम्मत व अनुरक्षण	6,28,474	
	9. अवकाश प्राप्ति हितलाभ :		
42,65,343	क. निगम के कर्मचारियों के लिये पेंशन आरक्षित निधि	40,51,493	
2,22,357	ख. क० रा० बी० निगम भविष्य निधि में निगम का अंशदान	2,51,088	
15,92,389	ग. क० रा०बी० नि० भविष्य निधि में दिया गया ब्याज	19,46,119	
—	घ. विनियोग की वसूली पर हानि	—	
—	ङ कम—भविष्य निधि के अतिशेषों के विनियोग	—	
(—) 29,59,087	द्वारा प्राप्त ब्याज	(—) 39,13,674	
12,250	10. अनुकंपा आरक्षित निधि	29,240	
	11. बीमा निधि से सम्बद्ध भविष्य निधि		
	जमा राशि	50,000	
4,506	12. विविध	8,104	
6	13 हानियाँ	—	
44,76,927	योग म—अन्य खर्चे		42,35,055
6,60,68,976	योग कुल शीर्ष—2 प्रशासन व्यय		7 77 62 505
	3 चिकित्सालय व औषधालय :		
24,83,087	1 चिकित्सालय की इमारतों का मूल्यह्रास	23,92,287	
71,00,034	2 चिकित्सालय/औषधालय की इमारतों की मरम्मत व अनुरक्षण	69,91,495	
95,83,121	योग शीर्ष—3 चिकित्सालय तथा औषधालय		93,83,782
54,01,78,457	आगे ले जाया गया योग		65,95,32,795

गत वर्ष (1974-75)	लेखा के शीर्ष	राशि	योग
1	2	3	4
रुपए		रुपए	रुपए
70,97,19,610	पीछे से लाया गया योग		83,71,36,732

70,97,19,610	आगे ले जाया गया योग	83,71,36,732

गत वर्ष (1974-75)	लेखा के शीर्ष	राशि	योग
1	2	3	4
रुपए		रुपए	रुपए
54,01,78,457	पीछे से लाया गया योग		65,95,32,795
	4. पूंजीगत निर्माण/आपात्कालीन आरक्षित निधि :		
6,35,22,960	1. पूंजीगत निर्माण	7,59,40,330	
2,12,03,639	2. आपात्कालीन आरक्षित निधि	2,03,32,720	
8,47,26,599			9,62,73,050
	कुल शीर्ष—4 पूंजीगत निर्माण/आपात्कालीन आरक्षित निधि ।		
62,49,05,056	राजस्व लेखा पर कुल व्यय		75,58 05,845
8,48,14,554	व्यय से अधिक आय को तुलनपत्र पर आगे ले जाना ।		8,13,30,887
70,97,19 610	महायोग		83,71,36,732

गत वर्ष (1974-75)	लेखा के शीर्ष	राशि	योग
5	6	7	8
रुपए		रुपए	रुपए
70,97,19,610	पीछे से लाया गया योग		83,71,36,732
70,97,19,610	महायोग		83,71,36,732

हस्ताक्षरित

(पी० एल० गुप्ता,)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

परिशिष्ट–

कर्मचारी राज्य

31 मार्च, 1976 को

पिछला वर्ष (1974-75)	दायित्व	राशि	योग
रुपए		रुपये	रुपये
	व्यय से अधिक आय का अतिशेष :		
58,13,76,353	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	66,61,90,907	
8,48,14,554	वर्ष के दौरान संचयन	8,13,30,887	
66,61,90,907		74,75,21,794	
—	कम—पिछले वर्ष के संचयन से आपात्कालीन आरक्षित निधि को हस्तांतरित राशि	—	
66,61,90,907			74,75,21,794
	पूर्जागत निर्माण आरक्षित निधि :		
14,01,15,495	आदि शेष	21,04,24,339	
—	व्यय से अधिक आय के अतिशेष से अहस्तांतरित राशि	—	
6,35,22,960	जमा—वर्ष में किया गया उपबंध	7,59,40,330	
67,85,884	विनियोजन पर प्राप्त ब्याज	1,13,02,800	
—	कम—वर्ष में किया गया भुगतान	—	
21,04,24,339			29,76,67,469
	स्थायी (आंशिक तथा पूर्ण) अपंगता हितलाभ आरक्षित निधि :		
10,01,29,732	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	11,61,23,653	
3,42,19,000	वर्ष के दौरान किया गया उपबंध	5,42,40,000	
76,42,100	विनियोग से प्राप्त ब्याज	99,05,014	
1,35,172	विनियोग की वसूली पर लाभ	—	
14,21,26,004	इस शीर्ष का आगे ले जाया गया योग	18,02,68,667	
87,66,15,246	आगे ले जाया गया योग		1,04,51,89,263

20

बीमा निगम

जैसा था—तुलनपत्र

पिछला वर्ष (1974-75)	परिसम्पत्ति	राशि	योग
रुपये		रुपये	रुपये
	भूमि तथा भवन (निगम के पूर्ण रूप से निजी) .		
	(क) निगम के कार्यालय के लिए भवन .		
1,31,76,888	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,38,46,193	
6,69,305	वर्ष के दौरान संकलन	21,42,814	
1,38,46,193		1,59,89,007	
	(ख) चिकित्सालय तथा औषधालय .		
21,80,26,815	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	23,74,66,984	
1,94,40,169	वर्ष के दौरान संकलन	2,46,70,535	
23,74,66,984		26,21,37,519	
	(ग) चिकित्सालयों आदि के लिए उपकरण .		
25,84,885	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	25,84,885	
—	वर्ष के दौरान संकलन	—	
25,84,885		25,84,885	
25,38,98,062			28,07,11,411
	भूमि व भवन (निगम तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से ली गई) में निगम का भाग।		
	(क) चिकित्सालय तथा औषधालय		
9,47,201	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	9,47,201	
—	वर्ष के दौरान संकलन	(—) 70 074	
9,47,201		8,77,127	
	(ख) चिकित्सालयों आदि के लिए उपकरण		
49,680	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	49,680	
—	वर्ष के दौरान संकलन	—	
49,680		49,680	
9,96,881			9,26,807
25,48,94,943	आगे ले जाया गया योग		28,16,38,218

पिछला वर्ष (1974-75)	दायित्व	राशि	योग
रुपये		रुपये	रुपये
87,66,15,246	पीछे से लाया गया योग	1,04,51,89,263	
14,21,26,004	इस मद में पीछे से लाया गया योग	18,02,68,667	
(–) 2,60,02,351	कम—वर्ष के दौरान अदायगी	(–) 2,93,42,742	
11,61,23,653			
	आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि		15,06,25,925
4,86,32,421	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	5,71,34,491	
93,97,000	वर्ष में किया गया उपबन्ध	1,16,99,000	
41,00,346	विनियोग से प्राप्त ब्याज	51,98,646	
1,17,785	विनियोग की वसूली पर लाभ	—	
6,22,47,552	कम—वर्ष के दौरान अदायगी	7,40,32,137	
(–) 51,13,061		(–) 57,96,685	
5,71,34,491			
	कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि		6,82,35,152
2,19,38,188	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	2,53,87,089	
	जमा – वर्ष के दौरान आकलित राशि		
65,23,706	1. कर्मचारी चंदा	78,78,103	
2,22,357	2. नियम का अंशदान	2,51,088	
15,92,389	3. ब्याज (कर्मचारी तथा निगम के अंशदान पर)	19,05,150	
5,16,519	4. मँहगाई भत्ता जमा	18,59,349	
3,07,93,159	इस मद को ले जाया गया योग	3,72,80,779	

1,04,98,73,390	आगे ले जाया गया योग	1,26,40,50,610

पिछला वर्ष (1974-75)	परिसम्पत्ति	राशि	योग
रुपये		रुपये	रुपये
25,48,94,943	पीछे से लाया गया योग		28,16,38,218
	उपान्त (1) पूंजीगत व्यय के लिये दिये गये अग्रिम राशि		
6,00,06,749	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	5,46,25,154	
—	जमा वर्ष के दौरान दी गई अदायगी	—	
(-) 53,81,595	कम -- समायोजन तथा वसूली	(--) 33,70,626	
5,46,25,154		5,12,54,528	
	(2) पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि में से दी गई अग्रिम राशि		
4,47,37,262	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	6,81,80,436	
3,96,28,100	जमा--वर्ष के दौरान की गई अदायगी	6,00,01,868	
(-) 1,61,84,926	कम -- समायोजन तथा वसूली	(--) 2,58,85,723	
6,81,80,436		10,22,96,581	
12,28,05,590			15,35,51,109
	स्टाक कारें		
3,90,759	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	4,43,407	
52,648	जमा -- वर्ष में की गई अदायगी	60,110	
4,43,407			5,03,517
37,81,43,940	आगे ले जाया गया योग		43,56,92,844

पिछला वर्ष (1974-75)	दायित्व		राशि	योग
रुपये			रुपये	रुपये
1,01,98,73,390	पीछे से लाया गया योग			1,26,40,50,640
3,07,93,159	इस उपशीर्ष के अन्तर्गत पीछे से लाया गया योग		3,72,80,779	
(—) 49,48,378	कम-वर्ष के दौरान की गई अदायगी		(—) 72,24,539	
	भ०नि०	65,05,037		
2,58,44,781	मं०भ०	7,19,502	3,00,56,240	
	कम - निम्नलिखित को हस्तांतरित राशि :			
(—) 1,57,592	1. पेंशन आरक्षित निधि		(—) 36,114	
—	2. बिना दावे के जमा		—	
2,53,87,089				3,00,20,126
	बीमा निधि से सम्बद्ध भविष्य निधि जमा :			
—	पिछले तुलनपत्र के अनुसार		—	
—	वर्ष में किया गया उपबन्ध		50,000	
—	कम – वर्ष के दौरान की गई अदायगी		—	
	निगम के कार्यालयों की इमारतों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) का मूल्यह्रास आरक्षित निधि :			
14,78,806	पिछले तुलनपत्र के अनुसार		17,92,087	
1,80,130	वर्ष में किया गया उपबन्ध		2,08,084	
1,33,151	विनियोग से प्राप्त लाभ तथा ब्याज		1,77,665	
17,92,087				21,77,836
1,07,70,52,566	आगे ले जाया गया योग			1,29,62,98,602

पिछला वर्ष (1974-75)	परिसम्पत्ति	राशि	योग
रुपये		रुपये	रुपये
37,81,43,940	पीछे से लाया गया योग		43,56,92,844
	निगम के प्रधान कार्यालयों के अध्यक्षों को स्थायी अग्रिम :		
41,038	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	51,011	
10,063	जमा - वर्ष में की गई अदायगी	6,840	
51,101		57,851	
(—) 90	कम - वर्ष के दौरान की गई वसूली	(—) 1,195	
51,011			56,656
18,734	निगम के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिए अग्रिम वेतन+आवायगी :	17,586	
83,804	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,06,651	
	जमा—वर्ष के दौरान की गई अदायगी		
1,02,538		1,24,237	
(—) 84,952	कम - वर्ष के दौरान की गई वसूली	(—) 96,422	
17,586			27,815
83,149	निगम के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिए अग्रिम यात्रा भत्ता :	91,711	
1,06,507	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,22,047	
	जमा—वर्ष के दौरान की गई अदायगी		
1,89,656		2,13,758	
(—) 97,945	कम-वर्ष में की गई वसूली	(—) 1,44,777	
(—) 91,711			68,881
37,83,04,248	आगे ले जाया गया योग		43,58,46,296

पिछला वर्ष (1974-75)	दायित्व	राशि	योग
रुपये		रुपये	रुपये
1,07,70,52,566	पीछे से लाया गया योग		1,29,62,98,602
	चिकित्सालयों की इमारतों का मूल्य ह्रास आरक्षित निधि :		
1,59,32,411	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,98,23,149	
24,83,087	वर्ष में किया गया उपबन्ध	23,92,287	
13,98,485	विनियोग से प्राप्त ब्याज	19,29,190	
9,166	विनियोग की वसूली पर लाभ या हानि	—	
1,98,23,149			2,41,44,626
	स्टाफकारों का मूल्यह्रास आरक्षित निधि :		
2,84,404	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	3,43,962	
34,565	वर्ष में किया गया उपबन्ध	45,522	
24,993	विनियोग से प्राप्त ब्याज	33,476	
3,43,962			4,22,960
	निगम के कार्यालयों की इमारतों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मरम्मत व अनुरक्षण आरक्षित निधि :		
28,44,143	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	32,69,903	
4,99,829	वर्ष में किया गया उपबन्ध	6,28,474	
1,56,253	विनियोग से प्राप्त ब्याज	2,07,034	
246	विनियोग की वसूली पर लाभ	—	
35,00,471		41,05,411	
(—) 2,30,568	कम—वर्ष में की गई अदायगी	(—) 2,11,833	
32,69,903			38,93,578
	चिकित्सालयों की इमारतों की मरम्मत व अनुरक्षण आरक्षित निधि का लेखा :		
3,47,42,825	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	4,38,57,162	
71,00,034	वर्ष में किया गया उपबन्ध	69,91,495	
24,94,428	विनियोग से प्राप्त ब्याज	35,89,108	
228	विनियोग की वसूली पर लाभ	—	
4,43,37,515	इस शीर्ष के अन्तर्गत आगे ले जाया गया योग	5,44,37,765	
1,10,04,89,580	आगे ले जाया गया शेष योग		1,32,47,59,766

पिछला वर्ष (1974-75)	परिसम्पत्ति	राशि	योग
रुपये		रुपये	रुपये
27,83,04,248	पीछे से लाया गया योग		43,58,46,296
	निगम के कर्मचारियों को वाहन क्रयण के लिए अग्रिम राशि ।		
9,62,131	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	10,07,452	
5,79,740	जमा—वर्ष में की गई अदायगी	5,81,031	
15,41,871		15,88,483	
(—) 5,34,419	कम—वर्ष के दौरान की गई वसूली	(—) 6,47,039	
10,07,452			9,41,444
	निगम के कर्मचारियों को विविध अग्रिम राशि (त्यौहार अग्रिम राशि) :		
3,63,551	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	2 49,430	
5,07,497	जमा—वर्ष के दौरान की गई अदायगी	5,90,115	
8,71,048		8,39,545	
(—) 6,21,618	कम—वर्ष के दौरान की गई वसूली	(—) 5,69,906	
2,49,430			2,69,639
	मकान निर्माण हेतु अग्रिम :		
21,23,703	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	32,96,614	
14,87,537	जमा वर्ष के दौरान की गई अदायगी	19,34,700	
36,11,240		52,31,314	
(—) 3,14,626	कम—वर्ष के दौरान की गई वसूली	(—) 5,58,417	
32,96,614			46,72,897
	राज्य सरकारों की ओर से अग्रिम राशि की अदायगी ।		
6,107	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	6,779	
6,191	जमा वर्ष के दौरान की गई अदायगी	13,389	
12,298		20,168	
(—) 5,519	कम वर्ष के दौरान की गई वसूली	(—) 5,405	
6,779			14,763
38,28,64,523	आगे ले जाया गया योग		44,17,45,039

पिछला वर्ष (1974-75)	दायित्व	राशि	योग
रुपये		राशि	रुपये
1,10,04,89,580	पीछे से लाया गया योग		1,32,47,59,766
4,43,37,515	इस शीर्ष के अन्तर्गत पीछे से लाया गया योग	5,44,37,765	
(—) 4,80,353	कम—वर्ष में की गई अदायगी	(—) 24,24,882	
4,38,57,162			5,20,12,883
	निगम के कर्मचारियों की पेंशन आरक्षित निधि		
4,13,37,616	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	4,96,82,756	
46,59,136	वर्ष में किया गया उपबन्ध	45,25,675	
36,87,266	विनियोग से प्राप्त ब्याज	49,44,749	
51,960	विनियोग की बसूली पर लाभ	—	
4,97,35,978		5,91,53,180	
(—) 5,10,914	कम—वर्ष में की गई अदायगी	(—) 6,73,813	
4,92,25,064		5,84,79,367	
4,57,692	जमा—क० रा० बी० निगम भविष्य निधि से हस्तान्तरित राशि	36,114	
4,96,82,756			5,85,15,481
	निगम के कर्मचारियों के लिये अनुकम्पा आरक्षित निधि—		
10,000	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	10,000	
12,250	वर्ष में किया गया उपबन्ध	29,240	
22,250		39,240	
(—) 12,250	कम—वर्ष के दौरान की गई अदायगी	(—) 29,240	
10,000			10,000
1,19,40,39,498	आगे ले जाया गया योग		1,43,52,98,130

पिछला वर्ष (1974-75)	परिसम्पत्ति	राशि	योग
रुपये		रुपये	रुपये
38,28,64,523	पीछे से लाया गया योग		44,17,45,039
	चिकित्सालयों/औषधालयों, निगम के कार्यालयों तथा स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत व अनुरक्षण के लिये राज्य सरकारों, राज्य लोक निर्माण विभाग आदि को अग्रिम राशि		
	(क) निगम के कार्यालय		
8,38,038	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	9,35,419	
2,23,982	जमा—वर्ष में किया गया भुगतान	7,73,394	
10,62,020		17,08,723	
(—) 11,26 601	कम—वर्ष में की गई वसूली/समायोजन	(—) 78,892	
9,35,419			16,29,831
	(ख) चिकित्सालय/औषधालय/क्लीनिकियां		
65,04,817	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	78,49,227	
13,45,175	जमा—वर्ष में किया गया भगतान	38,55,943	
78,49,992		1,17,05,170	
(—) 765	कम—वर्ष में हुई प्राप्ति	(—) 2,60,718	
78,49,277			1 14,44,452
	विविध-अग्रिम		
12,32,435	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	18,42,317	
10,11,002	जमा—वर्ष में किया गया भुगतान	10,45,288	
22,43,437		28,87,605	
(—) 4,01,120	कम—वर्ष में हुई प्राप्ति	(—) 10,97,088	
18,42,317			17,90,517
39,34,91,486	आगे ले जाया गया योग		45,66,09,839

पिछला वर्ष (1974-75)	दायित्व	राशि	योग
रुपये		रुपये	रुपये
1,19,40,39,498	पीछे से लाया गया योग :	—	1,43,52,98,130
	आपात्कालीन आरक्षित निधि :		
5,63,56,000	पिछले वर्ष के संचयन से	8,22,60,672	
2,12,03,639	वर्ष में किया गया उपबन्ध	2,03,32,720	
47,01,033	विनियोग पर वसूली किया गया ब्याज	74,22,703	
—	कम—आय से अधिक व्यय के लिए	—	
	राजस्व लेखा को हस्तांरित राशि		
8,22,60,672			11,00 16,095
	जमानत जमा :		
2,40,402	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	3,91,910	
3,19,799	जमा—वर्ष में जमा	2,82,672	
5,60,201		6,74,582	
(—) 1,68,291	कम—वर्ष में जमानत जमा की प्रति अदायगी	(-) 2,90,742	
3,91,910			3,83,840
	अन्य पार्टियों को देय बिलों से कटौती :		
38,214	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	73,830	
6,89,878	जमा—वर्ष में आंकलित राशि	8,58,697	
7,28,092		9,32,527	
(—) 6,54,262	कम—वर्ष में किया गया भुगतान	(-) 9,05,833	
73,830			26,694
	क०रा०बी०नि० भविष्य निधि में अदाबी जमा राशि :		
8,366	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	5,795	
(—) 653	जमा—वर्ष में आंकलित राशि	784	
7,713		6,579	
(—) 1,918	कम—वर्ष में किया गया भुगतान	—	
5,795			6,579
1,27,67,71,705	आगे ले जाया गया योग		1,54,57,31,338

पिछला वर्ष (1974-75)	परिसम्पत्ति	राशि	योग
रुपये		रुपये	रुपये
39,34,91,486	पीछे से लाया गया योग		45,66,09,839
	राज्य सरकारों/अन्य पार्टियों को ऋण :		
2,60,33,333	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	3,02,99,999	
54,00,000	जमा—वर्ष में किया गया भुगतान	23,58,500	
3,14,33,333		3,26,58,499	
(—) 11,33,334	कम—राज्य सरकारों द्वारा ऋण की वापसी	(—) 15,33,333	
3,02,99,999			3,11,25,166
	प्रेषित धन :		
	नकद प्रेषित धन		
(—) 66,76,000	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	8,48,061	
1,34,97,14,531	जमा—वर्ष में समायोजित विकलन	1,57,08,83,966	
1,34,30,38,531		1,57,17,32,027	
(—) 1,34,21,90,470	कम—वर्ष में समायोजित आकलन	(—) 1,57,15,33,028	
8,48,061			1,98,999
	अन्य प्रेषित धन-विनिमय लेखा :		
3,786	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	(—) 1,28,536	
5,91,67,305	जमा—वर्ष विकलन	7,00,90,766	
5,91,71,091		6,99,62,230	
(—) 5,92,99,627	कम—वर्ष में आकलन	(—) 6,98,63,584	
(—) 1,28,536			98,646
42,45,11,010	आगे ले जाया गया योग		48,80,32,650

पिछला वर्ष (1974-75)	दायित्व	राशि	योग
रुपये		रुपये	रुपये
1,27,67,71,705	पीछे से लाया गया योग		1,54,57,31,338
	परिवार नियोजन परियोजना हेतु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से ली गई जमा राशि		
—	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	—	
—	जमा—वर्ष में जमा	5,00,000	
—	कम—परिवार नियोजन परियोजना को अदायगी	(—) 5,00,000	
	विविध जमा		—
17,88,767	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	20,19,046	
10,93,435	जमा—वर्ष में प्राप्त जमा	59,10,770	
28,82,202		79,29,816	
(—) 8,63,156	कम—वर्ष में जमा राशि के प्रति अदायगी	(—) 61,54,912	
20,19,046			17,74,904
1,27,87,90,751	योग आगे ले जाया गया		1,54,75,86,242

पिछला वर्ष (1974-75)	परिसम्पत्ति	राशि	योग
रुपये		रुपये	रुपये
42,45,11,010	पीछे से लाया गया योग		48,80,32,650
	विनियोग लागत पर		
	(1) स्थायी (आंशिक तथा पूर्ण) अपंगता हितलाभ आरक्षित निधि		
10,01,27,929	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	11,61,23,101	
2,62,78,175	जमा—वर्ष में किया गया विनियोग	3,45,95,000	
12,64,06,104		15,07,18,101	
(–) 1,02,83,003	कम—विनियोग की बिक्री या परिपाक पर वसूली	(–) 95,000	
11,61,23,101			15,06,23,101
	(2) आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि		
4,86,31,507	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	5,71,32,292	
1,59,91,400	जमा—वर्ष में किया गया विनियोग	1,11,03,000	
6,46,22,907		6,82,35,292	
(–) 74,90,615	कम—विनियोग के बिक्री या परिपाक पर वसूली	—	
5,71,32,292			6,82,35,292
	(3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि		
2,19,18,000	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	2,48,70,000	
61,63,200	जमा—वर्ष में किया गया विनियोग	37,22,000	
2,80,81,200		2,85,92,000	
(–) 32,11,200	कम—विनियोग के बिक्री या परिपाक पर वसूली	(–) 2,35,000	
2,48,70,000			2,83,57,000
	(4) निगम के कार्यालयों की इमारतों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) का मूल्यह्रास आरक्षित निधि		
14,76,509	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	17,91,509	
3,15,000	जमा—वर्ष में किया गया विनियोग	3,85,000	
17,91,509		21,76,509	
—	कम—विनियोग की बिक्री या परिपाक पर वसूली	—	
17,91,509			21,76,509
62,44,27,912	आगे ले जाया गया योग		73,74,24,552

पिछला वर्ष (1974-75)	दायित्व	राशि	योग
रुपये		रुपये	रुपये
1,27,87,90,751	पीछे से लाया गया योग		1,54,75,06,242

1,27,87,90,751	आगे ले जाया गया योग	1,54,75,06,242

पिछला वर्ष (1974-75)	परिसम्पत्ति	राशि	योग
रुपये		रुपये	रुपये
62,44,27,912	पीछे से लाया गया योग		73,74,24,552
	(5) चिकित्सालयो तथा परीक्षा केन्द्रों में उपकरणों का मूल्यह्रास आरक्षित निधि		
—	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	—	
—	जमा—वर्ष में किया गया विनियोग	—	
—	कम—विनियोग की बिक्री या परिपाक पर वसूली	—	
—			
	(6) चिकित्सालयों की इमारतों का मूल्यह्रास आरक्षित निधि		
1,58,04,359	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,98,22,525	
47,23,225	जमा वर्ष में किया गया विनियोग	43,20,000	
2,05,27,584		2,41,42,525	
(—) 7,05,059	कम-विनियोग की बिक्री या परिपाक पर वसूली	—	
1,98,22,525			2,41,42,525
	(7) स्टाप कारों का मूल्य ह्रास आरक्षित निधि		
2,83,735	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	3,42,735	
89,100	जमा—वर्ष में किया गया विनियोग	80,000	
3,72,835		4,22,735	
(—) 30,100	कम—विनियोग की बिक्री या परिपाक पर वसूली	—	
3,42,735			4,22,735
64,45,93,172	आगे ले जाया गया योग		76,19,89,812

पिछला वर्ष (1974-75)	दायित्व	राशि	योग
(1)	(2)	(3)	(4)
रुपये		रुपये	रुपये
12,78,79,075	पीछे से लाया गया योग		1,54,75,06,242
1,27,87,90,751	आगे ले जाया गया योग		1,54,75,06,242

पिछला वर्ष (1974-75)	परिसम्पत्ति	राशि	योग
(1)	(2)	(3)	(4)
रुपये		रुपये	रुपये
64,45,93,172	पीछे से लाया गया योग		76,49,89,812
	(8) निगम के कार्यालयों की इमारतों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मरम्मत व अनुरक्षण आरक्षित निधि :		
19,29,994	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	23,00,240	
5,67,400	जमा वर्ष में किया गया विनियोग	(—) 37,000	
24,97,394		22,63,240	
(—) 1,97,154	कम—विनियोग की बिक्री या परिपाक पर वसूली	—	
23,00,240			22,63,240
	(9) चिकित्सालयों की इमारतों की मरम्मत व अनुरक्षण आरक्षित निधि .		
2,81,37,050	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	3,59,47,278	
78,24,800	जमा वर्ष में किया गया विनियोग	46,15,000	
3,59,61,850		4,05,62,278	
(—) 14,572	कम-विनियोग की बिक्री या परिपाक पर वसूली	—	
3,59,47,278			4,05,62,278
	(10) निगम के कर्मचारियों के लिये पेंशन आरक्षित निधि :		
4,12,31,581	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	4,96,58,541	
1,81,68,200	जमा—वर्ष में किया गया विनियोग	88,54,000	
5,93,99,781		5,85,12,541	
(—) 97,41,240	कम—विनियोग की बिक्री या परिपाक पर वसूली	—	
4,96,58,541			5,85,12,541
73,24,99,231	आगे ले आया गया योग		86,33,27,871

पिछला वर्ष (1974-75)	दायित्व	राशि	योग
(1)	(2)	(3)	(4)
रुपये		रुपये	रुपये
1,27,87,90,751	पीछे से लाया गया योग		1,54,75,06,242
1,27,87,90,751	महायोग		1,54,75,06,242

पिछला वर्ष (1974-75)	परिसम्पत्ति	राशि	योग
रुपये		रुपये	रुपये
73,24,99,231	पीछे से लाया गया योग		86,33,27,871
	(11) **पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि**		
8,20,28,000	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	11,30,28,000	
8,10,00,000	जमा—वर्ष में किया गया विनियोग	2,73,30,000	
(—) 5,00,00,000	कम—विनियोग की बिक्री या परिपाक पर वसूली	—	
11,30,28,000			14,03,58,000
	(12) **आपत्तकालीन आरक्षित निधि**		
5,60,00,000	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	8,20,00,000	
2,60,00,000	जमा—वर्ष में किया गया विनियोग	2,80,00,000	
—	कम—विनियोग की बिक्री या परिपाक पर वसूली	—	
8,20,00,000			11,00,00,000
	सामान्य रोकड़ शेष		
23,25,00,000	पिछले तुलनपत्र के अनुसार विनियोग	30,79,37,000	
19,54,37,000	जमा—वर्ष में किया गया विनियोग	22,63,63,000	
42,79,37,000		53,43,00,000	
(—) 12,00,00,000	कम—विनियोग की बिक्री या परिपाक पर वसूली	(—) 16,60,00,000	
30,79,37,000		36,83,00,000	
13,72,174	रोकड़ हाथ रोकड़	16,61,888	
4,19,54,346	बैंक के पास रोकड़	6,38,58,483	
4,33,26,520		6,55,20,371	
35,12,63,520	कुल रोकड़ अतिशेष		43,38,20,371
1,27,87,90,751	महायोग		1,54,75,06,242

हस्ताक्षरित

(पी० एम० गुप्ता)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

परिशिष्ट—21

हितलाभों के भुगतान आदि की तुलना में प्रशासनिक लागत

	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76
1. कुल प्रशासनिक लागत	3,71,91,289	4,77,39,056	4,40,34,287	7,34,57,795	6,60,68,976	7,77,62,505
2. (1) कर्मचारी तथा नियोजक अंशदान	—	—	—	20,37,86,214	60,31,74,995	73,15,86,339
(2) नियोजक विशेष अंशदान	29,55,06,981	33,34,80,630	39,61,61,207	21,41,95,502	2,16,80,542	1,78 07,427
(3) कर्मचारी अंशदान	16,49,66,819	17,70,05,192	19,16,27,812	22,76,75,964	1,00,74,058	1,00,09,537
कुल अंशदान	46,04,73,800	51,04,85,822	58,77,89,019	64,56,39,680	63,52,29,595	75,94,03,303
3. कुल व्यय (राजस्व लेखों पर खर्च)	44,74,00,835	47,61,40,297	47,23,75,970	59,90,70,572	62,49,05,056	75,58,05,845
4. कुल हितलाभ	36,68,88,880	38,16,11,406	37,13,48,489	45,14,88,325	46,45,26,360	57,23,86,508
प्रशासन व्यय का अनुपात :—						
2.	8.08%	9.35%	7.50%	7.72%	10.40%	10.24%
3	8.31%	10.03%	9 32%	8.32%	10.57%	10.29%
4.	10.14%	12.15%	11.85%	11.04%	14.22%	13.59%

नोट :—4 में राज्य सरकारों द्वारा सहन किये गये लाभ खर्च का अंश सम्मिलित नहीं है ।

[सं० जेड-16016/1/77-एच० आई०]

एस० एस० सहस्रनामन, उप सचिव

New Delhi, the 18th April, 1977

S.O. 3972.—In pursuance of Section 36 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Annual Report of Employees' State Insurance Corporation for the year 1975-76 is hereby published for general information :—

ANNUAL REPORT OF THE EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION FOR THE YEAR 1975-76

List of Members of the Employees' State Insurance Corporation, 1975-76

Chairman

Shri K. V. Raghunatha Reddy
Minister for Labour
Government of India

Vice-Chairman

Shri A. K. M. Ishaque
Deputy Minister for Health and Family Planning
Government of India

Members

Representatives of Central Government

3. Shri Balgovind Verma,
Deputy Minister of Labour,
Government of India.

4. Shri N. P. Dube,
Secretary to the Government of India,
Ministry of Labour.

5. Shri D. S. Nim,
Joint Secretary to the
Government of India,
Ministry of Labour.

6. Dr. J. B. Srivastava,
Director General of Health Services,
Government of India.

7. Shri A. K. Sen,
Joint Secretary to the
Government of India,
Ministry of Finance,
Department of Expenditure.

Representatives of State Governments

8. Shri M. R. Pai,
Secretary to the
Government of Andhra Pradesh,
Health, Housing & Municipal,
Administration Department.

9. Shri T. S. Gill,
Secretary to the
Government of Assam,
Labour Department.

10. Shri I. C. Kumar,
Secretary to the
Government of Bihar,
Labour & Employment Department.

11. Shri S. H. Jagad,
Secretary to the Government of Gujarat,
Panchayat & Health Department.

12. Shri P. P. Caprihan,
Secretary to the
Government of Haryana,
Labour & Employment Department.

13 Shri P. K. Mattoo,
Secretary to the
Government of Himachal Pradesh,
Labour & Employment Department.

14 Shri U. Mahabala Rao,
Secreary to the
Government of Kerala,
Labour Department

15. Dr. Prakash Narain,
Director, Health Services,
Government of Madhya Pradesh.

16. Shri R. Pasupathi,
Secretary to the
Government of Tamil Nadu,
Labour Department.

17. Smt Pratibha D. Patil,
Minister of Public Health,
Government of Maharashtra.

18. Shri T. J. Ramakrishnan,
Secretary to the
Government of Karnataka,
Social Welfare & Labour Department.

19 Shri Sovan Kanungo,
Secretary to the Government of Orissa,
Labour, Employment & Housing Department.

20. Shri N. K. Joshi,
Labour Commissioner &
Additional Secretary to
the Government of Rajasthan,
Labour Department.

21. Shrimati G. K. Sekhon,
Secretary to the
Government of Punjab,
Health & Family Planning Department.

22. Shri K. N. Srivastava,
Commissioner-cum-Secretary to the
Government of Uttar Pradesh,
Department of Labour.

23. Shri R. N. Sengupta,
Secretary to the
Government of West Bengal,
Labour Department.

Representatives of Union Territories

24. Shri K. D. Gupta,
Labour Commissioner & Ex-Officio
Secretary (Labour)
Delhi Administration.

Representatives of Employers

25. Shri D. P. Mukherjee.

26. Shri R. N. Joshi.

27. Shri Madan Mohan Mangaldas.

28. Shri P. Chentsal Rao.

29. Prof. V. K. Kamath.

Representatives of Employees

30. Shri T. N. Siddhanta.

31. Miss. E. D'Souza.

32 Shri Bishnu Banerjee.

33. Shri K. Rengasamy.

34 Shri Ram Desai.

Representatives of Medical Profession

35. Dr. J. Majumdar.

36. Shri Kaviraj Keshav Prasad Attey.

Representatives of Parliament

37. Shri D. Y. Pawar.

38. Shri S M. Banerjee.

39. Shri Raja Kulkarni.

Ex-Officio Member

40. Shri T. N. Lakshmi Narayanan,
Director General,
E.S.I. Corporation.

List of Members of the Standing Committee of the E.S.I. Corporation, 1975-76.

Chairman

Shri Balgovind Verma

Deputy Minister for Labour,

Government of India

Members

Representatives of Central Government

2. Shri N. P. Dube,
Secretary to the
Government of India,
Ministry of Labour.

3. Dr. J. B. Srivastava,
Director General of Health Services.

4. Shri A. K. Sen,
Joint Secretary to the
Government of India,
Ministry of Finance,
Department of Expenditure.

Representatives of State Governments

5. Shri T. J. Ramakrishnan,
Secretary to the
Government of Karnataka,
Social Welfare & Labour Department,
Bangalore.

6 Smt. Pratibha D. Patil,
Minister for Public Health,
Government of Maharashtra.

7. Shri R. N. Sen Gupta,
Secretary to the
Government of West Bengal,
Labour Department.

Representatives of Employers

8. Shri R. N. Joshi.

9 Shri P. Chentsal Rao.

10. Prof. V. B. Kamath.

Representatives of Employees

11. Shri T. N. Siddhanta.

12. Shri Bishnu Banerjee.

13. Shri Ram Desai.

Representative of Medical Profession

14. Dr. J. Majumdar.

Representative of Parliament

15. Shri Raja Kulkarni.

Ex-Officio Member

16. Shri T. N. Lakshmi Narayanan,
Director General, E.S.I. Corporation.

List of Members of the Medical Benefit Council, 1975-76

Chairman

Dr. J. B. Srivastava

Director General, Health Services.

Members

Representatives of Central Government and the Corporation

2. Dr. Sharad Kumar,
Deputy Director General of
Health Services (Medical).

3. Medical Commissioner, E.S.I. Corporation

Representatives of State Governments

4. Dr. T. N. Sanghi,
Deputy Director of Medical & Health Services,
Government of Andhra Pradesh.

5. Shri B. L. Das,
Administrative Medical Officer,
E.S.I. Scheme,
Government of Assam.

6. Dr. S. K. Verma,
Administrative Medical Officer,
Government of Bihar.

7. Dr. H. N. Patel,
Director of Medical Services,
(E.S.I. Scheme)
Government of Gujarat.

8. Dr Hakumat Roy,
Assistant Director, Health Services,
(Social Insurance),
Government of Haryana.

9. Dr. Krishan Swaroop,
Director of Health Services,
Government of Himachal Pradesh

10. Dr. B. V. Puttaraj Urs,
Director of Health and Family Planning
Services,
Government of Karnataka.

11 Dr. T. N. N. Bhattathiripad,
Administrative Medical Officer, E.S.I. Scheme.
Government of Kerala.

12 Dr. P. S. Dave,
Administrative Medical Officer,
(E.S.I. Scheme),
Government of Madhya Pradesh.

13. Dr. R. C. Dighe,
Director E.S.I. Scheme,
Government of Maharashtra.

14. Dr. P. C. Rath,
Administrative Medical Officer,
E.S.I. Scheme,
Government of Orissa.

15. Dr. Sohan Singh,
Director of Healtht & Family Planning,
Government of Punjab.

16. Dr. B. M. Sharma,
Additional Director,
Medical & Health Services (Family Planning),
Government of Rajasthan.

17. Dr. P. R. Balakrishnan,
Director of Health Services and
Family Planning,
Government of Tamil Nadu.

18. Shri M. K. Aggarwal,
Joint Director of Health Services,
E.S.I. Scheme,
Government of Uttar Pradesh.

19. Shri S. S. Mukherjee,
Director, E.S.I. (M.B.) Scheme,
Government of West Bengal.

Representatives of Employers

20. Dr. Surendra Pranlal Shah.

21. Shri R. N. Joshi.

22. Shri R. L. Moitra.

Representatives of Employees

23. Shri S. W. Dhabe.

24. Dr. T. Rajagopal.

25. Dr. G. Kannabiran.

Representatives of Medical Profession

26. Dr. D. S. Munagakar.

27. Dr. Narendra Nath Bhattacharjee.

28. Vaidya Lilavati Patel.

"ESIC" AT A GLANCE

	31-3-75	31-3-76	Progress During 1975-76
States	18	18	..
Centres	365	388	23
Employees	43,85,000	51,50,000	7,65,000
Insured Persons	47,75,000	56,00,000	8,25,000
Family Units	47,54,150	55,84,050	8,29,900
Insured Women	3,46,550	4,35,450	88,900
Total Beneficiaries	1,84,66,950	2,16,82,050	32,15,100
Employees Yet to be Covered	6,65,000	7,25,000	60,000
Cash Offices	613	653	40
Inspection Offices	121	114	(—)7
ESI Hospitals	57	57	—
ESI Annexes	25	24	(—)1
Beds			
(a) ESI Hospitals	9,255	10,631	1,376
(b) ESI Annexes	467	465	(—)2
(c) Reserved	3,302	4,204*	902
Total	13,024	15,300*	2,276
S.I. Dispensaries	804	864*	60
I.M.Os. & I.M.Ps.	6,348	7,121*	773

CAPITAL CONSTRUCTION (RUPEES IN LAKHS)

Sanctioned Upto	5,486.00	6,974.98	1,488.98
Advanced Upto	4,080.01	4,663.14	583.13
Income & Outgo	1974-75	1975-76	
Revenue Income	7,097.20	8,371.37	
Revenue Expenditure	6,249.05	7,558.06	

*Provisional.

1. ACHIVEMENTS

Extension of the Scheme

1.1 The most significant step taken during the year was the enhancement in the wage limit for coverage of employees under the ESI Scheme from Rs. 500 to Rs. 1000 p.m. by the ESI Amendment Act, 1975 with effect from 30 November, 1975, thereby bringing about 8 lakhs additional employees under coverage, including a large number of those employees who had gone out of coverage due to progressive rise in wages during the recent years. The other salient features of the Amendment Act, 1975 which came into force during the year are as follows :—

(a) The Table of contributions and corresponding daily standard benefit rates in the First Schedule of the Principal Act has been revised due to enhancement of the monthly wage limit for coverage from Rs. 500 to Rs. 1,000. In the revised Table, the employees in receipt of average daily wage below Rs. 2 have been exmpted from payment of employee's contribution. Previously, this limit was Rs. 1-50 ps. The rate of daily standard benfit rate has also been increased in the case of employees in receipt of average daily wages below Rs. 2, Rs. 12 and above but below Rs. 15, Rs. 16 and above.

(b) Provision has been made for imposition of enhanced and more deterrent penalties for defaults in payment of contributions and imprisonment has been made a compulsory punishment for failure to pay contributions payable under the Act. Provisions have also been made for enhanced punishment in certain cases after previous conviction for the same offence, recovery of damages by the Corporation as arrears of land revenue from a defaulting employer for failure to pay the amounts due in respect of any contributions or any other amount payable under the Act, and empowering the courts to make orders requiring the defaulting employers to pay the amount of contributions within a specified period.

(c) Provision has been made that in case of transfer of a factory or establishment in whole or in part by sale, gift, lease or licence or in any other manner whatsoever, the transferer and the person to whom the factory or the establishment is so transferred, shall jointly and severally be liable to pay the amount due in respect of any contributions or any other amount payable under the Act in respect of the periods upto the date of such transfer.

(d) The maximum monthly salary limit for creation of posts by the Corporation without sanction of the Central Government has been raised from Rs. 500 to Rs. 1,200.

While the provisions relating to the enhancement of the wage ceiling and revised Table of contribution and standard benefit rates have been brought into force from 30-11-75, all other provisions have been brought into force from 1-9-75.

Extension to new classes of establishments

1.2 (a) During the year under report, the Scheme was further extended to the new classes of establishments in different centres in the States of Kerala, West Bengal, Assam, Bihar, Rajasthan, Karnataka, Uttar Pradesh and Union Territories of Pondicherry and to some additional classes of establishments in Delhi from different dates covering an estimated number of about 67,400 employees. Details are given in Appendix 1, Part B.

(b) The Families of these employees also become entitled to medical care on expiry of 13 weeks.

1.3 The State Governments of Punjab, Madhya Pradesh Orissa, West Bengal and Union Territory of Goa, Daman and Diu issued preliminary notifications giving six month's notice of their intention to extend the Scheme to new classes of establishments. The Central Government also notified their intention to extend the provisions of the Act to the hotels owned by the India Tourism Development Corporation Ltd. and to the Delhi Transport Corporation and the Scheme was expected to be extended to those establishments after expiry of six months' notice period.

Implementation in new areas

1.4 The Scheme was implemented to cover additional 39,700 employees (excluding the employees in the sub-centres which have been included in the main centre as shown in the Appendix-1) in 44 new areas in the States of Assam, Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal and in the Union Territory of Goa, Daman and Diu. Details are given in Appendix I, Part A. Efforts were continuing for early extension of the Scheme in the State of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Meghalaya and Tripura where the Scheme has not been implemented in any centre so far.

1.5 At the close of the year, the Scheme was in force in 388 centres in various States and Union Territories of Chandigarh, Delhi, Pondicherry and Goa, Daman and Diu covering a total number of about 51,50,000 employees (including employees covered in new classes of establishments).

Extension of medical care to families

1.6 Medical care was extended to additional 41,650 family (I.P.) units (i.e., about 1,19,950 additional beneficiaries) excluding the number of families (I.P) in the sub-centres which have been included in the main centre as shown in the Appendix-1 in 52 areas in the States of Assam, Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal and Union Territory of Goa, Daman and Diu. Details are given in Appendix-1, Part-A. The Total number of family units covered for medical care at the close of the year was about 55,84,050 (i.e. 2,16,82,050 beneficiaries comprising insured persons and their families including those covered in new classes of establishments and on account of increase in wage ceiling.)

2. HOSPITALISATION :

(i) ESI Hospitals and Annexes already constructed.

The ESI Hospital, Kansbahal (Orissa) with 50 beds was commissioned on 21-1-76. ESI Hospital at Gandhi Nagar, Kottayam (Kerala) with 80 General beds was sold out to the Government of Kerala on 14-7-75, as the same was not required for the purposes of the Corporation. Thus the No. of commissioned ESI Hospitals remained 57. In addition, 24 ESI Annexes were functioning under the ESI Scheme on 31-3-76 as 16 bedded ESI ward at Rajgangpur was later reported to have not been commissioned.

The position with regard to beds constructed in these institutions is as under :—

Type of projects	No. of projects	No. of beds constructed		
		Genl.	T.B.	
Hospitals . . .	57	9,236	1,395	
Annexes	24	183	282	
Total . . .		9,419+	1,677	=11096

Details of these hospitals and annexes are given in appendix II.

(ii) ESI Hospitals and Annexes under construction.

The following hospitals and annexes were under constrction :—

S. No.	Place and State	No. of beds		Remarks
		Genl.	T.B.	
1	2	3	4	
HOSPITALS :				
1.	Gwalior (M.P.) .	75	..	
2.	Andheri (Maharashtra).	600	..	
3.	Washi (Maharashtra) .	600	..	

1	2	3	4	5
4.	Ulhasnagar (Maharashtra)	100	..	
5.	Kandivalli (Maharashtra)	624	..	
6.	Manicktolla (West Bengal)	400	..	
7.	Kanyapur-Asansol (West Bengal)	..	150	
8.	Thakurpukur (West Bengal)	..	250	
9.	Mangalore (Karnataka)	100	..	
10.	South Madras (Tamil Nadu)	500	.	
11.	Pondicherry	50	.	
12.	Naini (Allahabad) (U.P.)	100	..	
ANNEXES :				
(i)	Cauverynagar (Tamil Nadu)	10	..	
(ii)	Hissar (Haryana)	12	..	
(iii)	Sonepat (Haryana)	12	..	
(iv)	Gulbarga (Karnataka)	20	..	
(v)	K.G.F. Roberts Sonpett (Karnataka)	32	..	
(vi)	Rajgangpur (Orissa)	16	..	

(iii) ESI Hospitals and Annexes sanctioned.

The following hospitals and annexes have been sanctioned :—

HOSPITALS :

S. No.	Place and State	No. of beds	
		Genl.	T.B.
(i)	Thana (Maharashtra)	300	..
(ii)	Bandel (West Bengal)	..	250
(iii)	Ghaziabad (U.P.)	100	..
(iv)	Lucknow (U.P.)	100	..
(v)	Agra (U.P.)	100	..
(vi)	Mysore City (Karnataka)	100	..
(vii)	Jaykaypore (Orissa)	25	..
(viii)	Baroda (Gujarat)	200	..
(ix)	Surat (Gujarat)	150	..
ANNEXES :			
(i)	Bhiwani (Haryana)	20	..
	Total	1095+	250=1345

(iv) 171 State Insurance Dispensaries were commissioned at the close of the year, all over the country. In addition, 18 more dispensaries were at the different stages of construction all over the country at the close of the year.

(v) The amount sanctioned as on 31-3-76 towards Capital construction under the Scheme it as under :—

Category of the Projects	Amount sanctioned as on 31-3-75	Amount sanctioned as on 31-3-76
	(Rupees in Lakhs)	
(a) Hospitals/Annexes/Dispensaries/ Equipment and Staff Quarters, Etc.	4603.50	6020.43
(b) Loan to the Govt. of Maharashtra	334.00	357.58
(c) Grant-in-Aid	100.00	100.00
(d) Offices and Staff Quarters of the Corporation	448.50	496.97
Total	5486.00	6974.98

3. Type of medical care to families of insured persons

The State-wise position in regard to the type of medical care provided to family (I.P.) units is given in Appendix III.

COMMISSIONS, COMMITTEES AND CONFERENCES

4. Corporation :

The E.S.I. Corporation held three meetings on 25 April, 1975, 20 July, 1975 and 28 February, 1976. Important decisions arrived at these meetings are given in Appendix IV.

5. Standing Committee :

The Standing Committee of the E.S.I Corporation held four meetings on 2 June, 1975, 16 September, 1975, 20 December, 175 and 27 February, 1976. Important decision arrived at these meetings are given in Appendix V.

6. Medical Benefit Council

The Medical Benefit Council held two meetings on 22-12-1975 and 24-2-1976. Important recommendation of the Council are given in Appendix VI.

7. Regional Boards

At the end of the year, Regional Boards were constituted in all the States. The number of meetings of various Regional Boards held during the year is given below :

Name of Regional Board	Number and date of the meetings	Name of Regional Board	Number and date of the meetings
Andhra Pradesh	.. ..	Pondicherry	4 17-4-75, 25-8-75, 23-12-75 & 12-3-76
Assam	2 11-4-75 & 9-8-75		
Bihar	3 4-8-75, 2-12-75 & 9-3-76	Orissa	3 25-4-75, 10-8-75 & 26-11-75
Delhi	3 15-7-75, 13-8-75 & 8-1-76		
Gujarat	2 6-8-75 & 16-12-75	Rajasthan	4 10-7-75, 18-8-75, 5-9-75 & 1-12-75
Haryana	2 19-8-75 & 23-10-75		
Karnataka	3 2-4-75, 18-8-75 & 7-12-75	Tamil Nadu	3 1-4-75, 22-8-75 & 20-12-75
Kerala	3 14-7-75, 26-8-75 & 13-2-76		
Madhya Pradesh	3 13-8-75, 21-9-75 & 9-3-76	Uttar Pradesh	3 2-5-75, 23-7-75 & 2-9-75
Maharashtra	3 2-7-75, 7-8-75 & 22-11-75	West Bengal	3 29-4-75, 12-8-75 & 17-12-75
Punjab	2 25-8-75 & 9-3-76		

8. Local Committees

Under Regulation 10-A of the E.S.I. (General Regulations, 1950 at the close of the year, 194 Local Committees had been constituted throughout the country.

9. The details of the work done by Medical Service and allocation Committee during the year under report is as under :

Sl. No.	Name of the State	No. of meetings	No. of cases brought on the list	No. of cases pending
1	2	3	4	5
1.	Gujarat	2	18	..
2.	Gr. Bombay	5	16	..
3.	Western Maharashtra	6	29	.
4.	Punjab	4	6	..
5.	West Bengal	Nil	Nil	.

10. General Purposes Sub-Committee

During the year under report, General Purposes Sub-Committee of the Employees' State Insurance Corporation visited Andhra Pradesh from 8 March 1976 to 12 March 1976 and inspected various ESI Institutions functioning in the State.

ADMINISTRATION

11. Regional Organisation

15 Regional Offices, 2 Sub-Regional Offices, 287 Local Offices, 94 Miniature Local Offices, 3 Sub-Local Offices, 269 Pay Offices and 114 Inspection Offices were functioning in all the States and the Union Territories as on 31 March 1977.

12. Strength of Staff

The total authorised strength of officers and staff (excluding D.M.D's Office/E.S.I. Hospital, Delhi) in the Corporation as on 31 March, 1976 was 7,920 as against 7,752 as on 31 March 1975. The staff authorised for Headquarters Office and various Regional Offices as on 31 March 1976 is shown in Appendix VII (Part I). The staff authorised for the office of Directorate (Medical) Delhi and E.S.I. Hospital, Delhi is shown in Part II of the Appendix VII.

13. Confirmation of Staff

The approval of the Central Govt. to the creation of permanent posts in Class I and II categories of staff for the year 1974-75 has since been received and action for confirmation against these posts is already under process. The confirmations of Class III and IV staff have been made against the sanctioned posts in most of the Regional/Offices. Action is being taken for confirmation of staff in the remaining offices.

14. O. & M. Studies

During the year, the O & M Division continued its Project Studies in several functional areas, including Work-Measurement Study of selected Local Offices in the country for evolving norms and standards for the various functionaries in the Local Offices in the country, job analysis in the Hqrs. Office and also job analysis of IDCs & UDCs in the Regional Offices of the Corporation for refixing the ratio for LDCs & UDCs. These studies were conducted with the representative of the Federation as an observer.

During the year the O. & M. Division conducted a work-study (method study) of the revenue recovery branches of Regional Offices and systematised methods for coverage of factories/establishments and other matters connected therewith. Procedure for recovery of contributions in cash, instead of through Contribution Stamps was also worked out and the system was introduced in Delhi on an experimental basis.

During the year final decisions on work studies conducted by O. & M. Division in respect of (i) Recasting of Annual Report and Statistical Abstarct (ii) Revision of proforma for Monthly Progress Report from Regional Offices (iii) Weeding out of old Declaration Forms (iv) Standard, for scrutiny of Inspection Reports by Insurance Inspectors and (v) Elimination/simplification of a number of forms used in Regional Offices were also taken.

15. Suggestion Award Scheme

The Central Committee which has been set up under "Suggestion Award Scheme" to scrutinise the suggestions for grant of awards—awarded Rs. 125 to Shri P.S. Krishmachary, Head Clerk, Regional Office, Tamil Nadu, for his suggestion to use the Benefit File Covers (rendered surplus on introduction of ledger system) as file covers in Regional Office which resulted in economy.

16. Training of Officers and Staff

During the year under report, the Central Training Institute started functioning at Headquarters Office and 4 Zonal Training Institutes were also set up with their Headquarters at Delhi, Calcutta, Bombay and Bangalore.

Training Programmes are now being conducted regularly at different centres. For the Local Office Managers and Insurance Inspectors 4 Training Courses were conducted at New Delhi, Bombay, Calcutta and Trichur in which 91 officials participated.

In November 1975, an Orientation Training Course was organised at New Delhi for the Officers of mid-management level of the Corporation, viz., Dy. Regional Directors/Account Officers/Assistant Regional Directors etc. Apart from discussions on procedures under the ESI scheme and related problems, the Officers received lectures on some modern management techniques during the Course.

For the officials of the rank of Lower Division Clerks/Upper Division Clerks/Head Clerks 24 training courses were conducted at various centres in which training was imparted to 569 employees.

In March 1976, a Training Course on Vigilance Methods was conducted at Headquarters Office in which 29 Officials of different categories drawn from Headquarters Office, Directorate (Medical) Delhi and various Regional Offices were imparted comprehensive training to meet the increasing demand of vigilance in all the offices of the Corporation. Services of experts in the field of vigilance from the Department of Personnel and Administrative Reforms, the Central Vigilance Commission etc. and two ex-Directors of the Institute of Secretariat Training and Management were requisitioned for this Course.

17. Publicity

A number of talks and discussions in different languages were broadcast over various stations of All-India Radio. Lectures were also delivered by the officers of the Corporation to the workers and trainees at different centres.

Apart from the above, news items giving progress of the Employees' State Insurance Scheme were published in many important newspapers in English and regional language.

A close liaison continued to be maintained with all the parties concerned in order to ensure smooth working of the ESI Scheme. Doubts of employers, insured persons and Trade Union representatives, who approached Corporation Offices were also removed and necessary guidance rendered,

COVERAGE

18. No. of employees etc. covered (Appendices VIII & IX)

Appendices VIII and IX give particulars regarding coverage under the Scheme (including additional sectors of employment) About 34,384 employers stood covered under the scheme as on 31-3-76 as against 27,444 a year back, of these about 32,04 employers were in the implemented centres; the corresponding number last year being 25,654 and the remaining 1,980 employers in areas yet to be implemented. The total number of employees in the implemented centres was about 51.50 lakhs; the number of employees in the areas yet to be covered was about 7.25 lakhs. The number of insured persons entitled to medical treatment was about 56.00 lakhs and the number of family (insured persons) units about 55.84 lakhs. In all, the total number of beneficiaries (including the insured persons) entitled to medical treatment on 31-3-76 was estimated at about 216.82 lakhs.

19. Improvement in the Standard of Medical Care ;

19.1 Provision of hospital beds for inpatient treatment

During the year 1975-76, 548 additional beds were provided in the following E.S.I. Hospitals :—

(i) E.S.I. Hospital, Sanatnagar (A.P.)	100
(ii) E.S.I. Hospital, Vijaywada (A.P.)	20
(iii) E.S.I. Hospital, Delhi	40
(iv) E.S.I. Hospital, Faridabad (Haryana)	102
(v) E.S.I. Hospital, Rajajinagar (Karnataka)	50
(vi) E.S.I. (Genl.) Hospital, Nanda Nagar Indore	51
(vii) E.S.I. (Chest) Hospital, Indore	35
(viii) E.S.I. Hospital, Worli (Maharashtra)	100
(ix) E.S.I. Hospital, Kansabahal (Orissa)	50

In the E.S.I. Hospitals at Maithon (Bihar), Ezukone (Kerala) and Ujjain (M.P.), the number of beds were reduced from 110, 150 and 65 to 100, 25 and 40 respectively.

The total number of beds provided under ESI Scheme as on 31-3-1976 was 14303 the details of which are given in Appendix—X.

19.2 During the year under report, percentage of occupancy and the average recurring cost per bed per day of the E.S.I. Hospitals was as under :

Name of the Hospital	No. of beds provided				Percentage of occupancy during the year 1975-76	Cost per bed per day during the year 1975-76
	Genl.	Mat.	T.B.	Total		
1	2	3	4	5	6	7
Andhra Pradesh						
1. E.S.I. Hospital, Sanatnagar Hyderabad	235	45	30	310	61%	40.97
2. E.S.I. Hospital, Sirpur, Kagaznagar	60	..	..	60	93%	26.17
3. E.S.I. Hospital, Vijayawada	86	..	10	96	95%	25.83
4. E.S.I. Hospital, Warangal	20	10	..	30	160%	20.51
5. E.S.I. Hospital, Adoni	25	..	..	25	180%	17.70
6. E.S.I. Hospital, Visakhapatnam	39	2	9	50	94%	21.94
Bihar						
7. E.S.I. Hospital, Maithon	100	..	..	100	63%	27.35
8. E.S.I. Hospital, Monghyr	30	..	..	30	47%	16.32
9. E.S.I. Hospital, Dalmianagar	50	..	..	50	68%	21.75
Delhi						
10. E.S.I. Hospital, Basaidarapur	286	54	..	340	84%	28.92
Gujrat						
11. E.S.I. Hospital Bapunagar, Ahmedabad	500	..	..	500	67%	36.47
12. E.S.I. Hospital, Naroda, Ahmedabad	..	..	200	200	75%	18.82
Haryana						
13. E.S.I. Hospital, Faridabad	170	..	12	182	52%	17.80
14. E.S.I. Hospital, Jagadhri	60	..	..	60	47%	31.20
15. E.S.I. Hospital, Panipat	15	..	35	50	52%	34.85
Karnataka						
16. E.S.I. Hospital, Rajajinagar, Bangalore	335	35	44	414	90%	26.40
17. E.S.I. Hospital, Dandeli	24	..	..	24	112%	11.45

1	2	3	4	5	6	7
Kerala						
18. E.S.I. Hospital Mulakunathakavu (Trichur Distt.)	..	..	100	100	82%	20.40
19. E.S.I. Hospital, Asramam (Quilon Distt.)	80	20	..	100	120%	21.65
20. E.S.I. Hospital, Allepey	51	4	..	55	99%	22.93
21. E.S.I. Hospital, Paroorkada (Trivandrum Distt).	50	..	..	50	158%	20.77
22. E.S.I. Hospital, Trichur	55	5	..	60	127%	18.35
23. E.S.I. Hospital, Udhyogmandal (Distt. Ernakulam)	112	8	..	120	86%	21.51
24. E.S.I. Hospital, Ernakulam	40	10	..	50	64%	26.03
25. E.S.I. Hospital, Vadavathur (Distt. Kottayam)	50	..	..	50	78%	15.56
26. E.S.I. Hospital, Paripally.	100	..	..	100	102%	16.77
27. E.S.I. Hospital, Ezhukone	25	..	..	25	143%	14.60
Madhya Pradesh						
28. E.S.I. Hospital (General) Indore	150	..	..	150	99%	25.30
29. E.S.I. Hospital (Chest) Indore	..	..	75	75	132%	11.10
30. E.S.I. Hospital, Ujjain	40	..	..	40	160%	16.00
Maharashtra						
31. M.G.M. Hospital, Bombay	671	14	15	700	99%	34.13
32. E.S.I. Hospital, Mulund Bombay	60	..	300	360	76%	37.05
33. E.S.I. Hospital, Worli Bombay	325	25	..	350	62%	46.38
34. E.S.I. Hospital, Nagpur	130	20	..	150	101%	24.65
35. E.S.I. Hospital, Aundh Poona	200	..	120	320	51%	30.41
Orissa						
36. E.S.I. Hospital Choudwar	44	6	..	50	N.A.	27.00
37. E.S.I. Hospital, Kansabahal	50	..	..	50	N.A.	48.84
38. E.S.I. Hospital, Brijraj nagar	25	..	..	25	N.A.	52.50
Punjab						
39. E.S.I. Hospital, Amritsar.	100	25	..	125	50%	44.12
40. E.S.I. Hospital, Ludhiana	56	24	..	80	63%	46.34
41. E.S.I. Hospital, Jullundur	48	12	..	60	50%	42.15
Rajasthan						
42. E.S.I. Hospital, Jaipur	87	26	..	113	80%	36.54
Tamil Nadu						
43. E.S.I. Hospital, Madras	486	100	39	625	90%	29.68
44. E.S.I. Hospital, Coimbatore	250	25	25	300	118%	29.43
45. E.S.I. Hospital, Madurai	140	50	12	202	103%	18.19
Uttar Pradesh						
46. E.S.I. Hospital, Pandunagar, Kanpur	212	..	..	212	97%	20.67
47. E.S.I. Azad Nagar, Kanpur (Chest Hosp.)	..	..	180	180	99%	24.81
48. E.S.I. Hospital, (Maternity and General) Kanpur	74	70	..	144	100%	24.08
49. E.S.I. Hospital, Modinagar	70	24	6	100	98%	25.72
West Bengal						
50. E.S.I. Hospital, Sealdah	250	..	..	250	82%	26.82
51. E.S.I. Hospital, Kumarhatti	171	4	..	175	86%	25.22
52. E.S.I. Hospital, Baltikuri	400	16	..	416	56%	23.18
53. E.S.I. Hospital, Serampore	150	16	..	166	97%	21.17
54. E.S.I. Hospital, Kalyani	266	..	..	266	72%	24.90
55. E.S.I. Hospital, Uluberia	166	..	..	166	91%	22.89
56. E.S.I. Hospital, Ballur-Bally	..	..	150	150	91%	23.99
57. E.S.I. Hospital, Gourhati	147	19	..	166	74%	23.50
58. E.S.I. Hospital, Budge-Budge	150*	..	..	150	57%	17.98

*Out of 300 beds sanctioned 150 beds have been commissioned.

20. Particulars in respect of Dispensaries, Specialists, Insurance Medical Officers/Insurance Medical Practitioners and Ambulance as on 31-3-1976 are shown in appendix X.

21. Provision of Artificial Limbs to Insured Persons

During the year under report, 69 cases were provided with artificial limbs. In all, 796 Insured Persons had been or were being fitted or refitted with artificial limbs so far under the Scheme.

22. Provision of artificial dentures

During the year under report artificial dentures free of cost were provided to 7 Insured persons who had lost their teeth due to employment injury. In all, 56 Insured Persons had been provided with Artificial Dentures so far under the Scheme.

23. Provision of Spectacles

During the year under report, spectacles free of cost were provided to 4 Insured persons who suffered loss of vision due to employment injury.

PROVISION OF MEDICAL BENEFIT

24. Attendances at Dispensaries and Hospitals and home visits. (Appendix XI and XII)

24.1 Statistics relating to (a) the attendances per annum per 1000 insured persons and also per 1000 family (insured person) Units, (b) the number of home visits in respect of Insured persons and families and (c) the number of cases (i) admitted in hospitals and (ii) refered for specialist investigations in respect of insured persons are given in these Appendices. These figures are based on returns furinshed primarily by the Dispensaries and Panel Practitioners. For working out the rates of medical attendances, the number of insured persons family (Insured person) units attached to the reporting Dispensaries Clinics only are deemed to be "exposed".

24.2 During the year under report, the All India rate of new attendances per 1000 insured persons decreased from 3367 in 1974-75 to 3078; the number of old attendances per 1000 insured persons has also registered a decrease from 6,404 in 1974-75 to 6,008. This year, the proportion of old attendances to new has been 1.95 against 1.90 experienced in 1974-75.

24.3 The All-India rate of new attendances per 1000 family units increased from 3,226 in 1974-75 to 3,309; the number of old attendances per 1000 family units has registered a decrease from 6,574 in 1974-75 to 6,431. The proportion of old attendances to new has, however, decreased from 2.04 during 1974-75 to 1.94 during 1975-76.

24.4 The total number of home visits in respect of insured persons has decreased by about 9 per cent compared to that in 1974-75. In respect of families, decrease is about 32 per cent. The incidence of home visits as measured by the number of visits per 1000 insured persons has shown a decrease from 73 in 1974-75 to 60 in 1975-76.

24.5 The total number of cases admitted in hospitals has shown an increase from 1,89,912 in 1974-75 to 2,11,269 in 1975-76. The number of cases referred for Specialists' investigation has also registered an increase from 9,79,257 in 1974-75 to 10,75,341 in 1975-76.

25. Sickness Pattern (Appendix XIII)

25.1 Information on the sickness pattern for the country as a whole expressed as number of new cases per 1000 insured persons exposed, is indicated in this Appendix for each of 51 cause groups, separately for the insured workers and members of their family.

25.2 The incidence rates for all cause groups taken together is lower in 1975-76 than in 1974-75 in respect of insured persons and higher in number of their families. For every spell in respect of an insured person, there has been this year 1,075 fresh spells in respect of the members of the family of an insured person as against 0.958 in the year 1974-75. When it is borne in mind that as against one insured person, there are 2.88 family members, the incidence of morbidity, as measured by incidence of new cases, continues to be lower among members of the family of the insured persons when compared with the insured persons themselves.

25.3 Cause group-wise incidence of sickness in respect of insured persons bears a close resemblance to the corresponding rates experienced by members of the family of insured persons for almost all the diseases listed. However, wide deviation in incidence in a few cause-groups only, bring out in high relief the peculiar ailments to which the particular group (viz. insured persons or families) is comparatively more prone.

OTHER MATTERS RELATING TO MEDICAL BENEFIT

26. Medical Referee

The following is a detailed statement of full-time and part-time Medical Referees posted at the end of the year for duties in the respective states alongwith the number of cases disposed off by them.

Sl. No.	Name of the State	No. of Medical Referees		No. of cases disposed off during the year 1975-76
		Part-time	Full-time	
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	10	..	7604
2.	Assam	5	..	695
3.	Bihar	5	..	2811
4.	Chandigarh Administration	1	..	18
5.	Delhi	.	1	2165
6.	Goa	..	..	..
7.	Gujarat	13	2	25471
8.	Haryana	12	..	1445
9.	Karnataka	15	..	12893
10.	Kerala	8	1	6373
11.	Madhya Pradesh	13	..	12369
12.	Maharashtra—			
	Gr. Bombay	3	3	21611
	Nagpur Area	8	..	4726
	Western Maharashtra	2	..	1999
13.	Orissa	5	..	1851
14.	Punjab	10	..	1409
15.	Rajasthan	12	..	2679
16.	Tamil Nadu	2	1	4889
17.	Pondicherry	1	..	596
18.	Uttar Pradesh	17	.	1409
19.	West Bengal	7	5	27618
	Total	149	13	140631

27. Expenditure on the provision of Medical Benefit payments authorised to State Governments.

During the year under report a sum of Rs 30,54 77,703 74 P was authorised by the Corporation for payment to the State Governments against its share of the expenditure on the provision of medical benefit under the E S I Scheme The break up of the above amount is as under —

		Rs P
1	Final payment for 1970-71	3 72,132 70
2	Final payment for 1971-72	19,32,392 52
3	Final payment for 1972-73	57,17,681 07
4	Final payment for 1973-74	41 84 011 40
5	Final payment for 1974-75	34,29,486 05
6	"On Account" Payment for 1974-75	1,28,25,000 00
7	"On Account" Payment for 1975-76	27,70,17,000 00
	Total	30,54,77,703 74

Estimated expenditure incurred by the State Governments alongwith per capita cost is detailed in Appendix XXV

28. Measures for control over expenditure on medical care.

The Corporation has entered into Rate Contract with manufacturers of drugs in respect of 530 medicines, injection and drugs during the year under report The Rate Contracts have been communicated to the State Governments for their operation

29. Agreement between the State Government and the ESI Corporation under Section 58(3) of the E.S.I. Act, 1948.

S No	Name of the State Govt with whom negotiations were going on for signing of the agreement during the year	Latest action taken or proposed to be taken
1	Govt of Uttar Pradesh .	The agreed draft deed of agreement has been sent to the State Govt for execution
2	Govt of Maharashtra .	Final draft deed of the agreement has been received and action is being taken for execution
3	Govt of Gujarat	Agreement has been signed

IMPROVEMENTS IN SERVICE TO INSURED PERSONS

30. Efficiency in the working of Local Offices

During the year under report, Ledger System was in operation in 266 out of 287 Grade I and II Local Offices in the country, the Teller System was also working in 44 Local Offices on an experimental basis

31. Improvement in the Cash Benefit

In all hard cases of disablement where the estimated disablement is likely to be more than 25 per cent immediate cash relief is afforded in the form of provisional payments up to 75 per cent of the benefit estimated to be due by authorising payment straightaway in anticipation of regular assessment in due course by Medical Board Necessary adjustment of dues is effected subsequently when the award of the Medical Board is known

The operation of this procedure which was extended from year to year has now been adopted permanently

32. Other Improvements

32 1 The Corporation at its meeting held on 28-2 76 and in supersession of its earlier Resolution dated 22 3-69 regarding grant of Extended Sickness Benefit decided that a common list of 21 diseases be drawn for the payment of Extended Sickness Benefit Initially the Extended Sickness Benefit will now be paid for 124 days which may be extended upto 309 days in chronic suitable cases by R D M C /Medical Referee/ A M O /Chief Executive of the ESI Scheme of the State or his nominee Payment beyond 124 days would be made on confirmation from the above authorities -

List of diseases

1 Tuberculosis
2 Leprosy
3 Mental diseases (psychoses)
4 Malignant diseases
5 Paraplegia
6 Hemiplegia
7 Chronic congestive heart failure
8 Immature cataract with vision 6/60 or less in the affected eye
9 Lung Abscess
10 Bronchiectasis
11 Myocardial infarction
12 Dislocation and prolapse of intervertebral disc
13 Parkinson's disease
14 Aplastic Anaemia
15 Cirrhosis of Liver with ascites
16 Detachment of Retina
17 Non-union OR delayed union of fracture
18 Empyema
19 Intra-cranial space occupying lesion
20 Spinal cord compression
21 Chronic (Simple) Primary glaucoma

Apart from the above diseases, the Medical Commissioner can sanction the payment of E S B for a maximum period of 124 days or 309 days depending upon the merits of the case on the recommendation of the above authorities, in cases of any rare disease or special circumstances

32 2 The Extended Sickness Benefit rate has been enhanced by 25 per cent more than the Standard rate rounded to the next higher multiple of 5 paise applicable when the Sickness Benefit was last payable This increase in the rate, has however, taken effect from 1-4 76

32 3 The Corporation at its meeting held on 20-7 75 decided to pay conveyance allowance and/or compensation for loss of wages to Insured Persons called to appear before a Medical Appeal Tribunal in cases filed by the Corporation or the Insured Person, at the same scale and subject to the same conditions as are applicable in cases where the Insured Person appears before the Medical Board The present rate of conveyance charges is 35 paise per K M Where, however, the Insured Person is not fit to travel by bus or other ordinary means of conveyance or needs an attendant, the Insured Person may be paid the actual charges incurred by him at a rate not exceeding 65 paise per K M Likewise, where an Insured Person has lost wages on account of attendance at a meeting of the Medical Appeal Tribunal, he shall be paid by way of compensation a day's wages or half a day's wages for each day or days on which he lost wages depending on whether more or less than half a day's wages are lost subject to the maximum of the daily rate of Temporary Disablement Benefit under the 1st Schedule of the E S I Act, 1948 (highest wage group)

CASH BENEFITS

(Appendix XV to XVII)

33. Number of cash benefit payments (Col. 4 of Appendix XV)

33 1 Cash Benefits are paid at the Local/Miniature/Sub-Local/Pay Offices set up by the Corporation in different areas The number of such offices was about 653 on 31 March 1967 as against 613 a year earlier

33.2 The total number of cash benefit payments made in each State during the years 1974-75 and 1975-76 is shown in column 4. In all, about 50.32 lakhs payments (including 9,510 claims relating to lump sum payments in respect of requests for commutation of permanent disablement claims) were effected during the year 1975-76. These were about 1.26 lakhs more than those during the preceding year. On the average, about 4.19 lakhs payments were effected every month as against 4.09 lakhs payments during 1974-75. The number of payments per employee during 1975-76 was the same as that during 1974-75 viz. 1.15.

34. Sickness Benefit (Cols. 3 and 6 to 8 of Appendix XV)

34.1 As a result of the implementation of the benefit provisions of the Scheme in new centres and to new sectors of employment between 1 July 1974 and 30 June 1975 and also due to the increase in employment in the already implemented areas, an additional 1,15,300 employees became eligible for sickness benefit during the year under report. The total number of employees entitled to claim sickness benefit during 1975-76 is estimated at 43.71 lakhs as against 42.56 lakhs last year (vide column 3).

34.2 During the year, an amount of Rs. 1281.80 lakhs was paid as sickness cash benefit as against Rs. 1135.37 lakhs in 1974-75.

34.3 The average number of fresh spells per employee has decreased from 0.73 in 1974-75 to 0.72 in 1975-76; the average number of benefit days per annum per employee has also shown a decrease from 5.5 in 1974-75 to 5.0 in 1975-76. The amount of daily rate of benefit per employee has increased from 4.87 in 1974-75 to 5.83 in 1975-76

34.4 As in the preceding years this year also witnessed wide variations among the States inter se in respect of incidence and duration of sickness benefit claims. The Director General has, however, been keeping continuous watch over the duration of sickness claims at various Centres. The relevant statistics received at the Headquarters every month are analysed periodically, and any abnormal variation in the trend in any centre is taken up with the Regional Directors and Administrative Medical Officers with a view to enable them to take suitable and prompt remedial measures whenever necessary and possible.

34.5 Excessive sickness benefit under Section 58(2).

The incidence of Sickness Benefit payment to Insured Persons has been found to exceed the all India average in certain States. The excessive Sickness Benefit for the year 1974-75 has been shared between the Corporation and the State Governments as under :—

Name of the State Govt.	Total excess S.B. amount paid in the State (Actual)	State Govt's share of excess over all India Average
Andhra Pradesh	8,94,317	22,503
Bihar	6,21,656	44,964
Karnataka	24,83,186	3,40,523
Kerala	31,35,597	12,32,604
Madhya Pradesh	25,53,002	8,65,034
Orissa	3,91,984	39,378
Pondicherry and Mahe	3,32,519	1,21,233
Tamil Nadu	89,31,529	33,45,985

35. Extended Sickness Benefit (Cols. 9 and 10 of Appendix XV).

35.1 Insured Persons suffering from certain specified diseases, e.g., Tuberculosis, Leprosy, Mental and Malignant diseases etc. are eligible for Extended Sickness cash benefit for an extended period beyond 56 days of sickness benefit.

35.2 For the year 1975-76 a sum of Rs. 140.18 lakhs was paid to insured persons on this account as against Rs. 114.56 lakhs in the previous year.

35.3 The incidence of extended sickness benefit claims expressed as the number of claims per 1,000 employees exposed to risk and also the duration of terminated claims are shown for the years 1974-75 and 1975-76 in columns 9 and 10.

36. Maternity Benefit (Cols. 11 and 12 of Appendix XV).

36.1 The number of women employees eligible for maternity benefit has increased from 3,13,750 in 1974-75 to 3,30,050 in 1975-76. The total amount paid as maternity claims was Rs. 102.65 lakhs, as against 86.03 lakhs in 1974-75. The average amount of cash benefit per maternity claim has increased from Rs. 509 in 1974-75 to Rs. 536.

36.2 The number of claims per 1000 insured women employees has increased from 53.8 in 1974-75 to 58.0 in 1975-76.

37. Temporary Disablement Benefit (Cols. 3 to 6 of Appendix XVI).

During the year 1975-76 the number of employees exposed to employment injury was 46.89 lakhs as against 43.36 lakhs during 1974-75 (vide col. 3). The sum paid as temporary disablement benefit during 1975-76 was Rs. 248.55 lakhs as against Rs. 207.66 lakhs in 1974-75. The average number of fresh spells and the number of benefit days per annum per employee and the average benefit rate are 0.06, 0.77 and Rs. 6.91 respectively as against corresponding figures of 0.06, 0.85 and Rs. 5.64 in 1974-75 (vide cols. 4 to 6). The average duration per spell has decreased from 14.67 to 13.19. As in the last year, this year also recorded variations in different States in the incidence and duration of these claims.

38. Permanent Disablement Benefit (Cols. 7 to 10 of Appendix XVI).

38.1 The number of fresh cases admitted during the year 1975-76 was 16,670 as against 11,167 during the previous year. The incidence per 1000 insured employees increased to 3.55 from 2.58 in 1974-75. The State of West Bengal has experienced a significantly high incidence.

38.2 The number of claimants on the Fund increased from 36,479 at the beginning of the year to 43,517 at the end (vide column 10). The actual amount disbursed as benefit was Rs. 296.43 lakhs (including the commuted amount of Rs. 176.59 lakhs) as against Rs. 260.02 lakhs (including the commuted amount of Rs. 161.39 lakhs) in 1974-75.

38.3 The Capitalised value of Permanent Disablement Benefit Claims in respect of fresh cases admitted during the year was Rs. 542.40 lakhs as against Rs 342.19 lakhs in 1974-75. The Permanent Disablement Benefit Reserve Fund stood at Rs. 1506.26 lakhs at the close of the year, the corresponding amount at the beginning of the financial year being Rs. 1161.24 lakhs.

38.4 The number of claimants to Permanent Disablement Benefit who have opted for receipt of commuted value in lieu of periodic payments has decreased from 9,957 in 1974-75 to 9,510 in 1975-76.

39. Permanent Disablement Benefits claims (Appendix XVII)

39.1 Analysis of 16,670 cases of permanent disablement admitted during the year was made according to (a) the main groups of industry and (b) the incidence of claims per 1000 employees exposed industry-wise. As in the last year the highest number of accidents was recorded in 'Textiles' followed at a distance by 'Engineering' and 'Metallic Minerals'. The incidence is high in 'Textiles' and 'Metallic Minerals' and low in 'Food Beverages and Tobacco'. From a comparison of the corresponding incidence for the year 1974-75, it is observed that the incidence experienced this year bears a close resemblance to that experienced last year in most of the industries.

39.2 The average degree of permanent disablement experienced was 9.83 per cent as against 9.48 per cent for the last year. The largest number of accidents occurred in the eighth wage group i.e., between the daily wages of Rs. 8 and Rs. 15.

39.3 The number of permanent disablement benefit cases that arose among women employees is only 278. The incidence is low presumably because women are not generally employed on hazardous occupations, duties, etc.

40. Dependants' Benefit (Cols. 11 and 12 of Appendix XVI).

40.1 The number of fresh claims admitted for Dependants' Benefit during the year under review increased from 429 in 1974-75 to 534 (vide columns 11 and 12). Compared to the previous year, the incidence is higher. The total number of dependants admitted during the year was 1337.

40.2 The category-wise distribution of all the dependants as at the beginning and end of the year is as under :—

Description	As on 31 March	
	1975	1976
Widow	3,702	4,052
Son and Daughter	6,317	6,727
Father	493	578
Mother	696	769
Other Dependant children	493	555
Total	11,701	12,681

40.3 The amount paid as dependants benefit has increased from Rs. 51.13 lakhs in 1974-75 to Rs. 57.97 lakhs in 1975-76. The Capitalised value in respect of dependants' benefit claims admitted during the year was 116.99 lakhs as against Rs. 93.97 lakhs in 1974-75. The Dependants' Benefit Reserve Fund stood at Rs. 682.35 lakhs on 31 March 1976 as gainst Rs. 571.34 lakhs on 31 March 1975.

CONTRIBUTION AND ENFORCEMENT

41. Income from Contributions

During the year 1975-76, total amount collected was Rs. 75,94,03,303.21.

42. Mode of Collection of Contributions

Mainly contributions are collected in the form of E.S.I. Stamps which are sold through branches of our Bankers. Contributions are also received by franks 38 new Licences were issued and 18 were cancelled during the year under report bringing the total to 739 for the use of Franking Machines for franking contribution cards : Besides this, the system of payment of contributions in cash has also been introduced on an experimental basis in Delhi Regional with effect from 30-11-75.

43. Inspection

During the year under report, progress of the inspection work continued to be under the close watch of the Headquarters' Office. Inspectors continued to provide guidance and training to employers and their staff in maintaining record and complying with the various provisions of the E.S.I. Act and Regulations framed thereunder.

At the end of the year, there were in all 242 Insurance Inspectors (200 regular plus 42 leave reserve). The total number of inspections carried out during the year was 23822.

44. Employees' Insurance Courts

New Employees Insurance Courts have been set up in the following States during the year 1975-76 :

State	Place
Maharashtra	Satara
Madhya Pradesh	Durg
	Sudhar
	Bilaspur

45. Legal Action

The amount involved in respect of Court/Revenue Recovery cases instituted during the year as also the amount recovered under the various sections of the E.S.I. Act, is shown Region-wise in Appendix XVIII.

BUDGET AND FINANCE

46. Financial and accounting arrangements

46.1 The Revised Estimates for the year 1975-76 and Budget Estimates for the year 1976-77 were adopted by the Corporation at its meeting held on the 28 February 1976 and approval of the Central Government was communicated on the 1 April 1976. These were laid on the Tables of Rajya Sabha/Lok Sabha on 2-4-1976 and 8-4-1976 respectively.

46.2 The audit of the accounts of the Corporation has been entrusted by the Central Government to the Accountant General, Central Revenues, New Delhi in consultation with the Comptroller and Auditor General of India. The former conducts the audit through the respective States' Accountants General acting as Sub-Audit Officers. The consolidated Audit Report is prepared by the Accountant General, Central Revenues. The consolidated Audit Report for the year 1972-73 in respect of the Accounts of the E.S.I. Corporation was forwarded by the Accountant General, Central Revenues to the Central Government on 8-1-1976 and the same was received in the E.S.I. Corporation on 15-1-1976. The Report has been examined and the Audited Accounts of the E.S.I. Corporation for the year 1972-73 will be submitted to the Standing Committee/E.S.I. Corporation for adoption. Thereafter, these will be forwarded to the Central Government for being placed on the Tables of Lok Sabha and Rajya Sabha.

47. Banking Arrangements

Twenty five Banking accounts were opened against four closed during the year for the offices of the Corporation with the branches of the State Bank of India, its subsidiaries and with Nationalised banks. The total number of Bank accounts with the State Bank of India, its subsidiaries and with nationalised banks stood at 436 as on 31 March 1976.

Arrangements for the sale of E.S.I. Contribution Stamps were made with 26 more branches of the State Bank of India and its subsidiaries. The total number of branches handling the sale of contribution stamps was 408 as on 31 March 1976.

48. Investments

There was an investment of Rs. 30,79,37,000 in General Cash Balance at the beginning of the year. During the year, investments aggregating Rs. 34,90,00,000 were made in the Term Deposits of the State Bank of India out of which Rs. 16,60,00,000 were realised and Deposit Receipts worth Rs. 12,26,37,000 were transferred to various reserve fund accounts against their annual investment, thus leaving a balance of Rs. 36,83,00,000 as investment in General Cash Balance at the end of the year.

The Total investment under the various reserve funds and General Cash Balance as on 31 March 1976 stood at Rs. 99,39,53,222.33 as against Rs. 81,09,53,222.33 at the beginning of the year.

Details of the investments are given below :—

	As on 1-4-1975	As on 31-3-1976
	Rs.	Rs.
1. Securities of Central and State Govts. in India	3,32,94,442.33	3,32,94,442.33
2. 12-year Postal Certificates	21,15,000.00	—
3. Fixed Deposit with State Bank of India	77,55,43,780.00	96,06,58,780.00
Total	81,09,53,222.33	99,39,53,222.33

49. Income and expenditure accounts and balance Sheet

The Income and Expenditure Account for the year 1975-76 and Balance Sheet of the Corporation as on 31 March 1976 are given in Appendix XIX and XX respectively. These have not been audited by External Auditors. The accounts for the year 1974-75 have also been audited, but audit certificate is still awaited from the A.G.C.R., New Delhi.

50. Relative cost of administration

The statement of Appendix XXI shows the relative cost of Administration since the year 1970-71. The comparative cost of administration during the past five years (1971-72 to 1975-76) judged with reference to cost of benefit, amount of contributions collected, ratio of ESIC staff to insured employees and the number of cash benefits payments is indicated below :—

	1971–72	1772–73	1773–74	1974–75	1975–76
No. of Cash Benefit payments per ESIC Employee	780	627	701	633	635
Contributions, collected per ESIC Employee	Rs. 68,192	Rs. 79,334	Rs. 86,154	Rs. 81,944	Rs. 95,872
Ratio of Administrative Expenditure to total benefits	12.51%	11.86%	11.04%	14.22%	13.59%
Ratio of Administrative Expenditure to total Contribution	9.35%	7.50%	7.72%	10.40%	10.24%
No. of ESIC staff per lakh insured employees	192	182	177	171	154

Definition of the terms 'Employees' 'Insured Persons' and 'Beneficiaries'

(a) The number of the 'employees' as on a specified date is the estimated number of effective posts in the factories covered under the scheme. This would broadly represent the average number of employees per day employed by the factories round about that date and normally may not vary significantly from the number of employees actually employed on that date. It should, however, be noted that the actual number of persons who have occupied a particular sanctioned post during a period may be more, in as much as a leave reserve or badli worker may have officiated temporarily during absence, leave etc. of a regular worker.

(b) The number of 'insured persons' on any date indicates, for purposes of this Report, the number of persons who may be deemed to be entitled to medical benefit on such date. Further the number of 'insured persons' on any day would noramlly be in excess of the number of 'employees' as on that day because, under the eligibility conditions for medical benefit under the Act the persons entitled to medical benefit on any day would comprise not only the persons actually employed on that day but also the ex-employees, who by virtue of the contribution conditions during the period earlier to that would be entitled to such benefit on that date.

(c) The total number of 'beneficiaries' on any date represents all the persons who may be deemed to be entitled to medical benefit under the Scheme on that date. It comprises the 'insured persons' and where medical benefit has been extended to families of insured persons, the member of their families. The total number of members of the family of insured persons (not including the insured person) is arrived at by assuming an average of 2.88 members, for each 'insured person'.

APPENDIX-I

Extension of ESI Scheme during 1975-76

Part—A—Implementation in new areas

State	Centre Area	Date of implementation	No of employees as on 31-3-76	Medical care for families	
				Date of extension	No. family (I.P.) units covered)
1	2	3	4	5	6
Assam	Chandrapur	—	—	22-6-1975	1,100
	Margherita	21-12-1975	1,050	21-3-1976	1,100
	Jogighopa	1-2-1976	800	To be covered on expiry of 13 weeks	—
Andhra Pradesh	Anthergaon	—	—	29-6-1975	1,000
	Basantnagar	—	—	29-6-1975	1,050
	Sriramnagar	13-7-1975	2,500	12-10-1975	2,650
	Gopalapatnam	28-9-1975	500	28-12-1975	550
	Outskirts of Rajahmundry	26-10-1975	Included in Rajahmundry	25-1-1976	Included in Rajahmundry
	Outshirts of Cuddapah	29-2-1976	included in Cuddapah	To be covered on expiry of 13 weeks.	—
Goa, Daman and Diu	Panaji Bicholim, Margoa, Xeldem and Marmagao.	5-10-1975	10,000	4-1-1976	11,200
Gujarat	Hasanpur	29-2-1976	Included in Wankaner	To be covered on expiry of 13 weeks	—
Haryana	Dhulkot	14-9-1975	850	14-12-1975	950
	Bahalgarh (includes Bahalgarh Road).	25-1-1976	1,900	To be covered on expiry of 13 weeks	—

1	2	3	4	5	6
Karnataka	Kengeri	—	—	27-4-1975	included in Bangalore
	Shimoga	—	—	25-5-1975	550
	Hoskote Road	—	—	29-6-1975	
	Sarakki	—	—	29-6-1975	included in Bangalore
	Konanakunte	—	—	29-6-1975	
	Dyavasandra	28-9-1975	included in Bangalore	28-12-1975	included in Bangalor
	Outskirts of Bellary	25-1-1976	included in Bellary	to be covered on expiry of 13 weeks.	—
Kerala	Pangappara	27-4-1975	250	27-7-1975	250
	Chettivilakom	27-4-1975	50	27-7-1975	50
	Kidangur	27-4-1975	50	27-7-1975	50
	Changanacherry	27-4-1975	1,000	27-7-1975	1,050
	Wadakkancherry	27-4-1975	300	27-7-1975	300
	Cheruthuruthy	27-4-1975	100	27-7-1975	100
	Mullurkara	27-4-1975	200	27-7-1975	200
	Pattambi	27-4-1975	200	27-7-1975	200
	Mayyanad	27-4-1975	300	27-7-1975	300
	Ollurkara	27-4-1975	200	27-7-1975	200
	Nettissery	27-4-1975	100	27-7-1975	100
	Kumaranellur	27-4-1975	50	27-7-1975	50
	Karamuck	28-12-1975	100	28-3-1976	100
	Vadanappally	28-12-1975	150	28-3-1976	150
	Nattika	28-12-1975	300	28-3-1976	300
	Veluthur	28-12-1975	50	28-3-1976	50
Maharashtra	Talegaon	28-12-1975	2,500	28-3-1976	2,650
	Dehu Cantonment	28-12-1975		28-3-1976	
	Dehu Village	28-12-1975		28-3-1976	
	Lonavala	28-12-1975		28-3-1976	
	Khandkala	28-12-1975		28-3-1976	
	Madhavnagar	1-2-1976	1,000	to be covered on expiry of 13 weeks.	—
	Chikhalthana	1-2-1976	5,700	do.	—
Orissa	Rourkela (excluding Hindustan Steel Ltd.)	10-8-1975	2,500	9-11-1975	2,800
	Jajpur Road	28-3-1976	1,500	to be covered on expiry of 13 weeks.	—
Punjab	Mohali	25-1-1976	2,500	do.	—
Rajasthan	Chittorgarh	—	—	29-6-1975	1,600
	Bechhwal	27-7-1975	(included in Bikaner)	26-10-1975	included in Bikaner
Tamil Nadu	Mellur	—	—	22-6-1975	300
	Attur	—	—	22-6-1975	600
	Karur	—	—	22-6-1975	1,300
	Ambur	—	—	22-6-1975	2,450
	Karamadai	—	—	22-6-1975	1,700
	Nandambakkam	—	—	22-6-1975	included in Madras City
	Thiruvanmiyur	13-4-1975	included in Madras City	13-7-1975	included in Madras City
	Thoraipakkam	13-4-1975	-do-	13-7-1975	do.
Uttar Pradesh	Suburbs of Naini	—	—	22-6-1975	included in Allahabad
	Najibabad	—	—	22-6-1975	1,400
West Bengal	Haringhata	27-7-1975	1,200	26-10-1975	1,300
	Ranaghat	27-7-1975	1,300	26-10-1975	1,400
	Chakdah	27-7-1975	500	26-10-1975	550

PART—B—EXTENSION TO NEW CLASSES OF ESTABLISHMENTS

State	Centres	Date of Extension	Establishments covered	No. of employees (provisional estimated figures)	Medical care to families (Date of extension)
1	2	3	4	5	6
Kerala	Revenue villages of Mayanad in Quilon Taluk of Quilon District of Kerala State	27-4-75	Non-power cashew processing factories employing 20 or more persons.	1,600	27-7-75
West Bengal	City of Calcutta Howrah District Hooghly District 24-Paraganas Distt. Kalyani Notified Area	27-4-75	(a) Smaller power using factories employing 10 to 19 persons ; and (b) Non-power using factories employing 20 or more persons.	19,000	27-7-75
Kerala	All other districts of Kerala State except Quilon District	27-7-75	Non-power using cashew processing factories employing 20 or more workers.	3,100	26-10-75
Assam	Charduar, Dhubri Dibrugarh, Gauhati includes suburbs of Gauhati, Jeypore, Jorhat, Mariani Tejpur and Tinsukia includes (i) Makum (ii) Outskirts of Tinsukia.	3-8-75 & 17-8-75	(a) Power using factories employing 10 to 19 persons; (b) Non-power using factories employing 20 or more persons; (c) Hotels, Restaurants, Shops, Cinemas including preview theatres, Road Motor Transport Establishments and Newspaper Establishments, employing 20 or more persons.	3,042	2-11-75 & 16-11-75
Bihar	Monghyr, Katihar, Samastipur, Dalmianagar, Japla, Mokameh, Marhowrah, Ramgarh, Adityapur and Kumardhubi	17-8-75	(a), (b) and (c) -do-	4,000	16-11-75
Rajasthan	Alwar ,Ajmer, Bikaner, Jaipur, Jodhpur Kota, Sriganganagar and Udaipur.	26-10-75	-do-	8,000	25-1-76
Karnataka	(i) Bangalore City and Suburbs.	29-2-76	Hotels and Restaurants employing 20 or more persons.	5,500	To be covered on expiry of 13 weeks.
	(ii) Cundapur,Channa Patna, Chitradurga, Dandeli, Devangere, Gokak, Gulbarga, Harihar, Hospet, Dharwar, Kollegal, Kollar Gold Fields, Kanakpura, Nanjangud and T. Narsipur.	29-2-76	(a) Small power using factories employing 10 to 19 persons; (b) Non-power using factories employing 20 or more persons; (c) Hotels, Restaurants, Shops, Cinemas including preview theatres, Road Motor Transport Establishments and Newspaper Establishments employing 20 or more persons.	8,000	To be covered on expiry of 13 weeks.

Uttar Pradesh	Ghaziabad (includes Ghaziabad suburbs), Kanpur (includes Kalyanpur) and Modinagar.	7-3-76	(a) Power using factories employing 10 to 19 persons ; (b) Non-power using factories employing 20 or more persons; (c) Hotels, Restaurants, Shops, Cinemas including preview theatres, Road Motor Transport Establishments and Newspaper Establishments employing 20 or more persons.	9,500	To be covered on expiry of 13 weeks.
Union Territory of Pondicherry	The areas of Pondicherry Municipal limits and Oulgaret commune Panchayat, of the Union Territory of Pondicherry.	29-2-76	(a), (b) & (c) Do.	650	To be covered on expiry of 13 weeks.
Union Territory of Delhi	Whole of Union Territory of Delhi	27-3-76	Road Motor Transport Establishments and Newspaper Establishments employing 20 or more persons.	5,000	To be covered on expiry of 13 weeks.

Appendix II

E.S.I. Hospitals and Annexes

Hospitals

S. No.	State	Place	No of beds		Remarks
			Genl.	T.B.	
1	2	3	4(i)	4(ii)	
(i)	Andhra Pradesh	Hyderabad	310	—	
(ii)	Do.	Sirpurkagaz Nagar	110	—	
(iii)	Do.	Vijaywada	86	10	
(iv)	Do.	Warrangal	50	..	
(v)	Do.	Adoni	50	..	
(vi)	Do.	Visakhapatnam	110	..	
(vii)	Bihar	Maithon	110	..	
(viii)	Do.	Monghyr	30	..	
(ix)	Do.	Dalmianagar	50	..	
(x)	Delhi	Delhi	340	..	
(xi)	Gujarat	Bapunagar Ahmedabad	500	..	
(xii)	Do.	Naroda Ahmedabad	..	200	
(xiii)	Haryana	Faridabad	170	..	
(xiv)	Do	Yamuna Nagar	60	..	
(xv)	Do.	Panipat	15	35	
(xvi)	Kerala	Mulakunathakavu	..	100	
(xvii)	Do.	Asramam	100	..	
(xviii)	Do.	Alleppey	55	..	
(xix)	Do.	Peroorkada	50	..	
(xx)	Do.	Trichur	60	..	
(xxi)	Do.	Udyogmandal	120	..	
(xxii)	Do.	Ernakulam	50	..	
(xxiii)	Do.	Vadavathur	50	..	
(xxiv)	Do.	Paripally	100	..	
(xxv)	Do.	Ezhukone	150	..	
(xxvi)	Madhya Pradesh	Indore	150	..	
(xxvii)	Do.	Indore	..	75	
(xxviii)	Do.	Ujjain	50	15	
(xxix)	Maharashtra	M.G.M. Bombay	700	..	
(xxx)	Do	Worli	470	..	
(xxxi)	Do.	Nagpur	150	..	
(xxxii)	Do.	Mulund	60	540	

1	2	3	4(i)	4(ii)	
(xxxiii)	Maharashtra	Aundh	410	..	
(xxxiv)	Karnataka	Rajajinagar Bangalore	380	40	
(xxxv)	Do.	Dandeli	24	..	
(xxxvi)	Orissa	Choudwar	50	..	
(xxxvii)	Do.	Kansbhal	50	..	
(xxxviii)	Punjab	Amritsar	125	..	
(xxxix)	Do.	Ludhiana	80	..	
(XL)	Do.	Jullunder	60	..	
(XLi)	Rajasthan	Jaipur	113	..	
(XLii)	Tamil Nadu	Madras	600	25	
(XLiii)	Do.	Coimbatore	500	..	
(XLiv)	Do.	Madurai	177	25	
(XLv)	Uttar Pradesh	Kanpur (Chest Hosp)	..	180	
(XLvi)	Do.	Kanpur (Maternity)	144	..	
(XLvii)	Do.	Kanpur	212	..	
(XLviii)	Do.	Modinagar	100	..	
(XLix)	West Bengal	Sealdah	250	..	
(L)	Do.	Kamarhati	175	..	
(Li)	Do.	Bellur-Bally	..	150	
(Lii)	Do.	Serampore	166	..	
(Liii)	Do.	Uluberia	166	..	
(Liv)	Do.	Bankra	416	..	
(Lv)	Do.	Kalyani	266	..	
(Lvi)	Do.	Gourhati	166	..	
(Lvii)	Do.	Budge-Budge	300	..	
		Total	9,236	1,395	=10,631

ANNEXES

S. No.	State	Place	No. of beds		Remarks
			Genl.	T.B.	
(i)	Andhra Pradesh	Irrumnumma	..	24	
(ii)	Bihar	Itki	..	20	
(iii)	Haryana	Faridabad	..	12	
(iv)	Do.	Dharampur	..	12	
(v)	Karnataka	Bangalore	..	32	
(vi)	Kerala	Pulaynarkota	..	24	
(vii)	Maharashtra	Nagpur	..	25	
(viii)	Orissa	Choudwar	..	12	
(ix)	Do.	Brajrajnagar	25	..	
(x)	Punjab	Amritsar	..	12	
(xi)	Rajasthan	Jaipur	..	15	
(xii)	Do.	Bari-Udaipur	..	16	
(xiii)	Do.	Pali	12	..	
(xiv)	Do.	Bhilwara	12	..	
(xv)	Do.	Jodhpur	20	..	
(xvi)	Do.	Sriganga Nagar	12	..	
(xvii)	Do.	Kota	24	..	
(xviii)	Do.	Udaipur	12	..	
(xix)	Do.	Bharatpur	12	..	
(xx)	Tamil Nadu	Sivakasi	12	..	
(xxi)	Do.	Tambaram	..	52	
(xxii)	Do.	Kollpatti	32	..	
(xxiii)	Do.	Lalgudi	10	..	
(xxiv)	Do.	Nagercoil	..	26	
		Total	183	282	=465

APPENDIX III

Type of Medical Care to Families (I.P) units as on 31-3-1975 and 31-3-76

S No.	Name of the State	Restricted care		Expanded care		Full care	
		31-3-75	31-3-76	31-3-75	31-3-76	31-3-75	31-3-76
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Andhra Pradesh	..	..	38,500	47,800 (44,850)	1,19,700	1,75,200 (1,64,650)
2.	Assam	..	.	20,100	25,650 (24,200)	..	..
3.	Bihar	.	..	85,000	1,04,000 (93,000)	..	..
4.	Chandigarh	..	.	9,000	9,000 (8,000)	..	..
5.	Delhi	..	..	..	..	1,56 000	2,06,000 (1,80,000)
6	Gujarat	..	..	1,47,500	1,60,350 (1,43,500)	3,61,500	4,09,650 (3,66,500)
7.	Haryana	..	..	1,29,450	1,41,300 (1,30,500)	12,800	22,200 (20,000)
8.	Karnataka	.	..	1,06,400	77,600 (72,950)	1,36,400	2,08,400 (1,96,050)
9.	Kerala	..	..	..	..	1,96,250	2,63,600 (2,48,700)
	Mahe	..	..	750	1,400 (1,300)	..	..
10.	Madhya Pradesh	..	..	76,300	89,750 (84,000)	50,700	59,250 (55,500)
11.	Maharashtra:—						
	Bombay Area	..	..	8,80,000	11,37,800 (10,20,000)	..	..
	Goa	..	..	..	11,200 (10,000)	..	..
	Nagpur Area	5,750	..	45,250	51,450 (48,300)	..	..
	Poona Area	26,600	..	54,700	55,100 (52,000)	82,700	1,21,850 (1,15,000)
12.	Orissa	..	..	54,500	72,300 (64,500)	..	..
13.	Pondicherry	.	..	14,500	15,500 (14,500)	..	..
14.	Punjab	..	..	53,550	..	81,450	1,60,200 (1.44,500)
15.	Rajasthan	.	..	13,400	24,950 (17,000)	76,450	87,550 (89,000)
16	Tamil Nadu	..	..	1,11,200	85,750 (1,05,500)	2,62,400	3,19,250 (2,74,500)
17.	Uttar Pradesh	2,19,950	2,32,850 (2,18,000)	..	..	2,25,400	2,37,150 (2,22,000)
18.	West Bengal	3,60,000	3,74,150 (3,51,000)	2,13,850	2,31,850 (2,17,500)	3,26,150	3,64,000 (3,41,500)
	TOTAL:	6,12,300	6,07,000 (5,69,000)	20,53,950	23,42,750 (21,51,600)	20,87,900	26,34,300 (24,17,900)

NOTE: The figures appearing in brackets denote employees families units.

APPENDIX IV

Important decisions taken by the Employees' State Insurance Corporation during the year 1975-76

(i) 20 July 1975

1. The Corporation decided to pay conveyance allowance and/or compensation for loss of wages to Insured Persons called to appear before a Medical Appeal Tribunal in cases filed by the Corporation or the Insured Person, at the same scale and subject to the same conditions as are applicable in cases where the Insured Person appeals before the Medical Board (The present rate of conveyance charges is 35 paise per K.M. Where, however, the Insured Person is not fit to travel by bus or other ordinary means of conveyance or needs an attendant, the Insured Person may be paid the actual charges incurred by him at a rate not exceeding 65 paise per K.M. Like-wise where an Insured Person has lost wages on account of attendance at a meeting of the Medical Appeal Tribunal he shall be paid by way of compensation a day's wages or half a day's wages for each day or days on which he lost wages depending on whether more or less than half a day's wages are lost subject to the maximum of the daily rate of Temporary Disablement Benefit under the 1st schedule of the E.S.I Act, 1948—Highest wage group—).

(ii) 28 February 1976

1. The Corporation decided that payment of Extended Sickness Benefit will now be paid for 124 days in respect of 21 diseases listed below, which may be extended up to 309 days in Chronic suitable cases by Regional Deputy Medical Commissioner/Medical Reference Administrative Medical Officer/Chief Executive of the

E.S.I. Scheme of the State or his nominee. Payment beyond 124 days would only be made on receipt of re-commendations of the above authorities.

List of Diseases :

1. Tuberculosis.
2. Leprosy.
3. Mental diseases (Psychoses).
4. Malignant diseases
5. Paraplegia.
6. Hemiplegia.
7. Chronic congestive heart failure.
8. Immature cataract with vision 6/60 or less in the affected eye.
9. Lung Abscess.
10. Bronchiectasis.
11. Mycoardial infraction.
12. Dislocation and prolapse of intervertebral disc.
13. Parkinson's disease.
14. Aplastic Anaemia.
15. Cirrhosis of Liver with ascites.
16. Detachment of Retina.
17. Non-union OR delayed union of fracture.
18. Empyema.
19. Intera-cranial space occupying lesion.
20. Spinal cord compression.
21. Chronic (simple) Primary glaucoma.

The Medical Commissioner can sanction the payment of Extended Sickness Benefit for a maximum period of 124 days or 309 days, depending upon the merits of the case, on the recommendations of the above authorities, in case of any rare disease or special circumstances.

2. The Corporation approved the enhancement of Extended Sickness Benefit rate at 25 per cent more than the standard rate rounded to the next higher multiple of 5 paise applicable when the Sickness Benefit was last payable. This will take effect from 1-4-1976.

3. The Corporation adopted the following resolution :—

"Resolved that for the purposes of levy of damages under Section 85-B(I) of the Employees' State Insurance Act, 1948 as amended up to date, the Director General or any other Officer authorised by him may levy and recover damages from the Employers not exceeding the rates as per table annexed.

4. The Corporation decided to have its own machinery to look after the Repair and Maintenance of E.S.I. Projects constructed all over India at its sole cost. As an experimental measure, a few regions for the time being have been selected where it is proposed to have such a machinery.

APPENDIX V

Important decisions taken by the Standing Committee of the Employees' State Insurance Corporation during the year 1975-76

(i) 2 June 1975

1. The Standing Committee adopted the following resolution :—

'Resolved that subject to the approval of the Central Government, the Corporation may pay conveyance allowance and/or compensation for loss of wages to insured persons called to appear before a Medical Appeal Tribunal, in cases filed by the Corporation or the insured persons at the same scale and subject to the same condition as are applicable in cases where the insured person appears before a Medical Board."

(ii) 16 September 1975

1. The Standing Committee approved the revision of the ceiling on expenditure on medical care with effect from 1-4-75 as under :—

(i) for restricted medical care from Rs. 65 to Rs. 70	...	Per employee Per annum.
(ii) for expanded medical care from Rs. 70 to Rs. 75	..	—do—
(iii) for full medical care from Rs. 85 to Rs. 95	...	—do—

The Standing Committee also agreed that expenditure on drugs medicines and other medicaments exceeding Rs. 25 but not exceeding Rs. 45 per employee per annum would be allowed over and above the ceiling but would be shared in the usual ratio between the State Government and the E.S.I. Corporation.

2. The Standing Committee approved the revised pharmacopoeia as recommended by the Medical Benefit Council at its meeting held on 11-2-1975.

(iii) 20 December 1975

1. The Standing Committee approved the proposal for enhancement of Extended Sickness Benefit rate and recommended the adoption of the following resolution by the Corporation :—

"Resolved that the rate of Extended Sickness Benefit during an extended sickness benefit period shall be 25 per cent more than the standard benefit rate rounded to the next higher multiple of five paise applicable when the sickness benefit was last payable under the Act."

"Resolved further that this Resolution will come into force with effect from 1-4-1976 and shall be given effect to as follows :—

(1) The benefit at enhanced rate shall be admissible to all cases of Extended Sickness Benefit which arise on or after 1-4-1976.

(2) Insured Persons whose cases of Extended Sickness Benefit are current on 1-4-1976 and where the Insured Persons have not already exhausted Extended Sickness Benefit shall also be entitled to the Benefit at the enhanced rate with effect from 1-4-1976.

(3) Insured Persons who may not have received Extended Sickness Benefit because of the fact that the decision regarding eligibility in their cases has not been taken before 1-4-76 shall also be eligible to enhanced rate with effect from 1-4-1976 only."

2. The Standing Committee approved and recommended the following resolution to the Corporation for adoption :—

"Resolved that for the purposes of levy of damages under Section 85-B(1) of the Employees' State Insurance Act, 1948 as amended up-to-date, the Director General or any other officer authorised by him may levy and recover damages from the Employer/s not exceeding the rates indicated in Table enclosed."

(iv) 27 February 1976

1. The Standing Committee agreed to provide wheel-chair to Insured Persons who are disabled due to paralysis or other diseases and implementable Cardic Pacemaker to Insured Persons and members of their families, wherever considered necessary by a competent Cardiologist as recommended by the Medical Benefit Council.

2. The Standing Committee approved the yardstick for provision of ambulance vans under E.S.I. Scheme and the revised norms of the staff in the E.S.I. Dispensaries as recommended by the Medical Benefit Council at its meeting held on 22-12-1975.

TABLE A

STANDARD TABLE FOR LEVY OF DAMAGES

Sl. No of the default	One month or less	Over 1 month upto two months	Over 2 months upto three months	Over 3 months upto four months	Over 4 months upto five months	Over 5 months upto six months	Over 6 months upto seven months	Over 7 months upto eight months	Over 8 months upto nine months	Over 9 months upto ten months	Over 10 months upto eleven months	Over 11 months upto twelve months	Over 12 months
1st default	2%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	For default
2nd ,,	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	exceeding
3rd ,,	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	twelve months
4th ,,	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	the damages
5th ,,	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	leviable
6th ,,	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	shall be amo-
7th ,,	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	unt equal to
8th ,,	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	the amount
9th ,,	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	in arrears
10th ,,	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	
11th ,,	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	
12th ,,	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	

Where number of default exceeds 12 the damages leviable shall be an amount equal to the amount in arrear.

APPENDIX VI

Important recommendations of the Medical Benefit Council during the year 1975-76

(i) 22 December 1975

1. The Council considered the question of provision of artificial appliances to I.Ps. and members of their families as part of medical care under the E.S.I. Scheme and recommended :—

(a) The provision of a Wheel Chair to I.Ps. who are disabled due to Paralysis or other diseases.

(b) The provision of Implementable Cardic Pace-maker to I.Ps. and their family members wherever considered necessary by a competent cardiologist

2. The Council recommended a revised yard-stick of staff of various sizes of the E.S.I. Dispensaries and a yard stick for provision of Ambulance Vans for the Scheme.

3. The Medical Benefit Council set up a small Sub-Committee to suggest norms and standards of staff and equipment for different sizes of E.S.I. Hospitals

(ii) 24 February 1976

The Council recommended adoption of an Ayurvedic Formulary for the E.S.I Ayurvedic Institutions

APPENDIX

PART

E.S.I.C. Staff authorised

Sl. No.	Designation of posts	Hqrs.	Andhra Pradesh		Assam		Bihar		Delhi		Gujarat		Karnataka	
			RO	LOs	RO	LOs	RO	LOs	RO	LOs	RO	LOs	RO	LOs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Director General	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2.	Insurance Commissioner	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3.	F.A. and C.A.O.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4.	Medical Commissioner	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5.	Actuary	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6.	Director of Adminis.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
7.	Regional Dy. Medical Commissioner	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..
8.	J.I.C./R.D. Gr.I	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
9.	Dir. (O & M/R D.Gr. II/ Dir.(P&D)/Dir (Vig.)	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
10.	A O./D.I.C./R.D. Gr. III/ Dy. C.A.O./J.R.D./Vig. Officer	8	1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..
11.	Dy. M.C./M.R.	4	1	..	..	..	1	..	2	..	3	..	2	..
12.	R.D. Gr. IV/Dy.A.O/ Asstt. Actuary/ A.C.O./ D.R.D./Asstt. Dir. (Planning).	13	3	..	1	..	1	..	4	..	5	..	5	..
13.	A.R.D./Mgr. Gr. I/Dy. A.C.O./S.O.	22	2	..	..	..	3	..	2	..	5	1	2	2
14.	I.I./A I./Mgr. Gr. II/ Dy. Mgr./Inspector (O & M)	6	14	15	..	3	7	6	19	4	19	20	13	17
15.	P.S. to D.G.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
16.	Mgr. Gr. III/H.C./ Asstt./H.C. Cashier	81	8	8	1	3	4	9	6	2	17	11	11	9
17.	P.A.	11	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	2	..
18.	Technical Asstt.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
19.	Artist	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
20.	Librarian	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
21.	Receptionist	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
22.	UDCI/c/UDC Cashier/ UDC	69	33	40	4	4	18	14	38	16	69	64	45	65
23.	Stenographer	19	2	..	1	..	2	..	4	..	5	..	4	..
24.	Computor	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
25.	LDC/A. Operator/Telex Operator/Telephone Operator	91	80	53	8	4	36	17	68	12	153	66	101	65
26.	Gestetner Operator	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
27.	Staff Car Driver/Driver Delivery Van	4	1	..	..	..	1@	..	..	..	1	..	1	..
28.	Jr. Library Attendant	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
29.	Jamadar	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
30.	Record Sorter/Daftry (including Selection Grade Daftries)	29	13	19	1	6	7	13	12	6	32	28	20	24
31.	Peons	57	12	17	4	1	8	7	13	8	23	31	16	25
32.	Chowkidars	3	2	..	1*	..	1	..	1	..	2	..	3	1
33.	Farash	7	1	..	..	..	1	..	1	..	3	..	2	..
34.	Mali.	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
35.	Lift Man	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
36.	Sweepers	9	2	..	..	..	1	..	1	..	3	..	2	..
	Total	457	177	152	21	21	91	66	175	48	342	221	231	208

*Chowkidar-cum-Farash

@Staff Car Driver-cum-Peon

VII

I

as on 31 March 1976

Kerala		Madhya Pradesh		Maharashtra				Orissa		Punjab		Rajasthan		Tamil Nadu		Uttar Pradesh		West Bengal		Total
RO	LOs	RO	LOs	RO	Sub RO Poona	Sub RO Nagpur	LOs	RO	LOs	RO	LOs	RO	LOs	RO	LOs	RO	LOs	RO	LOs	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	4
..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	5
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..	7
1	..	1	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	3	..	21
2	..	1	..	12	..	..	..	..	..	2	..	1	..	4	..	3	..	10	..	48
3	..	3	..	11	1	1	..	1	..	4	..	1	..	5	..	5	..	11	..	78
2	1	1	3	11	1	..	17	2	1	3	..	3	..	6	10	5	2	13	19	139
18	26	9	9	78	..	1	33	5	3	23	14	7	5	28	27	19	14	58	33	553
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
10	8	6	10	45	7	3	36	3	5	12	4	5	9	19	34	18	12	39	24	479
1	..	1	..	2	1	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..	25
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
44	72	31	38	181	26	10	153	13	12	51	22	19	11	69	127	65	35	147	170	1775
3	..	2	..	15	1	1	..	2	..	3	..	3	..	6	..	5	..	18	..	96
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4
90	80	59	31	406	50	17	186	25	10	105	25	36	12	165	151	146	39	347	204	2938
..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	2	..	7
1	..	1	..	2	..	..	..	1(a)	..	..	..	1(a)	..	1	..	1	..	4	..	20
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
18	28	12	17	92	12	4	64	4	9	20	18	7	14	29	53	31	25	75	69	811
15	24	10	12	54	8	5	94	5	4	15	9	7	5	20	53	23	25	56	101	767
2	..	2	..	6	..	1	..	1	..	2	..	1	..	3	..	2	..	4	..	39
1	..	1	..	6	1	1	..	1	..	2	..	1	..	2	..	2	..	6	..	39
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	4
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2
1	..	1	..	7	1	1	..	1	..	2	..	1	..	3	..	2	..	8	..	46
212	239	141	120	935	111	45	583	64	44	247	92	93	56	364	455	331	152	806	620	7920

APPENDIX VII

PART II

Statement showing the position of staff authorised and in position in respect of Directorate (Medical) Delhi, E.S.I. Dispensaries and E.S.I. Hospital as on 31-3-1976

Sl. No.	Designation of post	Director's Office		E.S.I. Dispensaries		E.S.I. Hospital		Total	
		autho-rised	In position	autho-rised	In position	autho-rised	In position	autho-rised	In-position
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
1.	Director (Medical) Delhi	1	1	..	..	..	..	1	1
2.	Medical Supdt.	..	..	..	..	1	..	1	..
3.	Specialists in surgery, orthopaedic, Medicines Gyanaecology, Radiology, Pathology, Anaes-thesiology and Paediatrics.	..	..	..	..	11	4	11	4
4.	Dy. Chief Accounts Officer.	1	1	..	..	..	..	1	1
5.	Administrative Medical Officer.	1	1	..	..	..	..	1	1
6.	Dy. Administrative Officer	1	1	..	..	1	1	2	2
7.	Insurance Medical Officers (GDO Gr. I & Gr. II)	..	..	142	117	..	..	142	117
8.	Accounts Officer (M)	1	1	..	..	..	..	1	1
9.	Medical Officers G.D.O. Gr. II	..	..	..	..	16	15	16	15
10.	Registrars	..	..	..	..	3	1	3	1
11.	House Surgeons	..	..	..	..	10	8	10	8
12.	Radiologist	..	..	..	..	1	1	1	1
13.	Nursing Superintendent	..	..	..	..	1	1	1	1
14.	Dy. Accounts Officer	..	..	..	..	1	1	1	1
15.	*Part time consultant/ Specialists*	..	..	..	..	*10*	*8*	*10*	*8*
16.	Audit Inspector	2	2	..	..	..	..	2	2
17.	Head Clerks	10	8	..	..	3	3	13	11
18.	Inspector Stores	1	1	..	..	..	..	1	1
19.	P.A. to Director (M) Delhi & Medical Supdt.	1	1	..	..	..	..	1	1
20.	U.D.C. Cashier	1	1	..	..	1	1	2	2
21.	U.D.C.s	31	29	22	22	6	5	59	56
22.	Stenographers	4	3	..	..	1	1	5	4
23.	L.D.C.	45	36	75	74	20	13	140	123
24.	Laundary Supervisor	..	..	..	..	1	..	1	..
25.	Boiler Attendent	..	..	..	..	1	..	1	..
26.	Laundary Operator	..	..	..	..	10	..	10	..
27.	Telephone Operator	..	..	..	..	2	..	2	..
28.	Care Taker	..	..	..	..	1	1	1	1
29.	Asstt. Matron	..	..	..	..	1	..	1	..
30.	Sister Incharge	..	..	..	..	2	1	2	1
31.	Nursing Sister	..	..	..	..	17	13	17	13
32.	Staff Nurses	..	..	..	..	90	63	90	63
33.	Nurse A/B Grade/L.H.V.	..	..	48	43	..	..	48	43
34.	Dietician	..	..	..	..	1	1	1	1
35.	Lab. Tech. Gr. I	..	..	..	..	8	6	8	6
36.	X-Ray Technician/Radiographer	..	..	..	..	7	5	7	5
37.	E.C.G. Technician	..	..	..	..	1	1	1	1
38.	Chief Pharmacist	1	1	..	..	1	..	2	1
39.	Pharmacist-cum-Clerk (Stores)	2	2	19	13	..	..	21	15
40.	Pharmacist	3	3	77	77	3	3	83	83
41.	Social Guide	2	1	..	..	..	..	2	1
42.	Lab. Technicians	..	..	11	10	..	..	11	10
43.	Store Keepers	..	..	..	..	2	1	2	1
44.	C.S.R. Attendents	..	..	..	..	6	3	6	3
45.	O.T. (Technician)	..	..	..	..	3	3	3	3
46.	O.T. (Asstt.)	..	..	..	..	6	4	6	4
47.	Librarian		..	..	..	1	..	1	..
48.	Asstt. Librarian	..	..	..	..	1	1	1	1
49.	Midwife/Dais	..	..	57	49	..	..	57	49
50.	Ambulance Driver/Staff Car Driver	7	6	..	..	5	1	12	7
51.	Dressers	..	..	61	61	6	6	67	67
52.	Metal worker-cum-Mistry	..	..	..	..	1	..	1	..
53.	Opto-meterist	..	..	..	..	1	1	1	1
54.	Linen Mistress	..	..	..	..	1	..	1	..

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.	Occupational Therapist	..	..	..	..	1	..	1	..
56.	Physio Therapist	..	..	..	..	1	..	1	1
57.	Senior M.R.T.	..	..	..	..	1	..	1	..
58.	Junior M.R.T.	..	..	..	..	1	..	1	..
59.	Gestetner Operator	1	1	..	..	..	..	1	1
60.	Daftry	4	4	..	..	2	2	6	6
61.	Dark room Asstt.	..	..	..	..	1	..	1	..
62.	Head Cook	..	..	..	..	1	1	1	1
63.	Cook-cum-Masalchi	..	..	..	..	20	13	20	13
64.	Peon	15	15	61	61	8	8	84	84
65.	Ayas	..	..	36	36	4	3	40	39
66.	Chowkidars	..	..	23	23	19	19	42	42
67.	Sweepers/Sweeperess	..	..	74	74	60	42	134	116
68.	Tailor	..	..	..	..	2	1	2	1
69.	Nursing orderlies	..	..	..	..	95	79	95	79
70.	Stretcher Bearer	..	..	..	..	9	5	9	5
71.	Ambulance Attendents	2	..	..	..	3	2	5	2

APPENDIX VIII

Number of Employers and Employees covered under the E.S.I. Act during 1975-76

STATE-WISE

State	Implemented Area*		Non-Implemented Area		All Areas	
	No. of employers	No. of employees as on 31-3-76	No. of employers	No. of employees as on 31-3-76	No. of employers	No. of employees as on 31-3-76
1	2	3	4	5	6	7
Andhra Pradesh	2,081	2,09,500	22	14,500	2,103	2,24,000
Assam	303	25,000	40	11,500	343	36,500
Bihar	661	93,000	226	1,80,000	887	2,73,000
Chandigarh	89	8,000	..	..	89	8,000
Delhi	3,121	1,80,000	..	..	3,121	1,80,000
Gujarat	1,877	5,10,000	459	90,000	2,336	6,00,000
Haryana	1,537	1,50,500	20	5,500	1,557	1,56,000
Himachal Pradesh	..	..	11	1,500	11	1,500
Karnataka	1,441	2,69,000	52	31,000	1,493	3,00,000
Kerala and Mahe	1,486	2,50,000	15	10,000	1,501	2,60,000
Madhya Pradesh	603	1,39,500	15	71,500	618	2,11,000
Maharashtra	6,822	12,52,000	331	56,000	7,153	13,08,000
Orissa	198	66,000	75	24,000	273	90,000
Pondicherry	67	14,500	.	..	67	14,500
Punjab	2,954	1,47,000	46	2,500	3,000	1,49,500
Rajasthan	834	1,06,000	36	5,000	870	1,11,000
Tamil Nadu	2,195	3,80,000	187	37,000	2,382	4,17,000
Uttar Pradesh	1,405	4,40,000	342	45,000	1,747	4,85,000
West Bengal	4,730	9,10,000	103	1,40,000	4,833	10,50,000
ALL-INDIA (1976)	32,404	51,50,000	1,980	7,25,000	34,384	58,75,000
ALL-INDIA (1975)	25,654	43,85,000	1,790	6,65,000	27,444	50,50,000

*Also includes the coverage under section 1(5) of the Act.

APPENDIX IX

Number of Centres, Employees, Insured Persons, Family (Insured Person) Units and Beneficiaries Covered as on 31-3-76 STATE-WISE (including Coverage under section 1(5) of the Act)

STATE	No. of Centres	No. of Employees	No. of Insured Persons	No. of Family (Insured Person) Units	No. of Beneficiaries
1	2	3	4	5	6
Andhra Pradesh	43	2,09,500	2,23,000	2,23,000	8,65,250
Assam	12	25,000	26,500	25,650	1,00,350
Bihar	19	93,000	1,04,000	1,04,000	4,03,500
Chandigarh	1	8,000	9,000	9,000	34,900
Delhi	1	1,80,000	2,06,000	2,06,000	7,99,300
Gujarat	14	5,10,000	5,70,000	5,70,000	22,11,600
Haryana	19	1,50,500	1,67,000	1,63,500	6,37,900
Karnataka	28	2,69,000	2,86,000	2,86,000	11,09,700
Kerala and Mahe	54	2,50,000	2,65,000	2,65,000	10,28,200
Madhya Pradesh	20	1,39,500	1,49,000	1,49,000	5,78,100
Maharashtra	33	12,52,000	13,84,500	13,77,400	53,51,400
Orissa	15	66,000	74,000	72,300	2,82,200
Pondicherry	1	14,500	15,500	15,500	60,150
Punjab	22	1,47,000	1,63,000	1,60,200	6,24,400
Rajasthan	18	1,06,000	1,12,500	1,12,500	4,36,500
Tamil Nadu	42	3,80,000	4,05,000	4,05,000	15,71,400
Uttar Pradesh	39	4,40,000	4,70,000	4,70,000	18,23,600
West Bengal	7	9,10,000	9,70,000	9,70,000	37,63,600
ALL-INDIA (1976)	388	51,50,000	56,00,000	55,84,050	2,16,82,050
ALL-INDIA (1975)	365	43,85,000	47,75,000	47,54,150	1,84,69,590

APPENDIX X

No. of beds, specialists, dispensaries, penal doctors and ambulances as on 31-3-1976

Sl. No.	Name of the State	Total No. of beds provided under the E.S.I. Scheme				Specialists		Total No. of Dispensaries	No. of I.M.Os.		No. of I.M.Ps.	Ambulance	Remarks
		Genl.	Maternity	T.B.	Total	Full-time	Part time		Sanctioned	Present			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Andhra Pradesh	490	57	85	632	9	76	79	199	199	5	13	
2.	Assam	16	..	2	18	..	..	17	18	18	..	..	
3.	Bihar	196	..	30	226	5	..	30	90	57	..	21	
4.	Chandigarh Admn.	2	..	..	2	..	4	1	3	2	..	..	
5.	Delhi	390	..	125	515	4	27	26	156	117	..	5	
6.	Goa	18	..	2	20	..	..	..	..	..	56	..	
7.	Gujarat	1069	..	278	1347	21	217	82	364	338	203	11	
8.	Haryana	227	..	53	330	12	22	44	104	99	..	2	
9.	Karnataka	1025	37	103	1165	8	60	97	214	206	..	11	
10.	Kerala	659	47	165	871	27	73	93	193	172	..	4	
11.	Madhya Pradesh	272	..	130	402	1	81	50	138	116	3	8	
12.	Maharashtra												
	Gr. Bombay	1283	164	550	1997	42	105	14	13	8	2132	11	
	Nagpur Area	171	20	52	243	3	33	23	70	69	..	2	
	Western Maharashtra	363	..	177	540	..	36	19	61	39	348	2	
13.	Orissa	119	6	12	137	3	..	19	58	48	..	7	
14.	Pondicherry	14	4	10	28	..	9	6	11	11	..	..	
15.	Punjab	317	5	29	351	20	19	16	41	32	84	4	
16.	Rajasthan	184	26	31	241	4	52	37	101	98	..	1	
17.	Tamil Nadu	1200	387	370	1957	37	70	115	339	321	..	21	
18.	Uttar Pradesh	356	94	186	636	19	..	91	253	244	..	6	
19.	West Bengal	1945	12	688	2645	..	266	5	..	..	1757	15	
	Total	10366	859	3078	14303	215	1150	864	2426	2194	4588	144	

APPENDIX

NO. of attendances, Medical Certificates issued, Admission to Hospitals, Reference (In respect of

State		Period	ATTENDANCES			
			No. of Insured Persons deemed exposed to risk	New Cases	Old Cases	Total Cases
1		2	3	4	5	6
Andhra Pradesh	(SS)	1974-75	1,54,500	5,48,235	18,53,944	24,02,179
		1975-76@	1,88,100	5,11,092	17,89,015	23,00,107
Assam	(SS)	1974-75	21,500	66,326	69,200	1,35,526
		1975-76	23,350	81,990	87,321	1,693,11
Bihar	(SS)	1974-75				Not
		1975-76@	92,900	1,52,316	2,61,280	4,13,596
Chandigarh	(SS)	1974-75	9,000	12,776	61,780	74,556
		1975-76	8,850	12,595	55,768	68,363
Delhi	(SS)	1974-75	1,53,000	1,90,902	9,17,990	11,08,892
		1975-76	1,77,900	2,11,090	11,36,510	13,47,600
Gujarat	(SS)	1974-75	4,58,050	5,76,894	30,01,875	35,78,769
		1975-76	4,81,300	6,27,247	31,30,305	37,57,552
Gujarat	(PS)	1974-75	46,450	1,68,465	1,85,777	3,54,242
		1975-76	49,550	1,92,293	2,07,463	3,99,756
Haryana	(SS)	1974-75	1,05,850	3,08,568	4,80,980	7,89,548
		1975-76	1,24,000	3,72,661	6,08,686	9,81,347
Haryana	(PS)	1974-75	2,300	10,222	13,146	23,368
		1975-76	2,650	4,537	5,546	10,083
Karnataka	(SS)	1974-75	2,45,500	8,81,246	20,91,486	29,72,732
		1975-76	2,61,150	9,58,360	20,16,970	29,75,330
Kerala	(SS)	1974-75	1,97,050	6,38,489	17,31,349	23,67,838
		1975-76	2,25,550	7,80,617	19,71,831	27,52,448
Kerala	(PS)	1974-75	700	7,668	11,544	19,212
		1975-76	400	5,273	7,157	12,430
Madhya Pradesh	(SS)	1974-75	1,29,350	3,14,011	16,68,816	19,82,827
		1975-76	1,33,700	3,56,086	18,28,919	21,85,005
Madhya Pradesh	(PS)	1974-75	21,50	3,771	12,521	16,292
		1975-76	2,050	4,501	15,411	19,912
Maharashtra						
(i) Bombay Area	(SS)	1974-75	18,400	58,774	1,64,464	2,23,238
		1975-76	1,350	3,523	19,517	23,040
(ii) Bombay Area	(PS) @	1974-75	6,50,900	31,70,099	31,26,911	62,97,010
		1975-76	5,93,450	24,21,741	26,17,952	50,39,693
(iii) Nagpur Area	(SS)	1974-75	50,000	1,48,375	5,54,933	7,03,308
		1975-76	53,400	1,53,862	6,43,373	7,97,235
(iv) Poona Area	(SS)	1974-75				Included
		1975-76@	28,750	91,660	2,31,320	3,22,980
(v) Poona Area	(PS)	1974-75				Included
		1975-76@	66,100	3,01,364	3,41,068	6,42,432
Orissa	(SS)	1974-75	54,750	1,60,811	2,02,616	3,63,427
		1975-76	63,150	1,83,762	1,89,684	3,73,446
Pondicherry & Mahe	(SS)	1974-75	15,000	52,733	1,68,046	2,20,779
		1975-76	15,800	52,112	1,60,823	2,12,935
Punjab	(SS)	1974-75	31,400	1,40,561	1,55,402	2,95,963
		1975-76	24,100	1,39,053	1,53,658	2,92,711
Punjab	(PS)	1974-75	33,150	1,87,829	1,67,814	3,55,643
		1975-76	31,850	1,84,180	1,52,558	3,36,738
Rajasthan	(SS)	1974-75	89,000	2,74,394	6,51,522	9,25,916
		1975-76	1,00,050	3,14,829	6,49,904	9,64,733
Tamil Nadu	(SS)	1974-75	3,86,050	12,90,550	34,47,875	47,38,425
		1975-76	3,82,400	11,47,746	33,78,801	45,26,547
Tamil Nadu	(PS)	1974-75	4,950	22,802	55,345	78,147
		1975-76	4,800	23,645	50,764	74,409
Uttar Pradesh	(SS)	1974-75	4,40,000	14,44,568	16,95,393	31,39,961
		1975-76	4,52,900	15,83,050	19,09,700	34,92,750
West Bengal	(PS)	1974-75	5,83,000	23,91,814	23,68,378	47,60,192
		1975-76	6,96,650	23,21,083	21,31,076	44,52,159
All-India		1974-75	38,82,000	1,30,70,883	2,48,59,107	3,79,29,990
		1975-76	42,86,200	1,31,92,268	2,57,52,380	3,89,44,648

@Figures for certain months not received; weighted average taken.

XI

to Specialists and No of home visits during 1974-75 and 1975-76 State-wise.
Insured Persons)

	No of attendances per 1000 Insured persons per annum		No of Medical Certificates issued	No of cases admitted in Hospitals	No of Cases referred to the specialists for investigations	No of Home Visits
	New Cases	Old Cases				
	7	8	9	10	11	12
	3,548	12,000	3,69,336		52,570	N A
	2,717	9,511	3,81,576	N.A	66,398	N A.
	3,085	3,219	44,482	81	5,014	3,088
	3,511	3,740	50,741	135	5,093	3,169
Available						
	1,640	2,812	1,54,851	2,093	10,069	7,396
	1,420	6,864	5,728	4,057	7,121	540
	1,423	6,301	4,574	3,445	6,933	N A
	1,248	6,000	1,13,388	3,269	26,825	38,974
	1,187	6,388	1,44,311	4,172	36,017	30,272
	1,259	6,554	4,63,546	25,650	1,06,434	3,452
	1,303	6,504	4,75,687	16,618	1,20,667	4,587
	3,627	4,000	1,13,768	1,531	9,799	1 640
	3,881	4,187	1,26,253	1,171	10 496	1,933
	2,915	4,544	78,132	2,992	23,679	10 750
	3,005	4,909	88,658	5,637	44,264	7,596
	4,444	5,716	1,273	.	76	130
	1,712	2,093	503	5	57	288
	3,590	8,519	6,62,696	18,334	1,07,117	30,616
	3,670	7,723	5,34,853	18,389	97,360	20,204
	3,240	8,786	5,78,007	24,887	26,899	10,087
	3,461	8,742	4,08,532	34,974	30,713	7,436
	10,954	16,491	4,753	1,255	984	..
	13,183	17,893	1,645	1,390	700	2
	2,428	12,902	4,81,603	7,087	56,318	16,138
	2,663	13,679	5,44,367	6,702	55,584	17,399
	1,754	5,824	3,063	44	509	55
	2,196	7,516	3,703	47	668	54
	3,194	8,938	43,822	29,440	3,401	138
	2,610	14,457	4,519	25,541	594	9
	4,870	4,804	16,52,611	2,770	1,44,401	19,271
	4,081	4,411	13,07,541	707	1,30,726	15,560
	2,968	11,099	1,13,768	4,265	18,276	12,333
	2,881	12,048	1,64,800	7,511	19,556	9,481
in Bombay Area (SS)						
	3,188	8,046	62,696	N A	2,808	672
in Bombay Area (PS)						
	4,559	5,160	2,46,542	342	12,418	1,742
	2,937	3,701	1,14,898	1,477	12,037	9,877
	2,910	3,004	67,128	1,434	12,041	6,250
	3,516	11,203	58,504	498	12 066	1,978
	3,298	10,177	43,453	939	7,560	3,854
	4,476	47,949	13,767	19,851	2,430	2,417
	5,770	6,376	20,067	30,437	2,458	2,773
	5,666	5,062	36,467	10,131	12,927	8,042
	5,783	4,790	32,176	11,943	13,700	7,917
	3,083	7,320	1,50,609	7,379	35,090	1,590
	3,147	6,496	1,53,342	8,256	40,504	2,479
	3,343	8,931	15,66,172	12,039	1,29,413	3,408
	3,001	8,836	12,99,473	14,175	1,33,171	5,304
	4,606	11,181	19,491	861	1,924	1,386
	4,926	10,576	17,120	1,016	1,692	1,451
	3,283	3,853	4,90,655	11,983	67,626	2,782
	3,495	4,217	5,46,145	14,124	1,04,702	4,482
	4,103	4,062	14,19,210	31	1,16,321	1,06,406
	3,332	3,059	15,01,327	66	1,08,392	96,588
	3,367	6,404	88,99,749	1,89,912	9,79,257	2,85,098
	3,078	6,008	83,87,583	2,11,269	10,75,341	2,58,898

(SS)—Service System (PS)—Panel System.

APPENDIX XII

No. of Attendances and Home visits during the 1974-75 and 1975-76 State-Wise (in respect of Family members of Insured Persons)

State	Period	No. of family (Insured Person) Units deemed exposed to risk	Attandances			No. of attendances per 1000 family (Insured Person) units per annum		No. of Home visits
			New Cases	Old Cases	Total cases	New Cases	Old Cases	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Andhra Pradesh (SS)	1974-75	1,53,600	6,95,837	21,13,040	28,08,877	4,530	13,757	38,124
	1975-76@	1,87,200	6,48,802	22,40,608	28,89,410	3 466	11,969	52,879
Assam (SS)	1974-75	20,600	49,805	35,219	85,024	2,418	1,710	789
	1975-76	22,500	60,552	43,771	1,04,323	2,691	1,945	466
Bihar (SS)	1974-75	—Not Available—						
	1975-76@	92,950	2,57,885	3,53,126	6,11,011	2,774	3,799	10,535
Chandigarh (SS)	1974-75	9,000	24,841	10,685	35,526	2,760	1,187	1,404
	1975-76	8,850	23 783	11,521	35,304	2,687	1,302	1,377
Delhi (SS)	1974-75	1,53,000	5,09,268	9,83,372	14,92,640	3,329	6,427	14,027
	1975-76	1,77,900	5,75,565	10,81,980	16,57,545	3,235	6,082	12,705
Gujarat (SS)	1974-75	4,57,600	8,85,895	37,40,997	46,26,892	1,936	8,175	2,754
	1975-76	4,80,900	9,36,362	38,90,542	48,26,904	1,947	8,090	1,798
Gujarat (PS)	1974-75	44,900	2,19,877	2,22,715	4,41,592	4,688	4,727	403
	1975-76	47,950	2,42,763	2,32,171	4,74,934	4,860	4,648	472
Haryana (SS)	1974-75	1,17,650	3,06,434	4,46,593	7,53,027	2,605	3,796	5,873
	1975-76	1,36,950	3,39,138	4,76,512	8,15,650	2,476	3,479	10,041
Haryana (PS)	1974-75	2,600	14,523	21,395	35,918	5,586	8,229	386
	1975-76	2,800	6,824	12,372	19,196	2,437	4,419	359
Karnataka (SS)	1974-75	2,44,150	12,05,205	24,95,994	37,01,279	4,937	10,223	11,882
	1975-76	2,60,050	13,76,586	27,07,771	40,84,357	5,294	10,413	12,149
Kerala (SS)	1974-75	1,97,050	6,11,023	16,83,445	22,94,468	3,101	8,543	640
	1975-76	2,25,600	7,63,405	19,79,493	27,42,898	3,384	8,774	672
Kerala (PS)	1974-75	700	8,323	12,828	21,151	11,890	18,326	..
	1975-76	350	5,661	7,997	13,658	16,174	22,849	N.A.
Madhya Pradesh (SS)	1974-75	1,29,100	6,66,452	18,64,348	25,30,800	5,162	14,441	727
	1975-76	1,33,650	6,85,353	17,97,386	24,82,739	5,128	13,448	758
Madhya Pradesh (PS)	1974-75	2,050	7,046	13,698	20,744	3,437	6,682	..
	1975-76	2,100	8,175	13,740	21,915	3,893	6,543	..
MAHARASHTRA								
(i) Bombay Area (SS)	1974-75	24,150	71,196	1,53,385	2,24,581	2,948	6,351	932
	1975-76	1,350	3,061	13,082	16,143	267	9,690	220
(ii) Bombay Area (PS)	1974-75	6,15,900	17,14,018	15,73,471	32,87,489	2,783	2,555	11,594
	1975-76	5,15,000	16,61,862	12,07,278	28,69,140	3,227	2,344	10,261
(iii) Nagpur Area (SS)	1974-75	50,000	2,19,832	8,95,555	11,15,387	4,397	17,911	3,746
	1975-76	50,450	2,22,383	10,54,830	12,77,213	4,408	20,908	3,809
(iv) Poona Area (SS)	1974-75	—Included in Bombay Area (SS)—						
	1975-76@	32,200	1,05,116	2,17,440	3,22,556	3,264	6,753	3,184
(v) Poona Area (PS)	1974-75	—Included in Bombay Area (PS)—						
	1975-76@	68,800	2,91,476	3,04,728	5,96,204	4,237	4,429	3,464
Orissa (SS)	1974-75	53,400	1,52,866	1,75,691	3,28,557	2,863	3,290	1,955
	1975-76	62,300	1,83,373	1,85,382	3,68,755	2,943	2,976	1,849
Pondicherry and Mahe (SS)	1974-75	15,000	54,004	1,25,700	1,79,704	3,600	8,380	2,949
	1975-76	15,800	59,130	1,58,791	2,17,912	3,742	10,050	3,068
Punjab (SS)	1974-75	27,750	1,22,101	1,26,117	2,48,218	4,400	4,545	2,732
	1975-76	20,200	1,10,225	99,940	2,10,165	5,457	4,948	1,786
Punjab (PS)	1974-75	30,800	1,67,660	1,61,858	3,29,518	5,444	5,255	5,651
	1975-76	30,300	1,60,793	1,40,839	3,01,632	5,307	4,648	5,791
Rajasthan (SS)	1974-75	88,450	3,77,627	6,69,181	10,46,808	4,269	7,566	1,457
	1975-76	99,450	4,43,185	7,72,029	12,15,214	4,456	7,763	1,545
Tamil Nadu (SS)	1974-75	3,82,300	14,65,142	40,50,149	55,15,291	3,832	10,594	12,172
	1975-76	3,78,400	14,76,184	44,03,718	58,79,902	3,901	11,638	15,538
Tamil Nadu (PS)	1974-75	4,500	31,240	79,781	1,11,021	6,942	17,729	13,87
	1975-76	4,750	35,596	76,031	1,11,627	7,494	16,007	1,936
Uttar Pradesh (SS)	1974-75	4,36,200	7,69,921	17,39,229	25,09,150	1,765	3,987	54,735
	1975-76	4,50,550	9,12,036	17,47,262	26,59,298	2,024	3,878	27,708
West Bengal (PS)	1974-75	5,63,650	19,92,190	17,58,931	37,51,121	3,534	3,121	1,38,404
	1975-76	6,32,850	21,19,044	14,20,802	35,39,846	3,348	2,245	28,106
ALL-INDIA	1974-75	38,26,100	1,23,42,406	2,51,52,377	3,74,94,783	3,226	6,574	3,14,723
	1975-76	41,44,150	1,37,14,318	2,66,51,142	4,03,65,460	3,309	6,431	2,12,476

@Figures for certain months not received; weighted average taken. (SS)—Service System (PS)—Panel System.

APPENDIX XIII

Incidence of Morbidity *i.e.*, number of new Cases per 1,000 Insured Persons and 1,000 Family (I.P.) Units 1974-75 and 1975-76.

ALL-INDIA

Cause Group No.	Disease	Insured Persons		Families	
		1974-75	1975-76	1974-75	1975-76
1	2	3	4	5	6
1.	T.B. respiratory system	16.5	16.6	11.5	10.9
2.	T.B. other forms	6.4	6.1	5.4	5.1
3.	Syphilis and its sequeale	4.2	4.6	1.6	2.2
4.	Gonococcal infection	6.8	7.6	4.0	4.7
5.	Dysentery, all forms	246.0	217.3	226.2	202 2
6.	Cholera, Entric fever, other infective diseases arising in intestinal tract	20.4	25.2	25.3	24.9
7.	Scarlet fever, Diptheria, Whooping Cough, Measles, Mumps, Chicken-pox	14.0	14.8	28.6	31.9
8.	Typhus and other rickettsial diseases	0.8	1.6	0.8	1.5
9.	Malaria	24.7	27.7	27.5	31.8
10.	Filariasis, Ankylostomiasis and other Helminths	46.0	49.4	72.2	84.3
11.	All other diseases classified as infective and parasitic	43.8	49.3	42.5	60.0
12.	Malignant neoplasms all sites	0.4	0.9	0.8	1.0
13.	Benign neoplasms all sites	1.1	1.1	1.3	1.8
14.	Allergic disorders	99.5	97.3	94.1	103.2
15.	Diseases of Thyroid gland	1.9	2.7	2.3	3.4
16.	Diabetes Mellitus	5.5	5.1	5.2	6.6
17.	Avitaminosis and other deficiency states	124.7	98.2	127.7	126.2
18.	Anaemias	91.6	83.1	117.1	105.5
19.	Psychoneuroses and Psychoses	3.9	3.6	3.3	3.2
20.	Vascular Lesions C.N.S.	1.0	0.9	1.1	1 4

1	2	3	4	5	6
21.	Diseases of eye	102.5	114.0	108.8	123.7
22.	Diseases of ear and Mostoid Process	50.8	48.7	64.2	63.7
23.	Rheumatic fever	9.1	7.2	8.8	7.5
24.	Chronic Rheumatic heart diseases	2.3	1.0	1.7	2.8
25.	Arteriosclerotic and degenerative heart diseases	1.2	1.0	1.2	1.7
26.	Hypertensive disease	6.7	6.3	5.7	6.4
27.	Diseases of Veins	9.4	9.3	9.7	8.1
28.	Acute nasopharyngitis (Common Cold)	291.9	257.0	271.0	287.1
29.	Acute Pharyngitis and tonsillitis	100.1	81.2	110.3	103.8
30.	Influenza	195.7	160.7	151.1	143.3
31.	Pneumonia	9.0	7.0	15.4	12.1
32.	Bronchitis	249.7	228.1	224.0	242.9
33.	Silicosis and Occupational pulmonary fibrosis	1.2	0.3	0.4	0.3
34.	Other respiratory	82.2	71.3	84.6	88.5
35.	Diseases of stomach and duodenum	131.9	112.3	102.3	101.6
36.	Appendicitis	2.9	2.8	2.9	3.2
37.	Hernia of abdominal cavity	2.7	3.3	2.6	2.7
38.	Diarrhoea and enteritis	212.1	174.4	208.9	205.3
39.	Diseases of gallbladder and bile ducts	3.0	3.3	3.7	2.8
40.	Other diseases of digestive system	167.5	143.2	143.1	139.7
41.	Nephritis and nephrosis	2.5	3.3	2.2	4.0
42.	Diseases of genital organs	18.8	17.9	32.7	34.9
43.	Deliveries, complications of pregnancy, Child birth and the Puerperium	68.5*	75.7*	12.7	11.6
44.	Boil, abscess, cellulitis and other skin infections	185.6	172.1	204.5	206.5
45.	Other diseases of skin	91.5	95.9	90.6	101.2
46.	Arthritis and rheumatism	162.6	137.3	119.3	121.4
47.	Diseases of bones and other organs of movement	10.6	11.9	6.6	6.8
48.	Congenital Malformations and diseases peculiar to early infancy	0.5	0.6	0.9	1.0
49.	Other specific and ill-defined diseases	306.0	288.3	268.9	274.2
50.	Accidents, poisoning and Violence	188.6	196.2	165.3	184.7
51.	Other Miscellaneous Groups	3.7	2.7	3.4	3.9
	TOTAL NO. OF NEW CASES	3367.0	3077.8	3225.8	3309.8

*Per 1000 insured women employees.

APPENDIX XIV

Estimated Expenditure incurred on provision of medical benefit during the year 1975-76

Sl. No.	Name of the state	No. of employees deemed exposed to risk	Total estimated expenditure on medical benefit as intimated by the State Government	Per capita cost
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	1,76,750	1,77,30,027.54	100.31
2.	Assam	21,300	11,54,076.51	54.18
3.	Bihar	84,900	65,75,534.05	77.45
4.	Chandigarh Admn.	7,500	5,25,141.00	70.02
5.	Delhi	1,54,750	1,85,63,601.45	119.96
6.	Goa	4,850	1,34,895.24	27.18
7.	Gujarat	4,57,750	4,01,47,220.00	87.71
8.	Haryana	1,34,300	88,36,724.59	65.80
9.	Karnataka	2,42,650	2,56,95,513.00	105.90
10.	Kerala	2,13,200	2,42,50,792.29*	113.75
11.	Madhya Pradesh	1,27,800	1,10,42,207.75	86.40
12.	Maharashtra	11,18,500	8,06,09,805.67	72.07
13.	Orissa	57,750	41,15,532.00	71.26
14.	Pondicherry	14,750	9,75,761.00	66.15
15.	Punjab	1,25,750	78,86,736.90	62.72
16.	Rajasthan	94,250	83,30,514.00	88.39
17.	Tamil Nadu	3,64,500	4,54,92,339.96*	124.81
18.	Uttar Pradesh	4,22,000	2,53,56,214.12	60.09
19.	West Bengal	8,66,200	7,36,99,695.00	85.08
	TOTAL	46,89,450	40,11,22,332.01	85·54

*Provisional.

APPENDIX

Incidence of Sickness and Maternity Benefit

State	Period	No. of employees deemed exposed to risk for Sickness/Ext. Sickness Benefit	Total No. of cash Benefit payments	Average No. of cash Benefit payments per employee per annun
1	2	3	4	5
Andhra Pradesh	1974-75	1,41,150	2,31,040	1.6
	1975-76	1,48,800	2,55,649	1.7
Assam	1974-75	18,400	27,204	1.5
	1975-76	18,850	23,659	1.3
Bihar	1974-75	76,500	82,569	1.1
	1975-76	78,900	96,703	1.2
Chandigarh	1974-75	7,100	2,492	0.4
	1975-76	7,200	2,160	0.3
Delhi	1974-75	1,27,900	60,155	0.5
	1975-76	1,35,050	72,691	0.5
Gujarat	1974-75	3,94,200	3,35,846	0.9
	1975-76	4,15,400	3,50,677	0.8
Haryana	1974-75	1,22,550	49,745	0.4
	1975-76	1,24,600	57,747	0.5
Karnataka	1974-75	2,26,300	3,41,113	1.5
	1975-76	2,26,750	2,78,423	1.2
Kerala and Mahe	1974-75	1,80,050	3,94,883	2.2
	1975-76	1,87,900	3,53,568	1.9
Madhya Pradesh	1974-75	1,26,450	2,22,010	1.8
	1975-76	1,22,650	2,58,964	2.1
Maharashtra	1974-75	10,04,250	8,92,278	0.9
	1975-76	10,28,700	9,12,227	0.9
Orissa	1974-75	48,650	63,267	1.3
	1975-76	51,950	54,462	1.0
Pondicherry	1974-75	11,700	34,218	2.9
	1975-76	13,200	24,952	1.9
Punjab	1974-75	1,06,200	46,130	0.4
	1975-76	1,09,750	49,064	0.4
Rajasthan	1974-75	80,500	76,835	1.0
	1975-76	85,050	73,316	0.9
Tamil Nadu	1974-75	3,74,550	8,51,699	2.3
	1975-76	3,63,700	7,99,794	2.2
Uttar Pradesh	1974-75	3,85,050	2,18,463	0.6
	1975-76	4,10,500	2,56,829	0.6
West Bengal	1974-75	8,24,400	9,75,991	1.2
	1975-76	8,42,250	11,10,948	1.3
TOTAL	1974-75	42,55,900	49,05,938	1.2
	1975-76	43,71,200	50,31,833	1.2

XV

Claims in 1974-75 and 1975-76 STATE-WISE

Sickness Benefit			Extended Sickness		Maternity Benefit	
Rate of fresh spells per employee per annum	Average No of S B days per employee per annum	Average daily rate	Rate of fresh cases per 1000 employees per annum	Average duration per terminated case	Rate of confinement per 1000 insured women employees exposed	Average Amount per confinement
6	7	8	9	10	11	12
		Rs.				Rs.
1 09	7 0	4 28	3 6	169.2	83.1	551
1 14	7 1	4 73	3 2	188 9	71.9	692
0 97	6 3	3 84	3 2	218 0	52.7	296
0 72	5 2	3 99	3 5	184 2	52 0	449
0 61	7 2	4 65	2 5	231.1	28 3	498
0 62	7 6	5 15	2 8	277 7	41 3	615
0 25	2 3	4 31	1 4	80 0	82.9	613
0 22	1 8	5 00	0 6	300.0	32 2	668
0 22	2 7	4 80	4 2	230 2	15 6	601
0 26	3 8	5 86	4 4	192 3	16.4	608
0 44	3 9	5 02	5 0	158.1	99.3	346
0 44	3 6	6 49	5 1	149 6	70.4	422
0 24	2 2	4 36	2 5	187.5	15.8	427
0 26	2 4	4 65	2 4	160 7	14.9	514
1 03	7 8	4 72	2 5	171.2	62.0	696
0 83	5 2	5.05	2 2	175.0	57 7	709
1 41	10 5	3 50	3.2	167.9	91.5	370
1 07	6 8	4 18	3.9	165 4	123.1	398
1 01	9 7	4 83	6 3	153.1	32 6	498
1 20	11 2	6 42	14 2	167.8	44.9	442
0 50	3 5	5 34	7 3	143.9	37.0	825
0 52	3 4	6.67	7.4	141 4	29 9	921
0 83	7 4	4 11	2 3	205.3	88.6	402
0 65	5 6	4 49	2 3	180 6	55 4	541
1 54	10 2	5 92	2 6	122 6	37.0	1,091
1 36	6 4	5 71	3 1	175 0	51.0	775
0 24	2 0	3 83	2 3	160 9	14 3	408
0 25	2 0	4.12	1 6	154 5	13.2	484
0 51	4 2	4 78	4 2	171 1	49 5	493
0 41	3 4	5 43	5 9	159 3	33 3	775
1 71	10 2	5 09	3 6	154 4	41 3	494
1 70	8 0	6 43	2 6	153 0	41 8	657
0 38	4 3	4 80	2 4	179 8	50 8	111
0 40	4 9	5 69	2 6	190 7	12 6	530
0 74	5 6	5 24	3 2	202 3	26 1	809
0 84	5 8	5 80	7 4	210 2	35 6	609
0 73	5 5	4 87	4 4	165 0	53 8	509
0 72	5 0	5.83	5 4	166 8	58 0	536

APPENDIX

Incidence of Disablement and Dependants Claims

State	Period	No. of employees deemed exposed to risk	Temporary Disablement Benefit: Rate of fresh spells per employee per annum	Temporary Disablement Benefit: No. of T.D.B. days per employee per annum	Temporary Disablement Benefit: Average daily rate of T.D.B.
1	2	3	4	5	6
Andhra Pradesh	1974-75	1,44,550	0.06	0.89	4.83
	1975-76	1,76,750	0.06	0.80	5.38
Assam	1974-75	18,550	0.04	0.82	4.27
	1975-76	21,300	0.03	0.66	4.49
Bihar	1974-75	78,050	0.03	0.77	5.13
	1975-76	84,900	0.03	0.78	6.01
Chandigarh	1974-75	7,200	0.02	0.34	4.13
	1975-76	7,500	0.01	0.27	4.47
Delhi	1974-75	1,33,500	0 03	0.62	5.17
	1975-76	1,54,750	0 03	0.62	7.64
Gujarat	1974-75	4,09,050	0.07	0.89	5.78
	1975-76	4,57,750	0.07	0.84	7.77
Haryana	1974-75	1,25,250	0.04	0.70	4.64
	1975-76	1,34,300	0.04	0.68	5.47
Karnataka	1974-75	2,26,250	0.06	0.82	5.12
	1975-76	2,42,650	0.06	0.73	6 02
Kerala	1974-75	1,87,050	0.05	0.73	5.25
	1975-76	2,14,150	0.05	0.59	6.27
Madhya Pradesh	1974-75	1,24,200	0.19	3.08	6.02
	1975-76	1,27,800	0.30	2.91	8.03
Maharashtra	1974-75	10,20,150	0.04	0.52	6.04
	1975-76	11,23,350	0.03	0.44	7.48
Orissa	1974-75	51,850	0.05	0.78	4.26
	1975-76	57,750	0.04	0.59	4.89
Pondicherry	1974-75	13,000	0.10	1.16	5.88
	1975-76	13,800	0.09	0.95	7.46
Punjab	1974-75	1,09,000	0.03	0.56	4.64
	1975-76	1,25,750	0.02	0.52	5.11
Rajasthan	1974-75	83,400	0.06	0.87	5.35
	1975-76	94,250	0.03	0.61	5.87
Tamil Nadu	1974-75	3,63,100	0.07	0.72	5.53
	1975-76	3,64,500	0.05	0.52	7.23
Uttar Pradesh	1974-75	4,04,500	0.03	0.70	5.61
	1975-76	4,22,000	0.03	0 68	7.16
West Bengal	1974-75	8,37,500	0.08	1 16	5.85
	1975-76	8,66,200	0.09	1.13	6.59
TOTAL	1974-75	43,36,150	0.06	0.85	5 64
	1975-76	46,89,450	0 06	0.77	6.91

XVI

admitted in 1974-75 and 1975-76—STATE-WISE

Permanent Disablement Benefit				Dependants' Benefit	
No. of fresh cases admitted	Rate of fresh cases per 1000 employees per annum	No. of cases commuted for lumpsum	No. of beneficiaries at the end of the year	No. of death cases admitted	No. of beneficiaries at the end of the year
7	8	9	10	11	12
409	2.83	377	476	26	382
490	2 77	311	655	61	561
53	2.86	40	103	4	73
61	2.86	43	117	2	78
145	1.86	53	423	7	231
152	1.79	144	431	16	254
20	2.78	15	20	..	12
11	1.47	12	19	2	8
543	4.28	372	1,652	16	401
29S					
562	3.88	509	1,742	18	458
38S					
1,693	4.38	1,610	1,134	77	1,150
98S					
1,355	3 19	1,072	1,523	57	1,271
106S					
480	3 83	415	646	16	397
521	3 88	448	718	26	424
581	2 59	498	494	19	535
5S					
491	2.02	324	657	18	567
342	1.83	288	409	7	501
289	1 35	280	418	19	542
208	1.67	130	592	15	440
259	2.03	109	742	13	464
3,664	3.70	2,384	12,961	80	3,196
113S					
3,442	3.38	3,461	13,197	98	3,352
356S					
54	1.04	56	256	5	114
97	1.70	73	275	5	137
1S					
11	0.85	8	23	.	5
22	1.59	26	19	..	5
335	3.07	316	555	15	355
421	3.35	382	591	20	391
172	2.06	131	293	23	327
214	2.27	178	329	14	332
685	1.89	517	999	29	722
3S					
615	1.70	818	798	20	774
4S					
319	0 79	308	3,842	19	957
440	1 04	301	3,981	60	1,128
1,205	1.44	2,439	11,601	71	1,903
6,723	7.76	1,019	17,305	85	1,935
10,919	2.58	9,957	36,479	429	11,701
248S					
16,165	3 55	9,510	43,517	534	12,681
505S					

APPENDIX XVII

Incidence of Permanent Disablement Benefit Claims admitted in 1974-75 and 1975-76—INDUSTRY-WISE

Industry	Period	Estimated No. of employees exposed to risk	No. of accident cases admitted	Rate of P.D.B. cases per 1000 employees per annum
1	2	3	4	5
Food, Beverages and Tobacco	1974-75	2,88,028	289	1.00
	1975-76	3,13,766	324	1.03
Textiles	1974-75	16,92,753	5,715	3.38
	1975-76	17,36,793	9,472	5.45
Leather and Rubber	1974-75	98,014	178	1.82
	1975-76	1,03,692	273	2.63
Chemicals and Chemical Products	1974-75	2,41,767	437	1.81
	1975-76	2,82,452	439	1.55
Non-Metallic Minerals	1974-75	2,25,696	348	1.54
	1975-76	2,03,771	447	2.19
Metallic Minerals	1974-75	3,91,947	1,186	3.03
	1975-76	4,26,461	1,735	4.07
Engineering	1974-75	6,12,542	1,541	2.52
	1975-76	7,24,157	2,015	2.78
Transport	1974-75	2,73,743	638	2.33
	1975-76	2,97,656	876	2.94
Paper and Printing	1974-75	1,83,020	365	1.99
	1975-76	1,99,111	449	2.26
Miscellaneous	1974-75	3,28,640	470	1.43
	1975-76	4,01,591	640	1.59
TOTAL	1974-75	43,36,150	11,167	2.58
	1975-76	46,89,450	16,670	3.55

APPENDIX

The number of Legal Cases filed during the

Name of the Region	Amount involved in cases filed under					
	Section 66		Section 67		Section 73-D	
	Cases	Amount	Cases	Amount	Cases	Amount
		Rs.		Rs.		Rs.
Andhra Pradesh	..	..	..	..	43	254745
Assam	..	..	..	..	..	..
Bihar	..	..	..	..	70	538020
Delhi	..		..	..	9	61462
Gujarat	..	..	..	..	160	124487
Karnataka	1	2751	..	..	77	427353
Kerala	..	..	.	..	..	..
Madhya Pradesh	..	..	..	..	91	210558
Maharashtra	..	.	..	..	449	1665554
Poona	..	..	..	..	153	633342
Nagpur	..	..	..	..	17	855237
Orissa	..	..	..	..	9	49177
Punjab	..		..	..	101	245983
Rajasthan	..	..	..	..	009	11779
Tamil Nadu	..	..	..	..	144	971629
Uttar Pradesh	..	.	..	..	109	873435
West Bengal	..	..	..	..	441	2647528
Total	1	2751	..	..	1882	9570489

XVIII

year 1975-76 and the amount involved Region wise

Section 75(2)/45-B		Amount recovered by action under				No. of Prosecution filed under Section 85
Cases	Amount	Sec. 66	Sec. 67	Sec. 73-D	Sec. 75(2)/45-B	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
509	2765780	2200	..	431456	460680	19
78	294220	..	.	..	132722	..
188	1964418	..	..	330030	436525	45
416	4520969	3567	.	82263	3056554	26
93	1087442	..	..	13026	13463	185
427	2230824	..	..	63636	1027344	32
1375	5243976	..	..	..	1408651	80
165	1695945	28625	..	10927	67721	20
532	2594353	21963	..	485169	517836	1052
127	654465	..	..	82629	87222	102
24	1117867	..	..	16278	16456	33
8	70906	.	..	268344	85575	9
628	3366954	13781	..	962529	2443687	204
113	1445769	11225	..	1783455	118315	9
252	1077581	..	..	222328	305726	66
213	1946380	..	..	1515832	5688947	23
274	1846590	450	..	3498783	16926	350
5422	33924439	81811	..	9766683	15884350	2255

APPENDIX

EMPLOYEES' STATE

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

EXPENDITURE

Previous Year (1974-75)	Heads of Account	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
	1. Benefits to Insured Persons & their families.		
	A. Medical Benefits.		
24,98,12,608	(i) Payments to State Governments etc. as Corporations Share of their expenses on providing medical treatment and maternity facilities etc.	30,80,17,039	
	Deduct :—Payments to State Govts. towards medical care during the year transferred to the Capital Construction/ Medical Reserve Fund.		
24,98,12,608		30,80,17,039	
1,51,80,636	(ii) Medical treatment and care and Maternity facilities (expenses incurred direct by the Corporation)	1,94,95,306	
26,49,93,244	Total A—Medical Benefits		32,75,12,345
	B—Cash Benefits		
11,35,36,831	(1) Sickness Benefit	12,81,80,389	
1,14,56,000	(2) Extended Sickness Benefit	1,40,17,842	
86,03,268	(3) Maternity Benefit	1,02,64,553	
	(4) Disablement Benefit		
2,07,65,636	(a) Temporary	2,48,54,977	
3,42,19,000	(b) Permanent (Capitalised Value)	5,42,40,000	
-	(5) Dependants' Benefit		
93,97,000	(Capitalised Value)	1,16,99,000	
8,96,653	(6) Funeral Benefit	8,95,585	
19,88,74,388	Total B—Cash Benefits		24,41,52,346
46,38,67,632	Total Carried Over		57,16,64,691

XIX

INSURANCE CORPORATION

FOR YEAR ENDED 31ST MARCH 1976

INCOME

Previous Year (1974-75)	Heads of Account	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
	1. Contributions		
60,34,74,995	Employer's and Employees' Shares	73,15,86,339	
2,16,80,542	Employers' Share only	1,78,07,427	
1,00,74,058	Employees' Share only	1,00,09,537	
63,52,29,595	Total Contributions		75,94,03,303
22,50,000	State Government/Union Territories shares towards medical benefits initially incurred by the Corporation	9,94,702	
			9,94,702
..	Grants-in-Aid	..	
	Other Heads of Revenue		
3,47,90,454	Interest & Dividends	4,29,03,524	
1,55,75,398	Compensations	64,48,911	
	Rents, Rates and Taxes :		
5,58,488	(i) Offices of the Corporation (including Staff Quarters)	6,91,664	
1,82,59,511	(ii) Hospitals, Dispensaries & Staff Quarters	2,47,78,048	
93,042	Fees, Fines & Forfeitures	1,69,145	
29,63,122	Miscellaneous	17,47,435	
7,22,40,015	Total of Other Heads of Revenue		7,67,38,727
70,97,19,610	Total Carried Over		83,71,36,732

Previous Year (1974-75)	Heads of Account	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
46,38,67,632	Total Brought Forward		57,16,64,691
	C—Other Benefits		
	(a) Expenditure on the Rehabilitation of Disabled Insured		
74,890	Persons	33,683	
2,44,176	(b) Medical Boards and Appeal Tribunals	3,15,771	
	(c) Payments to Insured Persons :		
1,14,139	(i) Conveyance Charges and/or loss of wages	1,36,509	
..	(ii) Incidental Charges under family planning	..	
..	(b) Grants-in-aid	..	
2,25,523	(e) Miscellaneous	2,35,854	
6,58,728	Total C—Other Benefits		7,21,817
46,45,26,360	Total Benefits to Insured Persons and their families		57,23,86,508
	2. Administration Expenses		
	A—Superintendence		
69,556	1. Corporation, Standing Committee Regional Boards etc.	57,683	
1,81,013	2. Principal Officers	2,30,286	
36,64,180	3. Other Officers	45,15,551	
1,97,92,448	4. Ministerial Establishment	2,38,73,028	
35,21,247	5. Class IV Servants	43,07,210	
79,34,854	6. Contingencies	98,82,613	
3,51,63,298	Total A—Superintendence		4,28,66,371
	B—Field Work		
9,87,722	1. Officers	9,02,917	
1,99,03,554	2. Ministerial Establishment	2,34,96,864	
33,81,517	3. Class IV Servants	38,10,214	
21,55,958	4. Contingencies	24,51,084	
2,64,28,751	Total B—Field Work		3,06,61,079
52,61,18,409	Total Carried Over		64,59,13,958

Previous Year (194-75)	Heads of Account	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
70,97,19,610	Total Brought Forward		83,71,36,732

70,97,19,610	Total Carried Over.	83,71,36,732

Previous Year (1974-75)	Heads of Account	Amount	Total
Rs.		Rs	Rs.
52,61,18,409	Total Brought Forward		64,59,13,958
	C—Other Charges		
2,81,330	1. Legal Charges	2,72,245	
29,282	2. Insurance Courts	3,05,080	
26,133	3. Publicity & Advertisement Charges	22,127	
61,046	4. Charges for maintaining Banking Accounts.	69,319	
1,29,950	5. Audit Fees.	1,39,635	
96,818	6. Leave & Pension Contribution	1,22,199	
2,14,695	7. Depreciation of Office Building/Staff Cars.	2,53,606	
4,99,829	8. Repairs and Maintenance of Office Buildings.	6,28,474	
	9. Retirement Benefits		
42,65,343	(a) Pension Reserve Fund for the Employees of the Corporation.	40,51,493*	
	(b) Corporations' Contribution towards Employees' State		
2,22,357	Insurance Corporation Provident Fund.	2,51,088	
15,92,389	(c) Interest paid to ESIC Provident Fund.	19,46,119	
—	(d) Loss on realisation of Investment.	—	
	(e) Less Interest realised on investment of Provident Fund	--	
(–)29,59,007	Balances.	(—)39,13,674	
12,250	10. Compassionate Reserve Fund	29,240	
	11. Provident Fund Deposit-Linked Insurance Fund.	50,000	
4,506	12. Miscellaneous	8,104	
6	13. Losses	-	
44,76,927	Total C—Other Charges		42,35,055
6,60,68,976	Total Head 2—Administration expenses		1,77,62,505
	3. Hospitals & Dispensaries.		
24,83,087	1. Depreciation of Hospital Buildings	23,92,287	
71,00,034	2. Repairs & Maintenance Hospitals/Dispensaries	69,91,495	
95,83,121	Total Head 3—Hospitals & Dispensaries		93,83,782
54,01,78,457	Total carried over		65,95,32,795

*This excludes Rs. 4,74,182/- pertaining to pensionary liability of the employees of D.M.D. office which is included under "A (ii) Medical Benefits" being shareable expenditure with Delhi Administration.

Previous Year (1974-75)	Heads of Account	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
70,97,19,610	Total Brought Forward		83,71,36,732

70,97,19,610	Total carried over		83,71,36,732

Previous Year (1974-75)	Heads of Account	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
54,01,78,457	Total Brought Forward		65,95,32,795
	4. Capital Construction/Emergency Reserve Fund.		
6,35,22,960	1. Capital Construction	7,59,40,330	
2,12,03,639	2. Emergency Reserve Fund	2,03,32,720	
8,47,26,599	Total Head 4—Capital Construction/Emergency Reserve Fund		9,62,73,050
62,49,05,056	Total Expenditure on Revenue Account		75,58,05,845
8,48,14,554	To excess of Income over Expenditure carried over to Balance Sheet		8,13,30,887
70,97,19,610	GRAND TOTAL		83,71,36,732

New Delhi
Dated 31st May, 1976.

Previous Year (1974-75)	Heads of Account	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
70,97,19,610	Total Brought Forward		83,71,36,732
70,97,19,610	GRAND TOTAL		83,71,36,732

(P. L. GUPTA)
Financial Adviser & Chief Accounts Officer
Employees' State Insurance Corporation

APPENDIX

EMPLOYEES' STATE

Balance Sheet as on

Previous Year (1974-75)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
	Balance of Excess of Income over expenditure		
58,13,76,353	As per last Balance Sheet	66,61,90,907	
8,48,14,554	Accumulations during the year	8,13,30,887	
66,61,90,907		74,75,21,794	
—	LESS Amount transferred to Emergency Reserve Fund from Last Years' Accumulation	—	
66,61,90,907			74,75,21,794
	Capital Construction Reserve Fund		
14,01,15,495	Opening Balance	21,04,24,339	
	Amount transferred from Balance of Excess of Income over Expenditure	—	
6,35,22,960	ADD Provision made during the year	7,59,40,330	
67,85,884	Interest received on Investments	1,13,02,800	
—	LESS Payments made during the year	—	
21,04,24,339			29,76,67,469
	Permanent (Partial and Total) Disablement Benefit Reserve Fund		
10,01,29,732	As per last Balance Sheet	11,61,23,653	
3,42,19,000	Provision made during the year	5,42,40,000	
76,42,100	Interest received from Investments	99,05,014	
1,35,172	Gain on realisation of Investments	—	
14,21,26,004	Total Carried over of this Head	18,02,68,667	
87,66,15,246	Total Carried over		1,04,51,89,263

XX*

INSURANCE CORPORATION

31 March 1976

Previous Year (1974-75)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
	Lands and Buildings (wholly owned by the Corporation).		
	(a) Buildings for Offices of the Corporation		
1,31,76,888	As per last Balance Sheet	1,38,46,193	
6,69,305	Additions during the year	21,42,814	
1,38,46,193		1,59,89,007	
	(b) Hospitals and Dispensaries.		
21,80,26,815	As per last Balance Sheet	23,74,66,984	
1,94,40,169	Additions during the year	2,46,70,535	
23,74,66,984		26,21,37,519	
	(c) Equipments for Hospitals etc.		
25,84,885	As per last Balance Sheet	25,84,885	
—	Additions during the year	—	
25,84,885		25,84,885	
25,38,98,062			28,07,11,411
	Lands and Building (Jointly owned by the Corporation and State Governments) Corporations Share.		
	(a) Hospitals and Dispensaries.		
9,47,201	As per last Balance Sheet	9,47,201	
—	Additions during the year	(—)70,074	
9,47,201		8,77,127	
	(b) Equipments for Hospitals etc.		
49,680	As per last Balance Sheet.	49,680	
	Additions during the year	—	
49,680		49,680	
9,96,881			9,26,807
25,48,94,943	Total Carried over		28,16,38,218

Previous year (1974-75)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
87,66,15,246	Total Brought Forward		1,04,51,89,263
14,21,26,004	Total Brought Forward of this Head	18,02,68,667	
(—)2,06,02,351	LESS Payments made during the year	(—)2,96,42,742	
11,61,23,653			15,06,25,925
	Dependents' Benefit Reserve Fund		
4,86,32,421	As per last Balance Sheet	5,71,34,491	
93,97,000	Provision made during the year	1,16,99,000	
41,00,346	Interest received from Investments	51,98,646	
1,17,785	Gain on realisation of Investments	—	
6,22,47,552		7,40,32,137	
(—)51,13,061	LESS Payments made during the year	(—)57,76,685	
5,71,34,491			6,82,35,452
	Employees' State Insurance Corporation Provident Fund.		
2,19,38,188	As per last Balance Sheet	2,53,87,089	
	ADD amount credited during the year		
65,23,706	(i) Employees' Subscription	78,78,103	
2,22,357	(ii) Corporation's Contribution	2,51,088	
15,92,389	(iii) Interest on (Employees' and Corporation's Shares)	19,05,150	
5,16,519	(iv) D.A. Deposits	18,59,349	
3,07,93,159	Total Carried over of this head	3,72,80,779	

1,04,98,73,390	Total Carried Over	1,26,40,50,640

Previous Year (1974-75)	*Assets*	*Amount*	*Total*
Rs.		Rs.	Rs
25,48,94,943	Total Brought Forward		28,16,38,218
	Suspense (i) Amount Advanced for Capital Expenditure		
6,00,06,749	As per last Balance Sheet	5,46,25,154	
--	ADD Payments made during the year	--	
(-)53,81,595	LESS Adjustments and Recoveries	(-)33,70,626	
5,46,25,154		5,12,54,528	
	(ii) Amount advanced from Capital Construction Reserve Fund.		
4,47,37,262	As per last Balance Sheet	6,81,80,436	
3,96,28,100	ADD Payments made during the year	6,00,01,868	
(—)1,61,84,926	LESS Adjustments and Recoveris	(—)2,58,85,723	
6,81,80,436		10,22,96,581	
12,28,05,590			15,35,51,109
	Staff Cars.		
3,90,759	As per last Balance Sheet	4,43,407	
52,648	ADD Payments made during the year	60,110	
4,43,407			5,03,517
37,81,43,943	Total Carried Over		43,56,93,844

Previous Year (1974-75)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
1,04,98,73,390	Total Brought Forward		1,26,40,50,640
3,07,93,159	Total Brought Forward of the Sub-Head	3,72,80,779	
	LESS Payments made during the year.		
	PF : 6505037		
(—)49,48,378	DA : 719502	(—)72,24,539	
2,58,44,781		3,00,56,240	
	LESS amount transferred to :—		
(—)4,57,692	(i) Pension Reserve Fund	(—)36,114	
—	(ii) Unclaimed deposit	—	
2,53,87,089			3,00,20,126
	Provident Fund Deposit linked Insurance Fund		
—	As per last Balance Sheet	—	
—	Provision made during the year.	50,000	
—	LESS Payments made during the year	—	
—			50,000
	Depreciation Reserve fund of Buildings for the Offices of the Corporation (including Staff Quarters)		
14,78,806	As per last Balance Sheet	17,92,087	
1,80,130	Provision made during the year	2,08,084	
1,33,151	Interest and gain received from investments	1,77,665	
17,92,087			21,77,836

1,07,70,52,566	Total Carried Over	1,29,62,98,602

Previous Year (1974-75)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
37,81,43,940	Total Brought Forward		43,56,92,844
	Permanent Advance to the Heads of Offices of the Corporation	51,011	
41,038	As per last Balance Sheet		
10,063	ADD Payments made during the year	6,840	
51,101		57,851	
(—)90	LESS Recoveries made during the year	(—)1,195	
51,011			56,656
	Advance of Pay on transfer to the Employees of the Corporation		
18,734	As per last Balance Sheet	17,586	
83,804	ADD Payments made during the year	1,06,651	
1,02,538		1,24,237	
(—)84,952	LESS Recoveries made during the year	(—)96,422	
17,586			27,815
	Advance of T.A. on transfer to the Employees of the Corporation		
83,149	As per last Balance Sheet	91,711	
1,06,507	ADD Payments made during the year	1,22,047	
1,89,556		2,13,758	
(—)97,945	LESS Recoveries made during the year	(—)1,44,777	
91,711			68,981
37,83,04,248	Total Carried Over		43,58,46,296

Previous Year (1974-75)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
1,07,70,52,566	Total Brought Forward		1,29,62,98,602
	Depreciation Reserve Fund of Hospital Buildings.		
1,59,32,411	As per last Balance Sheet	1,98,23,149	
24,83,087	Provision made during the year	23,92,287	
13,98,485	Interest received from Investments	19,29,190	
9,166	Loss or Gain or realisation of Investments	—	
1,98,23,149			2,41,44,626
	Depreciation Reserve Fund of Staff Cars		
2,84,404	As per last Balance Sheet	3,43,962	
34,565	Provision made during the year	45,522	
24,993	Interest received from investments	33,476	
3,43,962			4,22,960
	Repairs & Maintenenace Reserve Fund of Buildings for the Offices of the Corporation (including Staff Quarters)		
28,44,143	As per last Balance Sheet	32,69,903	
4,99,829	Provision made during the year	6,28,474	
1,56,253	Interest received from Investments	2,07,034	
246	Gain on realisation of investments	—	
35,00,471		41,05,411	
(—)2,30,568	LESS Payments made during the year	(—)2,11,833	
32,69,903			38,93,578
	Repairs & Maintenance Reserve Fund Accounts of Hospital Buildings		
3,47,42,825	As per last Balance Sheet	4,38,57,162	
71,00,034	Provision made during the year	69,91,495	
24,94,428	Interest received from Investments	35,89,108	
228	Gain on realisation of Investments	—	
4,43,37,515	Total Carried over of this Head	5,44,37,765	
1,10,04,89,580	Total Carried Over		1,32,47,59,766

Previous Year (1974-75)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
37,83,04,248	Total Brought Forward		43,58,46,296
	Advance for the purchase of Conveyance to the Employees of the Corporation.		
9,62,131	As per last Balance Sheet	10,07,452	
5,79,740	ADD Payments made during the year	5,81,031	
15,41,871		15,88,483	
(—)5,34,419	LESS Recoveries made during the year	(—)6,47,039	
10,07,452			9,41,444
	Miscellaneous Advances to the Employees of the Corporation. (Festival Advances)		
3,63,551	As per last Balance Sheet	2,49,430	
5,07,497	ADD Payments made during the year	5,90,115	
8,71,048		8,39,545	
(—)6,21,618	LESS Recoveries made during the year	(—)5,69,906	
2,49,430			2,69,639
	House Building Advance		
21,23,703	As per last Balance Sheet	32,96,614	
14,87,537	ADD Payments made during the year	19,34,700	
36,11,240		52,31,314	
(—)3,14,626	LESS Recoveries made during the year	(—)5,58,417	
32,96,614			46,72,897
	Advance Payments on behalf of State Governments		
6,107	As per last Balance Sheet	6,779	
6,191	ADD Payments during the year	13,389	
12,298		20,168	
(—)5,519	LESS Recoveries made during the year	(—)5,405	
6,779			14,763
38,28,64,523	Total Carried Over		44,17,45,039

Previous Year (1974-75)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
1,10,04,89,580	Total Brought Forward		1,32,47,59,766
4,43,37,515	Total Brought Forward of this Head	5,44,37,765	
(—)4,80,353	Less Payments made during the year	(—)24,24,882	
4,38,57,162			5,20,12,883
	Pension Reserve Fund for the Employees of the Corporation		
4,13,37,616	As per last Balance Sheet	4,96,82,756	
46,59,136	Provision made during the year	45,25,675	
36,87,266	Interest received from Investments	49,44,749	
51,960	Gain on realisation of Investments	—	
4,97,35,978		5,91,53,180	
(—)5,10,914	Less Payment made during the year	(—)6,73,813	
4,92,25,064		5,84,79,367	
	ADD Amount transferred from ESIC		
4,57,692	Provident Fund	36,114	
4,96,82,756			5,85,15,481
	Compassionate Reserve Fund for the Employees of the Corporation		
10,000	As per last Balance Sheet	10,000	
12,250	Provision made during the year	29,240	
22,250		39,240	
(—)12,250	Less Payments made during the year	(—)29,240	
10,000			10,000
1,19,40,39,498	Total Carried Over		1,43,52,98,130

Previous Year (1974-75)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs
38,28,64,523	Total Brought Forward.		44,17,45,039
	Amount advanced to State Govt./ State P.W.D. etc. towards Repairs and Maintenance of Hospitals/Dispensaries, Offices of the Corporation and Staff Quarters.		
	(a) Offices of the Corporation		
8,38,038	As per last Balance Sheet.	9,35,419	
2,23,982	ADD Payments made during the year.	7,73,304	
10,62,020		17,08,723	
(—)1,26,601	LESS Recoveries/Adjustments made during the year.	(—)78,892	
9,35,419			16,29,831
	(b) Hospitals/Dispensaries/Annexes.		
65,04,817	As per last Balance Sheet.	78,49,227	
13,45,175	ADD Payments made during the year.	38,55,943	
78,49,992		1,17,05,170	
(—)765	LESS Receipts during the year.	(—)2,60,718	
78,49,227			1,14,44,452
	Miscellaneous Advances.		
12,32,435	As per last Balance Sheet.	18,42,317	
10,11,002	ADD Payments made during the year.	10,45,288	
22,43,437		28,87,605	
(—)4,01,120	LESS Receipts during the year	(—)10,97,088	
18,42,317			17,90,517
39,34,91,486	Total Carried Over.		45,66,09,839

Previous Year (1974-75)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs	Rs.
1,19,40,39,498	Total Brought Forward		1,43,52,98,130
5,63,56,000	Emergency Reserve Fund From Last Year's Accumulation.	8,22,60,672	
2,12,03,639	Provision made during the year	2,03,32,720	
47,01,033	Interest realised on Investment,	74,22,703	
—	LESS amount transferred to the Revenue Account for meeting the Excess of Expenditure over the Income.		
8,22,60,672			11,00,16,095
	Deposits of Securities.		
2,40,402	As per last Balance Sheet.	3,91,910	
3,19,799	ADD Deposits during the year.	2,82,672	
5,60,201		6,74,582	
(—)1,68,291	Less Deposits repaid during the year.	2,90,742	
3,91,910			3,83,840
	Deduction from Bills Payable to other Parties.		
38,214	As per last Balance Sheet.	73,830	
6,89,878	ADD amount Credited during the year.	8,58,697	
7,28,092		9,32,527	
(—)6,54,262	LESS Payments made during the year	(—)9,05,833	
73,830			26,694
	Unclaimed Deposits in the ESIC Provident Fund.		
8,366	As per last Balance Sheet.	5,795	
(—)653	ADD Amount Credited during the year.	784	
7,713		6,579	
(—)1,918	Less Payments made during the year	—	
5,795			6,579
1,27,67,71,705	Total Carried Over.		1,54,57,31,338

Previous Year (1974-75)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
39,34,91,486	Total Brought Forward.		45,66,09,839
	Loans to State Governments/ Other Parties.		
2,60,33,333	As per last Balance Sheet.	3,02,99,999	
54,00,000	ADD Payments made during the year.	23,58,500	
3,14,33,333		3,26,58,499	
(—)11,33,334	LESS amount refunded by State Governments.	(—)15,33,333	
3,02,99,999			3,11,25,166
	Remittances.		
	Cash Remittances.		
(—)66,76,000	As per last Balance Sheet.	8,48,061	
1,34,97,14,531	ADD Debits adjusted during the year	1,57,08,83,966	
1,34,30,38,531		1,57,17,32,027	
(—)1,34,21,90,470	LESS credits adjusted during the year.	(—)1,57,15,33,028	
8,48,061			1,98,999
	Other Remittances. Exchange Account.		
3,786	As per last Balance Sheet.	(—)1,28,536	
5,91,67,305	ADD Debits during the year.	7,00,90,766	
5,91,71,091		6,99,62,230	
(—)5,92,99,627	LESS Credits during the year.	(—)6,98,63,584	
(—)1,28,536			98,646
42,45,11,010	Total Carried over.		48,80,32,650

Previous Year (1974-75)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
1,27,67,71,705	Total Brought Forward.		1,54,57,31,338
	Deposits from I.L.O. for family Planning Project.		
..	As per Last Balance Sheet.	—	
—	ADD Deposits during the year.	5,00,000	
—	LESS Payments to the Family Planning Project.	(—)5,00,000	—
—	Miscellaneous Deposits.		
17,88,767	As per Last Balance Sheet.	20,19,046	
10,93,435	ADD Deposits received during the year.	59,10,770	
28,82,102		79,29,816	
(—)8,63,156	Less Deposits repaid during the year.	(—)61,54,912	
20,19,046			17,74,904
1,27,87,90,751	Total carried over.		1,54,75,06,42

Previous Year (1974-75)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
42,45,11,010	Total Brought Forward.		48,80,32,650
	Investments at Cost.		
	(1) Permanent (Partial and Total) Disablement Benefit Reserve Fund.		
10,01,27,929	As per last Balance Sheet.	11,61,23,101	
2,62,78,175	ADD Investments made during the year.	3,45,95,000	
12,64,06,104		15,07,18,101	
(—)1,02,83,003	LESS Realisation on Maturity or Sale of Investments.	(—)95,000	
11,61,23,101			15,06,23,101
	(2) Dependants' Benefit Reserve Fund.		
4,86,31,507	As per last Balance Sheet.	5,71,32,292	
1,59,91,400	ADD Investments made during the year.	1,11,03,000	
6,46,22,907		6,82,35,292	
(—)74,90,615	LESS Realisation on Maturity or Sale of Investments.	—	
5,71,32,292			6,82,35,292
	(3) Employees' State Insurance Corporation Provident Fund		
2,19,18,000	As per last Balance Sheet.	2,48,70,000	
61,63,200	ADD Investment made during the year.	37,22,000	
2,80,81,200		2,85,92,000	
(—)32,11,200	LESS Realisation on Maturity or Sale of Investments	(—)2,35,000	
2,48,70,000			2,83,57,000
	(4) Depreciation Reserve Fund of Buildings for the Offices of the Corporation (including Staff Quarters).		
14,76,509	As per last Balance Sheet.	17,91,509	
3,15,000	ADD Investments made during the year.	3,85,000	
17,91,509		21,76,509	
—	LESS Realisation on Maturity or Sale of Investments.	—	
17,91,509			21,76,509
62,44,27,912	Total Carried Over.		73,74,24,552

Previous Year (1974-75)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
1,27,87,90,751	Total Brought Forward.		1,54,75,06,242

1,27,87,90,751	Total Carried Over,	1,54,75,06,242

Previous Year (1974-75)	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
62,44,27,912	Total Brought Forward.		73,74,24,552
	(5) Depreciation Reserve Fund of Equipments in Hospital and Examination Centres.		
—	As per last Balance Sheet.	—	
—	ADD Investments made during the year.	—	
—		—	
	LESS Realisation on Maturity or		
—	Sale of Investments.	—	
—		—	
	(6) Depreciation Reserve Fund of Hospital Buildings.		
1,58,04,359	As per last Balance Sheet.	1,98,22,525	
47,23,225	ADD Investments made during the year.	43,20,000	
2,05,27,584		2,41,42,525	
	LESS Realisation on Maturity or		
(—)7,05,059	Sale of Investments.	—	
1,98,22,525			2,41,42,525
	(7) Depreciation Reserve Fund of Staff Cars.		
2,83,735	As per last Balance Sheet.	3,42,735	
89,100	ADD Investments made during the year.	80,000	
3,72,835		4,22,735	
	LESS Realisation on Maturity or		
(—)30,100	Sale of Investment.	—	
3,42,735			4,22,735
64,45,93,172	Total Carried over.		76,19,89,812

Previous Year (1974-75)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
1,27,87,90,751	Total Brought Forward.		1,54,75,06,242

1,27,87,90,751	Total Carried Over.	1,54,75,06,242

Previous Year 1974-75	Assets	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs.
64,45,93,172	Total Brought Forward.		76,19,89,812
	(8) Repairs and Maintenance Reserve Fund of Buildings for the Offices of the Corporation (including Staff Quarters).		
19,29,994	As per last Balance Sheet.	23,00,240	
5,67,400	ADD Investments during the year.	(—)37,000	
24,97,394		22,63,240	
(—)1,97,154	LESS Realisation on Maturity or Sale of Investments.	—	
23,00,240			22,63,240
	(9) Repairs and Maintenance Reserve Fund of Hospital Buildings.		
2,81,37,050	As per last Balance Sheet.	3,59,47,278	
78,24,800	ADD Investments made during the year.	46,15,000	
3,59,61,850		4,05,62,278	
(—)14,572	LESS Realisation on Maturity or Sale of Investments	—	
3,59,47,278			4,05,62,278
	(10) Pension Reserve Fund for the Employees of the Corporation.		
4,12,31,581	As per last Balance Sheet.	4,96,58,541	
1,81,68,200	ADD Investments made during the year,	88,54,000	
5,93,99,781		5,85,12,541	
(—)97,41,240	LESS Realisation on Maturity or Sale of Investments.	—	
4,96,58,541			5,85,12,541
73,24,99,231	Total Carried Over.		86,33,27,871

Previous Year (1974-75)	Liabilities	Amount	Total
Rs.		Rs.	Rs
1,27,87,90,751	Total Brought Forward		1,54,75,06,242
1,27,87,90,751	GRAND TOTAL		1,54,75,06,242

New Delhi
Dated 31st May, 1976.

Previous Year (1974-75)	Assets	Amount	Total
Rs		Rs	Rs.
73,24,99,231	Total Brought Forward	—	86,33,27,871
	(11) Capital Construction Reserve Fund.		
8,20,28,000	As per last Balance Sheet	11,30,28,000	
8,10,00,000	ADD Investments during the year	2,73,30,000	
	Deduct-Realisation on Maturity or		
(—)5,00,00,000	Sale of Investments	—	
11,30,28,000			14,03,58,000
	(12) Emergency Rserve Fund.		
5,60,00,000	As per last Balance Sheet.	8,20,00,000	
2,60,00,000	ADD Investments during the year.	2,80,00,000	
	Deduct-Realisation on Maturity		
—	Sale of Investments	—	
8,20,00,000			11,00,00,000
	General Cash Balance		
23,25,00,000	Investment as per last Balance Sheet	30,79,37,000	
19,54,37,000	ADD Investments made during the year	22,63,63,000	
42,79,37,000		53,43,00,000	
	LESS Realisation on Maturity or		
(—)12,00,00,000	Sale of Investments	(—)16,60,00,000	
30,79,37,000		36,83,00,000	
13,72,174	Cash in Hand.	16,61,888	
4,19,54,346	Cash with Bankers	6,38,58,483	
4,33,26,520		6,55,20,371	
35,12,63,520	Total Cash Balance		43,38,20,371
1,27,87,90,751	GRAND TOTAL.		1,54,75,06,242

(P L GUPTA)
Financial Adviser and Chief Accounts Officer
Employees' State Insurance Corporation

APPENDIX XXI

Administrative cost compared with Benefits paid etc.

		1970–71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76
I.	Total Administrative cost.	3,71,91,289	4,77,39,056	4,40,34,287	7,34,57,795	6,60,68,976	7,77,62,505
II.	(i) Employees' & Employer's share.	—	—	—	20,37,86,214	60,34,74,995	73,15,86,339
	(ii) Employer's Special Contribution.	29,55,06,981	33,34,80,630	39,61,61,207	21,41,25,502	2,16,80,542	1,78,07,427
	(iii) Employees' Contribution.	16,49,66,819	17,70,05,192	19,16,27,812	22,76,57,964	1,00,74,058	1,00,09,537
	Total Contributions.	46,04,73,800	51,04,85,822	58,77,89,019	64,56,39,680	63,52,29,595	75,94,03,303
III.	Total outgoings (Expenditure on Revenue Accounts.)	44,74,00,835	47,61,40,297	47,23,75,970	59,90,70,572	62,49,05,056	75,58,05,845
IV.	Total Benefits.	36,68,88,880	38,16,11,406	37,13,48,489	45,14,88,325	46,45,26,360	57,23,86,508
	Ratio of Administrative cost to :—						
	II.	8.08%	9.35%	7.50%	7.72%	10.40%	10.24%
	III.	8.31%	10.03%	9.32%	8.32%	10.57%	10.29%
	IV.	10.14%	12.51%	11.86%	11.04%	14.22%	13.59%

Note :—IV does not include share of benefit expenditure borne by the State Governments.

[No. Z-16016/1/77-HI]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(वार्षिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1977

का०आ० 3973—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक आफ बड़ौदा के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का नाम सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इन नियमो में, जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है ।

(ख) 'बैंक' से सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है ।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम मे परिभाषित है, वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में है।

3. बोर्ड के अधिवेशनो की न्यूनतम सख्या—एक वर्ष मे बोर्ड के कम से कम छ. अधिवेशन होगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा ।

4 अधिवेशनो का संयोजन :—अधिवेशनो का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

5. अधिवेशनो का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिर्दिष्ट करे ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :—(1)(क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणत कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नही किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशको के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से माग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम)—बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी .

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अलावा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वत. स्थगित हो जाएगा

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार का कागजो के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत मे बाहर गये निदेशको से भिन्न) को निविष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशको के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशको के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को ससूचित किया जाएगा।

(5) कागजो के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयो को अभिलेखो के लिए अगले अधिवेशन मे रखा जाएगा।

11. कारबार के अभिलेख—(1)(क) बोर्ड के अधिवेशनो के कार्यवृत्तो की पुस्तको (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्याक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तो की प्रतिया प्रत्येक निदेशकों को भेजी जायेगी।

(3) जब कोई कारबार कागजो के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त-पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन मे रखे जाएंगे ।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमो के उपबंधों के अनुसार रखे जाएंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होगे।

[संख्या एफ 4-33/76-ए०सी० (1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 24th November, 1977

S.O. 3973.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Bank of Baroda, hereby makes the following rules, namely. —

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Sultanpur Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);

(b) "bank" means the Sultanpur Kshetriya Gramin Bank;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board, sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four:

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum. If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman of the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each directors as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC(1)]

का० आ० 3974—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सैंट्रल बैंक आफ इंडिया के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) 'बैंक' से 'उत्तर बंग क्षेत्रीय 'ग्रामीण बैंक' अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में है।

3 बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या —एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छ अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन :—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) :—बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अलावा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन :—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, उन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा।

11. कारबार के अभिलेख :—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशकों को भेजी जायेंगी।

(3) जब कोई कारबार कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जाएंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

[संख्या एफ० 4-33/76-ए० सी० (2)]

S.O. 3974.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Central Bank of India, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);

(b) "bank" means the Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board, sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman of the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC(2)]

का०आ० 3975.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 की धारा 29) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और इण्डियन ओवरसीज बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ · (1) इन नियमो का नाम पांड्यान ग्राम्य बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977 है ।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है ।

(ख) 'बैंक' से पांड्यान ग्राम्य बैंक अभिप्रेत है ।

(ग) ऐसे शब्दो और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नही है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है, जो उसके अधिनियम में है ।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या .—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा ।

4. अधिवेशनों का संयोजन —अधिवेशन का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

5 अधिवेशनों का स्थान .—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिर्दिष्ट करे ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची .—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा ।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी ।

(ग) अधिवेशन मे किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी ।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नही किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी ।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन .—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशको से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा ।

(2) इस माग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा ।

8 अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) : बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी ।

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबन्ध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अलावा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी ।

9 गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन : यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वत: स्थगित हो जाएगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10 परिचालन द्वारा कारबार : (1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार की कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा ।

11. कारबार के अभिलेख : (1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा ।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्याक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशकों को भेजी जायेंगी ।

(3) जब कोई कारबार कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे ।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार रखे जाएंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे ।

[सं० एफ० 4-33/76-ए०सी० (3)]

S.O. 3975.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Indian Overseas Bank, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Pandyan Grama Bank (Meetings of Board) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) ;

(b) "bank" means the Pandyan Grama Bank ;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board, sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board :

(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting

stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialled or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC (3)]

का०आ० 3976—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है ।

(ख) 'बैंक' से वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है ।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा ।

4. अधिवेशनों का संयोजन :—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

5. अधिवेशनों का स्थान —बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची —(1)(क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा ।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी ।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी ।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी ।

7 बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा ।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा :

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) :—बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी ।

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबन्ध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अलावा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी ।

9 गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन. यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक-अवकाश दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10 परिचालन द्वारा कारबार.—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा

चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हो, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानो ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशको के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशको को ससूचित किया जाएगा ।

(5) कागजो के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयो को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा ।

11 कारबार के अभिलेख —(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनो के कार्यवृत्तो की पुस्तको (जिन्हे इसमे इसके पश्चात् कार्यवृत पुस्तक कहा गया है) मे रखा जाएगा ।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्याक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक मे प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियो के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तो की प्रतिया प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेगी ।

(3) जब कोई कारबार कागजो के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त पुस्तक मे उसकी प्रविष्टि की जाएगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन मे रखे जायेंगे ।

(5) अधिवेशनो के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबन्धो के अनुसार रखे जाएगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियो का साक्ष्य होगें ।

[सं० एफ० 4-33/76-ए०सी० (4)]

S.O. 3976.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Central Bank of India, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Vaishali Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1977.

They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) ;

(b) "bank" means the Vaishali Kshetriya Gramin Bank;

(c) wards and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board, sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board :

(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3 The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of Board shall be four :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any direcor is unable to take part is the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman of the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC (4)]

का० आ० 3977—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का नाम मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) 'बैंक' से मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं, जो उनके अधिनियम में हैं।

3 बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छ अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4 अधिवेशनों का संयोजन—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

5 अधिवेशनों का स्थान—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6 अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची—(1)(क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिये प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिये प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी।

7 बोर्ड का विशेष अधिवेशन—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिये कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त करने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिये अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इकतीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8 अधिवेशन के लिये गणपूर्ति (कोरम)—बोर्ड के अधिवेशन के लिये गणपूर्ति चार की होगी

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबन्ध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अलावा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9 गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिये, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिये स्वतः स्थगित हो जायेगा

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिये अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10 परिचालन द्वारा कारबार—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उस निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और मान्य कर होगा मानो ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस तारीख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख में लिये अगले अधिवेशन में रखा जायेगा।

11 कारबार के अभिलेख—(1)(क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जायेगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्याक्षरित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशकों को भेजी जायेंगी।

(3) जब कोई कारबार कागजों के परिचालन द्वारा किया जाय तो इस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख का अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जायेगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिये अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार रखे जायेंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

[सं० एफ० 4-33/76-ए० सी० (4)]

S.O. 3977.—In In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and United Commercial Bank, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may the called the Mongthyr Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) ;

(b) "bank" means the Monghyr Kshetriya Gramin Bank;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A busines, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board, sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board :

(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one doys from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.

If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting, stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Busines by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decision on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hreinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialled or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC(5)]

का० आ० 3978.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम मुन्देलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) 'बैंक' से बुन्देलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में है।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या.—एक वर्ष में बोर्ड से कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन.—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

5. अधिवेशनों का स्थान.—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिये प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिये प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के स्थान ही परिचालित की जायेगी।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची मे किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशको के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिये कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिये अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. अधिवेशन के लिये गणपूर्ति (कोरम):—बोर्ड के अधिवेशन के लिये गणपूर्ति चार की होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबन्ध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अलावा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन:—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नही हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिये, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिये स्वतः स्थगित हो जायेगा।

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहा अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिये अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नही हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार:—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजो के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशको के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और बाध्यकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशको के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस तारीख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हो।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशको को संसूचित किया जायेगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख के लिये अगले अधिवेशन मे रखा जायेगा।

11. कारबार के अभिलेख :—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनो के कार्यवृत्तो की पुस्तको (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जायेगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक मे प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियो के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतिया प्रत्येक निदेशकों को भेजी जायेगी।

(3) जब कोई कारबार कागजो के परिचालन द्वारा किया जाये तो इस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और कार्यवृत्त-पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जायेगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिये अगले अधिवेशन में रखे जायेगे।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमो के उपबन्धो के अनुसार रखे जायेंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियो का साक्ष्य होगे।

[सं० एफ० 4-33/76-ए० सी० (6)]

S.O. 3978.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and State Bank of India, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) ;

(b) "bank" means the Bandelkhand Kshetriya Gramin Bank ;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A busines, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of

the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board, sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board :

(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8 Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9 Adjournment of meeting for want of quorum.

If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting, stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11 Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initiated or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC(6)]

का०आ० 3979.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम संथाल परगना ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है ।

(ख) 'बैंक' से संथाल परगना ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है ।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में है ।

3 बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छ अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा ।

4 अधिवेशनों का संयोजन.—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

5 अधिवेशनों का स्थान —बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिर्दिष्ट करे ।

6 अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची —(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी ।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी ।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी ।

7 बोर्ड का विशेष अधिवेशन.—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा ।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा ।

8 अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) —बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी ।

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबन्ध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अलावा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी ।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन.—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10. परिचालन द्वारा कारबार.—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को ससूचित किया जाएगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा ।

11. कारबार के अभिलेख.—(1)(क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों को पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा ।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी ।

(3) जब कोई कारबार कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त-पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे ।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जाएंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे ।

[संख्या एफ० 4 33/76-ए०सी० (7)]

S.O. 3979.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India and State Bank of India, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Santhal Parganas Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" mean the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);

(b) "bank" means the Santhal Parganas Gramin Bank;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of the meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board, sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman of the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC (7)]

का० आ० 3980.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक आफ इंडिया के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम हरदोई-उन्नाव ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है ।

(ख) 'बैंक' से हरदोई-उन्नाव ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है ।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में हैं ।

3 बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छः अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा ।

4. अधिवेशनों का संयोजन :—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची:—(1)(क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा ।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएगी ।

(ग) अधिवेशन में किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जाएगी ।

(घ) यदि इस प्रकार परिचालित कारबार की सूची में किसी कारबार को सम्मिलित नहीं किया गया हो तो अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सम्मति के बिना वह अधिवेशन में नहीं किया जा सकेगा ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाएगी ।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन:—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा ।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा ।

8. अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) :—बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अलावा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी ।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन :—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निविष्ट किया जा सकता है ।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा ।

11. कारबार के अभिलेख :—(1)(क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जाएगा ।

(ख) कार्यवृत्त-पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथासीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशकों को भेजी जायेंगी ।

(3) जब कोई कारबार कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो ऐसे प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त-पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे ।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जाएंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होगे।

[संख्या एफ० 4-33/76-ए० सी० (8)]

सी० आर० विश्वास, उप सचिव

S.O. 3980.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India and Bank of India, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Hardoi-Unnao Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" mean the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);

(b) "bank" means the Hardoi-Unnao Gramin Bank;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) A business, not included in the list of business so circulated, shall not be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and the majority of the directors present.

(2) Where it is necessary to call an emergency meeting of the Board, sufficient notice shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be four :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned, till the same day in the next week, at the same time and place or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by the majority of directors who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in books (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman of the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 4-33/76-AC (8)]

C. R. BISWAS, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1977